

समाज कल्याण विभाग  
बिहार सरकार

# राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय



## वार्षिक प्रतिवेदन



**ANNUAL REPORT 2019-20**





माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैसला बढ़ाते हुये स्पेशल ओलंपिक बिहार के दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय के खिलाड़ी के साथ ।



राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ शिवाजी कुमार डिप्टी चीफ द मिशन एशियन पैरागेम्स की बैठक में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के साथ।



राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) को सम्मानित करते हुये डॉ मौसमी मौमिक (आरसीआई, नई दिल्ली) एक्सपर्ट मेंबर।



मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, भारत सरकार द्वारा आयोजित वार्षिक बैठक नई दिल्ली को संबोधित करते हुये राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) डॉ शिवाजी कुमार।

# वार्षिक प्रतिवेदन

**ANNUAL REPORT**

**2019-20**



राज्य आयुक्त  
निःशक्तता  
(दिव्यांगजन)  
का कार्यालय



# रामसेवक सिंह

मंत्री

समाज कल्याण विभाग  
बिहार सरकार



बिहार सरकार



मुख्य  
सचिवालय

पटना : 800015

दूरभाष : 0612-2215045

फैक्स : 0612-2215045



## संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, अधिकार संरक्षण एवं कल्याण के लिए कार्यरत राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय अपना वार्षिक प्रतिवेदन -2019-20 प्रकाशित कर रहा है. दिव्यांगजनों के लिए अति उपयोगी एवं महत्वपूर्ण यह कार्यालय दिव्यांगजनों के लिए प्रदत्त अधिकारों के संरक्षण एवं अनुपालन कराने का दायित्व का लगातार निर्वहन कर रहा है. साथ ही दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी समाज में सुनिश्चित कर सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराता आ रहा है. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय दिव्यांगजनों से संबंधित परिवारों का निष्पादन कर उन्हें लगातार लाभ पहुंचाया जा रहा है.

मुझे आशा एवं विश्वास है कि यह वार्षिक प्रतिवेदन-2019-20 विभिन्न विभागों के लिए और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयोगी साबित होगा.

मैं इस वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन के अवसर पर राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं.

<https://www.scdisabilities.org/>

-रामसेवक सिंह





## अतुल प्रसाद

भा0प्र0से0, अपर मुख्य  
सचिव समाज कल्याण  
विभाग, बिहार, पटना।



बिहार सरकार

Atul Prasad, IAS  
Social Welfare  
Department, Bihar,  
Patna



## संदेश

दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ कार्यरत राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय, बिहार द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन किया जा रहा है जो एक सराहनीय है। दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत यह कार्यालय जहां एक ओर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति लगातार जागरूक करता रहा है और लगातार संबंधित परिवारों का निष्पादन करता रहा है, वहीं दूसरी ओर समस्त समाज को भी इस ओर अपनी जिम्मेदारियों का अहसास करा कर उस दिशा में सार्थक प्रयास करने के लिए उन्मुख भी करता रहा है।

मैं इस वार्षिक प्रतिवेदन- 2019-20 के प्रकाशन के अवसर पर राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

-अतुल प्रसाद









वा



मुख्य  
सचिवालय



**डॉ. शिवाजी कुमार**

State Commissioner  
Disabilities  
राज्य आयुक्त निःशक्तता  
बिहार, पटना

 **0612-2215041**

 **94310-15499**

scdisability2008@gmail.com  
web: www.scdisabilities.org

षिक प्रगति प्रतिवेदन के संस्करण 2019-20 को प्रकाशित करने में कार्यालय प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। पिछले वर्ष कार्यालय ने सफलता का नया आयाम स्थापित किया है और विकास के नए क्षितिज की ओर अग्रसर है। बिहार के दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम संचालन में मदद करने, कानून प्रदत्त अधिकारों का संरक्षण एवं अनुपालन करवाने, क्षमता का विकास करने में, समाज में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने सहित उन्हें सम्मान जनक स्वतंत्र एवं निर्भीक जीवनयापन के लिए अवसर उपलब्ध कराने की हर संभव कोशिश राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय कर रहा है। इसका मकसद है बिहार के हर दिव्यांगों को एक प्रोडक्टिव नागरिक बनाना। ... और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। समीक्षात्मक बैठक, औचक निरीक्षण, एडवोकेसी बैठक एवं विभिन्न जिलों के भ्रमण सह चलंत न्यायालयों का आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। इससे दिव्यांग लाभुकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है।

गत वर्ष 2019-20 में 20 जिलों में चलंत न्यायालय, 243 प्रखंडों में वादों की सुनवाई कर 72064 परिवादों का निपटारा किया गया, 18 से अधिक कार्यशाला, सेमिनार एवं संबंधित दिवसों का आयोजन में सहभागिता रहा, 89 ऑन द स्पॉट (ग्राउंड जीरो) पर निरीक्षण आदि माध्यमों से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु सार्थक प्रयास किया जा रहा है।

**-डॉ. शिवाजी कुमार**





# विषय सूची



## विषय सूची 2019

क्र०सं०	विषय	
1.	न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्य	13
2.	परिचय : राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय का विवरण	15-22
3.	वार्षिक प्रतिवेदन-2019-20 की समीक्षा	23
4.	नवादा जिला: समीक्षात्मक बैठक/जागरूकता कार्यक्रम	27
5.	कटिहार जिला: लोकसभा चुनाव जागरूकता कार्यक्रम	29
6.	राज्यस्तरीय कार्यशाला (एंटी ट्रैरिज्म डे एवं हिंदी साहित्य)	34
7.	अनुसंधान एवं विकास विषय पर कार्यशाला का आयोजन	35
8.	रक्सौल अनुमंडल : औचक निरीक्षण (ग्राउंड जीरो भ्रमण)	39
9.	नवादा जिला: प्रखंडों में समीक्षात्मक बैठक	40
10.	नवादा जिला: दिव्यांगों को घर पर न्याय (चलंत न्यायालय)	44
11.	दिव्यांगजनों की हितायत बैठक	47
12.	सुपौल : प्रखंडों में औचक निरीक्षण/एडवोकेसी बैठक	50
13.	पंचायत स्तरीय पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक	52
14.	शिवहर जिला : अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक	57
15.	चलंत न्यायालय (शिवहर जिला)	59
16.	खगड़िया जिला में प्रखंडों का भ्रमण एवं परिवादों की सुनवाई	60
17.	खगड़िया जिला: समीक्षा बैठक एवं चलंत लोक अदालत (PwD)	62
18.	तृतीय राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप (पटना)	64
19.	बक्सर जिला : समीक्षात्मक बैठक एवं चलंत न्यायालय	65-68
20.	वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स जूनियर चैंपियनशिप 2019 (उपलब्ध)	72
21.	बिहार में दिव्यांगजन के लिये सरकारी कार्य (अवल देश में)	74
22.	कैमूर जिला : प्रखंडों में बैठक एवं चलंत न्यायालय (PwD)	76-80
23.	चीफ द मिशन बन टोक्यो गये राज्य आयुक्त	87
24.	पूर्वी चंपारण : समीक्षा बैठक एवं लोक अदालत (PwD)	88-91

# विषय सूची 2019-20

## विषय सूची

क्र०सं०	विषय	
25.	गोपालगंज जिला : प्रखंडों का दौरा एवं चलंत न्यायालय	92-94
26.	24 घंटे दर्ज होगी शिकायतें (हेल्पलाइन नंबर)	98
27.	मानसिक स्वास्थ्य विषय पर राज्यस्तरीय कार्यशाला	99
28.	मधुबनी जिला : प्रखंडों का निरीक्षण एवं परिवादों की सुनवाई	104-07
29.	बीएन मंडल विवि में समीक्षात्मक बैठक	101
29.	जिला अरवल : प्रखंडों का दौरा एवं चलंत न्यायालय	116-19
30.	अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर कई कार्यक्रम	121
31.	अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का पाक्षिक कार्यक्रमों- समापन	127
32.	कटिहार जिला : समीक्षात्मक बैठकें एवं चलंत न्यायालय	128-31
33.	किशनगंज जिला: प्रखंडों का दौरा एवं चलंत न्यायालय	133-38
34.	लुई ब्रेल की जयंती : कार्यशाला एवं समारोह आयोजित	142-43
35.	मकर संक्रांति के अवसर पर दिव्यांगजनों का कार्यक्रम	144
36.	न्यूरो दिव्यांगजनों की चिकित्सय उपचार (राज्यस्तरीय कार्यशाला)	146
37.	समस्तीपुर: प्रखंडों का निरीक्षण एवं चलंत न्यायालय	148-51
38.	लखीसराय : अधिकारियों के साथ बैठक एवं लोक अदालत	152-54
39.	शिविर आयोजित : थैलेसीमिया से पीड़ित दिव्यांगजन के लिये	155
40.	अररिया : पांच दिवसीय दौरा (समीक्षात्मक एवं चलंत न्यायालय)	158-62
41.	दिव्यांग व सामान्य खिलाड़ियों की की सहभागिता (बैठक)	164
42.	कोरोना महामारी में दिव्यांगजनों की सेवा	165
43.	सक्सेस स्टोरी: दिव्यांगजनों की सफलता की कहानियां	166-78
44.	एक्सेस ऑडिट (सुलभ एवं सुगम वातावरण) PwD	179-82
45.	समाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट	183-86
46.	स्वयंसेवी संस्थानों की सूची (कार्यालय द्वारा निबंधित)	187-196
47.	आंकड़ों/ग्राफ में कुछ उपलब्धियां	197-199
48.	तुलनात्मक प्रगति प्रतिवेदन (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016)	201



# न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन)

COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

समाज कल्याण विभाग/ Social Welfare Department

बिहार सरकार/ Government of Bihar



## दिव्यांगजनों के परिवादों का सुनवाई

दि

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। उसी कार्य दायित्व के तहत कार्यालय में डाक के माध्यम से प्राप्त, व्यक्तिगत रूप से समर्पित अथवा ई-मेल माध्यम से प्राप्त समस्त परिवादों के निष्पादन हेतु संबंधित सक्षम कार्यकारी पदाधिकारियों से पत्राचार कर मामले के निष्पादन हेतु त्वरित कार्रवाई की गई। गंभीर दीर्घकालिक लंबित मामलों में न्यायालयीय कार्रवाई द्वारा मामलों का निष्पादन किया गया। इस वर्ष वित्तीय 2019-20 कुल 108

(एक सौ आठ) मामलों में न्यायालयीय कार्रवाई के तहत निष्पादन की प्रक्रिया अपनायी गई है। एक ही विभाग आयोग से जुड़े मामलों को समेकित करते हुए परिवादों के त्वरित निष्पादन के लिए तीन विभागों आयोगों के मामलों में न्यायालयीय कार्रवाई/वाद के अन्तर्गत कार्रवाई

की गई। कार्यालय में अपनी शिकायत लेकर आने वाले दिव्यांगजनों के मामले में त्वरित निष्पादन प्रक्रिया के तहत कुल 108 (एक सौ आठ) मामलों में कार्रवाई करते हुए तत्समय ही मामलों का निष्पादन किया गया। इसके साथ विविध मामलों में सलाह प्राप्त करने एवं विविध योजनाओं का लाभ उठाने हेतु प्रक्रियागत जानकारी प्राप्त करने हेतु आगन्तुक दिव्यांगजनों को त्वरित अपेक्षित जानकारी प्रदान कर लाभान्वित किया गया। साथ ही अखबार एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं समस्याओं के विषय में प्राप्त समाचारों/ सूचनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित मामले का निष्पादन किया गया। वाद / परिवादों के अतिरिक्त राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय ने दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में तीन और माध्यम उपलब्ध कराये हैं। इन माध्यमों से भी दिव्यांगजन अपने घर बैठे-बैठे अपनी शिकायत या परेशानियां राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय को भेज सकते हैं जहां से त्वरित कार्रवाई होती है और उनका समाधान तुरंत करने का प्रयास किया जाता है।

20 जिलों, विभिन्न अनुमण्डलों एवं 243 से अधिक प्रखण्डों में हुई चलंत लोक अदालत/ ऑन द स्पॉट सुनवाई के माध्यमों से 72064 परिवाद

### 1. ई-मेल द्वारा समस्या की गई सुनवाई



आज के युग में ई-मेल का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी संवाद पल भर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। इसकी इसी उपयोगिता को देखते हुए राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय ने अपना ई-मेल आईडी scdisability2008@gmail.com जारी किया है। साथ ही प्रदेश भर के दिव्यांगजनों के बीच इस मेल आईडी को प्रसारित करने की कोशिश की है। साथ ही उनसे अनुरोध किया गया है कि जो दिव्यांगजन किसी कारणवश राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय पटना पहुंचने में अपने को असमर्थ पाते हैं वो अपनी शिकायत या समस्याओं को इस मेल आईडी के माध्यम से राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय को भेज सकता है। राज्य आयुक्त निःशक्तता उनकी शिकायत और समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने की कोशिश करता है। वर्ष 2019-20 में ईमेल के माध्यम से निपटारा किये गये मामलों की कुल संख्या 1209 है।





## 2. ध्वनि (voice) रिकॉर्डिंग द्वारा समस्या की सुनवाई

ई-मेल माध्यम के अतिरिक्त राज्य आयुक्त नि:शक्तता ने वैसे दिव्यांगजनों के लिए पहली बार फोन पर ध्वनि (voice) रिकॉर्डिंग कम्प्लेन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है जो ई-मेल पर उपलब्ध नहीं है या जो ई-मेल सुविधा से दूर हैं। ऐसे दिव्यांगजन कार्यालय द्वारा प्रसारित ध्वनि (voice) रिकॉर्डिंग फोन नम्बर 8448385590 पर। अपनी समस्या या शिकायत को किसी भी दिन किसी भी समय रिकार्ड करा सकते हैं। इस ध्वनि (voice) रिकार्ड को प्राथमिकता के आधार सुनकर राज्य आयुक्त नि:शक्तता आवश्यक और उचित कारवाई त्वरित रूप से करते हैं। वर्ष 2019-20 में ध्वनि (voice) रिकॉर्डिंग के माध्यम से आई कुल संख्या 1532 शिकायतों के निपटारे किए गए।

## 3. वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन कम्प्लेन समस्या की सुनवाई

राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) कार्यालय ने दिव्यांगजनों, उनके परिवारों, सरकारी-गैरसरकारी संगठनों, सरकार के विभिन्न विभागों की सुविधा के लिए एक वेबसाइट scdisabilities.org बना रखा है। यह वेबसाइट नियमित रूप से कार्यालय द्वारा अपडेट किया जाता है। इस वेबसाइट में दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाएं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं, राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय की गतिविधियां और उपलब्धियां और दिव्यांगजनों से संबंधित आवश्यक प्रपत्र सभी उपलब्ध होते हैं। यह वेबसाइट आज प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए एक मार्ग दर्शिका की तरह काम करता है। इसपर भी ऑनलाइन शिकायत आती हैं जिसका निपटारा किया जाता है। वर्ष 2019-20 कुल संख्या 534 में ऑनलाइन शिकायत की सुनवाई की गई।



## 4. त्वरित सुनवाई

बिहार राज्य के किसी भी कोने से आये हुए दिव्यांगजनों की विभिन्न तरह की समस्याओं का निष्पादन राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय में त्वरित कारवाई (ऑन द स्पॉट) निष्पादित राज्य आयुक्त नि:शक्तता महदोय द्वारा की जाती है जिसकी कुल आवदों की संख्या वित्तिय वर्ष 2019-2020 में कुल संख्या 487 है।

## 5. हेल्पलाइन द्वारा समस्या की सुनवाई

राज्य आयुक्त नि:शक्तता महदोय द्वार हेल्पलाइन नंबर (8448385590) 24X7 जारी किए। दिव्यांगजनों के लिए विशेष समस्या का समाधान के लिए यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया है इसके माध्यम से वित्तिय वर्ष 2019-2020 कुल संख्या 23,107 दिव्यांगजनों को लाभ मिला।



अगला पेज : 24



# परिचय

## राज्य आयुक्त निःशक्तता दिव्यांगजन का कार्यालय

### राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-60 (वर्तमान में नि-शक्त व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 की धारा-79) के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, बिहार के अंग के रूप में इस कार्यालय का गठन किया गया है। इस कार्यालय के मुख्य कृत्य निम्न है :-

- दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा एवं उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए उनसे प्राप्त आवेदनों/परिवादों पर निर्णय कर उन्हें न्याय उपलब्ध कराना।
- गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थानों का दिव्यांग के क्षेत्र में कार्य करने हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 51 अन्तर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र निर्गत करना।
- हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में विभिन्न विभागों/जिला पदाधिकारियों इत्यादि द्वारा किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण करना एवं तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कर वार्षिक/अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन केन्द्र सरकार/राज्य सरकार को समर्पित करना।

### संगठनात्मक संरचना

इसकी संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है:-

राज्य निःशक्तता आयुक्त

अपर राज्य निःशक्तता आयुक्त

विधि सलाहकार

प्रशाखा पदाधिकारी

सहायक





# राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के कार्यालय की स्थापना का उद्देश्य

के अधीन न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदत्त है।

सिविल प्रक्रिया संहिता

# 1908

**दि**व्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-79 के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को एक पूर्णकालिक राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की नियुक्ति करने का प्रावधान है, जो राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे। उक्त अधिनियम की धारा 80-82 के अधीन राज्य आयुक्त दिव्यांगजन को राज्य के दिव्यांगजनों के कल्याण से संबंधित सभी प्रकार के कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु व्यापक कर्तव्य एवं अधिकार सौंपे गए हैं। इनमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वीकृत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराने हेतु राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करना, योजनाओं के लिए स्वीकृत

राशि का सदुपयोग का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना तथा दिव्यांगजनों को प्रदत्त अधिकारों एवं सुविधाओं का संरक्षण सुनिश्चित करना आदि शामिल है। उक्त अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त दिव्यांगजन को अपने कर्तव्य के दौरान किसी वाद के विचारण हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदत्त है। इस योजना से दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने में मदद मिलेगी। तत्आलोक में बिहार सरकार द्वारा एक राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की नियुक्ति करते हुए राज्य योजना अन्तर्गत एक स्वतंत्र कार्यालय की स्थापना की गई है।

वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में डॉ० शिवाजी कुमार, राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा प्रतिभागिता की गई।

# 17



## राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की 17वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में प्रतिभागिता

राज्य आयुक्तों (दिव्यांगजन) की 23-24 जनवरी' 2020 को नई दिल्ली में आयोजित 17वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में डॉ० शिवाजी कुमार, राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा प्रतिभागिता की गई।

- उक्त बैठक में राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा दिव्यांगजनों से संबंधित अधिनियमों के बिहार राज्य में अनुपालन की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
- दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ राज्य में चालित सामान्य एवं विशिष्ट कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया गया।
- बिहार राज्य द्वारा दिव्यांगजन अधिकार नियम 2016 के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न अयामी कार्यों को सभी के द्वारा सराहा गया।





# दिव्यांगजनों के परिवादों से संबंधित कार्रवाई

**दि**व्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्तों को दिव्यांगजनों द्वारा समर्पित परिवादों के संबंध में कार्रवाई करने एवं इस संबंध में सक्षम प्राधिकारियों को अपनी अनुशंसा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत राज्य आयुक्त दिव्यांगजन को अपने कर्तव्य के दौरान किसी वाद के विचारण हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदत्त है। कार्यालय में डाक

के माध्यम से प्राप्त, व्यक्तिगत रूप से समर्पित अथवा ई-मेल माध्यम से प्राप्त समस्त परिवादों के निष्पादन हेतु संबंधित सक्षम कार्यकारी पदाधिकारियों से पत्राचार कर मामले के निष्पादन हेतु त्वरित कार्रवाई की गई। साथ ही अखबार एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं समस्याओं के विषय में प्राप्त समाचारों/सूचनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित मामले का निष्पादन किया गया। इस संबंध में निम्न आयोजन भी किए गए।

## चलंत न्यायालय का आयोजन



**दि**व्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या

अन्यथा निःशक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के संबंध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जांच करेगा, जिनके लिए राज्य समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इससे जुड़े प्रावधान धारा-80 (ग) से 80(च) में भी वर्णित है।

## उक्त कार्यदायित्व के निर्वहन हेतु दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनसे जुड़े परिवादों के निष्पादन हेतु राज्यन्तर्गत विविध जिलों में चलंत न्यायालय का आयोजन

चलंत न्यायालयों के कार्यक्रम की योजना के परिदृश्य काफी विस्तारित किया है। दिव्यांगों के अधिकारों एवं समस्याओं से जुड़े विषयों पर जिला प्रशासन के विविध विभागों के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य को जागरूक एवं संवेदित करने का कार्य भी इन कार्यक्रमों में प्रमुखता से शामिल किया गया है। इनका तात्कालिक एवं दूरगामी घनात्मक प्रभाव भी दृष्टिगोचर हो रहा है।



## वित्तिय वर्ष 2019-20 में अब तक निम्न जिलों में चलंत न्यायालय का आयोजन किया जा चुका है

वित्तिय वर्ष 2019-20 में अब तक निम्न जिलों में चलंत न्यायालय का आयोजन किया जा चुका है

क्र.सं.	जिला का नाम	आयोजन की तिथि
1.	सीतामढ़ी	27.01.2019 -30.01.2019
2.	सिवान	10.02.2019 -13.02.2019
3.	सुपौल	16.03.2019 -19.03.2019
4.	नवादा	07.06.2019 -11.06.2019
5.	बेगूसराय	19.06.2019 -22.06.2019
6.	शिवहर	02.07.2019 -05.07.2019
7.	खगड़िया	09.07.2019 -12.07.2019
8.	बक्सर	23.07.2019 -26.07.2019
9.	कैमूर (भभुआ)	19.08.2019 -22.08.2019
10.	गोपालगंज	24.09.2019 -27.09.2019
11.	मधेपुरा	09.10.2019 -12.10.2019
12.	पूर्वी चंपारण	15.10.2019 -18.10.2019
13.	मधुबनी	12.11.2019 -15.11.2019
14.	अरवल	19.11.2019 -22.11.2019
15.	कटिहार	17.12.2019 -20.12.2019
16.	किशनगंज	26.12.2019 -30.12.2019
17.	बांका	07.01.2020 -10.01.2020
18.	समस्तीपुर	11.02.2020 -14.02.2020
19.	लखीसराय	18.02.2020 -20.02.2020
20.	अररिया	05.03.2020 -09.03.2020

20 जिलों, विभिन्न अनुमण्डलों एवं 243 से अधिक प्रखण्डों में हुई चलंत लोक अदालत/ ऑन द स्पॉट सुनवाई के माध्यमों से 72064 परिवाद

**समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन एवं परिवादों का निष्पादन**

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के राज्य अन्तर्गत अनुपालन के संबंध में राज्य के सभी जिलों में जिलावार एवं सभी जिलों में प्रखण्डवार विविध क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन किया गया। इस क्रम में राज्य के 38 जिलों, 454 प्रखण्डों एवं 7081 पंचायतों में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन स्थिति की समीक्षा की गई एवं इसके संबंध में आने वाली कठिनाइयों, सुधार इत्यादि के संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये।



लाख दिव्यांगजनों की शिकायतों  
अथवा आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष रूप  
से निष्पादन किया गया।

इन समीक्षात्मक बैठकों के साथ ही कुल-1122 एडवोकेसी बैठके भी आयोजित की गई एवं दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के विविध पहलुओं के संबंध में जागरूकता प्रसार एवं अन्य अनुसंगी कार्य सम्पादित किये गये। चलंत न्यायालयों के दौरान काफी बड़ी संख्या में न्यायालय के समक्ष उपस्थित दिव्यांगों की समस्याओं का चलंत

न्यायालय स्थलपर ही निष्पादन किया गया। इन चलंत न्यायालयों के दौरान लगभग 3.2 लाख दिव्यांगजनों की शिकायतों अथवा आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष रूप से निष्पादन किया गया। साथ ही लगभग 72 लाख दिव्यांगजनों/ आमजनों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एवं राज्य द्वारा दिव्यांगों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं के संबंध में जागरूक किया गया।

## दिव्यांगजन समूहों का गठन

दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम की धारा-72 अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति से संबंधित बैठक एवं त्रिस्तरीय (पंचायत स्तर, प्रखण्ड स्तर व जिला स्तर) दिव्यांगजन समूह का गठन राज्य आयुक्त निःशक्तता के निदेशानुसार किया गया। दिव्यांगजन समूह विविध स्तर पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। इसके माध्यम से करीब 1 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को पंचायत लेवल, प्रखंड लेवल, अनुमंडली लेवल एवं जिला स्तर के दिव्यांगजन समूहों से जुड़ा जा चुका है

## सरकार के सभी विभागों के नोडल पदाधिकारी एवं अतिमहत्वपूर्ण विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव के साथ समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80 (छ) व 80 (ज) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त दिव्यांगजनों के लिए आशयित इस अधिनियम के उपबंधों और स्कीमों, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करेगा तथा दिव्यांगजनों के फायदे के लिए राज्य सरकार द्वारा वितरित निधियों के उपयोजन की मॉनिटरिंग करेगा। इसके अन्तर्गत संबंधित सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ निम्न समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन किया जा चुका है।

विभिन्न जिलों/अनुमंडलों/प्रखंडों/संस्थानों के नोडल पदाधिकारियों के साथ एडवोकेसी/समीक्षात्मक बैठकें।

3.2



# राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, बिहार, पटना के कार्यालय से संबंधित वित्तिय वर्ष 2019-20 का वार्षिक प्रतिवेदन

इसके साथ ही दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण एवं परिवादों के निष्पादन की दृष्टि से निम्न विभागों के सचिव के साथ समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन किया गया।

क्र.सं.	विभाग	बैठक तिथि
1.	विधि विभाग	11.03.2019
2.	बिहार कौशल विकास मिशन	7.06.2019
3.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	05.12.2019
4.	उद्योग विभाग	06.12.2019
5.	आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार	12.12.2019
6.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम	21.12.2019
7.	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार	24.12.2019



## दिव्यांगता प्रक्षेत्र से जुड़े/ कार्यरत स्थानीय संस्थानों/ संस्थाओं व जन सुविधा स्थलों का निरीक्षण



### क्र.सं. संस्थान

1. STET मामले से जुड़े न्यायलीय सुनवाई के तहत सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ बैठक 21.12.2019
2. सरकारी सेवा प्रदाता संस्थानों/दिव्यांगता प्रक्षेत्र से जुड़े

### क्र.सं. संस्थान

- संस्थानों का निरीक्षण जिला में स्थित यथा बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों, विश्व विद्यालय, कॉलेजों, सदर अस्पतालों का निरीक्षण
- जिला के सभी प्रखण्डों का निरीक्षण

जिलों में आयोजित समीक्षात्मक बैठक सह चलंत न्यायालय की तिथियों को

जिलों में आयोजित समीक्षात्मक बैठक सह चलंत न्यायालय की तिथियों को



## अंकेक्षकों के पैनल निर्माण हेतु विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन



सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign) के सफल कार्यान्वयन हेतु अंकेक्षकों के पैनल निर्माण हेतु विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक-09.06.2019 को किया गया।

### प्रशिक्षण/कार्यशाला

क्र.सं.	कार्यशाला का विषय	कार्यशाला की तिथि
1.	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिव्यांग महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण विषय पर कार्यशाला	08.03.2019
2.	विश्व ऑटिज्म दिवस जागरूकता कार्यशाला	02.04.2019
3.	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में विधिक सामर्थ्य (Legal Capacity), संरक्षकता के लिए उपबंध (Provision for Guardianship & Limited Guardianship) तथा समर्थन के लिए प्राधिकारियों के पदाभिधान (Designation of authorities to support) के संबंध में प्रावधानित धाराओं के विषय में कार्यशाला	13.04.2019
4.	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के राज्य अन्तर्गत अनुपालन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों से संबंधित कार्यशाला	15.04.2019
5.	विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर कार्यशाला	12.10.2019
6.	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-72 तथा बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अध्याय-VIII कंडिका-22 के राज्य अन्तर्गत सम्यक अनुपालन एवं दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवृत्त कल्याणकारी उपायों पर जागरूकता का संवर्धन हेतु राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला (Workshop for Capacity Building) प्रतिभागी राज्य के सभी जिलों में गठित त्रिस्तरीय दिव्यांगजनों समूहों के सदस्य।	29.11.2019 एवं 30.11.2019
7.	अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर कार्यालय राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन), बिहार, पटना द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन	03.12.2019
8.	सहायक तकनीकी (Assistive Technology) तथा सहायक उपकरण (Assistive Devices) विषय पर कार्यशाला व उच्च स्तरीय बैठक	29.01.2020 (पूर्वा० व अप० के सत्र में)



# दिव्यांगता से जुड़े महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन



दिव्यांगजनों को दिए गए अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियानों और सुग्रहता का संचालन, प्रोत्साहनसहारा या संवर्धन के कार्यदायित्व का निष्पादन के लिए दिव्यांगता से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यदिवसों का आयोजन किया गया है। इस कड़ी में निम्न दिवसों का आयोजन किया जा चुका है।

## क्र.सं. दिव्यांगजन दिव्यांगता से संबंधित दिवसों का नाम तिथि

1.	विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस (World Autism Awareness Day-WAAD)-ऑटिज्म पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, उनके अधिकारों और स्वतंत्रता का उपयोग करने में सक्षमता हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में वर्णित प्रावधानों एवं उसके अनुप्रयोग हेतु जागरूकता प्रसार से संबंधित कार्यशाला	02.04.2019
2.	हेलेन केलर डे का आयोजन	27.06.2019
3.	विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर कार्यशाला	12.10.2019
4.	अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह	26.09.2019
5.	अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के परिप्रेक्ष्य में दिनांक-02 दिसंबर से 08 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग सप्ताह मनाने एवं इससे जुड़े आयोजन	03.12.2019
6.	लूई ब्रेल दिवस समारोह	04.01.2020

## दिव्यांगता प्रक्षेत्र में गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थानों का निबंधन/पुनर्निबंधन

**दि**व्यांगजन प्रक्षेत्र में कार्यरत संस्थानों का निबंधन/पुनर्निबंधन के संबंध में यथानिर्धारित सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर समाज कल्याण विभाग के अधीन सरकारी/ गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं का माह अप्रैल से कुल 120 का निबंधन/पुनर्निबंधन किया गया है। राज्य निःशक्तता कार्यालय के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 भावी कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यालय हेतु निर्धारित उत्तरदायित्वों के पूर्णरूपेण निष्पादन का कार्य तत्परतापूर्वक किया जा रहा है।

दिव्यांगता से जुड़े महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन



20 जिलों  
में चलंत न्यायालय,  
243 प्रखण्डों में हुई  
वादों की सुनवाई

18  
कार्याशाला,  
सेमिनार, संबंधित  
दिवसों का आयोजन

89 ग्राउंड  
जीरो पर  
निरीक्षण

# वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20

123  
संस्थाओं का  
निबंधन

17  
विभिन्न  
विभागों के  
प्रमुखों के साथ  
बैठक

72064 वाद  
परिवारों का  
निपटारा

रा

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-60 (वर्तमान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-89) के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, बिहार के अंग के रूप में इस कार्यालय का गठन किया गया है। इस कार्यालय के मुख्य कृत्य निम्न है :- दिव्यांगजनों के अधिकारों का संरक्षण,

समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी के लिए उनसे प्राप्त आवेदनों/शिकायतों/परिवारों पर निर्णय कर उन्हें न्याय (आयुक्त न्यायालय/कार्यालय द्वारा) उपलब्ध कराना। सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थानों(NGO, DPO, Parents Association) का दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने हेतु निबंधन कर उन्हें दिव्यांगजनों के लिए शिक्षण/प्रशिक्षण/ खेलकूद/रोजगार एवं पुनर्वास हेतु सहयोग एवं

मार्गदर्शन करना। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों/जिला पदाधिकारियों/प्रखंड पदाधिकारियों/पंचायत स्तर के कर्मचारियों इत्यादि द्वारा दिव्यांगजनों के लिए किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण करना एवं तत्सम्बन्धी अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कर वार्षिक/अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार को समर्पित करना।



## वर्ष 2019-2020 में न्यायालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा गठित वादों व संबंधित सुनवाई की विवरण:-

क्र०सं०	वाद सं०	जिला	वादी एवं प्रतिवादी	विषय
1.	01/2019	पटना	वादी :- श्री रामनाथ प्रतिवादी:-सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना	पेंशन से संबंधित
2.	02/2019	पटना	वादी :- श्री अनिल कुमार, किदवईपुरी, पटना प्रतिवादी :- प्रबंध निदेशक, बी.एस.बी.सी.एल. बिहार स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना	बकाया राशि रूपये का भुगतान स्थगित रखने के संबंध में
3.	03/2019	भागलपुर	वादी :- सुदर्शन कुमार चौधरी, भागलपुर प्रतिवादी :-सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, भागलपुर	पेंशन से संबंधित
4.	04/2019	पटना	वादी :- संस्था "आशादीप" दीघाघाट, पटना प्रतिवादी :- प्रधानाध्यापक, श्री चन्द्र सीनियर सेकेण्ड्री+2 विद्यालय, पटना	कक्षा नवम (IX) में नामांकन/ निबंधन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में
5.	05/2019	मुजफ्फरपुर	वादी :- संस्थान 'शुभम', मुजफ्फरपुर के जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रतिवादी :- सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, मुजफ्फरपुर	संस्थान 'शुभम', मुजफ्फरपुर के जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने
6.	06/2019	पटना	वादी :- श्री अभय कुमार सिन्हा, पटना प्रतिवादी :-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना	अपनी पत्नी के स्थानान्तरण से सम्बन्धित
7.	07/2019	मुजफ्फरपुर	वादी :- मो० कलीम, मुजफ्फरपुर प्रतिवादी :- प्रतिवादी :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	दिव्यांग के साथ लापरवाही बरतने के संबंध में
8.	08/2019	पटना	वादी :- श्री अतुल रंजन, राजीवनगर, पटना प्रतिवादी :- अपर, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना	सरकारी सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण से संबंधित
9.	09/2019	पटना	वादी :- डॉ० प्रमोद चन्द्र तिवारी, पटना प्रतिवादी :- प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना	दानापुर में किसी एक पद पर पदस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में
10.	10/2019	पटना	वादी :- नवल किशोर शर्मा , महासचिव, बिहार नेत्रहीन परिषद, पटना, प्रतिवादी :- बिहार विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड , पटना	दशम वर्ग में नामांकन नहीं किये जाने से सम्बन्धित
11.	11/2019	सहरसा	वादी :- श्री कुन्दन कुमार, सहरसा , प्रतिवादी :-परीक्षा नियंत्रक,बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2019, बिहार, पटना	दृष्टिबाधितों को आरक्षण/ नामांकन नहीं दिये जाने के संबंध में







# अप्रैल 2019



ऑटिज्म जागरूकता  
दिवस के मौके पर...

pg-026



सरल, सुगम एवं  
समावेशी चुनाव...

pg-027



प्रशासन द्वारा PwDs  
वोटर के लिए...

pg-028

## लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदान को मिलेगी सभी सुविधा चुनाव जागरूकता कार्यक्रम



राज्य आयुक्त कहा कि मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं को इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होगी। वहीं दिव्यांगों को मतदान के प्रयोग में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो इसके लिए विद्यालय के बाल सांसद का भी सहयोग लिया जा रहा है।

pg-029



दृष्टिबाधितों ने क्रिकेट में दिखाया जलवा  
ईस्ट जोन क्रिकेट टूर्नामेंट...

pg-030



दिव्यांग मतदाताओं  
को राहत बूथ तक...

pg-031

APRIL 2019



02 | अप्रैल | 2019

# विश्व ऑटिज्म दिवस

जागरूकता कार्यशाला

सुविधा निःशुल्क



300

दिव्यांगजन ने लिया हिस्सा



038

जिलों में कार्यक्रम



15

लाख से अधिक लोग सोशल मीडिया से जुड़े



02

लाख से अधिक लोग जुड़े इस जनजागरण

■ प्रत्येक 20 मिनट पर एक ऑटिज्म के बच्चे की डायग्नोसिस हो रही है।



■ विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के मौके पर लोगों को सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी देते राज्य आयुक्त।

## योजनाओं की दी जानकारीयां

वि

विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के मौके पर लोगों को सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी दी गयी और लोकसभा चुनाव के संबंध में ऑटिज्म प्रभावित दिव्यांगजनों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। राज्य आयुक्त निःशक्तता के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रथम सत्र में मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त डॉ. सुभाष शर्मा

समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद को राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार व अपर आयुक्त, निःशक्तता डॉ. शंभू कुमार रजक ने नीला रीबन लगाकर स्वागत किया। दूसरे सत्र में निःशक्तता आयुक्त के कार्यालय स्थित सभाकक्ष में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विशेषज्ञ डॉ. विनोद भांति एवं बिहार पैरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ राजीव गंगौल, डॉ. उमा शंकर सिन्हा सहित अन्य प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए। कार्यक्रम में मौजूद दिव्यांगजन एवं उनके अभिभावकों व स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच ऑटिज्म पर चर्चा हुई। वहीं वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अक्सर पर अरुणिम स्कूल फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रेन के द्वारा ऑटिज्म पर चर्चा एवं संवाद हुआ। प्रत्येक 20 मिनट पर एक ऑटिज्म के बच्चे की डायग्नोसिस हो रही है। इसका कोई औषधीय उपचार नहीं है। मुख्य रूप से एबीए और अन्य थेरेपी के माध्यम से इसे संयमित एवं ठीक किया जाता है।

### ऑटिज्म पर लोगों को कई जरूरी जानकारीयां दी गईं

बिहार/राज्य - को अक्सर बच्चे में राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यक्रम में विशेष और बिहार पैरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. विनोद भांति और डॉ. सुभाष शर्मा उपस्थित रहे। जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उत्पीड़ित दिव्यांगजन, उनके अभिभावकों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ भाग करते हुए ऑटिज्म के विषय में जागरूकता कार्यक्रम की आयोजन में राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यक्रम के प्रति जागरूकता के प्रयास के लिए आयुक्त निःशक्तता कार्यक्रम की सराहना की।

### हमें साथ की आवश्यकता, सहानुभूति की नहीं



ऑटिज्म के बच्चों की विशेष देखभाल के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार की चिकित्सात्मक उपाय, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं पुर्नवास सहित सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगर अभिभावक ऐसे बच्चों के प्रति जागरूक जागरूक हों तो इसके बेहतर नतीजे देखे जा सकते हैं। **डॉ. शिवाजी कुमार (राज्य आयुक्त निःशक्तता)**



03 | अप्रैल | 2019



# सरल, सुगम एवं समावेशी चुनाव पर समीक्षात्मक बैठक/जागरूकता कार्यक्रम

# जनवादा जिला

रा

ज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा है कि जिले में 12 हजार 243 दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा व्हील चेयर व वाहन की व्यवस्था कराकर मतदान कराई जाएगी। वह बुधवार को समाहरणालय सभागार में 21 प्रकार के दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा मतदान की सुविधा की समीक्षा के दौरान पत्रकारों को की गयी व्यवस्था की जानकारी दे रहे थे। उनके साथ स्वीप प्रभारी व जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी गुप्तेश्वर कुमार भी उपस्थित थे। डॉ. शिवाजी ने कहा कि देश में पहली बार दृष्टिबाधित के लिए



### ■ दिव्यांगजनों को मतदान के प्रति जागरूकता रैली।

ईवीएम में ब्रेल लिपि की सुविधा प्रदान की गई है ताकि वे आराम से मतदान कर सकें। विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ के माध्यम से चिह्नित निःशक्त वोटों के लिए बूथों तक लाने व वोट करने के बाद उन्हें पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। विभिन्न प्रकार की दिव्यांगजन से पीड़ित वोटों को उनकी आवश्यकतानुसार मदद करने के लिए उपाय तैयार करने को राज्य निःशक्तता आयुक्त ने मौके पर कहा। बूथों पर स्काउट व गाइड के कैडरों को हेल्पर के रूप में तैनात किया गया है।

एक भी निःशक्त या दिव्यांग वोट से ना चुकें निर्वाचन आयोग इसके लिए पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था कर रहा है। यह बातें कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान राज्य निःशक्तता (सह

दिव्यांगजन) आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा। उन्होंने प्रेस वार्ता के क्रम में बताया कि लोकसभा चुनाव 2019 में निर्वाचन आयोग द्वारा निःशक्त जनों एवं दिव्यांगों को निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता के लिए घर से बूथ तक आने एवं घर पहुंचाने तक की वाहन की भी सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। पहली बार मतदान करने वाले दिव्यांगजन को सम्मान पत्र प्रदान किया जायेगा।

मौके पर आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं के लिए जानकारी व सहायता पुस्तिका बीएलओ व अन्य माध्यमों से बांटा जायेगा। स्वीप कार्यक्रम के तहत हो रहे आयोजन में निर्वाचन से संबंधित जानकारी दिया गया। पत्रकारों के लिए किये गये वर्कशॉप में प्रोजेक्टर के माध्यम से सभी प्रकार के जानकारियों को बारी-बारी से समझाया गया। विभिन्न बूथों पर की गयी तैयारियों तथा निःशक्त वोटों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताया गया। ईवीएम पर लिखे 1 से 16 तक की गिनती को भी दिखाया गया, जो दृष्टिबाधित वोटों के लिए मतदान करने में सहायक साबित होगा।



**12243**

दिव्यांगजन को मदद



**250**

दिव्यांगों ने लिया हिस्सा



**50000**

लोग सीधे जुड़े कार्यक्रम से



**25000**

से अधिक लोगों तक पहुंच

### दिव्यांगों को मिलेगी मतदान की सुविधा : शिवाजी



### व्यवस्था • आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा- घर से जाने एवं घर पहुंचाने तक की निःशुल्क व्यवस्था आयोग कर रहा ऐसी व्यवस्था कि एक भी दिव्यांग वोट से न चूके





11 | अप्रैल | 2019

# प्रशासन द्वारा PwDs वोटर के लिए सुलभ चुनाव जागरूकता कार्यक्रम



## बांका जिला

**लो**

कतंत्र की मजबूती के लिए एक-एक वोट का महत्व है। शत प्रतिशत मतदान से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। इस कड़ी में दिव्यांग मतदाताओं को विशेष रूप से सुविधा देने के प्रति निर्वाचन आयोग कटिबद्ध है। लिहाजा सभी पीसीसीपी को दिव्यांग मतदाता के घर पर पहुंचकर वाहन से मतदान केंद्र तक लाने और वोट के बाद उन्हें घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गयी है। उक्त बातें परिसदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि दिव्यांग का मतदान शत प्रतिशत हो इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा सभी प्रयास किये जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुगम, सरल एवं समावेशी मतदान कराने का निर्णय लिया है। बांका जिले में करीब 13,297 दिव्यांगों को चिह्नित किया गया है। जिसमें लोको मोटर के 7,530 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। दिव्यांग मतदाता की पहचान संबंधित प्रखंड के बीडीओ व बीएलओ द्वारा किया गया है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए सभी बूथों पर लगभग सारी तैयारी की गयी है। इस मौके पर टीओ नवल किशोर यादव, एडीपीआरओ योगेंद्र लाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। दिव्यांगों की सूची में 21 लक्षण वाले लोगों को शामिल किया गया है। इसमें चलन संबंधी, मांसपेशीय दुर्विकार, ठीक किया हुआ कुष्ठ, बौनापन, प्रमस्तिष्क घात, अम्ल हमले की पीड़ित, कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण क्षति, सुनने में कठिनाई, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट



■ दिव्यांगजनों की शिकायतों को सुनते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार।

**21** प्रकार के दिव्यांगजन को फायदा



शिक्षण दिव्यांगता, ऑटिज्म शिक्षण दिव्यांगता, मानसिक रूग्णता, क्रोनिक स्ननायविक स्थिति, बहुत काठिन्य, पार्किन्सन रोग, हीमोफीलिया, थैलेसिमिया, सिकल सेल रोग शामिल हैं। इसके पूर्व राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार औचक निरीक्षण करने शंभुगंज प्रखंड पहुंचे। जहां क्षेत्र के दर्जनों दिव्यांग मतदाताओं से मिलकर उनके हाल को जाना। गिरधारा गांव के दिव्यांग मतदाता चंदन कुमार, पवन पासवान, निर्मल मंडल, आरती कुमारी सहित आधे दर्जन से अधिक दिव्यांगों ने ट्रायसाइकिल नहीं मिलने की शिकायत की। वे जन्म से ही पैर से लाचार हैं।

फायदा



**13297**

दिव्यांग वोटर हुए चिह्नित



**150**

दिव्यांगजन ने लिया हिस्सा



**50**

हजार लोग सीधे जुड़े कार्यक्रम से



**23**

हजार से अधिक लोगों तक पहुंच

### दिव्यांगों के लिए बूथ पर विशेष सुविधा

बांका जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, बांका

05 अप्रैल को बूथों में 21 प्रकार के दिव्यांग मतदाताओं को विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी।

21 दिव्यांग मतदाताओं को विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी।

13297 दिव्यांग मतदाताओं को चिह्नित किया गया है।

आयुक्त निःशक्तता विभाग	बूथ पर लगे उपकरण
बांका जिला	1776
अररिया जिला	2280
बेगूसराय जिला	2100
बिहार जिला	4470
बक्सर जिला	1940
सुपौल जिला	2240
मधेपुरा जिला	1410

कुल 13297 दिव्यांग मतदाताओं को विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी।

बिहार सरकार सभी प्रकार के दिव्यांगों के लिए कार्य कर रही है। जिन्हें भी अबतक कोई भी सुविधा नहीं मिला है। उन्हें चिह्नित कर योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो इसके लिए समुचित व्यवस्था चुनाव आयोग की ओर से की जा रही है। आप सभी मतदान में हिस्सा जरूर लें। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार



12 | अप्रैल | 2019

VOTE

# लोकसभा चुनाव में मतदान को मिलेगी सभी सुविधा चुनाव जागरूकता कार्यक्रम



विभिन्न  
योजनाओं



11747

हैं दिव्यांग  
मतदाता



700

लोगों ने  
जागरूकता  
कार्यक्रम में लिया  
हिस्सा



50

हजार लोग  
सोशल मीडिया  
से जुड़े



30

हजार लोगों तक  
पहुंची सूचना



नेत्रहीन मानसी परिवर्जन के साथ।



■ दिव्यांगजनों को कई योजनाओं की दी गयी जानकारी

## दिव्यांगजनों को मिली सरकारी योजनाओं की जानकारी

संवाददाता कटिहार

चुनाव को लेकर निःशक्तता विभाग के राज्य आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार औचक निरीक्षण करने प्रखंड पहुंचे। जहाँ क्षेत्र के दर्जनों दिव्यांग मतदाताओं से मिलकर उनके हाल को जाना। गिरधारा गांव के दिव्यांग मतदाता चंदन कुमार, पवन पासवान, निर्मल मंडल, आरती कुमारी सहित आधे दर्जन से अधिक दिव्यांगों ने ट्रायसाइकिल नहीं मिलने की शिकायत की। वे जन्म से ही पैर से लाचार हैं। इसके बाद भी सुविधा नहीं मिली। चुनाव को

लेकर निःशक्तता विभाग के राज्य आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार औचक निरीक्षण करने प्रखंड पहुंचे।

जहाँ क्षेत्र के दर्जनों दिव्यांग मतदाताओं से मिलकर उनके हाल को जाना। गिरधारा गांव के दिव्यांग मतदाता चंदन कुमार, पवन पासवान, निर्मल मंडल, आरती कुमारी सहित आधे दर्जन से अधिक दिव्यांगों ने ट्रायसाइकिल नहीं मिलने की शिकायत की। वे जन्म से ही पैर से लाचार हैं। इसके बाद भी सुविधा नहीं मिली।

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर विशेष व्यवस्था की गयी है। जिला अतिथि गृह में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं को इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होगी। वहीं दिव्यांगों को मतदान के प्रयोग में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो इसके लिए विद्यालय के बाल सांसद का भी सहयोग लिया जा रहा है। बूथ तक लाने एवं वापस घर तक छोड़ने की प्रशासनिक स्तर से तैयारी की गयी है। इसके लिए वाहनों की व्यवस्था भी की जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों के लिए रैंप एवं व्हील चेरर की व्यवस्था रहेगी।

उन्होंने कहा कि पहली बार मताधिकार का प्रयोग करनेवाले दिव्यांग मतदाताओं को निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में सम्मान पत्र दिया जायेगा। राज्य आयुक्त ने कहा कि नेत्रहीन मतदाताओं के लिए बूथों पर ब्रेल लिपि में डमी बायलट पेपर की व्यवस्था रहेगी। दिव्यांग मतदाताओं के मतदान केंद्रों पर अलग कतार लगाया जायेगा। मानसिक एवं मंद बुद्धि दिव्यांग मतदाता अपने माता-पिता की मदद से वोट दे सकते हैं। उनको सहयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति होगी। प्रत्येक मतदान केंद्र के संबंध बीएलओ द्वारा पहचान के बाद डाटा बेस तैयार किया गया है। जहां तक संभव हो

# कटिहार जिला

सके मतदाता मार्ग दर्शिका, पर्ची एवं पहचान पत्र दिव्यांग जनों के लिए अलग से तैयार किया जाये। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अलावे जो दिव्यांगजन पहली बार मतदान करेंगे उन्हें संबंधित बीडीओ द्वारा सम्मान पत्र प्रदान किया जायेगा। इसके बाद जिला के अधिकारियों के साथ समाहरणालय में राज्य निःशक्तता आयुक्त ने समीक्षा बैठक की। जिसमें उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। गौरतलब है कि कटिहार जिला अंतर्गत 11,747 दिव्यांग मतदाता है। कटिहार जिला के लिए दिव्यांग आईकॉन के रूप में मानसी का चयन हुआ है, जो स्थानीय दुर्गा स्थान की रहनेवाली है। समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के जिला स्वास्थ्य प्रबंधक, जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक, बुनियाद केंद्र के डीपीएस, सहित विशाल फाउंडेशन एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।





15 | अप्रैल | 2019

# दृष्टिबाधितों ने क्रिकेट में दिखाया जलवा ईस्ट जोन क्रिकेट टूर्नामेंट

SCF मुजफ्फरपुर जिला

स्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से कैंप लगाकर उन्हें खेल के गुणों से अवगत कराया जा रहा है।

इधर पहले मैच में बीआरए बिहार विवि की टीम ने मुजफ्फरपुर में आयोजित लीग में नॉर्थ ओड़िशा विवि को 79 रनों से पराजित किया। टॉस जीत कर नॉर्थ ओड़िशा विवि ने पहले बीआरए बिहार विवि को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम ने निर्धारित 40 ओवरों में 199 रन बनाए। इसमें शिवम ने 50 रन, प्रांशु ऋषिकेश ने 35 और अभिषेक सिन्हा ने 29 रनों का योगदान दिया। जवाब में नॉर्थ ओड़िशा विवि की टीम 121 रनों पर सिमट गई। टूर्नामेंट में बेहतर करनेवाले बिहार टीम के सदस्यों का चयन नेशनल टूर्नामेंट के लिए किया गया।



क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन डॉ. शिवाजी कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया।



# बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे

बिहार के बच्चों के बीच निःशक्तता चिंता की बात है क्योंकि इसके व्यापक निहितार्थ होते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में दर्शाया गया कि उम्र 0 से 18 वर्ष उम्र समूह के 8.3 लाख बच्चे निःशक्त थे जिनका उम्र के कुल बच्चों में 1.63 प्रतिशत हिस्सा था। निःशक्त लड़कों का लड़कों की कुल आबादी में 1.80 प्रतिशत और निःशक्त लड़कियों का कुल लड़कियों में 1.44 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, संपूर्ण भारत के स्तर पर निःशक्त बच्चों का कुल बच्चों में 1.57 प्रतिशत हिस्सा था। यौतल्लव है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लगभग 90 प्रतिशत निःशक्त बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में थे और मात्र 10 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में। वहीं, तेज शहरीकरण के कारण संपूर्ण भारत के स्तर पर स्थिति कुछ भिन्न थी जहां 76 प्रतिशत निःशक्त बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में थे और 24 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में। दुख की बात है कि 2001 और 2011 के बीच निःशक्त बच्चों की संख्या बिहार और भारत, दोनों जगह शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बढ़ी।

तालिका 12.2 : विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (0-19 वर्ष) (2001 और 2011)

(आंकड़े हजार में)

भारत/ बिहार	लड़का/ लड़की	2011		2001	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
भारत	लड़का	3363.63	1054.93	3124.12	1258.01
	लड़की	2508.92	804.72	2466.35	1014.45
बिहार	लड़का	435.00	49.77	459.43	58.61
	लड़की	312.09	36.40	366.28	48.71

स्रोत : जनगणना 2001 और 2011



16 | अप्रैल | 2019

VOTE

## दिव्यांग मतदाताओं को राहत बूथ तक पहुंचाएगा प्रशासन

लो

मधेपुरा जिला



कसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं को सुगम सामग्री और सहज मतदान प्रक्रिया में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मधेपुरा के समाहरणालय सभागार में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजनों को मतदान करने में कोई परेशानी न हो इसके लिए पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। राज्य आयुक्त ने कहा कि मधेपुरा लोकसभा में 9,579 दिव्यांग मतदाता है। इसके बावजूद अगर दिव्यांग मतदाता का नाम पीडब्लूडी के मैपिंग पंजी में नहीं चढ़ पाया है वो अपना नाम मैपिंग पंजी में चढ़ा सकते हैं। राज्य आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं का शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने को मतदान केंद्र तक लाने एवं पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। इसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गयी है। दिव्यांगों के बूथ पर पहुंचने पर उसे पहली प्राथमिकता देते हुए बिना कतार में खड़ा किये मतदान करवाना सुनिश्चित करेंगे। सभी बीएलओ दिव्यांगजनों की पहचान उनके दिव्यांगता का प्रकार के रूप में करें। आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के आधार पर दिव्यांगजनों की सूची तैयार कर इसे केंद्र पर चिपकाएं। उन्होंने दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर,

दिशा निर्देश

9579

दिव्यांग वोटर हैं लोस में

120

जिला प्रशासन के लोग जानें

5000

लोग जुड़े कार्यक्रम से

21000

आमलोग हुए जागरूक



● स्कूल दिव्यांग बच्चों को सिर्फ इसलिए नामांकन लेने से नहीं मना कर सकता कि वे दिव्यांग हैं।

रैंप, शौचालय और पार्किंग सहित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे दिव्यांग मतदाता जो, मानसिक एवं बौद्धिक रूप से मतदान करने में सक्षम नहीं है उनके साथ उनके परिवार के कोई एक सदस्य सहयोग के लिए मतदान केंद्र के अंदर जा सकता है। वहीं दिव्यांगों को बूथ तक लाने के लिए वोलेंटियर भी रखा जाए। जिन्हें इसके एवज में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मौके पर अपर समाहता सह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पवन



दिव्यांगों के अधिकारों को लागू करें सीबीएसड स्कूल : आयुक्त

सीबीएसड ने सभी स्कूलों को एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि दिव्यांगों को दिये अधिकारों व सुविधाओं को स्कूलों में अक्षरशः पालन किया जाये। राज्य निःशक्तता आयुक्त के निर्देश के बाद सीबीएसड ने राज्य के सभी स्कूलों को पत्र के माध्यम से यह सूचना भेजी है। पत्र में सीबीएसड ने लिखा है कि जागरूकता की कमी की वजह से दिव्यांग बच्चों को उनके हिस्से का लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे दिव्यांग जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, उन्हें एग्जामिनेशन फीस व रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना है।

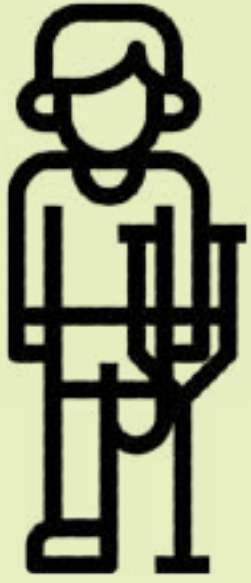
कुमार, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी रजनीश कुमार सहित अन्य मौजूद थे।

लोकसभा चुनाव - दिव्यांगजनों को राहत-पतिशत मतदान कराने का है उद्देश्य, आयुक्त ने दिशा निर्देश व सुझाव  
मतदान के दिन दिव्यांगों को बूथ पर लाने और घर पहुंचाने की व्यवस्था करेगा प्रशासन : आयुक्त



■ बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी लेते राज्य आयुक्त निःशक्तता।





MAY 2019

# मई 2019



## दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016

दिव्यांगजन व्यक्तियों का अधिकार विधेयक- 2016" को दोनों सदनों राज्य सभा और लोकसभा ने पारित कर दिया. इस दिव्यांगजनता विधेयक ने दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम.

pg-33

## दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 21 के ऊपर जनजागरूकता कार्यक्रम

राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ शिवाजी कुमार ने कहा कि किसी भी निजी संस्थान में कार्यरत 20 कर्मचारियों में एक दिव्यांगजन को रखना अनिवार्य है.

pg-34

## अनुसंधान एवं विकास कार्य...

समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने कहा कि दिव्यांगता के क्षेत्र में ऐसा शोध होना चाहिए...

pg-35

## बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन

कविताएँ मन की घनी-भूत पीड़ा को अभिव्यक्ति हीं नहीं करती, व्यथा को तरल बना, बहाकर निकालती भी है और आँखों के आँसू भी पोंछती है।

pg-34





16 | मई  
2019



# दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 अनुपालन हेतु समीक्षात्मक बैठक



दि

दिव्यांगजन व्यक्तियों का अधिकार विधेयक-2016" को दोनों सदनों राज्य सभा और लोकसभा ने पारित कर दिया. इस विधेयक ने दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान ले लिया है. अधिनियम में निर्धारित दिव्यांगजनता की 7 शर्तों के स्थान पर यह विधेयक 21 शर्तों को कवर करता है. साथ ही इस विधेयक ने दिव्यांगजनता के लिए

माने जानी वाली 21 शर्तें इस प्रकार हैं— दृष्टिहीनता, कमजोर- दृष्टि, कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुके व्यक्ति, बधिर ( बहरे और मुश्किल से सुन सकने वाले), चलने में अक्षम, बौनापन, बौद्धिक दिव्यांगजनता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, मांसपेशी दुरविकार, स्थानीय स्नायविक परिस्थितियां, विशिष्ट प्रज्ञता अक्षमताएं, मल्टीपल स्केलेरोसिस, भाषण और भाषा संबंधी दिव्यांगजनता, थैलेसीमिया, होमोफिलिया, सिकल सेल बीमारी, एसिड अटैक के पीड़ित और पार्किंसन बीमारी.

वर्ष 2011 की जनगणना से पता चलता है कि भारत में दिव्यांगजनों की कुल संख्या करीब 2.68 करोड़ या आबादी का 2.21% है. विधेयक से बड़ी संख्या में अक्षम लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने की उम्मीद की जा रही है क्योंकि इसमें 1995 के अधिनियम की तुलना में अधिक दिव्यांगजनों को कवर किया गया है. इसके अलावा विधेयक में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के फैसले को भी अपनाया गया है क्योंकि विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार दुनिया की कुल आबादी का करीब 15 प्रतिशत किसी- न- किसी प्रकार की दिव्यांगजनता से जूझ रहा है.

विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार दुनिया की कुल आबादी का करीब 15 प्रतिशत किसी- न- किसी प्रकार की दिव्यांगजन से जूझ रहा है.

किसी भी अन्य शर्त को अधिसूचित करने के लिए सरकार का रास्ता साफ कर दिया है. विधेयक को 2014 में पेश किया गया था. उस समय इस विधेयक में दिव्यांगजनता के लिए 19 शर्तें थीं. इस विधेयक के तहत दिव्यांगजनता

## श्रेणियों की सूची



1. Locomotor Disability
2. Leprosy Cured Person
3. Cerebral Palsy
4. Dwarfism
5. Muscular Dystrophy
6. Acid Attack Victims
7. Blindness
8. Low Vision
9. Deaf
10. Hard of Hearing
11. Speech and Language Disability
12. Intellectual

- Disability
13. Specific Learning Disabilities
14. Autism Spectrum Disorder
15. Mental Illness
16. Multiple Sclerosis
17. Parkinson's Disease
18. Haemophillia
19. Thalassemia
20. Sickle cell Disease
21. Multiple Disability



# दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 21 के ऊपर जनजागरूकता कार्यक्रम

रा

ज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ शिवाजी कुमार ने कहा कि किसी भी निजी संस्थान में कार्यरत 20 कर्मचारियों में एक दिव्यांगजन को रखना अनिवार्य है। अगर नयी नियुक्ति की जा रही है, तो दिव्यांगजन समान अवसर नीति के तहत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 21(2) का पालन करना जरूरी है। अन्यथा अधिनियम का पालन नहीं करनेवाले निजी संस्थानों का निबंधन रद्द होगा। 21 मई 2019 पूरे राज्य में अधिनियम 2016 की धारा 21(2) को लागू कर दिया गया है। राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय में निजी स्थापन के लिए दिव्यांगजन समान अवसर नीति जारी करते हुए बातचीत में डॉ शिवाजी ने उक्त बातें कहीं। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत समान अवसर नीति लागू करते हुए निजी संस्थानों में दिव्यांगों को पांच फीसदी आरक्षण मुहैया कराना है। साथ ही नियम के अनुसार सुविधा भी देनी है। राज्य सरकार ने राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय में इस संबंध में निबंधन कराया है।

अधिनियम का पालन नहीं करनेवाले निजी संस्थानों का निबंधन रद्द होगा।

अधिनियम के तहत समान अवसर नीति लागू करते हुए निजी संस्थानों में दिव्यांगों को 5% आरक्षण मुहैया कराना



**145**  
सेमिनार में  
थे शामिल



**3000**  
लोग सीधे जुड़े  
कार्यक्रम से



**500**  
दिव्यांग  
शामिल हुये



**26** हजार  
लोग जानें  
मीडिया से

मिली प्रशंसा

## बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन

क

विताएँ मन की घनी-भूत पीड़ा को अभिव्यक्ति हीं नहीं करती, व्यथा को तरल बना, बहाकर निकालती भी है और आँखों के आँसू भी पोंछती है। यह केवल कवि या कवयित्री की हीं नहीं होती, पीड़ा के सनासर से जुड़े हर एक व्यक्ति की होती है। संभवतः इसीलिए इसे लोक-रंजक और लोक-कल्याणकारी भी माना जाता है। इसे हीं 'साहित्य' कहा जाता है, जो सदैव हीं समाज के 'हित' में खड़ी दिखती है, भले हीं शब्दों में वह निजी पीड़ा लगती हो। इनकी सक्रियता और श्रम अत्यंत प्रशंसनीय है। कवयित्री ने नारी-मन, प्रकृति, प्रेम, समाज की पीड़ा और संघर्ष समेत मानवीय-पक्ष से जुड़े प्रायः सभी तत्त्वों को अपनी कविता का विषय बनाया है। इनकी भाषा 'काव्य-भाषा' बनने की प्रक्रिया में है। इनकी कविताओं में छंद के प्रति रुझान दिखती है, किंतु कोई विशेष आग्रह नहीं। बिहार के निःशक्तता आयुक्त डा शिवाजी कुमार ने अपने विचार व्यक्त किए तथा कवयित्री को शुभकामनाएँ दी।

लोक-रंजक और लोक-कल्याणकारी भी माना जाता है। इसे हीं 'साहित्य' कहा जाता है, जो सदैव हीं समाज के 'हित' में खड़ी दिखती है, भले हीं शब्दों में वह निजी पीड़ा लगती हो। इनकी सक्रियता और श्रम अत्यंत प्रशंसनीय है।



राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार शपथ दिलाते हुये, इधर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में सम्मान करते हुये।

कविताएँ हृदय की पीड़ा को अभिव्यक्ति हीं नहीं करती, आँसू भी पोंछती हैं



27 | मई | 2019



## अनुसंधान एवं विकास कार्य पर राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन



■ कार्यशाला में शामिल अतिथिगण और राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

स

माज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अतुल प्रसाद ने कहा कि दिव्यांगता के क्षेत्र में ऐसा शोध होना चाहिए, जो वास्तविकता में उनके जीवन में परिवर्तन ला सके। शोध का लाभ अंतिम पड़ाव पर खड़े दिव्यांग व्यक्ति को मिले। जो शोध वास्तव में दिव्यांगजनों के हित में होगा, उसे ध्यान में रखकर बिहार सरकार नीति भी बनायेगी और उन्हें पुरस्कृत

**चलेगा जागरुकता अभियान :**  
राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों को बहुत सारे अधिकार दिये गये हैं। उनके अधिकार को लेकर जागरुक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा। सरकार के द्वारा दिव्यांगों के लिए रोजगार और उन्नति के अवसर सृजित किये जा रहे हैं। आईजीआईएमएस के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल ने कहा कि दिव्यांग बच्चे पैदा न हों, इसके लिए पहले से सावधान होने की जरूरत है। इसके लिए जल्द ही आईजीआईएमएस में अलग से एक प्रकोष्ठ बनाने की योजना है। मनोवैज्ञानिक डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि समाज में दिव्यांगजनों के प्रति फैली गलत अवधारणा और अंधविश्वास को दूर करने की जरूरत है। मौके पर अपर आयुक्त निःशक्तता डॉ. शंभू कुमार रजक, डॉ. उमा शंकर सिन्हा, डॉ. हबीबुल्लाह अंसारी, संदीप कुमार, डॉ. सुभाष चंद्रा, डॉ. नरेंद्र कुमार सिन्हा, डॉ. ऋतु रंजन, डॉ. विनोद भांति, डॉ. अश्विनी कुमार, डॉ. नवल किशोर शर्मा आदि ने भी अपनी बातें रखीं।

उनके अधिकार को लेकर जागरुक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा। सरकार के द्वारा दिव्यांगों के लिए रोजगार और उन्नति के अवसर सृजित किये जा रहे हैं।

भी करेगी। उन्होंने ये बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय द्वारा आयोजित एकदिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन के बाद कहीं। उन्होंने कहा कि अच्छे शोध के आधार पर सरकार योजना बनायेगी और जरूरत हुई, तो इसके लिए विशेष फंड की व्यवस्था भी करेगी।



अंतिम पड़ाव



100

33000

विशेषज्ञों ने लिया था हिस्सा

लोगों ने देखा सोशल मीडिया पर



1200

32000

विशेषज्ञों के बीच परिचर्चा

लोग मीडिया से हुए जागरुक



<https://www.scdisabilities.org>

वार्षिक प्रतिवेदन : 2019-20



क्र०सं०	वाद सं०	जिला	वादी एवं प्रतिवादी	विषय
12.	12/2019	मुजफ्फरपुर	वादी :- श्री साधु प्रसाद यादव एवं श्री तुलसी प्रसाद यादव (दोनों अस्थिबाधित दिव्यांग), मुजफ्फरपुर	समर्पित परिवाद पत्र पर कार्रवाई करने के सम्बन्ध में
13.	13/2019	पटना	वादी :- डॉ० प्रभाष कुमार, मनेर, पटना। प्रतिवादी :- प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना	एक पद पर पदस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में। प्रक्रियाधीन
14.	14/2019	पटना	वादी :- श्री मनोज कुमार चौधरी, पटना। प्रतिवादी :- मुख्य महाप्रबन्धक, बिहार विकास मिशन, पटना।	नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण के संबंध में
15.	15/2019	बेगूसराय	वादी :- राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा स्वतः संज्ञान प्रतिवादी :- असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय	जिले में UDI कार्ड बनाने के संबंध में
16.	16/2019	मुजफ्फरपुर	वादी :- अतुल कुमार, पिता-श्री रंजीत शुक्ला, मुजफ्फरपुर प्रतिवादी :- सैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं अन्य	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनाने के संबंध में
17.	17/2019	मुजफ्फरपुर	वादी :- श्री शांति मुकुल एवं कुमारी सरिता, मुजफ्फरपुर प्रतिवादी :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	राशन कार्ड सुलभ कराने के संबंध में
18.	18/2019	नालन्दा	वादी :- श्रीमती शशिकला कुमारी, नालन्दा प्रतिवादी :- उप विकास आयुक्त नालन्दा	इंदिरा आवास योजना के संबंध में
19.	19/2019	नवादा	वादी :- श्रीमती मीना देवी (दिव्यांग) पत्नी श्री वीरेंद्र सिंह, नवादा प्रतिवादी :- शाखा प्रबंधक, मगध ब्रमीण बैंक, नवादा	पेंशन राशि भुगतान के संबंध में
20.	20/2019	नालन्दा	वादी :- श्री उमाशंकर प्रसाद, पिता-श्री श्याम साव, नालन्दा प्रतिवादी :- श्री श्याम साव, नालन्दा एवं अन्य	पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे के संबंध में
21.	21/2019	पटना	वादी :- श्री राजेश कुमार, बेऊर, पटना। प्रतिवादी :- शाखा प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बेऊर, पटना	इलाहाबाद बैंक में खाता खुलवाने के संबंध में
22.	22/2019	भागलपुर	वादी :- श्री नरेश कुमार शर्मा, भागलपुर प्रतिवादी :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय, भागलपुर	जनवितरण प्रणाली के लाईसेंस हेतु
23.	23/2019	समस्तीपुर	वादी :- श्री रणजीत कुमार सहनी, समस्तीपुर प्रतिवादी :- जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना) समस्तीपुर	मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के संबंध में
24.	24/2019	पटना	वादी :- श्री एस०सी० झा, J.S. Chandra & Co., Chartered Accountants, कंकड़बाग, पटना प्रतिवादी :- प्रबंधक निदेशक, कम्फेड, बिहार, पटना	अंकेक्षण कार्य का पारिश्रमि भुगतानके सम्बन्ध में
25.	25/2019	समस्तीपुर	वादी :- श्री ललित कुमार मिश्रा, गाँधी पार्क, समस्तीपुर प्रतिवादी :- बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना	दिव्यांगों के लिए अलग से कट ऑफ मार्क्स निर्धारित करने के संबंध में



# जून 2019



JUNE 2019



दिव्यांगजनों के हित में...

pg-038



रक्सौल अनुमंडल औचक निरीक्षण

pg-039



दिव्यांगों को प्रमाणपत्र तुरंत देने का निर्देश...

pg-041



दिव्यांग को अपमानित करने पर

pg-042



दिव्यांगों की अनदेखी पर कार्रवाई....

pg-051



पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक...

pg-052

## कौशल विकास व रोजगार से जोड़ें

दिव्यांगजनों को उनके हिस्से का हक व अधिकार दिलाने को लेकर राज्य में कई प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने परिसदन में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि दिव्यांगों को समाज में बराबरी के साथ रहने व काम के अधिकार दिये गये हैं। विभिन्न स्तरों पर बरती जानेवाले भेदभाव व दिव्यांगों के काम में होनेवाली देरी को दूर...

pg-40



01 | जून | 2019



एक दिवसीय कार्यशाला

विशेष अभियान



कार्यशाला में शामिल अतिथिगण और राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

कड़ा नियम



2500

दिव्यांग को मिला लाभ



1.5

लाख ने सोशल पर विजिट किया



30

ग्रुप ने हमें ज्वाइन किया



02

लोग जुड़ें मीडिया से

समाज कल्याण बिभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने कहा कि दिव्यांगता के क्षेत्र में ऐसा शोध -

**‘होना चाहिए, जो वास्तविकता में उनके जीवन परिवर्तन ला सके। शोध का लाभ अंतिम पड़ाव पर खड़े दिव्यांग व्यक्ति को मिले।**

# दिव्यांगजनों के हित में



माज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने कहा कि दिव्यांगता के क्षेत्र में ऐसा शोध होना चाहिए, जो वास्तविकता में उनके जीवन परिवर्तन ला सके। शोध का लाभ अंतिम पड़ाव पर खड़े दिव्यांग व्यक्ति को मिले। जो शोध वास्तव में दिव्यांग जनों के हित में होगा, उसे ध्यान में रखकर सरकार नीति भी बनाएंगी और उन्हें पुरस्कृत भी करेगी। राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन के बाद कही। डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों को बहुत सारे अधिकार दिये गये हैं। उनके अधिकार को लेकर जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए रोजगार और उन्नति के अवसर सृजित किये जा रहे हैं। समाज कल्याण बिभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने कहा कि दिव्यांगता के क्षेत्र में ऐसा शोध - ‘ होना चाहिए, जो वास्तविकता में उनके जीवन परिवर्तन आ सके। शोध का लाभ अंतिम पड़ाव पर खड़े दिव्यांग व्यक्ति को मिले। जो शोध वास्तव में दिव्यांग जनों के हित में होगा, उसे ध्यान में रखकर सरकार नीति भी बनाएगी और उन्हें पुरस्कृत भी करेगी। उन्होंने ये बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन के बाद कहीं। उन्होंने कहा कि अच्छे शोध के आधार सरकार योजना बनाएगी और जरूरत हुई तो इसके लिए विशेष फंड की व्यवस्था भी करेंगे। डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों की बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। उनके अधिकार के लेकर जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए

## दिव्यांगता के क्षेत्र में करें ऐसा शोध, जो उनके जीवन में परिवर्तन ला सके



रोजगार और उन्नति के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। आईजीआईएमएस के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल ने कहा कि दिव्यांग बच्चे पैदा न हों, इसके लिए पहले से सावधान होने की जरूरत है। है दिव्यांगजनों के प्रति फैली गलत अवधारणा और अंधविश्वास को दूर काने की जरूरत है। मौके पर अपर आयुक्त निःशक्तता डॉ. शंभू कुमार रजक डॉ. हबीबुल्लाह अंसरी, सट्टोंप कुमार, डॉ सुभाष चंद्रा, डॉ. उमा शंकर सिन्हा, डॉ. ऋतु स्वन, छो” विनोद भाति, डॉ. नवल किशोर शर्मा आदि ने भी अपनी बातें रखीं।





04 | जून | 2019

## औचक निरीक्षण

निर्देश

350

25 हजार

सेमिनार में  
थे शामिल

लोग जानें  
मीडिया से



■ दिव्यांगजनों से मिलकर राज्य आयुक्त पटना डॉ. शिवाजी कुमार ने सुनी उनकी शिकायत.

# रक्सौल अनुमंडल

रत-नेपाल सीमा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रक्सौल अनुमंडल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत जर्जर देखकर स्थानीय अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी ली। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारी से

पूछा कि अब तक यहां अनुमंडलीय अस्पताल क्यों नहीं बन पाया है। ऐसी लचर व्यवस्था के बीच दिव्यांग मरीजों का उपचार कैसे हो पायेगा? उन्होंने मरीजों की असुविधा को देखकर निर्देश दिया कि इसमें तत्काल सुधार करने की आवश्यकता है।



इसके उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शरतचंद्र शर्मा और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ बैठक की। बैठक में आयुक्त ने दिव्यांगजनों के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर ही प्रमाणपत्र बनाने के निर्देश दिये तथा दिव्यांगजनों के लिए पेंशन संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए कैंप लगाकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को युद्ध स्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया गया।

साथ ही दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ने हेतु अनुमंडल के सभी प्रखंडों के प्रोग्राम ऑफिसर (मनरेगा) को निर्देशित किया गया कि 18 वर्ष से ऊपर के दिव्यांगजनों को विशेष जॉब कार्ड रोजगार सेवकों की सहायता से उपलब्ध कराया जाये। सभी मार्केटिंग ऑफिसर तथा एसडीओ को निर्देशित किया गया कि दिव्यांगजनों को अंत्योदय योजना के तहत राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाये। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित

किया गया कि अभियान चलाकर दिव्यांगजनों को शिक्षा से जोड़ा जाये तथा सभी दिव्यांगजनों को आने जाने के लिए एस्कॉर्ट अलाउंस उपलब्ध कराया जाये। सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया कि कृत्रिम अंग उपकरण, जैसे व्हील चेर, ट्राईसाइकिल तथा अन्य जरूरत के सामान को उपलब्ध कराया जाये।

सभी प्रखंडों के प्रोग्राम ऑफिसर (मनरेगा) को निर्देशित किया गया कि 18 वर्ष से ऊपर के दिव्यांगजनों को विशेष जॉब कार्ड रोजगार सेवकों की सहायता से उपलब्ध कराया जाये।



07 | जून | 2019



# कौशल विकास व रोजगार से जोड़ें स्पेशल मोबाइल कोर्ट

# नवादा जिला

अधिकार

03

लाख रुपये शादी के लिए देती है सरकार

102

धाराओं का अधिकार मिले दिव्यांग को

21

कोटि में दिव्यांगता को बांटा गया है।



■ दिव्यांग बच्चे से मिलकर उसका होसला बढ़ाते व समागार में अधिकारियों के साथ बैठक करते आयुक्त.



व्यांगजनों को उनके हिस्से का हक व अधिकार दिलाने को लेकर राज्य

में कई प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने परिसदन में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि दिव्यांगों को समाज में बराबरी के साथ रहने व काम के अधिकार दिये गये हैं। विभिन्न स्तरों पर बरती जानेवाले भेदभाव व दिव्यांगों के काम में होनेवाली देरी को दूर करने के उद्देश्य से पूरे राज्य में यह अभियान शुरू किया

गया है। कई प्रभावकारी और सरकारी फैसले करने दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाया गया है।

चलंत न्यायालय में कोई भी दिव्यांग अपनी शिकायत को उठाने के लिए विभाग के प्रपत्र में शिकायत कर सकता है। दिव्यांगजन इसे भरकर अपनी शिकायत राज्य निःशक्तता आयुक्त के चलंत न्यायालय में ला सकते हैं। राज्य आयुक्त ने बताया कि दिव्यांगता प्रमाणपत्र नहीं बनने, पेंशन की समस्या, सामान्य रूप से व्यवहार नहीं कर भेदभाव करने, सरकारी योजनाओं का लाभ देने में परेशानी, साहयता उपकरण नहीं मिलने आदि की शिकायतें चलंत न्यायालय में लाये जा सकते हैं। 11 जून को सदर प्रखंड कार्यालय में चलंत न्यायालय लगेगा। आठ जून को राज्य आयुक्त विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक, किये। कॉलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों के साथ, लीड बैंक के प्रतिनिधियों के साथ बैठक किये।

राज्य आयुक्त ने जानकारी

देते हुए बताया कि कुल 21 कोटि में दिव्यांगता को बांटा गया है। राज्य में दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने के लिए नया खाका तैयार किया गया है। नये प्रमाणपत्र बनाने वालों को अब इसी खाका में निःशक्तता प्रमाणपत्र मिलेगा। उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के सभी 102 धाराओं के दिये जानेवाले अधिकारों को उन्हें दिये जाने की बात कही। राज्य आयुक्त ने कहा कि समाज कल्याण के तहत कई योजनाएं चलायी जा रही है, जिसका लाभ जानकारी के अभाव में नहीं मिल पाता है। मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन राशि के तहत शादी के जोड़े में एक के निःशक्त होने पर एक लाख रुपये, दोनों के निशक्त होने पर दो लाख रुपये तथा दोनों निःशक्त अंतरजातीय विवाह किये हैं तो तीन लाख रुपये की सरकारी मदद मिलती है। लेकिन इस प्रकार के योजनाओं की जानकारी नहीं होने के कारण वह लाभ से वंचित हो जाते हैं।

कुल 21 कोटि में दिव्यांगता को बांटा गया है। राज्य में दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने के लिए नया खाका तैयार किया गया है।



विभिन्न स्तरों पर बरती जानेवाले भेदभाव व दिव्यांगों के काम में होनेवाली देरी को दूर

करने के उद्देश्य से पूरे राज्य में यह अभियान शुरू किया गया है।





08 | जून | 2019



# दिव्यांगों को प्रमाणपत्र देने का निर्देश समीक्षा बैठक

**अधिकार**

600000

रुपये श्रवण बाधित को  
इलाज के लिए

55000

लोग मीडिया के माध्यम  
से हुए जागरूक

राज्य निःशक्तता

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने मोबाइल कोर्ट से पहले समाहरणालय के सभागार में बैठक कर जिले में दिव्यांगों की स्थिति और प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। मौके पर उन्होंने कहा कि दिव्यांगों की परेशानियों व समस्याओं को सामूहिक प्रयास से दूर करते हुए उन्हें समानता का अधिकार देने के लिए काम करना है। राज्य आयुक्त विभागीय अधिकारियों के अलावे पुलिस पदाधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों व बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके निःशक्तजनों के जीवन में सुधार के प्रयास से संबंधित बिंदुओं पर टिप्स दिये।

राज्य आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि समाज में सभी को सामान अधिकार दिया गया है। शारीरिक कमियों को हीन भावना से नहीं देखना है। बल्कि उनका मनोबल बढ़ाते हुए समाज में उन्हें सम्मानजनक अधिकार देना है पर प्रशासन के ढुल मूल रवैये इस जरूरी काम को भी समय से पूरा नहीं किया जा रहा है। निःशक्तता प्रमाणपत्र बनाने के लिए भी उन्हें कई बार भटकना पड़ता है। उन्होंने तय सीमा में सभी दिव्यांगों का प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से बनाने का निर्देश दिया। इस बैठक में खासकर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने के लिए मोबाइल कोर्ट में आवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा दिव्यांगजनों को उनके मुकदमा लड़ने के लिए मुफ्त सरकारी वकील की

व्यवस्था की गयी है। सरकार की ओर से मिलनेवाली इन सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। श्रम संसाधन, जीविका, बुनियादी केंद्र आपस में समन्वय स्थापित कर दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ दिलायें। खेल-कूद में दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी निर्देश बैठक में दिया गया। सरकार के सभी विकास योजनाओं में गरीबी उन्मूलन योजनाओं के तहत 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिव्यांगों को मिलना है। श्रवण बाधित 06 वर्ष के बच्चे को भारत सरकार द्वारा जरूरी इलाज के लिए छह लाख का खर्च का लाभ दिया जाता है। इसका लाभ लोगों को दिलायें। दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांगता के आधार पर नौकरी से नहीं हटाया जा सकता है। बैठक में राज्य आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग बच्चों को पागल व मंद बुद्धि जैसे अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना गलत है। अस्पताल के अधिकारियों से कहा कि इलाज के नाम पर बेवजह दिव्यांगों को जिले से बाहर रेफर नहीं करें।

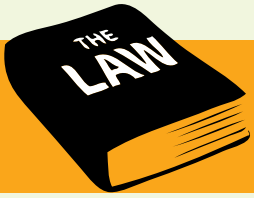


■ अधिकारियों के साथ बैठक और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते राज्य निःशक्तता आयुक्त.

विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा दिव्यांगजनों को उनका मुकदमा लड़ने के लिए मुफ्त सरकारी वकील की व्यवस्था की गयी है।



09 | जून | 2019



## दिव्यांग को अपमानित करने पर सजा नियम व कानून

रा

ज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने चलंत न्यायालय से पहले जिले के सभी प्रखंडों में भ्रमण कर वहां के अधिकारियों से बैठक कर दिव्यांगों की स्थिति के बारे में जायजा लिया। राज्य आयुक्त ने कौआकोल प्रखंड कार्यालय में बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को दिव्यांगों के लिए चलायी जा रही सभी योजनाओं का

योजनाएं चल रही हैं, उसमें 5 फीसदी दिव्यांगों के लिए खर्च किया जाना है। साथ ही प्रत्येक योजनाओं में दिव्यांगों को प्राथमिकता के तौर पर लाभ दिलाना है। दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम के तहत जिलास्तरीय कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के अध्यक्ष डीएम कौशल कुमार बनाए गये। इनके अलावा कमेटी में सदस्य सचिव के रूप में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक को रखा गया। वहीं सदस्य के रूप में सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव सहित सदर के एसडीओ को शामिल किया गया।

पकरीबरावां प्रखंड पहुंचकर आयुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 16 पंचायतों से आये कई दिव्यांगों से बातचीत की। आयुक्त ने अधिकारियों व पंचायत सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक पंचायत के सचिव पांच-पांच दिव्यांगों का चयन कर प्रखंड कार्यालय में उनकी सूची उपलब्ध कराये और पंचायत स्तर पर दिव्यांगों के साथ बैठक करें। नरहट प्रखंड कार्यालय पहुंच आयुक्त ने निर्देश दिया कि दिव्यांगों से जुड़े कानून का अनदेखी न करें। उन्होंने कहा कि इस कानून को अनदेखी करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। निःशक्तता कोर्ट इस मामले में आपको सम्मन भी जारी कर सकता है।

आयुक्त ने अधिकारियों व पंचायत सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक पंचायत के सचिव पांच-पांच दिव्यांगों का चयन कर प्रखंड कार्यालय में उनकी सूची उपलब्ध कराये।

कार्यान्वयन पूरी जिम्मेदारी के साथ करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार दिव्यांगों के कल्याण को लेकर अनेकों योजनाएं चला रही है। दिव्यांगत प्रमाणपत्र बनाने से लेकर हर योजनाओं में दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था की गयी है। सभी स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग-धंधा, कौशल विकास, ऋण सहित हर तरह के क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए योजनाएं बनी हुई हैं। लेकिन, जरूरत इस बात की है कि सभी विभाग के अधिकारी अपने अधीन दिव्यांगों से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से और इन्हें हर संभव मदद करें। निःशक्तता आयुक्त ने कहा कि गरीबी उन्मूलन से संबंधित जितनी भी



■ निरीक्षण करते राज्य निःशक्तता आयुक्त.

### स्थिति के बारे में

1413  
दिव्यांगता  
प्रमाण पत्र

518  
दिव्यांगता  
पेंशन

19  
आवास व  
मनरेगा

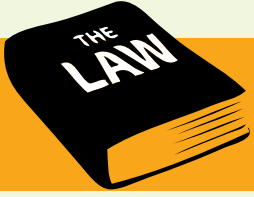
☞ सभी स्वास्थ्य, ऋण सहित हर तरह के क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए योजनाएं बनी हुई हैं।



जवादा जिला



10 | जून | 2019



## दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा राज्य आयुक्त का निर्देश

रा

ॐ

06-18

वर्ष के बच्चों को  
निःशुल्क शिक्षा

ज्य निःशक्तता आयुक्त ने जिला के अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी विभागों के क्रियाकलापों की समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली गयी तथा और बेहतर करने के लिए दिशा निर्देश दिये गये। निःशक्तता आयुक्त ने शहर के सर्किट हाउस में विभागवार समीक्षा की। उन्होंने दिव्यांगों के

अवसर उपलब्ध कराने की बात करते हुए कहा कि दिव्यांग जनों के लिए पारा ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक, डेफ ओलंपिक खेलों के लिए विशेष तैयारी की जाये। उन्होंने बुनियाद केंद्र के कर्मचारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि बुनियाद केंद्र दिव्यांगों और वृद्ध जनों का सहारा बनेगा।

आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिव्यांग बच्चों को मिले बेहतर माहौल राज्य निःशक्तता आयुक्त ने आईसीडीएस के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिव्यांग बच्चों को बेहतर माहौल मिलना चाहिए ताकि वे खुद को सबसे अलग नहीं समझे। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं और सहायिकाओं को निर्देश देकर व्यवस्था को दुरुस्त करें।

**दिव्यांगों को ड्राइविंग लाइसेंस**

जिला परिवहन पदाधिकारी को दिव्यांगजनों के लिए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

**तुरंत प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश**

आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि दिव्यांगता के सारे लाभ के लिए प्रमाणपत्र जरूरी है। इसलिए प्रमाणपत्र जारी करने में देर नहीं हो। जिस दिन दिव्यांगता की जांच हो उसी दिन उन्हें प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाये।



**मिले माहौल**

आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिव्यांग बच्चों को मिले बेहतर माहौल

सहायिकाओं को निर्देश देकर व्यवस्था को दुरुस्त कर रिसोर्स टीचर उन्हें उनके घर से विद्यालय में लाना सुनिश्चित करेंगे



**सारथी योजना**

**यानों में भी विभागीय शिकायतें दर्ज होंगी**



राज्य निःशक्तता आयुक्त ने आईसीडीएस के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिव्यांग बच्चों को बेहतर माहौल मिलना चाहिए ताकि वे खुद को सबसे अलग नहीं समझें।

लिए आयोजित होने वाले चलंत न्यायालय में भी सभी को उपस्थित रहने के निर्देश दिये ताकि दिव्यांगों की समस्याओं का ऑनस्पॉट निपटारा हो सके। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में कहा कि छह वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है और रिसोर्स टीचर उन्हें उनके घर से विद्यालय में लाना सुनिश्चित करेंगे।

शत प्रतिशत विद्यालयों में दिव्यांगों के लिए रैंप और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। विद्यालय में दिव्यांग बच्चे भी सहज महसूस करें इसके लिए उन्हें बेहतर माहौल देने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने दिव्यांगों के लिए खेल में

जवादा शिक्षा



11 | जून | 2019

## दिव्यांगों को घर पर न्याय चलंत न्यायालय



■ राज्य निःशक्तता आयुक्त ने दिव्यांगों की सभी समस्याओं का समाधान किया.

जि

ले के सदर प्रखंड कार्यालय में दिव्यांगों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए लगाये गये चलंत न्यायालय में दिव्यांगों का सैलाब उमड़ पड़ा। न्यायालय में 45 से अधिक काउंटर और 500 से अधिक कर्मी दिव्यांगों की समस्याओं

को चिह्नित करने के लिए लगे हुए थे। न्यायालय में कुल 2780 दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन किया गया और इनमें से 1431 को दिव्यांगता प्रमाणपत्र हाथों-हाथ सौंप दिया गया। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निदान के लिए विभिन्न विभागों का स्टॉल लगाया गया ऑन स्पॉट मामलों का निदान किया गया। कुछ मामले को संबंधित विभागों को स्थानांतरित किया गया, तो कुछ मामले में समय सीमा निर्धारित कर मामले को निपटारा करने के आदेश दिया गया।

नवादा जिला

इस न्यायालय का शुभारंभ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने किया। राज्य आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजन किसी से भी कम नहीं हैं। चलंत न्यायालय का उद्देश्य दिव्यांगों की समस्याओं को एक ही जगह दूर करना है। साथ ही दिव्यांग पेंशन, इंदिरा आवास, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक लोन, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, नियोजन आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गयी तथा ट्राईसाइकिल के लिए आये दिव्यांगजनों से भी आवेदन लिया गया। मौके पर सदर एसडीओ अनु कुमार, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी गुप्तेश्वर कुमार, प्रबंधक उपमा रानी व अन्य मौजूद थे। चलंत न्यायालय में बड़ी संख्या में दिव्यांगों ने ट्राईसाइकिल और अन्य उपकरणों के लिए आवेदन दिया। आये आवेदनों के आलोक में जल्द ही उपकरण मुहैया कराने की बात कही गयी। इसके अलावा जो दिवांगजन चलंत न्यायालय में शामिल नहीं हो सके, उन्हें अपने प्रखंड कार्यालय में आवेदन करने को कहा गया है। वे अपने आवेदन, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, जाति और आवास प्रमाणपत्र प्रखंड में जमा करेंगे। सभी प्रखंडों से डिमांड सूची आने पर क्रय कर उन्हें ट्राईसाइकिल व अन्य उपकरण दिये जायेंगे।

दिव्यांग पेंशन, इंदिरा आवास, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक लोन, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, नियोजन आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गयी तथा ट्राईसाइकिल के लिए आये दिव्यांगजनों से भी आवेदन लिया गया।

शिकायतें

• 2780

दिव्यांगों ने सुनाया फरियाद

• 2174

मामलों को निष्पादन

• 987

दिव्यांगों को तत्काल मिला प्रमाणपत्र

• 123

दिव्यांगों के पेंशन को मिली हरी झंडी



19 | जून | 2019

## दिव्यांगों को सशक्त करना प्राथमिकता पदाधिकारियों के साथ बैठक



■ कारगिल विजय भवन में शिक्षा विभाग व अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करते आयुक्त।

**RPwD** Act, 2016 की धारा 80 के बारे में जानकारी दी गयी **21** प्रकार के दिव्यांग होते हैं। अब नये कानून के तहत

दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना और सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आजादी के बाद पहली बार दिव्यांगों के लिए

चलंत लोक अदालत का आयोजन

22 जून को सदर प्रखंड परिसर

में किया जायेगा। परिसदन में

आयोजित प्रेसवार्ता में राज्य

निःशक्तता आयुक्त डॉ.

शिवाजी कुमार ने पत्रकारों

को संबोधित करते हुए

कहा कि पहले दिव्यांगता

सात प्रकार की होती थी।

अब नये कानून के तहत

कुल 21 प्रकार के दिव्यांग होते

हैं। वर्तमान समय में दिव्यांगों के लिए

सरकार दर्जनों योजनाएं चला रही है, जिससे

कि उन्हें सशक्त किया जा सके और वह

समाज में अपनी पहचान बना सकें। उन्होंने

कहा कि सरकार आपके द्वारा योजन के तहत

**बेगूसराय  
जिला**

हमलोग दिव्यांगजनों को चिह्नित कर उनके सतत विकास को प्रयत्नशील रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों का हमने तीन वर्षों की रिपोर्ट मंगवायी है कि दिव्यांगों के लिए इन तीन वर्षों में क्या काम हो पाया है? सभी विभाग की गरीबी उन्मूलन योजना की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी दिव्यांगों को मिल रही है कि नहीं इसका भी जांच होगा। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी देवेन्द्र कुमार झा, सिविल सर्जन ब्रजजन्दन शर्मा, भुवन कुमार आदि मौजूद थे।

इसके बाद राज्य आयुक्त ने

भगवानपुर प्रखंड के अधिकारियों

के साथ भी बैठक की, जिसमें उन्होंने

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की

धारा 80 के बारे में बताया। उन्होंने कहा

कि यह धारा राज्य आयुक्त को दिव्यांगजनों

के समस्याओं के निराकरण के लिए चलंत

न्यायालय लगाने का शक्ति प्रदान करता है।

इस न्यायालय में सुलभ रूप से विकालंग

प्रमाणपत्र सहित उनकी समस्याओं का

निवारण किया जायेगा। आयुक्त ने बीडीओ

को निर्देश दिया कि आवेदन जमा करने वाले

दिव्यांगों को गाड़ी की व्यवस्था कर उसे

चलंत न्यायालय तक लाया जाये। प्रखंड स्तर

पर दिव्यांगों की शिकायतों के निवारण के

लिए एक कमेटी का गठन करें।

**दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा चालायी जा रही प्रमुख योजनाएं**

☞ मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनाएं

☞ मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना

☞ मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना (कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण

☞ दिव्यांगजनों को रोजगार में चार प्रतिशत का आरक्षण

☞ गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ

पहले दिव्यांगता सात प्रकार की होती थी। अब नये कानून के तहत कुल 21 प्रकार के दिव्यांग होते हैं।

**वर्तमान समय में दिव्यांगों के लिए सरकार दर्जनों योजनाएं चला रही है।**



20 | जून | 2019

# दिव्यांगजनों के लिए रैंप सभी भवनों में बने



■ योजनाओं की जानकारी देते हुए राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।



4%

आरक्षण का लाभ देने का निर्देश दिया पदस्थापना में



बि

ना शपथ पत्र दिव्यांगों से लिए 31 अगस्त तक जिले के सभी दिव्यांगजनों को जांच कर प्रमाणपत्र दिया जायेगा। वहीं जिले के दो दर्जन दिव्यांगजनों को

लर्निंग ड्राईविंग लाइसेंस शीघ्र ही निर्गत किया जायेगा। कारगिल विजय सभा भवन में दिव्यांगजनों के लिए सरकार की ओर से चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगजन उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी होते हैं। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने की व्यवस्था करने का आदेश सिविल सर्जन को दिया। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिक से अधिक चलंत न्यायालय आयोजित करने पर भी जोर दिया।

**बेगूसराय जिला**

डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि सरकार के प्रत्येक विभाग के कार्यालयों, जिले के सभी मॉल, बैंक, रेलवे स्टेशन आदि भवनों में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए रैंप का निर्माण कराना अनिवार्य है। नगर निगम के अधिकारियों को अलग से शौचालय निर्माण कराने का निर्देश दिया। विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालय में दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों की देखरेख के लिए एक नॉडल अधिकारी को नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। सूचना पट्ट पर उनका नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर अंकित रहेगा।

बैठक में आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों को उनके घरों पर ही बैंकिंग सुविधा मिले। प्रधानमंत्री मुद्रा स्वरोजगार योजना में प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए किसी तरह की गारंटर की जरूरत नहीं होगी। खाता खुलवाने में दिव्यांगों की सुविधा का ख्याल रखना होगा। इसी तरह एटोएम में भी रैंप की सुविधा देनी होगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से भी दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने का आदेश दिया। वहीं स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को नामांकन में सुविधा देने का निर्देश दिया। पदस्थापना में 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का निर्देश दिया।

“ डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि सरकार के प्रत्येक विभाग के कार्यालयों, जिले के सभी मॉल, बैंक, रेलवे स्टेशन आदि भवनों में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सुगम्य रैंप का निर्माण कराना अनिवार्य है।

➡ प्रधानमंत्री मुद्रा स्वरोजगार योजना में प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए किसी तरह की गारंटर की जरूरत नहीं होगी।

➡ स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को नामांकन में सुविधा देने का निर्देश दिया।



बैठक में आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों को उनके घरों पर ही बैंकिंग सुविधा मिले। प्रधानमंत्री मुद्रा स्वरोजगार योजना में प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए कगारंटर की जरूरत नहीं होगी।





21 | जून | 2019

## विभागिये पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक



■ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुये।



7%

तक छूट वाहन  
खरीदारी में दिव्यांगों  
को



रा

ज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने निगम के प्रतिनिधियों को बताया कि अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग के साथ विवाह करता है तो, सरकार उस

व्यक्ति को एक लाख रुपया प्रोत्साहन के रूप में देती है। अगर विवाह करने वाला व्यक्ति भी दिव्यांग है, तो दोनों पति पत्नी को एक-एक लाख रुपये मिलेंगे। अगर दोनों अंतरजातीय विवाह करते हैं तो, सरकार और एक लाख रुपया अतिरिक्त देगी। जनप्रतिनिधियों, वार्ड सदस्यों और पंचायत प्रतिनिधियों को ये जानना जरूरी है कि दिव्यांगों को सरकार की ओर से कौन-कौन सी सुविधा दी जा रही है। ताकि

बेगूसराय  
जिला

वे अपने-अपने क्षेत्र के दिव्यांगों को बेहतर लाभ दिला सके व उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ सकें। ये बातें राज्य आयुक्त ने नगर निगम के सभागार में कहीं। आयुक्त ने निगम के पार्षदों, कर्मियों और पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने 22 जून को सदर प्रखंड में लगनेवाले चलंत न्यायालय के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही पॉवर प्वाइंट की मदद से दिव्यांगों को मिलने वाली सहायता, उनके लिए बनाये गए कानून, समाज कल्याण विभाग द्वारा उनको दी जानेवाली सुविधा के बारे में भी बताया।

आवास, रोजगार के लिए ऋण और अन्य मिलनेवाले लाभ के बारे में जानकारी दी। निजी या सरकारी विद्यालयों में दिव्यांगों का नामांकन लेना अनिवार्य होगा। वाहन खरीदारी में दिव्यांगों को सात प्रतिशत तक छूट, दिव्यांगों को एफआईआर के लिए थाना जाने की जरूरत नहीं बल्कि पुलिस दिव्यांग के पास आयेगी। उन्होंने हर बड़े भवनों में दिव्यांगों के लिए रैंप बनाने, बड़े-बड़े मॉल में दिव्यांगों को रोजगार देने, चौक चौराहों पर ट्रैफिक वाली जगह पर साउंड सिस्टम ट्रैफिक व्यवस्था करने सहित अन्य चीजों की जानकारी दी।

बैठक में आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों को उनके घरों पर ही बैंकिंग सुविधा मिले। प्रधानमंत्री मुद्रा स्वरोजगार योजना में प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए कगारंट की जरूरत नहीं होगी।

## खोदवंदपुर प्रखंड

### दिव्यांगों को मिलेंगी सभी सुविधाएं : आयुक्त

खोदवंदपुर प्रखंड मुख्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में राज्य आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजन भले शारीरिक रूप से कमजोर हों, परंतु ऐसे लोगों में प्रतिभाओं की कमी नहीं होती है। सरकार दिव्यांगों को हर सरकारी सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है। अधिकारी व कर्मी दिव्यांगों की समस्याओं का निपटारा करने में तेजी दिखाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिव्यांगों को किसी कार्यालय में आनेजाने में परेशानी नहीं हो। इसके लिए रैंप का निर्माण करवाएं। उनके लिए कार्यालय भवन में अलग से शौचालय की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। साथ ही खोदावंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही निःशक्तता प्रमाणपत्र निर्गत करने का निर्देश प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दिया। उन्होंने हर सप्ताह इसके लिए विशेष कैंप लगाने का भी निर्देश दिया। राज्य आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगों को किसी प्रकार की शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के हित में चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी भी बैठक में दी।



22 | जून | 2019



## सबकी सुनी गयी फरियाद चलंत न्यायालय

समस्याओं का किया गया निष्पादन



मोबाइल कोर्ट में त्वरित कार्रवाई से खुश हुए दिव्यांग



1080

आवेदन  
आये

374

दिव्यांगों को  
दिया प्रमाणपत्र

न्यायालय में फरियाद

बेगूसराय  
जिला

विकासात्मक, बौद्धिक  
और बहु दिव्यांगता ग्रसित  
दिव्यांगों के लिए सक्रिय संबद्धता  
सुनिश्चित करना है। इन्हें विवेक  
संगत, अनुकूल, बाधरहित  
और समुचित वातावरण उपलब्ध  
कराने के लिए सरकार और  
समाज कल्याण विभाग  
तत्पर है।

### ■ दिव्यांगजनों की फरियाद सुनते राज्य निःशक्तता आयुक्त।

दि

दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में विनिर्दिष्ट सेवाओं को लागू कराने के उद्देश्य से बेगूसराय में पहली बार चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया। इस न्यायालय में अपनी फरियाद सुनाने के लिए दिव्यांगों को होड़ लग गयी। भीषण गर्मी को देखते हुए दो पालियों में न्यायालय संचालित किया गया। न्यायालय में कुल 1080 दिव्यांगों ने अपनी फरियाद सुनाने के लिए अर्जी दी। जिसमें पहली पाली में सुबह 10 बजे तक 84 दिव्यांगों के आवेदनों का निपटारा किया गया। इसमें बुनियादी सेवा (एसटीवी) के 28, दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए 14, सामाजिक सुरक्षा के 20, आवास योजना के 09, स्वरोजगार कर्ज के 09, शिक्षा के 03 और डीआरसीसी से संबंधित 01 आवेदन थे।

द्वितीय पाली में शाम चार बजे से फिर कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। मोबाइल कोर्ट में बारह से अधिक विविध काउंटर बनाये गये थे। जहां कि सभी आवेदनों का सत्यापन के बाद बिहार सरकार के राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार की देखरेख में त्वरित सुनवाई की गयी। डॉ. शिवाजी कुमार ने बताया कि दिव्यांगों की सभी प्रकार की शिकायतों एवं मांगों को लेकर जमा किये जा रहे आवेदनों पर त्वरित आदेश जारी कर संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है।

जिले के सभी दिव्यांगों की समस्या समाप्त होने तक यह कार्रवाई सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा लगातार जारी रहेगी। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम में 21 प्रकार के दिव्यांग श्रेणी चयनित किये गये हैं और उन सभी दिव्यांगों को बुनियादी सुविधा, शिक्षा एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें पूरी तरह तत्पर हैं। इन्हें अधिक से अधिक मदद पहुंचाने के लिए हरसंभव उपाय किये जा रहे हैं। केंद्र एवं बिहार की सरकार मुख्यधारा के सभी प्रकार की औपचारिक एवं अनौपचारिक योजना एवं कार्यक्रमों में दिव्यांगों का समावेश कर रही है। विकासात्मक, बौद्धिक और बहु दिव्यांगता ग्रसित दिव्यांगों के लिए सक्रिय संबद्धता सुनिश्चित करना है। इन्हें विवेक संगत, अनुकूल, बाधरहित और समुचित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार और समाज कल्याण विभाग तत्पर है। उन्होंने बताया कि जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, बैंक, पुलिस, प्रशासन, रेल समेत तमाम विभागों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। गर्मी की छुट्टी के बाद विद्यालय खुलने पर सभी दिव्यांग बच्चों का नामांकन पोषक क्षेत्र के विद्यालयों में कराये जाने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जा चुका है। एक भी बच्चा अनामांकित पाये जाने पर संबंधित विद्यालय प्रधान के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।





27 | जून | 2019

## श्रम संसाधन एवं रोजगार विभाग, बिहार सरकार पदाधिकारियों के साथ एडवोकेसी बैठक



■ अधिकारियों के साथ बैठक करते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

**बि**हार एवं भारत सरकार दिव्यांगजनों के नियोजन विशेषकर उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु निम्न रियायती दर पर ऋण के प्रावधान सहित योजनाओं का निर्माण करेगी। उपरोक्त के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम एवं योजनाएँ होगी :-

☞ मुख्यधारा के सभी प्रकार के औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यावसायिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण योजनाओं एवं कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों का समावेश।

☞ विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजनों को पर्याप्त सहयोग एवं सुविधा सुनिश्चित करना।

☞ विकासात्मक, बौद्धिक, बहु दिव्यांगता एवं स्वलीनता (ऑटिस्म) से ग्रसित दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं बाजार से सक्रिय सहबद्धता सुनिश्चित करना।

☞ सूक्ष्म ऋण सहित रियायती दर पर ऋण

देना।

☞ दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित उत्पादों का विक्रय।

☞ दिव्यांगजनों के स्वरोजगार, कौशल विकास से संबंधित प्रगति का आंकड़ा रखना।

☞ सरकारी इकाई नियोजन से संबंधित किसी मामले में किसी भी दिव्यांगजन के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा। सरकारी इकाई दिव्यांग कर्मचारियों को विवेकसंगत अनुकूलन, बाधा रहित उपयुक्त एवं समुचित वातारण उपलब्ध कराएगी।

☞ केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति की प्रोन्नति से इंकार नहीं किया जाएगा।

☞ कोई भी सरकारी इकाई किसी कर्मचारी को सेवा के दौरान दिव्यांगता से ग्रसित होने पर उसे अभिमुक्त या रैंक में कमी नहीं करेगी।

### एडवोकेसी बैठक

अधिकार



■ अधिकारों पर चर्चा करते ग्रामीण दिव्यांगजन समूह।

राज्य आयुक्त निःशक्तता ने दिया निर्देश

## बीपीएससी : 63वीं मेंस के रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक

संबद्धता > चटना

राज्य निःशक्तता आयुक्त ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा ली गयी 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता (मुख्य) परीक्षा के रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी है, गुरुवार को अतुल रंजन की ओर से दायर मामले में दोबारा सुनवाई करते हुए आयोग ने बीपीएससी को दोबारा सुनवाई करने का निर्देश दिया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में संशोधन के बाद ही 63वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करें, राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार ने बताया कि अतुल रंजन मामले में 18 जनवरी को पहली सुनवाई में

● दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में संशोधन के बाद ही रिजल्ट होगा जारी

बीपीएससी पर रोक लगा का निर्देश दिया था, क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के मुताबिक सरकारी नौकरी में दिव्यांगों को रिक्तियों की संख्या का चार प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, लेकिन अधिनियम के मुताबिक आरक्षण रोस्टर सफ नहीं है, इस कारण से दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में जरूरी है कि अधिनियम के मुताबिक रोस्टर में सुधार कर ही 63वीं मुख्य परीक्षा के आरक्षित कोटे का रिजल्ट का प्रकाशन किया जाये।

**रा**ज्य निःशक्तता आयुक्त ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा ली गयी संयुक्त प्रतियोगिता (मुख्य) परीक्षा के रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। गुरुवार को अतुल रंजन की ओर से दायर मामले में दोबारा सुनवाई करते हुए आयोग ने बीपीएससी को दोबारा आदेश दिया है कि दिव्यांगजन

अधिकार अधिनियम 2016 में संशोधन के बाद ही 63वीं मुख्य परीक्षा रिजल्ट प्रकाशित करें। राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार ने बताया कि अतुल रंजन मामले में 18 जनवरी को पहली सुनवाई में भी रिजल्ट पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के मुताबिक सरकारी नौकरी में दिव्यांगों को रिक्तियों की संख्या का चार प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, लेकिन अधिनियम के मुताबिक आरक्षण रोस्टर सफ नहीं है। इस कारण से दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि अधिनियम के मुताबिक रोस्टर में सुधार कर ही 63वीं मुख्य परीक्षा के आरक्षित कोटे का रिजल्ट का प्रकाशन किया जाये।

इस कारण से बहु-दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है।  
ऐसे में जरूरी है कि अधिनियम के मुताबिक रोस्टर में सुधार कर ही 63वीं मुख्य परीक्षा के आरक्षित कोटे का रिजल्ट का प्रकाशन किया जाये।





28 | जून | 2019

## दिव्यांगों की अनदेखी पर कार्रवाई बैठक में निर्देश



# सरायगढ़ भपटियाही ब्लॉक में बैठक (सुपौल)

**दि**व्यांग लोगों के समस्याओं के प्रति सरकार पूरी गंभीरता से योजना बनाकर कार्य कर रही है। ऐसे लोगों के समस्याओं की अनदेखी सरकारी अधिकारी तथा कर्मियों के लिए जेल जाने का कारण भी बन सकता है। तीन बार आवेदने देने के बाद यदि दिव्यांगता प्रमाणपत्र नहीं बना तो संबंधित लोग थाना में मुकदमा दर्ज करें। उक्त बातें बिहार राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित दिव्यांगों की बैठक में अधिकारियों को कही। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को प्राथमिकता के साथ हर एक लाभ से जोड़ने का काम सरकारी अधिकारी तथा कर्मियों का है। अगर कोई जन प्रतिनिधि भी दिव्यांगों के हक को देने में मनमानी करते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

राज्य आयुक्त ने कहा कि स्कूलों में नामंकन, प्रधानमंत्री आवास लाभ, पेंशन योजना सहित सरकार के अन्य लाभों में दिव्यांगों को जोड़ा जाना है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों में जागरूकता लाने के लिए एक सूची



■ सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड कार्यालय परिसर में अयोजित दिव्यांगों की बैठक में उपस्थित लोग

बनाकर सुपौल के मरौना, निर्मली, सरायगढ़-भपटियाही, किशनपुर व सुपौल में 28 जून की बैठक रखी गयी है। 29 जून को त्रिवेणीगंज तथा छातापुर में बैठक निर्धारित है। राज्य आयुक्त ने कहा कि प्रखंड स्तर के बैठक में सर्वसम्मति से दिव्यांगों की प्रखंड कमेटी गठित कर उसे तत्क्षण जिला कार्यालय को भेजना है। दिव्यांगों लोग कमेटी के माध्यम से अपनी समस्याओं को जिला तक पहुंचाने का काम करेंगे।



राज्य आयुक्त ने कहा कि प्रखंड स्तर के बैठक में सर्वसम्मति से दिव्यांगों की प्रखंड कमेटी गठित कर उसे तत्क्षण जिला कार्यालय को भेजना है। **दिव्यांगों लोग कमेटी के माध्यम से अपनी समस्याओं को जिला तक पहुंचाने का काम करेंगे।**

513  
दिव्यांगता  
प्रमाण पत्र

255  
दिव्यांगता  
पेंशन

2780  
दिव्यांगों  
ने सुनाया  
फरियाद

1174  
मामलों को  
निष्पादन





28 | जून | 2019

दिव्यांगों को मिलने वाले लाभ पर चर्चा जिला सुपौल

# किशनपुर व निर्मली प्रखंड



■ फरियाद सुनते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

दिव्यांगजनों की मासिक आय 15 हजार रुपया से 20 हजार रुपये के बीच है वह दिव्यांग योजना के तहत 50 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा पाने के हकदार हैं। वैसे दिव्यांगजनों या उनके अभिभावकों की मासिक आय 15 हजार रुपया तक है। वह दिव्यांगजन योजना के तहत सौ प्रतिशत सहायता के पात्र है। इस योजना अंतर्गत ऐसे इन दिव्यांगजन को 25 हजार रुपये की छूट के साथ मोटर ट्राई साइकिल उपलब्ध करायी जाती है। दिव्यांगों के स्वरोजगार कौशल विकास से संबंधित किसी भी दिव्यांग से भेदभाव नहीं किया जायेगा। सरकारी इकाई दिव्यांग कर्मचारियों को विवेक संगत, अनुकूल, बाधारहित, उपयुक्त एवं समुचित वातावरण उपलब्ध करायेगी। केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति के प्रति इन्कार नहीं किया जा सकता है। कोई भी सरकारी इकाई किसी कर्मचारी को सेवा के दौरान दिव्यांगता के स्थिति में होने पर भी उसे मुख्यधारा से बाहर नहीं करेगी।



## दिव्यांगजनों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बना रही है सरकार

निर्मली अनुमंडल मुख्यालय स्थित टीसीपी भवन में दिव्यांगता को लेकर राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी। अनुमंडल में पहली बार आयोजित इस बैठक में पदाधिकारियों और दिव्यांगों को संबोधित करते हुए आयुक्त ने कहा कि बिहार एवं भारत सरकार दिव्यांगजनों के नियोजन विशेषकर उनके व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु रियायती दर पर ऋण के प्रावधान सहित अन्य योजनाओं का निर्माण कर रही है। पंचायत स्तर पर समूह बनाकर दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए जागरूक करने की बात कही।

**कि** शनपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सभा भवन में पंचायत स्तर पर दिव्यांग समिति को लेकर एक बैठक राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। जिसमें प्रखंड के विभिन्न पंचायत के दिव्यांग, पंचायत स्तरीय पदाधिकारी सहित अन्य लोगों ने दिव्यांगों को मिलने वाली लाभ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। बैठक में उपस्थित राज्य आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए पंचायत स्तरीय कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि एडीप योजना अंतर्गत गंभीर रूप से दिव्यांगजन के लिए और क्वाड्रीप्लेजिक, एससीआई, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, प्रमस्तिष्क अंगघात, पक्षाघात वाले दिव्यांगजन जिनके तीन से चार अंग अथवा शरीर का आधा हिस्सा गंभीर रूप से दिव्यांग हो उनके लिए मोटराइज्ड ट्राई साइकिल देने का प्रावधान है। जिन दिव्यांगजनों के अभिभावकों का मासिक आय सभी साधनों से 20 हजार रुपये से अधिक है ऐसे दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राई साइकिल पाने के पात्र नहीं है। जिन

राज्य आयुक्त ने कहा कि प्रखंड स्तर के बैठक में सर्वसम्मति से दिव्यांगों की प्रखंड कमेटी गठित कर उसे तत्क्षण जिला कार्यालय को भेजना है। दिव्यांगों लोग कमेटी के माध्यम से अपनी समस्याओं को जिला तक पहुंचाने का काम करेंगे।

613  
दिव्यांगता  
प्रमाण पत्र

421  
दिव्यांगता  
पेंशन

832  
दिव्यांगों  
ने सुनाया  
फरियाद

280  
मामलों को  
निष्पादन





29 | जून | 2019

पंचायत स्तरीय  
पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक



# सुपौल जिला

280  
दिव्यांगता  
प्रमाण पत्र

489  
दिव्यांगता  
पेंशन

1700  
दिव्यांगों  
ने सुनाया  
फरियाद

580  
मामलों को  
निष्पादन

दि

दिव्यांगों को अधिकार बोध के लिए शनिवार को टीपीसी भवन में बैठक हुई। बैठक में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की जानकारी अधिकारियों सहित दिव्यांगों को दी। उन्होंने बताया कि कुल 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है। उन्होंने प्रखंड और पंचायत स्तर पर समूह बनाने की बात करते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर तक समूह बनाये जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग धंधा, कौशल विकास ऋण आदि हरेक क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए योजनाएं बन रही है और चल भी रही हैं।



इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए पेंशन, छात्रवृत्ति, आवास सहित



■ पंचायत स्तरीय समिति के प्रखंड स्तरीय समिति बनेगी

अन्य योजनाओं को धरातल पर उतराने के लिए काम किये जा रहे हैं ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। आयुक्त ने बस स्टैंड पर दिव्यांगजनों के लिए रैंप बनाने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए संचालित सभी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना को प्रचारित करने का निर्देश दिया। एसडीएम विनय कुमार सिंह ने कहा कि कम से कम आठवीं कक्षा तक पढ़ाई कर चुके दिव्यांगों की सूची तैयार करें, ताकि उनका स्किल ट्रेनिंग करवाया जा सके।



उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए संचालित सभी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना को प्रचारित करने का निर्देश भी दिया।





30 | जून | 2019

## दिव्यांगों की बने कमेटी समीक्षा बैठक

# वीरपुर अनुमंडल

दिव्यांग जनों के अधिकार के प्रति पदाधिकारियों को होना होगा संवेदनशील : निःशक्तता आयुक्त



### समीक्षा

220 दिव्यांगता प्रमाण पत्र	152 दिव्यांगता पेंशन
20 छात्रवृत्ति एवं नामांकन	40 दिव्यांगजन राशन कार्ड

**अ** योजनाओं को निचले और अंतिम स्तर तक लागू करना अनिवार्य होगा।

नुमंडल मुख्यालय (वीरपुर) स्थित कौशिकी भवन के सभागार में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार द्वारा अनुमंडल क्षेत्र के सभी अधिकारियों के साथ दिव्यांग योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम सुभाष कुमार ने किया। इस बैठक में दिव्यांगों की समस्या को लेकर बिंदुवार चर्चा की गयी। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगों के अधिकारों के प्रति पदाधिकारियों को संवेदनशील होना होगा। आगे उन्होंने बताया कि यह बैठक पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड और अनुमंडल स्तर तक के सभी दिव्यांगों के अधिकारों को लेकर समूह बनाने के लिए भी आयोजित किया गया है। बनाये गये समूह का कार्य दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा जारी सभी योजनाओं को निचले और अंतिम स्तर तक लागू करना अनिवार्य होगा। इन समूहों को

दिव्यांगों के लिए संचालित सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लगातार प्रयास करना होगा। बैठक में आयुक्त ने कहा कि ऐसे बैठकों का उद्देश्य दिव्यांगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी है। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों को दिव्यांगों को उनके अधिकारों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहने की बात बतायी। समीक्षा बैठक में एसडीएम सुभाष कुमार, बसंतपुर के आरडीओ देवानंद कुमार सिंह, सीओ विद्यानंद झा, राघोपुर आरडीओ सुभाष कुमार, सीओ धर्मनाथ चौधरी, प्रतापगंज के आरडीओ राजाराम पासवान, सीओ नूर आलम, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बसंतपुर डॉ. अर्जुन चौधरी, मिथिलेश प्रसाद कुशवाहा, सभी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के विकास मित्र समते अन्य कई विभाग के कर्मी और दिव्यांग भी अपनी-अपनी समस्याओं के साथ बैठक में उपस्थित थे।

■ अनुमंडल क्षेत्र के सभी अधिकारियों के साथ दिव्यांग योजनाओं की समीक्षा बैठक

बनाये गये समूह का कार्य दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा जारी सभी योजनाओं को निचले स्तर तक लागू करना अनिवार्य होगा। इन समूहों को दिव्यांगों के लिए संचालित सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करना होगा। बैठक में आयुक्त ने कहा कि ऐसे बैठकों का उद्देश्य दिव्यांगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी है। बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों को दिव्यांगों को उनके अधिकारों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहने की बात बतायी।



क्र०सं०	वाद सं०	जिला	वादी एवं प्रतिवादी	विषय
26.	26/2019	नालन्दा	वादी :- श्री पंकज कुमार, पिता-स्व० केदार सिंह, नालन्दा। प्रतिवादी :- शाखा प्रबंधक, सरमेरा शाखा, नालन्दा।	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार हेतु ऋण के संबंध में।
27.	27/2019	भागलपुर	वादी :- श्री अभिषेक रौशन, भागलपुर। प्रतिवादी :-प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर।	दिव्यांगता प्रमाण पत्र से संबंधी।
28.	28/2019	मुजफ्फरपुर	वादी:- श्री राम बाबू साह, मुजफ्फरपुर। प्रतिवादी :-सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुजफ्फरपुर।	पेंशन से संबंधित।
29.	29/2019	पटना	वादी :- कुमारी वैष्णवी, पटना। प्रतिवादी :- गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना।	दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं रेलवे रियायत प्रमाण-पत्र के संबंध में।
30.	30/2019	मुजफ्फरपुर	वादी :- श्री लालू तुरहा, मुजफ्फरपुर। प्रतिवादी :-कार्यापालक अभियंता, वद्वित आपूर्ति प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर।	छात्रावास में दी गयी गलत बिजली बिल के त्रुटि सुधार के सम्बन्ध में।
31.	31/2019	खगड़िया	वादी :- मो० कासिम, पिता-महरूम इमामुद्दीन, खगड़िया। प्रतिवादी :-आरक्षी अधीक्षक, खगड़िया एवं अन्य।	दिव्यांग पत्नी के साथ हुये दुष्कर्म के सम्बन्ध में।
32.	32/2019	पटना	वादी :- श्री नवल किशोर शर्मा, नेत्रहीन कलाकार, पटना। प्रतिवादी :-जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	श्रावणी महोत्सव, 2019 के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के संबंध में।
33.	33/2019	पटना	वादी :- श्री राजीव लोचन कुमार, पटना। प्रतिवादी :-सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, पटना।	निःशक्तता पेंशन की राशि का भुगतान नहीं होने से संबंधित।
34.	34/2019	वैशाली	वादी :- मो० अनवर शबाब, महुआ, जिला-वैशाली। प्रतिवादी :-श्रम आवयुत, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	आई०टी०आई० कॉलेजों में नामांकन से इनकार करने सम्बन्धी।
35.	35/2019	पटना	वादी :- सुश्री रश्मि तिवारी, पटना। प्रतिवादी :- अपर सचिव, (स्थापना) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार।	राजस्व अधिकारीद्वारा नियुक्ति एवं पदस्थापन के विरुद्ध वेतनादि के भुगतान सम्बन्धी।
36.	36/2019	पश्चिम चम्पारण	वादी :- श्री विनय बिहारी, विधायक, पश्चिम चम्पारण। प्रतिवादी :- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण।	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के संबंध में।
37.	37/2019	पटना	वादी :- श्री परमेश्वर दयाल प्रभाकर, पटना। प्रतिवादी :- निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार, पटना।	आरा में किए गए स्थानान्तरण आदेश को स्थगित करवाने से संबंधित।
38.	38/2019	पटना	वादी :- श्री अनिल कुमार पाण्डेय, सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी, पटना। प्रतिवादी :- जिला पदाधिकारी-सह-बन्दोवस्त पदाधिकारी, पटना।	ए०सी०पी०/ एम०ए०सी०पी० का लाभ प्राप्त नहीं होने के सम्बन्ध में।





JULY 2019

# जुलाई 2019

## दिव्यांगों की समस्याओं से गंभीरता से सुने

मरी कटसरी प्रखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस बैठक में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा सत्येंद्र कुमार सिंह भी मौजूद थे।

pg-058



दिव्यांगों को मिले आरक्षण का लाभ...

pg-056



सरकारी योजनाओं में 5% लाभ दिव्यांगों...

pg-060



वहीं राज्य स्तर पर 24 घंटे कार्यरत टॉल...

pg-062



इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त...

pg-063



चौसा प्रखंड कार्यालय पहुंचे...

pg-068



आयुक्त ने पांच दिव्यांगजनों को दी...

pg-070





02 | जुलाई | 2019

# दिव्यांगों को मिले आरक्षण का लाभ पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक



## शिवहर जिला

उम्मीद जगी

1632 दिव्यांगता प्रमाण पत्र  
82 दिव्यांगता पेंशन

32 छात्रवृत्ति एवं नामांकन  
38 दिव्यांगजन राशन कार्ड



■ राज्य निःशक्तता आयुक्त शिवाजी कुमार ने तीन दिवसीय दौरे पर शिवहर पहुंच कर बीडीओ के साथ बैठक



राज्य निःशक्तता आयुक्त शिवाजी कुमार तीन दिवसीय दौरे पर शिवहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिवहर के तरियानी में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजनों के साथ

सामूहिक बैठक कर दिव्यांगता के प्रकार की जानकारी देते हुए जिले में शत प्रतिशत निःशक्तता प्रमाण पत्र बनाने पर बल दिया तथा उन्होंने सरकार द्वारा दिव्यांग जनों को मिलने वाली लाभ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों की श्रेणी को बढ़ाकर अब 21 श्रेणी कर दिया गया है। इसमें चलंत संबंधी दिव्यांगता, मांसपेशीय दुर्विकार, ठीक किया हुआ कुष्ठ, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, अम्ल हमले की पीड़ित, कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण क्षति, सुनने में कठिनाई, वाक और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता आदि शामिल हैं। राज्य आयुक्त ने बताया कि सरकार प्रायोजित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में आमजनों को मिलनेवाले लाभ से पांच फीसदी अधिक लाभ दिव्यांग जनों को दी जाएगी। इसके लिए पंचायतस्तर से लेकर राज्यस्तर तक दिव्यांगजनों के साथ एकसमूह का गठन किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगजनों को जीविका हेतु भी

कई योजना बनायी गयी है। निःशक्तता आयुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार एवं आर्थिक कार्यों के लिए कम दर पर ऋण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग हेतु तीन श्रेणी में 25 हजार से 10 लाख तक का कम दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। दीनदायल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण एवं रोजगार के साथ ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु सहयोग, जनधन योजना के तहत आर्थिक समावेश का प्रयास, पेट्रोल पंप के आवंटन में दिव्यांग शारीरिक दिव्यांगजनों को पांच फीसदी आरक्षण के साथ कई अन्य लाभ दिये जायेंगे। आयुक्त ने कहा कि आजीविका के लिए संस्थाओं के माध्यम से भी योजनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। दिव्यांगजनों के साथ विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गयी है। पांच जुलाई को दिव्यांगजनों के परिवारों की सुनवाई एवं चलंत न्यायालय का आयोजन किया जायेगा। मौके पर सिविल सर्जन धनेश्वर कुमार, डीपीएम पंकज कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी चिंता कुमारी सहित अन्य लोग मौजूद थे।

➔ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग हेतु तीन श्रेणी में 25 हजार से 10 लाख तक का कम दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

➔ चलंत संबंधी दिव्यांगता, मांसपेशीय दुर्विकार, वाक और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता आदि शामिल हैं।

निःशक्तता आयुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार एवं आर्थिक कार्यों के लिए कम दर पर ऋण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग हेतु तीन श्रेणी में 25 हजार से 10 लाख तक का कम दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। दीनदायल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण एवं रोजगार के साथ ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु सहयोग और पांच फीसदी आरक्षण के साथ कई अन्य लाभ दिये जायेंगे।





03 | जुलाई | 2019

## अधिकारियों के साथ बैठक

# शिवहर जिला

प्र

खंड कार्यालय के सभा कक्ष में राज्य आयुक्त निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार व सहायक निर्देशक, समाजिक सुरक्षा सत्येंद्र कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव में करीब 200 से अधिक दिव्यांगों ने भाग लिया। आयुक्त ने दिव्यांगजन अधिकार, अधिनियम 2016 की धारा 80 के तहत अधिकारियों को उनसे जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का निर्देश दिया।

## दिव्यांगों का पेंशन रोकने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

पं

चायत स्तर पर 18 से 40 वर्ष की व्यक्ति का एक समूह की स्थापना करना है। उस समूह में सभी व्यक्ति पढ़ा होना चाहिए। महीना में दो बार बैठक टोला सेवक, सहायिका, एएनएम, आशा द्वारा की जाएगी और दिव्यांगजन को चिन्हित कर पंचायत सचिव के माध्यम से प्रखंड स्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाना है। दिव्यांगजन को सरकारी ट्राई साइकिल, पेंशन के अलावे अन्य जनकल्याणकारी योजनाएं में 5 प्रतिशत आरक्षण, संविदा पर बहाली आदि कामों में भी प्राथमिकता दी जाएगी।

### डुमरी कटसरी प्रखंड



■ अधिकारियों के साथ बैठक में अधिकारियों को उनसे जुड़ी समस्याओं के निष्पादन पर चर्चा करते अधिकारीगण

मिला चस्का • प्रखंड कार्यालय के सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ हुई बैठक, दिए कई निर्देश  
**निःशक्तों की बात नहीं सुनते हैं अधिकारी तो थाने में दर्ज कराएं प्राथमिकी : आयुक्त**

बैठक में प्रखंड के विभिन्न गांव से करीब 200 से अधिक दिव्यांगों ने भाग लिया  
बैठक में आयुक्त ने प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव में करीब 200 से अधिक दिव्यांगों ने भाग लिया। आयुक्त ने दिव्यांगजन अधिकार, अधिनियम 2016 की धारा 80 के तहत अधिकारियों को उनसे जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का निर्देश दिया।



**250**

दिव्यांग शामिल हुये



**1500**

लोग सीधे जुड़े कार्यक्रम से



**335**

लोग सीधे जुड़े कार्यक्रम से



**05**

हजार लोग जानें मीडिया से

**पंचायत स्तर पर 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति के लिए बनाना है समूह**

पंचायत स्तर पर 18 से 40 वर्ष की व्यक्ति का एक समूह की स्थापना करना है। उस समूह में सभी व्यक्ति पढ़ा होना चाहिए। महीना में दो बार बैठक टोला सेवक, सहायिका, एएनएम, आशा द्वारा की जाएगी और दिव्यांगजन को चिन्हित कर पंचायत सचिव के माध्यम से प्रखंड स्तर प्राथमिक स्वास्थ्य

दिव्यांगजन को सरकारी ट्राई साइकिल, पेंशन के अलावे अन्य जनकल्याणकारी योजनाएं में 5 प्रतिशत आरक्षण, संविदा पर बहाली आदि कामों में भी प्राथमिकता दी जाएगी।



04 | जुलाई | 2019



## अधिकारियों के साथ बैठक

# शिवहर जिला

सबका अधिकार

200 दिव्यांग शामिल हुये

300 लोग सीधे जुड़े कार्यक्रम से

3000 से अधिक लोग मीडिया के माध्यम से हुए जागरूक



■ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

उद्देश्य

मरी कटसरी प्रखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस बैठक सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा सत्येंद्र कुमार सिंह भी मौजूद थे। बैठक में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव से करीब 200 से अधिक दिव्यांगों ने भी भाग लिया। आयुक्त ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 80 के तहत अधिकारियों को उनसे जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि दिव्यांगता 21 प्रकार

की है। उनमें चलंत संबंध, दिव्यांगता मांसपेशीय दुर्विकार ठीक किया हुआ कुष्ठ, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, अम्ल हमले की पीड़ित, कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण छाती, सुनने में कठिनाई, वाक और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता आदि शामिल है। बैठक में आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों को प्रखंड स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रमाण पत्र बनाया जाना है। अगर यहां पर प्रमाणपत्र नहीं बनता है, जैसे दिव्यांगजन का प्रमाणपत्र, सदर अस्पताल से जारी होगा। कोई निःशक्त व्यक्ति आरपीटीपीएस काउंटर पर आवेदन एक से तीन बार करता है,

उसके बाद भी विभागीय पदाधिकारी कोई ध्यान नहीं लेते है, तो निःशक्त व्यक्ति थाना में जाकर पदाधिकारी के विरुद्ध सनहा लिखा सकता है। उसकी सुनवाई न्यायालय में होगी। निःशक्त व्यक्ति को सुनवाई के दौरान नहीं जाना है, सिर्फ संबंधित पदाधिकारी ही रहेंगे। आयुक्त ने कहा कि पंचातय स्तर पर 18 से 40 वर्ष की व्यक्ति का एक समूह की स्थापना करना है। उस समूह में सभी व्यक्ति पढ़ा होना चाहिए। महीना में दो बार बैठक टोला सेवक, सहायिका, एएनएम, आशा द्वारा की जाएगी और दिव्यांगजन को चिह्नित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाना होगा।

बैठक में आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों को प्रखंड स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रमाण पत्र बनाया जाना है। अगर यहां पर प्रमाणपत्र नहीं बनता है, जैसे दिव्यांगजन का सदर अस्पताल से जारी होगा।

## दिव्यांगों के मामले निपटारे गये



05 | जुलाई | 2019



**चलंत न्यायालय  
सक्रिय है सरकार**

# शिवहर जिला

**जांच शिविर**



■ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने समस्याओं का समाधान करते।

कार्यों के लिए कम दर पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग के लिए तीन श्रेणी में 25 हजार से 10 लाख रुपये तक का कम दर पर ऋण दिव्यांगों को उलब्ध कराया जाना है। उन्होंने दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण और रोजगार के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान दिव्यांगों के

लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय महानिदेशालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण आर्थिक पुनर्वास में सहायता के बारे में जानकारी दी गयी।



**गां** धी नगर भवन में दिव्यांगजनों के परिवारों की सुनवाई के लिए चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, जिला पदाधिकारी अरशद अजीज, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रामसुजन पांडेय, सिविल सर्जन धनेश कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी अफाक अहमद, पूर्व जिला परिषद सदस्य अजब लाल चौधरी आदि ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान गांधी नगर भवन में दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जांच के बाद दिव्यांगों को ऑन द स्पॉट दिव्यांगता प्रमाणपत्र दिया गया। सरकार के इस पहल से दिव्यांगों में हर्ष व्याप्त रहा। इस दौरान गांधी भवन में दिव्यांगों की भीड़ उमड़ पड़ी। चिकित्सकों की टीम दिव्यांगों के जांच को सक्रिय रही। दिव्यांगों ने कहा कि जांच व प्रमाणपत्र के लिए कार्यालय का चक्कर लगाने से राहत मिली है। इससे हम सब खुश हैं।

मौके पर राज्य निःशक्तता आयुक्त ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दी जानेवाली लाभों के बारे में जानकारी दी तथा कहा कि दिव्यांगजनों का क्षमता एवं विकास करना सरकार की मंशा है, ताकि वह अपने समुदाय एवं समाज के आर्थिक विकास में प्रभावी भूमिका निभा सकें। जिलाधिकारी अजीज ने सभी प्रकार के औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यवसाय तथा कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के समावेश पर बल दिया। वहीं सहयोग का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम के दौरान आयुक्त ने सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय दिव्यांगता वित्त एवं विकास निगम के द्वारा स्वरोजगार एवं अन्य आर्थिक

1898

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

345

दिव्यांगता पेंशन

3165

दिव्यांगों ने सुनाया फेरियाद

2100

मामलों को निष्पादन



09 | जुलाई | 2019



## सरकारी योजनाओं में 5% लाभ दिव्यांगों को मिलेंगे

# खगड़िया जिला

रा

ज्य  
निःशक्तता  
आयुक्त डॉ.  
शिवाजी कुमार  
ने परिसदन

भवन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रचार-प्रसार के अभाव में दिव्यांग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे दिव्यांगों को मिलनेवाले लाभ की जानकारी के संबंध में प्रचार प्रसार करें।

राज्य निःशक्तता आयुक्त ने बताया कि राज्य सरकार 21 तरह के दिव्यांगों की पहचान की है। दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं में पांच प्रतिशत लाभ दिया जाना है। सरकारी सेवा में भी दिव्यांगों का आरक्षण तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया गया है। आयुक्त ने कहा कि दिव्यांग के प्रति उदासीनता बरतने वाले पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों की परेशानी का यदि स्थानीय स्तर पर अधिकारी निदान नहीं करते हैं, तो पीड़ित दिव्यांग पावती रसीद के साथ 15-15 दिन के अंतराल पर उन्हें जानकारी देंगे। उसके बाद मामला न्यायालय में चलेगा। जिसमें दोषी पाये जाने पर पदाधिकारियों को 10 हजार जुर्माना एवं कारावास की भी सजा दी जा सकती है।

आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों को इज्जत व सम्मान देना एवं घृणा एवं द्वेष से बचना बहुत जरूरी है। इसके लिए सामान्य सामाजिक दर्जा, सुविधाओं तक पहुंच, शिक्षा को बढ़ावा, रोजगार क्षमता एवं कानूनी क्षमता का पालन जैसे प्रयास तेज करने हैं। आयुक्त ने कहा कि पागल एवं मंदबुद्धि जैसे शब्दों का प्रयोग अपमानजनक है।



☞ दिव्यांगजनों को इज्जत व सम्मान देना एवं घृणा एवं द्वेष से बचना बहुत जरूरी है।

☞ सामान्य सामाजिक दर्जा, सुविधाओं तक पहुंच, शिक्षा को बढ़ावा, रोजगार क्षमता एवं कानूनी क्षमता का पालन जैसे प्रयास तेज करने हैं।

☞ पागल एवं मंदबुद्धि जैसे शब्दों का प्रयोग अपमानजनक है।

■ निःशक्तता आयुक्त पहुंचे खगड़िया, अधिकारियों के साथ की बैठक में उपस्थित हुए फरियादी

☞ दिव्यांगजनों के लिए मुफ्त सरकारी वकील की व्यवस्था करेगा।  
☞ खेलकूद में भी दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।



### श्रवण बाधित बच्चों के लिए छह लाख

राज्य आयुक्त ने बताया कि श्रवण बाधित छह वर्ष के बच्चों को भारत सरकार छह लाख खर्च का लाभ देगी। विधिक सेवा प्राधिकार दिव्यांगजनों के लिए मुफ्त सरकारी वकील की व्यवस्था करेगा। खेलकूद में भी दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। श्रम संशाधन, जीविका, बुनियादी केंद्र आपस में समन्वय बनाकर दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ मुहैया कराएंगे।



09 | जुलाई | 2019

अधिकारियों के साथ बैठक



# खगड़िया जिला



■ अधिकारियों के साथ की बैठक करते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार.

गांधी नगर भवन में दिव्यांगजनों के परिवारों की सुनवाई के लिए चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, जिला पदाधिकारी अरशद अजीज, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रामसुजन पांडेय, सिविल सर्जन धनेश कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी अफाक अहमद, पूर्व जिला परिषद सदस्य अजब लाल चौधरी आदि ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान गांधी नगर भवन में दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जांच के बाद दिव्यांगों को ऑन द स्पॉट दिव्यांगता प्रमाणपत्र दिया गया। सरकार के इस पहल से दिव्यांगों में हर्ष व्याप्त रहा। इस दौरान गांधी भवन में दिव्यांगों की भीड़ उमड़ पड़ी। चिकित्सकों की टीम दिव्यांगों के जांच को सक्रिय रही। दिव्यांगों ने कहा कि जांच व प्रमाणपत्र के लिए कार्यालय का चक्कर लगाने से राहत मिली है। इससे हम सब खुश हैं।

मौके पर राज्य निःशक्तता आयुक्त ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दी जानेवाली लाभों

के बारे में जानकारी दी तथा कहा कि दिव्यांगजनों का क्षमता एवं विकास करना सरकार की मंशा है, ताकि वह अपने समुदाय एवं समाज के आर्थिक विकास में प्रभावी भूमिका निभा सके। जिलाधिकारी अजीज ने सभी प्रकार के औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यवसाय तथा कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के समावेश पर बल दिया।

वहीं सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान आयुक्त ने सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय दिव्यांगता वित्त एवं विकास निगम के द्वारा स्वरोजगार एवं अन्य आर्थिक कार्यों के लिए कम दर पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग के लिए तीन श्रेणी में 25 हजार से 10 लाख रुपये तक का कम दर पर ऋण दिव्यांगों को उलब्ध कराया जाना है। उन्होंने दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण और रोजगार के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान दिव्यांगों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। राष्ट्रीय कौशल



विकास निगम के तहत व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय महानिदेशालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण आर्थिक पुनर्वास में सहायता के बारे में जानकारी दी गयी।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग के लिए तीन श्रेणी में 25 हजार से 10 लाख रुपये तक का कम दर पर ऋण दिव्यांगों को उलब्ध कराया जाना है।



# खगड़िया जिला

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

1900

दिव्यांगों ने सुनाया फरियाद



समीक्षा बैठक

10 | जुलाई | 2019



वहीं राज्य स्तर पर 24 घंटे कार्यरत टॉल फ्री नंबर 8448385590 के प्रचार प्रसार का भी निर्देश दिये। उन्होंने विभागवार समीक्षा करते हुए दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा की।

दि

व्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सभी दिव्यांगों को नियमानुसार योजनाओं का समुचित लाभ मिले। अब दिव्यांगता सात से बढ़कर 21 प्रकार हो गया है। यह बातें राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार ने समाहरणालय सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में बुधवार को अपने संबोधन में कही। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया की दिव्यांगों से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था सभी पीएचसी में करना सुनिश्चित कराने की बात कही। वहीं दिव्यांगों द्वारा आवेदन के समय प्रयुक्त होनेवाले फोटोग्राफ में उनका दिव्यांगता दिखना अनिवार्य नहीं है। वही डीडीओ को निर्देश दिया कि सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता दें।

वहीं डीटीओ को निर्देश दिया कि अगर कोई दिव्यांग लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो, उस पर त्वरित कार्रवाई कर प्राथमिकता दें। वहीं राज्य स्तर पर 24 घंटे कार्यरत टॉल फ्री नंबर 8448385590 के प्रचार प्रसार का भी निर्देश दिये। उन्होंने विभागवार समीक्षा करते हुए दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। बैठक में डीएम अनिरुद्ध कुमार ने कहा कि दिव्यांगों को सशक्त बनाने को लेकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग के लिए तीन श्रेणी में 25 हजार से 10 लाख रुपये तक के ऋण देने की बात कही। वहीं दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत प्रशिक्षण एवं रोजगार, जन-धन योजना के तहत आर्थिक समावेश का प्रयास, पेट्रोल पंप के आवंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था आदि के बारे में भी जानकारी दी। वहीं सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि 31 अगस्त तक अभियान चलाकर दिव्यांगों को हर हाल में प्रमाणपत्र जारी कर दें। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धीरज कुमार

भास्कर, एसपी मीनू कुमारी, डीडीसी राम निरंजन सिंह, एसडीओ धर्मेन्द्र कुमार, सुभाषचंद्र मंडल व अन्य मौजूद थे। आईसीडीएस की पर्यवेक्षिका रिंकी कुमारी से उन्होंने पूरी जानकारी ली। आयुक्त ने विभिन्न प्रावधान के तहत विभागीय स्तर से निःशक्तजनों को दी जाने वाली सुविधाओं पर बिन्दुवार समीक्षा किया।

■ दिव्यांगजनों का फरियाद सुनते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार.

## संचालित योजनाओं की समीक्षा

चौथम प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर ट्रायसेम भवन में राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। निःशक्त को प्रावधान के तहत दी जाने वाली सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा की गयी।



# खगड़िया जिला

ने किया आवेदन

518 दिया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र



12 | जुलाई | 2019 जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक



इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। यह बातें आयोजित चलंत न्यायालय के दौरान राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार ने कही।



■ दिव्यांगजनों का फरियाद सुनते राज्य निःशक्तता आयुक्त.

रा

जिले के निःशक्तों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के उद्देश्य से चार दिवसीय दौरे पर खगड़िया आये राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने समाहरणालय के सभागार में जिले के आला अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों को अपने-अपने पंचायत या क्षेत्र के निःशक्तों

की पहचान कर उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने कहा गया। पंचायत स्तर पर निःशक्तों की टीम बनाकर उनकी समस्याओं को सुनने तथा समाधान की बात कही गयी। आयुक्त ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से दिव्यांग एवं निःशक्तों को सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष ध्यान देना होगा। डीएम अनिरुद्ध कुमार ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि अलग-थलग रह रहे निःशक्तों को मजबूत करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार ने निःशक्तों के लिए आरक्षण, रोजगार के लिए विशेष सहायता, मुफ्त ट्रायसाइकिल, अस्पताल, बैंक, रेलवे स्टेशन पर विशेष काउंटर, कौशल विकास एवं रोजगार के लिए कई तरह की सुविधाओं का प्रवाधान किया है। जरूरी है उनके लिए बने नियम का पालन करते हुए निःशक्तों को उनका वाजिब हक दिलाया जाये। गोगरी व परबत्ता प्रखंड में भी पहुंचे आयुक्त, किया निरीक्षण : निःशक्तता आयुक्त ने गुरुवार को गोगरी एवं परबत्ता प्रखंड में निःशक्तों एवं स्थानीय अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इसमें स्थानीय निःशक्तों को सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली विशेष सुविधाओं पर चर्चा की गयी। इनके अलावा आयुक्त ने सदर अस्पताल प्रशासन को कई आवश्यक निर्देश दिये। आयुक्त ने सिविल सर्जन व अलग-अलग पीएचसी प्रभारी, आईसीडीएस के सुपरवाइजर, समावेशी शिक्षक व बुनियाद केंद्र के कर्मियों, जिला विधिक प्राधिकार के पीएलवी वॉलेंटियर, शिक्षा अधिकारी एवं निजी स्कूलों के प्रधानों के साथ अलग अलग बैठक की। गोगरी प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर राज्य निःशक्तता आयुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार निःशक्तों को समाज के मुख्य आधार में जोड़ने का कार्यक्रम चला रही है।

छह माह की सजा मिलेगी

निःशक्तों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं पहुंचाना एवं उन कानूनों की विस्तार से जानकारी दी जाये। अगर कोई व्यक्ति किसी को लंगड़ा कहता है, तो उसका वीडियो बनाकर सबूत पेश करने पर उस व्यक्ति को छह माह की सजा मिलेगी।

शिविर में 518 दिव्यांगों का ऑन द स्पॉट प्रमाण-पत्र बना, विभिन्न योजनाओं के लिए आए 4 हजार आवेदन



31 अगस्त तक आवेदनों का करें निष्पादन



21 जुलाई | 2019

# खेल बना रहा दिव्यांगों को सुदृढ़

22-21  
से पराजित  
किया  
पाटलिपुत्र  
खेल परिसर  
के इंडोर  
स्टेडियम में  
रविवार को  
खेले गये  
फाइनल  
मुकाबले में  
केरल ने  
बिहार को

19  
गोल किये  
एबिन ने



बि

हार के दिव्यांगों को खेल सुदृढ़ बना रहा है। तृतीय राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में पहुंचे राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि राज्य के दिव्यांग खिलाड़ी हर मोर्च पर देश और दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। इसमें राज्य सरकार भी अहम भूमिका निभा रही है। दिव्यांगों को खेल से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई अहम योजनाएं चलायी जा रही हैं। दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल कोटे में नौकरी भी दी जा रही है। इसके अलावा खिलाड़ी कल्याण कोष से उनकी मदद भी की जा रही है। पिछले कुछ सालों में राज्य के खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन कर बिहार का नाम रौशन किया है। ऐसे खिलाड़ियों को सरकार द्वारा राज्य के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। राज्य के पैरालिंपिक कमेटी और बिहार स्पेशल ओलिंपिक सहित तमाम खेल संघों को निर्देश दिया गया है कि वह गांव-गांव जाकर बेहतर प्रतिभा का चयन करें। दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल से जोड़ने के लिए सभी अहम प्रयास करें। ताकि उनका भविष्य बेहतर बनाया जा सके।

इसके पूर्व राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी में बिहार की टीम उपविजेता बनी। रग्बी फेडरेशन ऑफ इंडिया व रग्बी एसोसिएशन ऑफ बिहार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में केरल की टीम चैंपियन बनी। पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में रविवार को खेले गये फाइनल मुकाबले में केरल ने बिहार को 22-21 से पराजित किया। केरल से एबिन ने सर्वाधिक 19 गोल किये।

वहीं बिहार की ओर से दीपक ने सर्वाधिक 14 गोल दागे। छत्तीसगढ़ की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बिहार के दीपक कुमार और केरल के इविन को बेस्ट स्कोर का खिताब दिया गया। शैलेश को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। इंद्रा प्रसाद को उदयमान खिलाड़ी, प्रवीण कुमार, शाहरुख, सुनील एवं रिया गुप्ता को बेस्ट इनकरैजमेंट का पुरस्कार दिया गया। विजेता व उपविजेता को राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, उपाध्यक्ष लता गुप्ता (व्हील चेयर रग्बी फेडरेशन ऑफ इंडिया) व जापान से आये डेलिगेट ने संयुक्त रूप से ट्रॉफी व मेडल देकर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।



तृतीय राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप में बिहार टीम बनी उपविजेता



दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल कोटे में नौकरी भी दी जा रही है। पिछले कुछ सालों में राज्य के कुछ खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन कर बिहार का नाम रौशन किया है।

■ राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी में विजेता ट्रॉफी के साथ केरल की टीम।





# बक्सर जिला

452 ने किया शिकायत

26000 दिया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र

23 | जुलाई | 2019 प्रखंडों में भ्रमण



■ चलंत लोक अदालत में शिकायत लेकर पहुंचे दिव्यांगजन



ज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार बक्सर जिला में चार दिवसीय दौरे पर पहुंचे और विभिन्न प्रखंडों का निरीक्षण भी किया। जिले के अतिथि गृह में संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि वह विगत चार दिनों में दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं का समीक्षा करेंगे। वहीं दौरे के अंतिम दिन चलंत न्यायालय का आयोजन होगा, जिसमें सभी दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुनी जाएगी और जहां तक हो उसका निष्पादन तत्काल करने का प्रयास किया जायेगा।

आयुक्त ने बताया कि दिव्यांगों की मदद के लिए सरकार आपके द्वार पर पहुंची है। जिले के सभी प्रखंडों में जाकर दिव्यांगों के बीच फैली भ्रातियों को दूर करने के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की योजनाओं को उनके बीच पहुंचाने का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि आमतौर पर दिव्यांग यह मानते हैं कि उन्हें केवल ट्राइसाइकिल तथा पेंशन ही सरकार से मिलने चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। सरकार उन्हें हर वह सुविधा प्रदान करती है, जो गरीबी उन्मूलन के लिए बनायी गयी है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों की समस्याओं का त्वरित निबटान करने हेतु प्रखंड स्तर पर एक कमेटी बनायी गयी है, जो कि डोर टू डोर जाकर दिव्यांगों की सहायता करेगी। आयुक्त ने बताया कि दिव्यांगों की सहायता के लिए एक टोल फ्री नंबर 8448385590 भी जारी किया गया है। जिस पर वे अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं। डॉ. शिवाजी कुमार ने बताया कि सरकार की चाहत है कि दिव्यांगों की समस्याओं का

चक्की प्रखंड



उन्होंने बताया कि आमतौर पर दिव्यांग यह मानते हैं कि उन्हें केवल ट्राइसाइकिल तथा पेंशन ही सरकार से मिलने चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। सरकार उन्हें हर वह सुविधा प्रदान करती है, जो गरीबी उन्मूलन के लिए बनायी गयी है।

प्राथमिकता के आधार पर निदान किया जाये।

चक्की प्रखंड मुख्यालय पहुंचे आयुक्त ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों के लिए पंचायत स्तर पर एक समूह का गठन हो, जिससे उनके लिए बनायी जा रही लाभकारी योजनाओं का तुरंत फायदा प्राप्त हो। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि अभी सरकार की हर योजना से दिव्यांगों को समुचित सुविधाएं नहीं मिल रही है। इन्होंने समस्याओं के जल्द निदान होने का आश्वासन दिया। बैठक में कई अन्य मौजूद थे।



# बकसर जिला

5%

आरक्षण का लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी

हल्के एवं लर्निंग लाइसेंस भी दिये जाते है

जन वितरण प्रणाली का लाइसेंस लेने में भी दिव्यांगों को पांच फीसदी आरक्षण दिया जायेगा

मनरेगा में भी उन्हें पांच प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है

## समीक्षा बैठक

24 | जुलाई | 2019



■ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार बैठक करते।

**दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर निःशक्तता आयुक्त ने की बैठक**

**दिव्यांग जनों के लिए डीआरसीसी भवन में आज लगेगी चलंत अदालत, योजनाओं का मिलेगा लाभ**



दिव्यांगों के साथ किसी प्रकार का विभेद करना कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके लिए सजा का प्रावधान है। जिले के सभी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में राज्य निःशक्तता आयुक्त ने राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट के सभी प्रावधानों की जानकारी विस्तार दी। साथ ही जिले के प्रत्येक पंचायत में पांच-पांच दिव्यांगों का ग्रुप बनवाने की आवश्यकता

जतायी। ताकि, उनको समस्याओं का जल्द निष्पादन हो सके। बैठक में आयुक्त न सभी विभागों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। बैठक में जिले में दिव्यांगजनों को प्रमाणपत्र निर्गत करने की स्थिति दयनीय होने पर राज्य आयुक्त ने सिविल सर्जन एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का आदेश दिया। इस दौरान उन्होंने हर हाल में जिले के सभी दिव्यांगजनों को 31 अगस्त तक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके लिए सदर अस्पताल के साथ-साथ सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से उन्हें प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिए सख्त निर्देश दिया। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि बैठक में कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग को सर्किट हाउस में अविलंब रैप बनवाने का आदेश दिया। वहीं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को दिव्यांगजनों के लिए विशेष शौचालय बनवाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही सरकारी विद्यालयों में गंभीर दिव्यांगजनों को सरकारी प्रावधान के अनुरूप सालाना तीन हजार रुपये भुगतान करने का आदेश जारी किया। आयुक्त ने कहा कि सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को क्षैतिज रूप से

दिव्यांगजनों के लिए प्राइवेट नौकरियों में लाभ का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार दिव्यांगों के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन स्तर में सुधार के लिए बहुआयामी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सस्ते दर पर ब्याज के अलावा स्वरोजगार के अन्य उपायों पर विमर्श किया जा रहा है।

**विभिन्न विभागों के जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक**

पांच प्रतिशत का आरक्षण सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार दिया जाना है। वहीं आयुक्त ने कहा कि दिव्यांग चाहें तो कौशल विकास का प्रशिक्षण लेकर स्वयं हुनरमंद बन सकते हैं। यह हुनर उनको स्वरोजगार तथा प्राइवेट नौकरियों में बहुत काम आयेगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए प्राइवेट नौकरियों में लाभ का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार दिव्यांगों के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन स्तर में सुधार के लिए बहुआयामी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सस्ते दर पर ब्याज के अलावा स्वरोजगार के अन्य उपायों पर विमर्श किया जा रहा है। आयुक्त ने दिव्यांगों से विवाह करने पर एक लाख रुपये की सहायता राशि मिलने की भी जानकारी बैठक में दी। उन्होंने बताया कि अगर दोनों दिव्यांग हैं, तो उन्हें दो लाख रुपये की सरकारी सहायता राशि देने का प्रावधान है। वहीं अगर उनका विवाह अंतरजातीय होता है तो उस परिस्थिति में एक लाख रुपया अतिरिक्त सहायता राशि के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।



# षष्ठमर जिला

# 2243

दिव्यांगजनों का जॉब कार्ड भी 15 अगस्त से पहले खुलवाने का निर्देश पीओ को दिया।

# 121

यूनिट मनरेगा के तहत वृक्ष लगाने की योजना अगस्त में है।



## चौ चलंत न्यायालय

25 | जुलाई | 2019



■ चलंत लोक अदालत में शिकायत लेकर पहुंचे दिव्यांगजन



## चौ

सा प्रखंड कार्यालय पहुंचे राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार अधिकारियों और दिव्यांगजनों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए चालयी जा रही प्रमुख लाभकारी एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि ऐसा प्रायः देखा जाता है कि दिव्यांग व्यक्ति का प्रमाणपत्र बनवाने के बाद सिर्फ उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि का ही लाभ मिल पाता है। जागरुकता के अभाव में दिव्यांगों को उनका वास्तविक लाभ व अधिकार नहीं मिल पाता है। जिससे दिव्यांगजन को जमीनी स्तर पर सरकारी सहायता का लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों की सहायता के लिए पेंशन के अलावा दिव्यांग ऋण, आवास योजना, मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना आदि कई प्रकार की योजनाएं चला रखी है। परंतु जागरुकता व जानकारी के अभाव में समाज के वैसे व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है।

आयुक्त ने प्रत्येक पंचायत में दिव्यांग शिक्षित व्यक्ति का समूह बनाने का निर्देश दिया। उन्होमने कहा कि ऐसे समूह के लोग गांव-गांव घूमकर अन्य दिव्यांग लोगों की सहायता कर योजनाओं के बारे में जानकारी साझा करेंगे। जिसमें प्रखंड व जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक एक चेन की तरह काम करने वाला संगठन का निर्माण किया जायेगा। जिसमें 18 से 40 वर्ष तक के अलग-अलग दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को सदस्य बनाया जायेगा। समूह गठन के बाद पुलिस से जुड़ा मामला, प्रमाण पत्र

बनाने की जानकारी, पेंशन या रेलवे आदि में मिलने वाली सुविधाओं की जनाकारी आसानी से दिव्यांगों तक पहुंच जाएगी।

राजपुर प्रखंड मुख्यालय के सभागार में हुई बैठक में बीडीओ अरुण कुमार सिंह ने बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत राजपुर में कुल 2243 लोगों का पेंशन स्वीकृत होने की जानकारी दी। जिसमें 75 लोगों का नाम गलत व अन्य कारणों से पेंशन की राशि नहीं भुगतान होने की बात कही। इसके अलावा बैठक में बताया गया कि 111 दिव्यांगजनों के बीच वितरण करने के लिए सामग्री जैसे ट्राइसाइकिल और बैसाखी भी अनुमंडल स्तर पर उपलब्ध हो गया है। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब तीन प्रतिशत के बदले पांच प्रतिशत दिव्यांगजनों को दिया जायेगा।

## ऑन द स्पॉट स्थलीय निरीक्षण

अगस्त में मनरेगा के तहत वृक्ष लगाने की योजना : इसके अलावा 121 यूनिट मनरेगा के तहत वृक्ष लगाने की योजना अगस्त में है। जिसमें से सभी दिव्यांगजनों को ही वन रक्षा के लिए लक्ष्य रखा गया है। बैठक में राज्य आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार ने प्रखंड के सभी 2243 दिव्यांगजनों का जॉब कार्ड भी 15 अगस्त से पहले खुलवाने का निर्देश पीओ को दिया। इसके अलावा जेएसएस को एक माह के अंदर प्रखंड में सर्वे कराकर सभी दिव्यांगजनों की रिपोर्ट दें। इसके अलावा देवढिया पंचायत के वार्ड संख्या पांच के सचिव जो कि पैर से दिव्यांग है, उन्हें सम्मानित करने की बात भी कही। बैठक में बीडीओ द्वारा बताया गया कि उक्त दिव्यांग महिला ने जल नल योजना की कार्य को समय से पूर्ण करा दिया है। बैठक में सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक विशाल कुमार व अन्य मौजूद थे।



# बक्सर जिला



■ चलंत लोक अदालत में शिकायत लेकर पहुंचे दिव्यांगजन



3200

से अधिक  
आये आवेदन

1232

से अधिक  
प्रमाणपत्र  
मिला



चलंत न्यायालय

26 | जुलाई | 2019

1200

आवेदन  
प्रधानमंत्री  
आवास  
योजना के  
तहत आये

500

से अधिक  
आवेदन  
पेंशन के लिए  
आये

900

आवेदन बैंक  
ऋण के लिए  
दिव्यांगों ने  
दिये

**श** हर के चरित्रवन स्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (डीआरसीसी) में 26 जुलाई को चलंत लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिसमें प्राप्त 3200 शिकायतों का निष्पादन किया गया। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्राप्त वादों की

सुनवाई राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने की। दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत चलंत न्यायालय का आयोजन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा किया गया था। जिसका उद्घाटन निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों का स्वागत सिविल सर्जन डॉ. उषा किरण वर्मा एवं मंच संचालन की जिम्मेदारी सदर अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय एवं कोषांग के सहायक निदेशक हरिशंकर सिंह ने संयुक्त रूप से किया।

परिवादों की सुनवाई के दौरान निःशक्तता आयुक्त समस्याओं का निदान ऑन द स्पॉट करा रहे थे। इस मौके पर विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव

राजेश कुमार त्रिपाठी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश कुमार, जिला योजना पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी राम इकबाल राम, बक्सर नप के कार्यपालक पदाधिकारी रोहित कुमार व अन्य मौजूद थे।

दिव्यांगों की समस्याओं से संबंधित विभिन्न विभागों के अलग-अलग कुल 40 काउंटर लगाये गये थे। जहां आयुक्त के निर्देश पर वादों का निपटारा तुरंत किया जा रहा था। दिव्यांगता प्रमाणपत्र निबंधन के लिए बने दस काउंटर पर चिकित्सकों की 80 सदस्यीय टीम तैनात थी। वहीं बैंकों के पांच काउंटर्स के अलावा बुनियाद केंद्र की संजीवनी वाहन, डीआरडीए, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला परिवहन विभाग, पुलिस व आइसीडीएस समेत अन्य विभागों के काउंटर बने थे। विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक कुल 3200 परिवाद दर्ज किये गये। जिनमें दिव्यांगता प्रमाणपत्र के 1232, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 सौ, राशन कार्ड के पांच सौ तथा नौ सौ मामलों का प्रक्रियाधीन निष्पादन किया गया।



दिव्यांगों की समस्याओं से संबंधित विभिन्न विभागों के अलग-अलग कुल 40 काउंटर लगाये गये थे। जहां आयुक्त के निर्देश पर वादों का निपटारा तुरंत किया जा रहा था। दिव्यांगता प्रमाणपत्र निबंधन के लिए बने दस काउंटर पर चिकित्सकों की 80 सदस्यीय टीम तैनात थी।



# रोहतास जिला



आयुक्त द्वारा विभिन्न प्रखंडों का दौरा  
ऑन द स्पॉट दिव्यांगों की हुई सुनवाई एवं हुआ समस्या का समाधान



27 | जुलाई | 2019 समीक्षा बैठक



■ बिक्रमगंज पहुंचने पर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार का हुआ स्वागत।

दि

व्यांगता की वजह से को घबराना नहीं चाहिए। समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशक्तों के लिए कौशल विकास व रोजगार का प्रावधान किया गया है। उन्हें सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त

डॉ. शिवाजी कुमार ने सासाराम प्रखंड के इ-किसान भवन व बिक्रमगंज नगर परिषद सभागार में दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग की समीक्षा बैठक में कहीं।

उन्होंने बारी-बारी से सभी योजनाओं में दिव्यांगों की भूमिका व उनको मिलने वाले

लाभ के बारे में जानकारी ली। दिव्यांगों के प्रति शिक्षा विभाग की उदासीनता पर आयुक्त ने असंतोष जताते हुए एसडीएम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सासाराम प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी स्मृति व बिक्रमगंज एसडीएम विजयंत ने दिव्यांगजनों को औपचारिक व अनौपचारिक व्यवसायिक और कौशल विकास प्रशिक्षण व कार्यक्रमों में दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं पर प्रकाश डाला। कई दिव्यांगों ने समय से पेंशन नहीं मिलने, आवास समेत कई समस्याओं की ओर आयुक्त का ध्यान आकृष्ट कराया। बिक्रमगंज के बाद राज्य आयुक्त दिनारा प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर वहां दिव्यांगजनों के हित के लिए चल रही योजनाओं

का जायजा लिया और पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं निःशक्तजनों के साथ बैठक किया। बैठक में दिव्यांगजनों के लिए चालयी जा रही योजनाओं की जनाकारी दी। पंचायत व प्रखंडस्तर पर निःशक्तजनों, पंचायत प्रतिनिधियों व प्रखंड कर्मियों की कमेटी का गठन किया गया। जो पंचायत में हर 15 दिनों व प्रखंड में महीने में एक बार बैठक कर दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही दिव्यांगजन का तत्काल प्रमाणपत्र जारी करने का पीएचसी पदाधिकारियों को निर्देश दिया। बैठक के बाद पांच दिव्यांगजनों राजन पासवान, सुमन कुमार, धनजी कुमार, मिथिलेश सिंह और छोटेलाल को ट्राइसाइकिल दिया गया।

पंचायत व प्रखंडस्तर पर निःशक्तजनों, पंचायत प्रतिनिधियों व प्रखंड कर्मियों की कमेटी का गठन किया गया। जो पंचायत में हर 15 दिनों व प्रखंड में महीने में एक बार बैठक कर दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही निःशक्तों का तत्काल प्रमाणपत्र जारी करने का पीएचसी पदाधिकारियों को निर्देश दिया।





■ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार हुये सम्मानित।

👉 दिव्यांग परिवार को दिलाया त्वरीत लाभ

👉 ट्राइसाइकिल, ऑर्थो बेड तत्काल मुहैया कराया

👉 घर मरम्मत और वेस्टर्न टॉयलेट बनाने का दिया निर्देश



ज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार अपने कार्यों को लेकर बहुत ही संवेदनशील हैं। इस बात की पुष्टि इससे होती है कि एक अखबार में दिव्यांगों की दयनीय स्थिति की खबर देखने के बाद उनको न्याय दिलाने के लिए उनके घर पहुंच गये। यह वाक्या सासाराम जिले के संझौली प्रखंड के छुलकार गांव की है। इस गांव के देवमुनी सिंह यादव के तीन पुत्र पैरों से दिव्यांग हैं। बीते सात वर्षों से वह अपने पुत्रों की दवा खुद से करा रहे थे। उन्हें अधिकारियों की शिथिलता से राज्य सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा था। जिससे उनकी माली स्थिति बेहद ही खराब हो गयी थी। न रहने को घर और न ही आगे इलाज कराने के पैसे थे। इनके बारे में जानकारी मिलते ही राज्य आयुक्त 28 जुलाई को अपने सभी अधिकारियों के साथ गांव पहुंचे और तत्काल सारी व्यवस्थाएं करायी। मौके पर पहुंचे आयुक्त ने इतनी दयनीय स्थिति में दिव्यांगों को

देखकर हतप्रभ हो गये। आयुक्त को देवमुनी ने अपनी सभी व्यथा सुनायी। देवमुनी ने कहा कि हमारा परिवार बीपीएल सूची में आता है। फिर भी प्रशासन की तरफ से हमें कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। आयुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल तीन व्हीलचेयर देने का निर्देश दिया। इसके अलावा घर की मरम्मत करने और डॉक्टरों द्वारा मान्यता प्राप्त तीन बेड तुरंत मुहैया कराने का निर्देश दिया। साथ घर के बगल में वेस्टर्न टॉयलेट बनाने का भी निर्देश दिया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया कि तत्काल स्कूल से सर्कलरशिप इन्हें दिलवाया जाये।

28 | जुलाई | 2019

दिव्यांग से मुलाकात

इनके बारे में जानकारी मिलते ही राज्य आयुक्त 28 जुलाई को अपने सभी अधिकारियों के साथ गांव पहुंचे और तत्काल सारी व्यवस्थाएं करायी। आयुक्त को देवमुनी ने अपनी सभी व्यथा सुनायी।

**Disability Commissioner visits man who pleaded euthanasia for sons**



# AUGUST 2019

## अगस्त 2019

### सम्मान पाकर खिल उठे खिलाड़ियों के चेहरे

बिहार दिव्यांग खेल एकेडमी,  
पैरालिंपिक कमेटी ऑफ बिहार,  
बिहार स्पेशल ओलिंपिक और  
समर्पण के तत्वावधान में स्काडा  
बिजनेस सेंटर में आयोजित 19वें  
सम्मान समारोह में हाजीपुर के  
प्रमोद भगत और जमुई के शैलेश  
कुमार को खेलरत्न...



pg-082



पारा एथलेटिक्स  
जूनियर...

pg-073



बिहार देश का  
पहला राज्य...

pg-075



कई प्रखंडों का  
लिया जायजा...

pg-076



मोहनिया प्रखंड  
में बैठक...

pg-077



शिकायतों का हुआ  
निपटारा...

pg-081



ऑटिज्म  
पर चर्चा...

pg-084



04 | अगस्त | 2019



## पारा एथलेटिक्स जूनियर



यह चैंपियनशिप एक से चार अगस्त के बीच स्विटजरलैंड के नोटविल सिटी में खेला गया। जमुई के रहने वाले हैं। शैलेश का चयन बेंगलुरु में हुए ट्रायल के आधार पर वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स जूनियर चैंपियनशिप के लिया किया गया था।



## बिहार के शैलेश को वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स में स्वर्ण

पटना | खेल संवाद

### जूनियर प्रतियोगिता

स्विटजरलैंड के नोटविल में चल रहे वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स जूनियर चैंपियनशिप में बिहार के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीत लिया। बिहार पारा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की सचिव सुलेखा कुमारी ने बताया कि शैलेश ने यह पदक टी-42 कैटेगरी में जीत लिया।

- स्विटजरलैंड के नोटविल में आयोजित हुई प्रतियोगिता
- जमुई के रहने वाले शैलेश कैटेगरी टी-42 में जीत पदक



**व** वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स जूनियर चैंपियनशिप 2019 में बिहार के शैलेश कुमार ने टी-42 कैटेगरी (हाई जंप) में गोल्ड मेडल जीतकर अपने राज्य व देश का मान बढ़ाया है। यह चैंपियनशिप एक से चार अगस्त के बीच स्विटजरलैंड के नोटविल सिटी में खेला गया। जमुई के रहने वाले हैं। शैलेश का चयन बेंगलुरु में हुए ट्रायल के आधार पर वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स जूनियर चैंपियनशिप के लिया किया गया था। शैलेश के पदक जीतने पर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने बधाई दी। साथ ही आगे हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया। आयुक्त ने कहा कि शैलेश दिव्यांगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने यहां के दिव्यांगों यह सोचने पर मजबूर किया है कि पेंशन के अलावा दिव्यांगों के पास करने के लिए बहुत कुछ है। अपनी हुनर को राज्य के दिव्यांग पहचानें। जिस क्षेत्र में उन्हें जाना है वह दृढ़संकल्पित होकर उसमें लग जाये। राज्य सरकार उन्हें हर संभव मदद करेगी।

## दिव्यांग से शादी करने पर मिलेगा अनुदान, बैठक



**नौ** बतपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा भवन में दिव्यांग लोगों के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को लेकर कमेटी बनाने को बैठक हुई। बैठक में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पटना दिलीप कुमार कामत, अवर निर्वाचन पदाधिकारी दानापुर विपिन कुमार, बीडीओ नीरज आनंद व अन्य मौजूद थे। राज्य आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। बीडीओ ने कहा कि वे गत दिनों बीडीसी की बैठक में भी इस बात को रखे थे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के शादी-ब्याह में सरकार द्वारा एक-एक लाख रुपये दिये जाने का प्रवाधान है। दो वर्ष के भीतर यदि किसी दिव्यांग की शादी हुई तो वे एक लाख रुपये देने को तैयार हैं। प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करें।

## नौबतपुर प्रखंड







08 | अगस्त | 2019

## अधिकार की जानकारी



■ दिव्यांगजनों के सुगम्यता का निरीक्षण करते राज्य निःशक्तता आयुक्त।



1000

हजार दिव्यांग शामिल हुये



1200

लोग सीधे जुड़े कार्यक्रम से



125

सेमिनार में थे शामिल



12

हजार लोग जानें मीडिया से

### स्कूलों में दिव्यांग बच्चों यह सुविधाएं मिलेंगी

☞ नामांकन लेने आये छात्र नहीं लौटाये जायेंगे, रैंप, व्हील चेयर की सुविधा दी जाएगी

☞ जिस कक्षा में दिव्यांग छात्र होंगे, उनकी पढ़ाई नीचे के तल्ले पर होगी

☞ शौचालय अलग होगा, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो

☞ चेतना सत्र में दिव्यांग छात्रों को अखबार पढ़ने, प्रार्थना करने का मौका मिलेगा

☞ घर से स्कूल तक आने-जाने की सुविधा भी दी जाएगी

☞ कक्षा का मॉनिटर उन्हें बनाया जायेगा

☞ खेल गतिविधियों में शामिल होंगे

दि

व्यांग विद्यार्थी के नामांकन में कोई भेदभाव नहीं होगा। दिव्यांग छात्र के लिए शौचालय और क्लास रूम की सुविधा के साथ खेल में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यह शपथ सभी निजी स्कूलों के प्राचार्य ने ली। सामान्य छात्रों की तरह जगह देने का शपथ पत्र भी भरवाया गया। इसका आयोजन बांकीपुर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। दो

दिनों के इस कार्यक्रम में पहले दिन सरकारी स्कूल और दूसरे दिन निजी स्कूल के प्राचार्यों ने हिस्सा लिया था। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लागू होगा। इसके तहत धारा तीन, 16, 17, 18, 31 व 40 को लागू किया जाना है। इन सभी धाराओं के बारे में आयुक्त ने सभी को विस्तार से बताया।

### दिव्यांग छात्रों के लिए बनेंगे विशेष शौचालय

08/08 | बतौर संवादकर्ता

दिव्यांग विद्यार्थी के नामांकन में कोई भेदभाव नहीं होगा। दिव्यांग छात्र के लिए शौचालय और क्लास रूम की सुविधा के साथ खेल में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यह शपथ सभी निजी स्कूलों के प्राचार्य ने ली। सामान्य छात्रों की तरह जगह देने का शपथ पत्र भी भरवाया गया। इसका

वे सुविधाएं दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए हो स्कूल ले

- नामांकन लेने आये छात्र नहीं लौटाये जायेंगे, रैंप-व्हील चेयर की सुविधा
- जिस कक्षा में दिव्यांग छात्र होंगे, उनकी पढ़ाई नीचे के तल्ले पर
- शौचालय अलग होगा ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो
- कक्षा का मॉनिटर उन्हें बनाया जायेगा
- खेल गतिविधियों में शामिल होंगे

अखबार पढ़ने, प्रार्थना करने का मौका मिलेगा

- घर से स्कूल तक आने-जाने की सुविधा भी दी जाएगी
- कक्षा का मॉनिटर उन्हें बनाया जायेगा
- खेल गतिविधियों में शामिल होंगे

अदरत विद्यार्थियों को दिव्यांग व्हील चेयर स्कूलों का बिंदु

बांकीपुर बालिका उच्च विद्यालय पर दिव्य का अर्थात् विद्यालय है। इस स्कूल में रैंप लगे हैं। लेकिन व्हील चेयर नहीं है। इसको लेकर निःशक्तता विभाग के राज्य आयुक्त शिवाजी कुमार ने स्कूल को प्रत्येक रोज़ सुबारी को व्हील चेयर रखने का निर्देश दिया।





13 | अगस्त | 2019

## दिव्यांगजन अधिकार विषय पर संगोष्ठी



549080

दृष्टिबाधित  
दिव्यांग हैं

572163

श्रवण बाधित  
दिव्यांग हैं

70845

मूक बधिर  
दिव्यांग हैं

369577

अस्थि दिव्यांग  
हैं राज्य में

89251

मानसिक  
दिव्यांग

110844

एकाधिक  
दिव्यांगता

431728

अन्य प्रकार  
के दिव्यांग

# बिहार देश का पहला राज्य...

जानकारी के अनुसार राज्य आयुक्त निःशक्तता प्राप्त आवेदन के आधार पर की गयी मांग की उचित माध्यम से जांच करायेगे और अपनी अनुशासा समाज कल्याण विभाग या अन्य विभागों को भेजेंगे, ताकि दिव्यांग को सुविधा मिल सके।

बि

हार प्रदेश का पहला राज्य बन गया है, जहां दिव्यांगजन राज्य सरकार से अपने जीवन निर्वाह के लिए सामान्य सुविधाओं से इतर अन्य सुविधाओं की मांग कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा (1) को बिहार में लागू कर दिया है। इस संबंध में विभाग के संयुक्त निर्देशक (मुख्यालय) विजय रंजन ने आदेश जारी कर दिया है।

इसके साथ ही बिहार देश में दिव्यांगजनों को यह अधिकार देने वाला पहला राज्य हो गया है। इस अधिनियम के तहत दिये गये अधिकार के अनुसार कोई भी नागरिक या संगठन अगर दिव्यांगजन की दीन-हीन व लाचार स्थिति को देखता है और उनके लिए अधिक सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता महसूस करता है तो वह इसके लिए राज्य सरकार से अनुरोध कर सकता है। उसे इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन देना होगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत राज्य आयुक्त निःशक्तता को इसके लिए अधिकृत किया गया है।

### सामान्य से इतर सुविधा मांग सकते हैं दिव्यांगजन

व्यक्तिगत सुविधा	सामान्य सुविधा	संयुक्त सुविधा	संयुक्त सुविधा	संयुक्त सुविधा
व्यक्तिगत सुविधा	सामान्य सुविधा	संयुक्त सुविधा	संयुक्त सुविधा	संयुक्त सुविधा
...	...	...	...	...



दिव्यांग कोटे की  
मेडिकल सीटों का  
फिर से हुआ आवंटन

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पहले राउंड में दिव्यांग कोटे की सीटों पर हुए आवंटन को रिवाइज किया है। इन सीटों पर फिर से आवंटन किया गया है। बीसीइसीइ की ओर से जारी सूचना के अनुसार दिव्यांग कोटे की सीटों पर हुए आवंटन के आधार पर सात से 10 अगस्त तक काउंसिलिंग आयोजित की गयी थी, जिसमें प्रॉस्पेक्ट्स के आधार पर पहले 50 से 70 प्रतिशत

दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को सीट मिली। पूर्व के प्रावधान के अनुसार 50 प्रतिशत दिव्यांगता तक सीट आवंटन तथा नामांकन के बाद 40 से 80 प्रतिशत तक की दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों का सीट आवंटन होना था। लेकिन एमसीआइ के संशोधित नोटिफिकेशन के अनुसार दिव्यांगता की सीटों पर 40 से 80 प्रतिशत तक की दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों का सीट आवंटन मेधा सह विकल्प के आधार पर होगा।



17 | अगस्त | 2019



## पटना जिला

परीक्षा लेने वाले संस्थानों को कहा गया है कि कंपनसेटरी टाइम 20 मिनट प्रति घंटा से कम नहीं होना चाहिए, खासकर उन्हें जिन्हें लेखक की सुविधा मिली हुई है।

इसके अलावा जिन्हें लेखक की सुविधा नहीं है, उन्हें तीन घंटे की परीक्षा में एक घंटा अतिरिक्त मिलना चाहिए।

# कई प्रखंडों का लिया जायजा

जिसमें ब्रेल लिपि मे या कंप्यूटर, लार्ज प्रिंट या उतर पत्रों की रिकॉर्डिंग कर जवाब देने का व्यवस्था परीक्षा लेनेवाले संस्थान को करनी चाहिए। ताकि वे आसानी से जवाब दे सकें।



■ मसौडी के विभिन्न प्रखंडों का निरीक्षण करते राज्य निःशक्त विभाग के राज्य आयुक्त शिवाजी कुमार व अन्य

# जे

इइ, नीट, यूजीसी नेट समेत सभी प्रवेश परीक्षाओं में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट भारत सरकार की ओर से प्रवेश परीक्षाओं के लिए गाईडलाइन जारी की गयी है। आनेवाली सभी परीक्षाओं में इसका ख्याल रखा जायेगा। इसके तहत के यूनिफॉर्म नीति बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि नयी तकनीकों के आ जाने के कारण दिव्यांग परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत न हो। नियमित और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग-अलग नियम नहीं बनाये जायेंगे। दिव्यांग परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए कई सारे मोड उपलब्ध कराने को कहा गया है। विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में निर्देश दिया गया है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को जितनी ज्यादा हो सके उतने मोड में परीक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिसमें ब्रेल लिपि मे या कंप्यूटर, लार्ज प्रिंट या उतर पत्रों की रिकॉर्डिंग कर जवाब देने का व्यवस्था परीक्षा लेनेवाले संस्थान को करनी चाहिए। ताकि वे आसानी से जवाब दे सकें। परीक्षा लेने वाली बॉडी को तकनीक का उपयोग कर लार्ज प्रिंटस इ-टेक्सट या ब्रेल लिपि को अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषाओं में कन्वर्ट करने की व्यवस्था हो। दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में एक्स्ट्रा टाइम या एडिशनल टाइम टर्म को हटाकर कंपनसेटरी टाइम कर दिया गया है। परीक्षा लेने वाले संस्थानों को कहा गया है कि कंपनसेटरी टाइम 20 मिनट प्रति घंटा से कम नहीं होना चाहिए, खासकर उन्हें जिन्हें लेखक की सुविधा मिली हुई है। इसके अलावा जिन्हें लेखक की सुविधा नहीं है, उन्हें तीन घंटे की परीक्षा में एक घंटा अतिरिक्त मिलना चाहिए। एक घंटे की परीक्षा प्रो डाटा बेसिस पर समय मिले। किसी भी सूरत में पांच मिनट से कम का वक्त नहीं मिलेगा।



## इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग की छूट

इसके अलावा उन्हें परीक्षा में टॉकिंग कैलकुलेटर (जहां इसकी इजाजत हो), टेलर फ्रेम, ब्रेल स्लेट, अबेकस, ज्योमेट्री किट, ब्रेल मेजरिंग टेप आदि व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस

के उपयोग की छूट देनी चाहिए। लेखक रखने को लेकर भी निर्देश में बदलाव हुआ है। साथ ही एक दिन पहले परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर की जांच कर देखने की व्यवस्था भी की गयी है।



# कैम्प दिवांगी



1711

कुल दिव्यांग  
हुए चिह्नित

3000

रुपये  
वार्षिक  
स्काट  
एलाउंस



19 | अगस्त | 2019 मोहनिया प्रखंड में बैठक



राज्य निःशक्तता आयुक्त अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए।

आयुक्त ने बेलौड़ी पंचायत में प्रतिनिधियों के साथ की बैठक



बेलौड़ी पंचायत में बैठक करते दिव्यांगजन के आयुक्त।

जिला अधिकारी

दिव्यांगजन आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार ने बेलौड़ी पंचायत के प्रतिनिधि प्रखंड के बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान उन्होंने जिलाधिकारी के साथ बैठक में दिव्यांगजन के हितों का खयाल रखा जाये। सरकारी योजनाओं को उनके पास पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास किये जाये। मनरेगा को लेकर पीओ जितेंद्र कुमार को निर्देश देते हुए आयुक्त ने

रा

ज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने मोहनिया प्रखंड मुख्यालय के बीआरजीएफ भवन में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों व दिव्यांगों के साथ बैठक की। इसमें आयुक्त ने प्रखंड के दिव्यांगों को मिलने वाली सभी तरह की योजनाओं की जानकारी ली। बैठक में आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के हितों का खयाल रखा जाये। सरकारी योजनाओं को उनके पास पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास किये जाये। मनरेगा को लेकर पीओ जितेंद्र कुमार को निर्देश देते हुए आयुक्त ने

बैठक में आयुक्त ने बताया कि दिव्यांगता 21 प्रकार की होती है। अब तक रिकॉर्ड के अनुसार मोहनिया प्रखंड में पूर्व से 743 दिव्यांगों को चिह्नित किया गया था, जबकि वर्तमान सर्वे से 968 नये दिव्यांगों की खोज की गयी है। इस तरह प्रखंड में अभी तक 1711 दिव्यांगों का नाम सामने आया है।

कहा कि मनरेगा के तहत दिये जाने वाले रोजगार में पहली प्राथमिकता दिव्यांगजनों को दी जानी चाहिए। दिव्यांगजनों का जॉब कार्ड बनाकर उनको रोजगार देना सुनिश्चित किया जाये। इस पर मनरेगा पीओ ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर पंचायत के सभी दिव्यांगों को चिह्नित कर उनका जॉब कार्ड निर्गत कर दिया जायेगा। इस पर आयुक्त ने कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर दिव्यांगजनों

का जॉब कार्ड नहीं निर्गत होता है, तो आप पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी भी व्यक्ति की प्रोन्नति से भी इन्कार नहीं किया जायेगा। सरकारी किसी कर्मचारी को सेवा के दौरान दिव्यांगता से ग्रसित होने पर उसे अविमुक्त या उसके रैंक में कमी नहीं किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी दिव्यांगता से ग्रसित होने के बाद उस पद के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है। जिसमें वह धारित करता है तो समान वेतनमान और सेवा प्रावधानों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जायेगा।

बैठक में आयुक्त ने बताया कि दिव्यांगता 21 प्रकार की होती है। अब तक रिकॉर्ड के अनुसार मोहनिया प्रखंड में पूर्व से 743 दिव्यांगों को चिह्नित किया गया था, जबकि वर्तमान सर्वे से 968 नये दिव्यांगों की खोज की गयी है। इस तरह प्रखंड में अभी तक 1711 दिव्यांगों का नाम सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा निर्मित मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल का मूल्य 37000 रुपये है। यह राशि सांसद या विधायक द्वारा दी जाती है।

31 अगस्त तक चलेगा अभी तक 968 नये दिव्यांगों की खोज की गयी है।

इस तरह प्रखंड में अभी तक 1711 दिव्यांगों का नाम सामने आया है।



# कैमूर जिला



4%

आरक्षण दिव्यांगजनों को रोजगार में

4%

आरक्षण गरीबी निवारण योजना

- मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना
- मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना
- मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना

19 | अगस्त | 2019 रामगढ़ व दुर्गावती प्रखंड



■ कैमूर जिले में सबकी फरियाद सुनते निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।



## कै

मूर जिले में चलंत न्यायालय के आयोजन से पहले राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार जिले के विभिन्न प्रखंडों में बैठक कर दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की। इस क्रम में वह रामगढ़ पहुंचे और प्रखंड पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों व दिव्यांगों के साथ बैठक की। बैठक में सभी को संबोधित करते हुए आयुक्त ने कहा कि आप सभी दिव्यांग पंचायत स्तर पर बैठक कर एक पंचायत से कम से कम पांच दिव्यांगों का चुनाव करें। इनकी उम्र 18 से 40 वर्ष हो। चुनाव भी ऐसे पांच लोगों का करना है,

बैठक में शामिल एक दिव्यांग ने उपस्थिति पंजी में अपने पैरों से हस्ताक्षर किया। वह दोनों हाथों से दिव्यांग था। इसकी प्रतिभा व हौसला देखकर आयुक्त ने तारीफ की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसे जो भी जरूरत अपने जिविकोपार्जन के लिए चाहिए उसे दिया जाये।

जो पढ़े लिखे व तेज-तरार हो। उन्हें अपने अधिकार व सरकार से दिव्यांगों को मिलने वाली योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी हो। वहीं पांच लोग पंचायत स्तर से आपकी मांगों को प्रखंड स्तर तक व प्रखंड से जिला तक आपकी बातों को पहुंचायेंगे। शहर से गांव तक के विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्रों में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों को उनके मूलभूत सभी सुविधाओं को लेकर सरकार गंभीर है।

ऐसा भी नहीं कि जो लोग दिव्यांग है। केवल उन्हें ही मदद व रोजगार मिले सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं हैं, जिसका लाभ लेकर दिव्यांग अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आयुक्त ने एक दिव्यांग से मनरेगा द्वारा मिलने वाले जॉब कार्ड के बारे में पूछा तब महुआरी के दिव्यांग छटु शर्मा व ऊपरी के जयप्रकाश ने बताया कि जॉब कार्ड तो बना है पर अब तक हमें काम नहीं मिला है। आयुक्त ने बीडीओ प्रदीप कुमार को मामले को देखने का निर्देश दिया। आयुक्त ने कहा कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 80 के अंतर्गत राज्य आयुक्त द्वारा 22 अगस्त को जिला परामर्श केंद्र डीआरसीसी भभुआ (कैमूर) में चलंत अदालत लगाया जायेगा। जहां पर जिले के सभी दिव्यांग अपनी शिकायतों को रख सकते हैं।

दिव्यांगों को दें हर प्रकार की सुविधा : दुर्गावती प्रखंड कार्यालय पहुंचे राज्य निःशक्तता आयुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि दिव्यांगों को हर प्रकार की सुविधाएं दें, जो सरकार द्वारा उनके लिए चलायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में दिव्यांगों के सहायता के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलायी जा रही हैं। साथ ही मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया की मनरेगा के तहत दी जाने वाली सुविधाओं के तहत लाल जॉब कार्ड दिव्यांगों को दिया जाये। गरीब भूमिहीन दिव्यांगों को भूमि संबंधित सुविधा दिलायें। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया की प्रमाणपत्र कम समय में दिव्यांगों को दी जाये।



# कैमूर (मनुआ) जिला

# 3000

से अधिक दिव्यांगजन  
विभिन्न माध्यमों से  
कार्यक्रम से जुड़े

# 01

लाख तक अनुदान मुख्यमंत्री  
विवाह प्रोत्साहन योजना के  
तहत मिलता है

# 50%

आरक्षण दिव्यांगजनों को  
सरकार के विभिन्न योजनाओं  
में मिलता है

## 20 | अगस्त | 2019 समीक्षा बैठक

# रा

ज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने चलंत न्यायालय से पहले जिला मुख्यालय के अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार भवन में बैठक कर दिव्यांगजनों के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान आयुक्त ने

कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। योजनाओं का लाभ समय से दिव्यांगजनों तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए सरकार जनधन योजना के तहत आर्थिक समावेश की व्यवस्था की है। यहां तक कि पेट्रोल पंपों के आवंटन में भी दिव्यांगजनों को पांच प्रतिशत का आरक्षण है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दिव्यांगजनों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दी जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भी दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण तथा समूह को आर्थिक सहयोग प्रदान भी की जा रही है। आयुक्त ने बताया कि दिव्यांगजनों को सिविल सर्जन द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, समाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक द्वारा दिव्यांगता पेंशन, उपकरण व पुर्नवास की व्यवस्था, पुलिस द्वारा दिव्यांगजनों को प्रताड़ित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई, शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं स्कूलों में नामांकन कराने, परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया कराने, कृषि विभाग के द्वारा खाद्य व बीज की व्यवस्था करने, आपूर्ति विभाग द्वारा दिव्यांग महिला-पुरुषों को जनवितरण प्रणाली से संबंधित



■ कैमूर जिले में समस्या का समाधान करते निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

सेवा मुहैया कराने, डीडीसी द्वारा दिव्यांगजनों को आवास मुहैया कराने एवं बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के द्वारा दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री निःशक्तता स्वरोजगार ऋण योजना के तहत डेढ़ लाख रुपये शिक्षा ऋण देने का प्रवाधान है। उन्होंने संबंधित विभाग के अफसरों से यह कहा कि दिव्यांगजनों तक सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय से पहुंचाना होगा। ताकि उनकी आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति में व्यापक बदलाव हो सके। बहुउद्देशीय भवन में दिव्यांगों के साथ बैठक में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने

पंचायतस्तर पर दिव्यांगों की कमेटी बनाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया। उन्होंने चलंत संबंधी दिव्यांगता, मांसपेशीय दुर्विकार, ठीक किया हुआ कुष्ठ, प्रमास्तिष्क घात, अम्ल हमले से पीड़ित, कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण क्षति, सुनने की कठिनाई, वाक व भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मानसिक रुग्णता, क्रोनिक स्त्राविक स्थिति, बहुल काठिन्य, पार्किन्सन रोग, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग आदि से ग्रसित लोगों को दिव्यांगता की श्रेणी में रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों कल्याण के लिए सरकार कई विभागों के द्वारा योजनाएं चलायी जा रही है। लेकिन दिव्यांग जानकारी के आभाव में योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिव्यांगों की सुविधा के लिए चलंत न्यायालय का गठन किया गया है।



# कैमूर (मनुआ) जिला

# 400

रुपये हर माह दी  
जाये पेंशन

- 👉 प्राइवेट संस्थानों में भी दिव्यांगों के लिए बने रैंप
- 👉 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण दिव्यांगों को ध्यान में रखकर करें
- 👉 कैम्प में पहुंचने वाले दिव्यांगों को तत्काल जांच कर प्रमाणपत्र की देने व्यवस्था करें

## 21 | अगस्त | 2019 समीक्षा बैठक

# न

गर परिषद के सभागार में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने नगरपालिका के पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता नगरपालिका की सभापति उर्मिला देवी ने किया। बैठक में नगर पंचायत मोहनियां के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय उपस्थित थे। पटना से अपनी बुनियादी केंद्र की टीम के साथ पहुंचे आयुक्त ने पार्षदों से निःशक्तजनों के उत्थान में मददगार बनने को कहा। उन्होंने कहा कि निःशक्तजन भी हमलोगों की तरह इंसान हैं। उन्हें भी रोटी, कपड़ा व मकान की आवश्यकता है।

उनकी बुनियादी सुविधाओं के लिए हमलोगों मिल-जुलकर प्रयास करना चाहिए। कहा कि हमलोग की तहत वे भी बाजार में सामान खरीदते हैं। मॉल में जाकर अपनी आवश्यक वस्तुओं को क्रय करते हैं। आयुक्त ने कहा कि बाजार व मॉल में निःशक्तजनों की सुविधा के लिए रैंप की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा बाजार व मॉल का नक्शा पास करने से पहले उसमें रैंप की भी व्यवस्था नगर परिषद को बनवानी चाहिए। उन्होंने निःशक्तजनों के लिए शौचालय आदि के निर्माण की भी बात पार्षदों से की। बैठक में पार्षदों को जानकारी देते हुए आयुक्त ने बताया कि निःशक्तजनों की समस्याओं के निदान के लिए चलंत न्यायालय का आयोजन हो रहा है। उक्त न्यायालय में इनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारन किया जायेगा। बैठक में बुनियादी केंद्र के जिला प्रबंधक मनोहर पासवान के अलावा जाहिद हुसैन, पवन कुशवाहा के अलावा नगरपालिका की उपसभापति नाहिदा परवीन व सभी वार्डों के वार्ड पार्षद उपस्थित थे।



### ■ कैमूर जिले में फॉर्म भरते दिव्यांगजन।

**सदर अस्पताल का लिया जायजा :** राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर निशक्तजनों को मिलने वाली सुविधा का जायजा लिया। आयुक्त ने सदर अस्पताल के ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड की जांच कर दिव्यांगजनों को काउंटर तक पहुंचने के लिए सुविधा देने का निर्देश सीएस व डीएस डॉ. विनोद कुमार सिंह को दिया। दिव्यांगों के लिए सदर अस्पताल में व्हील चेर की व्यवस्था बनाने को कहा।

**प्रखंडों में कैम्प लगाकर दिव्यांगजनों की करें जांच :** राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने समाहरणालय सभागार भवन में

स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में आयुक्त ने सिविल सर्जन डॉ. अरुण कुमार तिवारी को प्रखंडों में शिविर लगाकर दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य की जांच नियमित रूप से करने को कहा। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगता का प्रकार एवं उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी स्वास्थ्य विभाग को विस्तार से बताया। उन्होंने जोर देकर यह कहा कि दिव्यांगजनों का हर हाल में सुविधाओं का ख्याल रखा जाये ताकि उन्हें किसी तरह की कठिनाई नहीं हो सके। उन्होंने कैम्प में पहुंचने वाले दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य की जांच कर तत्काल प्रमाणपत्र निर्गत करने की बात भी कही। बैठक में मौजूद चिकित्सकों को उन्होंने दिव्यांगता के दायरे में आनेवाले विभिन्न प्रकार के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कई विषयों को समझाया। आयुक्त ने चिकित्सकों को यह बताया कि यदि दिव्यांगजनों का सहयोग किया जाये, तो वह समाज के मुख्यधारा से जुड़कर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में बिहार के दिव्यांग प्रमोद को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है।



22 | अगस्त | 2019



# कैमूर (ममुआ)

चलंत न्यायालय

3450

से अधिक दिव्यांगजनों ने दर्ज करायी शिकायत



## शिकायतों का हुआ निपटारा

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार के निर्देशन में चलंत आदालत का आयोजन कराया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए आयुक्त ने बताया कि चलंत अदालत में बड़ी संख्या में दिव्यांग आये थे।



■ कैमूर जिले में समस्या का समाधान करते निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

म

भुआ मुख्यालय के निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रांगण में जिले में पहली बार राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार के निर्देशन में चलंत अदालत का आयोजन कराया गया। अदालत में दिव्यांगजनों की शिकायतों के निपटारे केलिए सभी विभागों का काउंटर लगाया गया था। चलंत न्यायालय में विभिन्न समस्याओं से संबंधित 1986 परिवारों का निबटारा किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार की सभी योजनाओं को दिव्यांगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में पिछले दिनों से लगातार दिव्यांगजनों की समस्याओं से रूबरू हो रहे राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार के निर्देशन में चलंत आदालत का आयोजन कराया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए आयुक्त ने बताया कि चलंत अदालत में बड़ी संख्या में दिव्यांग आये थे। जिनके द्वारा अपनी समस्याओं से संबंधित मामले अदालत के समक्ष रखे गये।

जिसमें मुख्य रूप से दिव्यांग पेंशन नहीं मिलना, प्रमाणपत्र नहीं बनाया जाना, प्रताणित करने, स्वरोजगार के लिए ऋण आदि जैसी विभिन्न समस्याओं से संबंधित परिवार थे। अदालत में लगभग तीन हजार से अधिक परिवार आये, जिसमें से 1986 परिवारों का निष्पादन कर लिया गया। अन्य आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। दिव्यांगों का आवेदन प्राप्त करने के लिए लगभग दर्जनभर काउंटर भी बनाये गये थे। इस चलंत अदालत में सरकार के 56 विभाग समस्याओं के निबटारे के लिए समन्वय कर रहे थे। दिव्यांगों के लिए लगाये गये चलंत अदालत में उनके दिव्यांगता की जांच के लिए दर्जन भर से ऊपर चिकित्सकों की टीम भी लगायी गयी थी।



प्रभावित लोगों का व्यापक जांच कराया

जिसमें मूकबधिर से लेकर हाथ पैर से दिव्यांग, नेत्रहीन अथवा मानसिक असमर्थता से प्रभावित लोगों का व्यापक जांच कराया गया। साथ ही अदालत में ही जिन्हें पहले से दिव्यांग प्रमाणपत्र नहीं मिला था,

उन्हें दिव्यांग प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराया गया। आयुक्त ने बताया कि जिन दिव्यांगों की जांच की गयी है, उन्हें कृत्रिम अंग या संबंधित उपकरण भी सरकार द्वारा शिविर लगाकर उपलब्ध कराया जायेगा।





28 | अगस्त | 2019

## दिव्यांग खेल सम्मान मेगा इवेंट



170

से अधिक  
खिलाड़ी हुए  
सम्मानित



50

से अधिक  
अन्य क्षेत्र के  
लोगों को मिला  
सम्मान



20000

से अधिक  
लोगों ने देखा



30000

से अधिक  
लोगों तक  
पहुंची सूचना

# सम्मान पाकर खिल उठे खिलाड़ियों के चेहरे

19वें सम्मान समारोह  
में हाजीपुर के प्रमोद भगत  
और जमुई के शैलेश कुमार  
को खेलरत्न सम्मान से  
नवाजा गया।

दिव्यांग खेल सम्मान. अतुल को लाइफटाइम एचीवमेंट अवार्ड  
जमुई के शैलेश व हाजीपुर के प्रमोद  
भगत को मिला खेलरत्न पुरस्कार



दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कार्य किये जा रहे हैं। उनको खिलाड़ी कल्याण कोष से मदद दी जा रही है। खेल सम्मान दिवस पर उन्हें सम्मानित करने के अलावा नकद राशि भी दी जाती है। हालांकि यह सामान्य खिलाड़ियों के बराबर नहीं है। इस संबंध में खेल मंत्री को दिव्यांग खिलाड़ियों ने बोला है, जिसपर वह विचार कर सामान्य पुरस्कार राशि करेंगे।

राज्य आयुक्त  
ने खिलाड़ियों  
से बोला

■ राज्य का नाम रोशन करने वाले दिव्यांग खिलाड़ी सम्मान के साथ राज्य निःशक्तता आयुक्त व अतिथियों के साथ।

बि

हार दिव्यांग खेल एकेडमी, पैरालिंपिक कमेटी ऑफ बिहार, बिहार स्पेशल ओलिंपिक और समर्पण के तत्वावधान में स्काडा बिजनेस सेंटर में आयोजित 19वें सम्मान समारोह में हाजीपुर के प्रमोद भगत और जमुई के शैलेश कुमार को खेलरत्न सम्मान से नवाजा गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अतुल प्रसाद को लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार, ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार, राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, छात्र एवं युवा कल्याण के निदेशक डॉ. संजय सिन्हा ने विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथि आइएएस अतुल प्रसाद, जिला खेल पदाधिकारी संजय कुमार थे। समारोह की अध्यक्षता विधायक सह स्पेशल ओलिंपिक बिहार के अध्यक्ष समीर कुमार महासेठ ने किया। सभी अतिथियों का स्वागत पैराओलिंपिक कमेटी ऑफ बिहार के खेल निदेशक संदीप कुमार ने किया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रमोद ने पिछले वर्ष जकार्ता एशियाड के बैडमिंटन स्पर्धा में एकल में स्वर्ण और युगल में रजत पदक जीता था। इन दोनों के अलावा मुंगेर की अंकिता को अभिमन्यु, कुंदन, प्रवीण, अमन, निशू सुमन, सुदर्शन, नेहा, राधा, राजन, विशाल, सौरव, युवराज, मोहित, पारस, अविनाश, कुणाल, सौरभ राज, फिरदौस को भी पुरस्कार दिया गया। सुमन, राहुल, साक्षी, रमेश, शेखर, अमन, सुनील, विश्वास, संजय, मेराज, शिशिर, अनुज, मानसी, विकास पांडे, राजकुमार, राजीव, हरिनाथ, अंकित, हरिमोहन, मीरा, धीरज, मिक्कू, रवि, गौरव, सौरभ कुमार, शिवम, राजेश, अफसर, अमीषा, आदित्य, उज्वल, किशन, प्रणव, मंजीत, राजमंगल को आजतशत्रु सम्मान से नवाजा गया।



31 | अगस्त | 2019

## ऑटिज्म पर चर्चा



■ कार्यक्रम एम्स के मानसिक विभाग द्वारा आयोजित किया गया

अधिकांश बच्चों में अनुवांशिक कारणों से यह बीमारी होती है। कहीं-कहीं पर्यावरण का असर इस बीमारी का कारण बनता है। डॉक्टरों के मुताबिक, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बच्चे को जीवनभर इस खामी के साथ जीना पड़ता है। हां, लक्षणों को जरूर कम किया जा सकता है। गर्भावस्था की जटिलताओं के कारण भी बच्चे इसका शिकार बनते हैं।



पटना एम्स में ऑटिज्म की शीघ्र पहचान और निदान के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम एम्स के मानसिक विभाग द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम एम्स के मानसिक विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन एम्स पटना के निदेशक डॉ प्रभात कुमार सिंह, निःशक्तता आयुक्त बिहार सरकार शिवाजी कुमार, डीन डॉ. नीरज अग्रवाल, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सीएक सिंह, मानसिक रोग के विभागाध्यक्ष डॉ. पंकज कुमार और बाल रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. लोकेश तिवारी द्वारा किया गया। ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक दिमागी बीमारी है। इसमें मरीज न तो अपनी बात ठीक से कह पाता है ना ही दूसरों की बात समझ पाता है और न उनसे संवाद स्थापित कर सकता है। यह एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। इसके लक्षण बचपन से ही नजर आ जाते हैं। यदि इन

लक्षणों को समय रहते भांप लिया जाए, तो काबू पाया जा सकता है। सामान्य इंसान में दिमाग के अलग-अलग हिस्से एक साथ काम करते हैं, लेकिन ऑटिज्म में ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि उनका बर्ताव असामान्य होता है। यदि ठीक से सहायता मिले तो मरीज की काफी मदद हो सकती है।

**छोटे बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण** : बच्चे हमारी भाषा तो नहीं समझते, लेकिन हाव भाव और इशारों को समझना शुरू कर देते हैं। जिन बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण होते हैं, उनका बर्ताव अलग होता है। वे इन हाव भाव को समझ नहीं पाते या इन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। ऐसे बच्चे निष्क्रिय रहते हैं। बच्चा जब बोलने लायक होता है तो साफ नहीं बोल पाता है। उसे दर्द महसूस नहीं होगा। आंखों में रोशन पड़ेगी, कोई छुएगा या आवाज देगा तो वे प्रतिक्रिया नहीं देंगे। थोड़ा बड़ा होने पर ऑटिज्म के मरीज बच्चे अजीब हरकतें करते हैं जैसे पंजों पर चलना।

### ऑटिज्म की जल्द पहचान और निदान पर हुई चर्चा

पटना एम्स

एम्स पटना

पटना एम्स में ऑटिज्म की शीघ्र पहचान और निदान के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

विभागाध्यक्ष डॉ. पंकज कुमार और बाल रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. लोकेश तिवारी द्वारा किया गया। निदेशक ने एम्स पटना में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में डॉ. सीएक सिंह, मानसिक रोग के विभागाध्यक्ष डॉ. पंकज कुमार और बाल रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. लोकेश तिवारी द्वारा किया गया।



**1.5**  
लाख दिव्यांग  
शामिल हुये



**2500**  
लोग सीधे जुड़े  
कार्यक्रम से



**500**  
सेमिनार में  
थे शामिल



**25** हजार  
लोग जानें  
मीडिया से



# सितंबर 2019

SEPTEMBER

चलंत लोक अदालत लगाने से पूर्व राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने गोपालगंज जिले के सभी प्रखंडों का दौरा कर वहां दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं का पिछले तीन वर्षों का जायजा लिया। राज्य निःशक्तता आयुक्त ने जिले के बैकुंठपुर, सिधवलिया, बरौली, मांझा और गोपालगंज प्रखंड का जायजा लिया। उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत बताया कि वर्ष 2016 तक दिव्यांगों की सात श्रेणी थी, जो बढ़कर 21 हो गयी है।



pg-094



राज्य सरकार ने प्रदेश के वैसे दिव्यांगों को...

pg-086



दिव्यांगों को लाभकारी योजनाओं...

pg-087



सुविधा देने में कोई लापरवाही बर्दाश्त...

pg-088



चीफ द मिशन बन टोक्यो गये आयुक्त...

pg-089



दिव्यांगों को लेकर सरकार चिंतित...

pg-092



एक स्थान पर सबको मिला न्याय...

pg-093



04 | सितंबर | 2019

## दिव्यांगों की सहायता सरकार की प्राथमिकता



**30**

हजार दिव्यांगों  
को मिलेगी मदद



**6243**

लोग सीधे जुड़े  
कार्यक्रम से



**393**

सेमिनार में थे  
शामिल



**12** हजार

लोग जानें  
मीडिया से



■ दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों से मुलाकात करते माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी।



राज्य सरकार ने प्रदेश के वैसे दिव्यांगों को अभिभावक उपलब्ध कराने का फैसला लिया है, जो खुद के बारे में निर्णय लेने में अक्षम होते हैं। अभिभावक दिव्यांग के परिवार से ही कोई एक होंगे। उन्हें

यदि दिव्यांग के लिए हिस्से में कोई संपत्ति या ट्रस्ट होगा, तो उसकी देखभाल करने की जवाबदेही होगी। यदि एनजीओ को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, तो उसे सरकार की ओर से कुछ आर्थिक लाभ मिलेंगे। इस योजना के लिए दिव्यांग अधिनियम धारा 14 के तहत सभी जिलों में उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित होगी। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगों को सुविधा मुहैया करना है और उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना है।

जब कोई दिव्यांग कमिटी के समक्ष आवेदन करेगा कि उसे कानूनी तौर पर अभिभावक चाहिए, तो उस दिव्यांग के बताये गये परिवार के लोगों में से किसी एक को दिव्यांग के पालन-पोषण की

### अक्षम दिव्यांगों को मिलेगा कानूनी तौर पर अभिभावक

संवादकर्ता > पटना

राज्य सरकार ने प्रदेश के वैसे दिव्यांगों को अभिभावक उपलब्ध कराने का फैसला किया है, जो खुद के बारे में निर्णय लेने में अक्षम होते हैं। अभिभावक दिव्यांग के परिवार से ही कोई एक होंगे। उन्हें यदि दिव्यांग के लिए हिस्से में कोई संपत्ति या ट्रस्ट होगा, तो उसकी देखभाल करने की जवाबदेही होगी। यदि एनजीओ को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, तो उसे सरकार की ओर से कुछ आर्थिक लाभ मिलेंगे। इस योजना के लिए दिव्यांग अधिनियम धारा 14 के तहत सभी जिलों में उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमिटी

गठित की जायेगी। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगों को सुविधा मुहैया करना है और उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। जब कोई दिव्यांग कमिटी के समक्ष आवेदन करेगा कि उसे कानूनी तौर पर अभिभावक चाहिए, तो उस दिव्यांग के बताये गये परिवार के लोगों में से किसी एक को दिव्यांग के पालन-पोषण की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। लेकिन, इसके पूर्व कमिटी उस व्यक्ति की पूरी छानबीन करेगी। इसके बाद उसे कानूनी तौर पर अभिभावक बनाया जायेगा। कमिटी की ओर से तय किये गये अभिभावक की मॉनीटरिंग भी खुद कमिटी करेगी। इसमें पुलिस की भी सहायता ली जाएगी। जब कभी अभिभावक की शिकायत मिलेगी, तो उस अभिभावक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

**कानूनी  
अभिभावक**



### कमेटी में ये होंगे शामिल

उपविकास आयुक्त (अध्यक्ष), सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार (सचिव), सिविल सर्जन (सदस्य), सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई (सदस्य) एवं सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण (सदस्य सचिव) होंगे।



## पटना जिला



1220  
दिव्यांगता  
प्रमाण पत्र



452  
दिव्यांगता  
पेंशन



20  
छात्रवृत्ति एवं  
नामांकन



40  
दिव्यांगजन  
राशन कार्ड



■ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगजनों की समस्या का समाधान करते हुये।



05 | सितंबर | 2019

प्रखंडों में  
कार्यक्रम

दिव्यांगों को लाभकारी योजनाओं के लिए परेशान नहीं करें : आयुक्त

दु

ल्हिनबाजार प्रखंड कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए एकदिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने प्रखंड के अधिकारियों एवं विकास मित्रों से दिव्यांगों को निःशक्तता पेंशन, राशन, मनरेगा, कृषि, प्रधानमंत्री आवास समेत मिलने वाली अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिव्यांगों को लाभकारी योजनाओं के लिए दौड़ा नहीं जाये। उन्होंने प्रखंड क्षेत्र के 14 पंचायतों में दिव्यांगजन समूह का चयन करवाया। उन्होंने बीडीओ से अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग खिलाड़ी धीरज कुमार को प्रखंड स्तर पर सम्मानित करवाने को कहा। इस मौके पर सीओ राजीव कुमार, जीविका प्रखंड समन्वयक सुनंदा, सीडीपीओ वीणा कुमारी सहित अन्य प्रखंड अधिकारी व दिव्यांगजन मौजूद थे।

दिव्यांगों को निःशक्तता पेंशन, राशन, मनरेगा, कृषि, प्रधानमंत्री आवास समेत मिलने वाली अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

दिव्यांगों के लिए चलने वाली योजनाओं को जमीन पर उतारें

पटना. बिहार में दिव्यांगजनों के लिये सरकार केंद्र व राज्य सरकार की कई योजनाएं चल रही है. सभी योजनाओं का लाभ दिव्यांगों को नियमित मिले. इसके लिये जरूरी है कि दिव्यांग संबंधी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाये. ये बातें समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने दिव्यांग सलाहकार समिति की बैठक में मौजूद अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहीं. उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को विशेष शिक्षा मिले

योजनाओं को जमीन पर उतारें : मंत्री

बिहार में दिव्यांगजनों के लिए केंद्र व राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। सभी योजनाओं का लाभ दिव्यांगों को नियमित मिले। इसके लिए जरूरी है कि दिव्यांग संबंधी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाये। ये बातें समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने दिव्यांग सलाहकार समिति की बैठक में मौजूद अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को विशेष शिक्षा मिले।



## पटना जिला के विभिन्न प्रखंडों में हुई सुनवाई



**1234**  
दिव्यांगता  
प्रमाण पत्र



**155**  
दिव्यांगता  
पेंशन



**40**  
छात्रवृत्ति एवं  
नामांकन



**45**  
दिव्यांगजन  
राशन कार्ड



■ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगजनों की समस्या की सुनवाई करते हुये।



07 | सितंबर | 2019

**चलंत  
न्यायलय**

## सुविधा देने में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं

**दि**

व्यांगों को सरकार की हर योजना को लाभ देना है, साथ ही इन लोगों की समस्याओं को तत्काल प्रभाव से निबटारा व समाधान करना है।

इसके लिए हम कटिबद्ध है। यह बात बुधवार को बिहार राज्य निःशक्तता के आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार ने कहीं। उन्होंने कहा कि जागरूकता के अभाव में अधिकतर दिव्यांग सरकारी सेवा का लाभ नहीं ले पाते हैं, जो निंदनीय है। योजना की लाभ देने के लिए सारी जिम्मेदारी संबंधित विभाग के अधिकारी की होती है पर जागरूकता के अभाव में दिव्यांगों की सरकारी सेवा नदारद हो जाती है। पर अब ऐसा नहीं होगा। नये नियम के तहत हर दिव्यांगों की सरकारी सेवा दी जाएगी। समस्याओं को तत्काल प्रभाव से निबटारा किया जायेगा।

इस योजना के लिए  
दिव्यांग अधिनियम धारा  
4 के तहत सभी जिलों में  
उपविकास आयुक्त की  
अध्यक्षता में एक कमेटी  
गठित होगी।

उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए एक हेल्पलाइन जारी किया जा रहा है। इस हेल्पलाइन पर कभी भी दिव्यांग पर समस्या को बता सकते है। शीघ्र ही हेल्पलाइन नंबर जारी होगा।

किसी भी समस्या का होगा ऑन द स्पॉट निबटारा

बिहार राज्य निःशक्तता के आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों की किसी भी प्रकार की समस्याओं को ऑन द स्पॉट निष्पादन किया जायेगा उन्होंने कहा कि इस चलंत लोक अदालत के माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों के अधिकारियों के संरक्षण व समस्याओं का समाधान के लिए उक्त कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है।



11 | सितंबर | 2019



## अंतर्राष्ट्रीय पैरा-ओलिंपिक सेमिनार



टोक्यो से लौटने के बाद राज्य आयुक्त ने कहा कि जापान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय ओलिंपिक कमेटी द्वारा सभी तैयारियों दिव्यांगों को ख्याल में रखकर की गयी हैं। वहां की व्यवस्था देखकर यह लगता है कि हमारे खिलाड़ी पूरी तरह से यहां पर एडजस्ट कर पायेंगे। दिव्यांगों को लेकर स्टेडियम के अंदर और बाहर सभी व्यवस्था बेहतर की गयी है।



■ टोक्यो में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

## चीफ द मिशन बन टोक्यो गये आयुक्त

400 से अधिक विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा

दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए तैयार किया बेहतर स्टेडियम व ग्राउंड

आयुक्त ने कुछ चीजों को लेकर वहां की कमेटी को दिये सुझाव

तो

क्यो (जापान) में 2020 ओलिंपिक व पैरालिंपिक की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए आठ से 13 सितंबर तक पूरे विश्व के चीफ द मिशन का सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने किया। इस सेमिनार में पूरे विश्व से 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस तीन दिवसीय सेमिनार में खेल स्थल, ओलिंपिक विलेज, आवास, खाद्य और पेय पदार्थ, लॉजिस्टिक्स, आगमन विभाग, परिवहन, प्रत्यायन, खेल प्रवेश, एनओसी सेवा, दिव्यांगजन और पैरालिंपियन के लिए सुलभ स्थल, टिकटिंग, ब्रांड प्रोटेक्शन, सेरेमनी, जापानी कल्चर एंड लॉज, मेडिकल सर्विसेज और एंटी डोपिंग की तैयारियों पर समीक्षा, प्रस्तुतिकरण पर चर्चा हुई।

टोक्यो से लौटने के बाद राज्य आयुक्त ने कहा कि जापान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय ओलिंपिक कमेटी द्वारा सभी तैयारियों दिव्यांगों को ख्याल में रखकर की गयी हैं। वहां की व्यवस्था देखकर यह लगता है कि हमारे खिलाड़ी पूरी तरह से यहां पर एडजस्ट कर पायेंगे। दिव्यांगों को लेकर स्टेडियम के अंदर और बाहर सभी व्यवस्था बेहतर



की गयी है। आयुक्त ने कुछ चीजों को लेकर वहां की कमेटी को सुझाव दिये, जिसमें बदलाव करने का आश्वासन भी दिया गया। भारतीय खिलाड़ियों के लिए अलग से खाने-पीने की व्यवस्था भी गयी है।



18 | सितंबर | 2019



## समीक्षा बैठक पूर्वी चंपारण



दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण व रोजगार और पेट्रोल पंप आवंटन में शारीरिक दिव्यांगजन को पांच प्रतिशत आरक्षण व चार प्रतिशत पीडीएस लाइसेंस दिव्यांगजन को निर्गत किया जाना है। उसी प्रकार दिव्यांगजन को सारथी योजनाअंतर्गत निर्धारित प्रतिशत के अनुरूप वाहन लाइसेंस निर्गत किया जाना अनिवार्य है।



■ प्रखंड अधिकारियों और दिव्यांगों के साथ बैठक करते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

## दिव्यांगों को मिले आरक्षण का लाभ

दि

व्यांगजन के उत्थान व सहायता के लिए विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अनुमंडल स्तर पर संचालित बुनियादी केंद्र व बुनियादी संजीवनी सेवा के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रवाधान है। सभी संबंधित विभाग इस संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराये। यह निर्देश राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने राधाकृष्णन भवन में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लेकर आयोजित समीक्षात्मक बैठक में दिया। आयुक्त ने कहा कि सभी प्रशिक्षण योजनाओं में दिव्यांगजन के लिए पांच प्रतिशत व नौकरी में चार

प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग के लिए तीन श्रेणी में 25 हजार से 10 लाख रुपये तक का कम दर पर ऋण का प्रावधान है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण व रोजगार और पेट्रोल पंप आवंटन में शारीरिक दिव्यांगजन को पांच प्रतिशत आरक्षण व चार प्रतिशत पीडीएस लाइसेंस दिव्यांगजन को निर्गत किया जाना है। उसी प्रकार दिव्यांगजन को सारथी योजनाअंतर्गत निर्धारित प्रतिशत के अनुरूप वाहन लाइसेंस निर्गत किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारियों व जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम 2016 के अंतर्गत 21 प्रकार के दिव्यांगता के संबंध में जानकारी दी गयी। कहा कि दिव्यांगजन प्रतिभा के धनी होते हैं। उनको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इस दिशा में कार्रवाई का निर्देश दिया।



300

से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा



20000

सोशल मीडिया से जुड़े



128

बैठक में थे शामिल



15000

लोग जानें मीडिया से





18 | सितंबर | 2019



प्रखंडों का निरीक्षण

पूर्वी चंपारण

30

दिव्यांगों ने लिया हिस्सा

21

प्रकार के दिव्यांगों को देना है प्रमाणपत्र

शिविर लगाकर दिव्यांगों के बीच बांटे प्रमाणपत्र

पंचायत स्तर पर दिव्यांगों के लिए कमेटी गठन करने में मदद करें

# योजनाओं की समीक्षा

दिव्यांगजन के बीच ट्राइसाइकिल व बैसाखी का भी वितरण करने को कहा। बीडीओ से ऐसे लोगों को योजनाओं का लाभ ससमय दिलाने के लिए प्रयासरत रहने को कहा।



■ पूर्वी चंपारण के एक प्रखंड मुख्यालय में बैठक करते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

दि

व्यांगजनों की अनदेखी नहीं करें। इन्हें हरसंभव मदद करने की जरूरत है। उक्त बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने रक्सौल प्रखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऐसे लोगों के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं। इनका लाभ इन्हें मिलना चाहिए। लेकिन कुछ अधिकारियों की निष्क्रियता से ऐसे लोग या तो इस योजना से वंचित रह जाते हैं या फिर ससमय इन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। बीडीओ प्रशांत को इन लोगों की संख्या को लेकर स्पेशल सर्वे कराने का निर्देश दिया। दिव्यांगजन के बीच ट्राइसाइकिल व बैसाखी का भी वितरण करने को कहा। बीडीओ से ऐसे लोगों को योजनाओं का लाभ ससमय दिलाने के लिए प्रयासरत रहने को



## रक्सौल प्रखंड

कहा। पीएससी प्रभारी डॉ. शरतचंद्र शर्मा को निर्देश दिया कि दिव्यांगजन को प्रमाणपत्र के लिए स्वास्थ्य केंद्र का चक्कर नहीं लगाना पड़े। एक शिविर लगाकर प्रमाणपत्र दें। ताकि इन लोगों को योजनाओं का लाभ ससमय मिल सके। मनरेगा पीओ गौरव से पूछा कि आपने कितने दिव्यांगजन को जॉब कार्ड बनवाया है। इसकी रिपोर्ट अविलंब देने का निर्देश दिया। वहीं प्रयास संस्था के स्वयंसेवकों से इस कार्य में सरकारी तंत्र को मदद करने को कहा। मौके पर जेएसएस मिथिलेश कुमार मेहता, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद कुमार, प्रयास संस्था की आरती कुमारी सहित अन्य लोग मौजूद थे।



## दिव्यांगजन को हक दिलाना पहली प्राथमिकता : निःशक्तता आयुक्त

राज्य निःशक्तता आयुक्त शिवाजी कुमार ने कहा कि तीन दिसंबर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राज्यस्तर के 50 हजार दिव्यांगों को उनका हक दिलवाना उनकी पहली प्राथमिकता है। कहा कि सरकार ने कानून में बदलाव कर प्राथमिकता के तौर पर दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगों को उनके हक और अधिकार के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। दिव्यांगता को कुल 21 श्रेणी में रखा गया है।

## महेसी प्रखंड का दौरा



19 | सितंबर | 2019



जनप्रतिनिधियों  
के साथ बैठक

पूर्वी  
चंपारण



500

से अधिक दिव्यांगों ने लिया हिस्सा

1500

रुपये पेंशन देने की उठी मांग

भूमिहीन दिव्यांगों को चिह्नित कर दें पांच डिसमिल जमीन

बैंक घर जाकर पहुंचाये पेंशन की राशि

दिव्यांगों को 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा को करें व्यवस्था

# दिव्यांगों को लेकर सरकार चिंतित

उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को नियत समय के अंदर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। बीडीओ ने बताया कि प्रखंड में 679 दिव्यांगजनों को पेंशन तथा 86 दिव्यांगजन को आवास की सुविधा दी गयी है।

■ पूर्वी चंपारण के एक प्रखंड मुख्यालय में बैठक करते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

दि

व्यांगों के लिए राज्य व केंद्र सरकार चिंतित है। इनकी सुविधा को लेकर संचालित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों की भूमिका अक्वल है। यह बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में कहीं। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष प्रियंका जायसवाल ने निःशक्तता आयुक्त से आग्रह किया कि दिव्यांगों के पेंशन की राशि को कम से कम 15 सौ रुपये मासिक करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजकर इसे लागू कराया जाये। आयुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि संसदीय पैनल ने दिव्यांगजनों के लिए मौजूदा योजनाओं में सुधार और इसे और बेहतर करने की सिफारिश सरकार को की है। केंद्र सरकार ने नयी प्रकार की अक्षमताओं को इस श्रेणी में शामिल किया है। इनके लिए छह से 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। मौके पर जप उपाध्यक्ष कमलेश्वर सिंह, पूर्व विधायक पवन जायसवाल, नप की मुख्य पार्षद अंजू देवी आदि उपस्थित थे।

बैठक के बाद पकड़ीदयाल पहुंचे आयुक्त ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में सरकार द्वारा दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए उठाये गये कदमों को विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को नियत समय के अंदर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। बीडीओ सूरज कुमार ने बताया कि अभी तक प्रखंड में 679 दिव्यांगजनों को पेंशन तथा 86 दिव्यांगजन को आवास की सुविधा दी गयी है।



एडवोकेसी  
बैठक

पताही प्रखंड  
का निरीक्षण

पताही प्रखंड मुख्यालय पहुंचे राज्य निःशक्तता आयुक्त ने दिव्यांगजन को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने शिविर लगाकर दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब बैंक दिव्यांगजन के घर जाकर पेंशन की राशि का भुगतान करेगा। इसके लिए उन्होंने बीडीओ मनोज कुमार को बैंक को पत्र भेज सूचित करने का निर्देश दिया। साथ भूमिहीन दिव्यांगजन को चिह्नित कर पांच डिसमिल जमीन देने का निर्देश भी दिया।



20 | सितंबर | 2019



चलंत  
न्यायालय

पूर्वी  
चंपारण



4500

# एक स्थान पर सबको मिला न्याय

से अधिक दिव्यांगजनों ने चलंत लोक अदालत में दर्ज कराया परिवाद

1203 से अधिक को ऑन द स्पॉट मिला दिव्यांगता प्रमाणपत्र

दिव्यांगों को मुख्यधारा में लाने के लिए उपलब्ध कराये समान अवसर

उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को नियत समय के अंदर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। बीडीओ ने बताया कि प्रखंड में 679 दिव्यांगजनों को पेंशन तथा 86 दिव्यांगजन को आवास की सुविधा दी गयी है।

मो

■ पूर्वी चंपारण के एक प्रखंड मुख्यालय में बैठक करते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

तिहारी के नगर भवन परिसर में शुक्रवार को दिव्यांगों की समस्याओं के लिए चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, ढाका सीडीपीओ कुमारी आलोका, रक्सौल की जयमाला कुमारी, आदापुर की रिया कुमारी व अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान दिव्यांगों की शिकायतों, दिव्यांगों का प्रमाणीकरण सहित उनके अधिकार से संबंधित बातों के बारे में उन्हें जागरूक किया गया व उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुआ निःशक्तता आयुक्त शिवाजी कुमार ने कहा कि आयोग का मकसद है कि समाज में पल बढ़ रहे निःशक्त लोगों को उनका वाजिब हक मिले, इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। परंतु जानकारी नहीं होने क कारण उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। आयुक्त ने कहा कि चलंत न्यायालय में दिव्यांगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा रहा है। कुछ ऐसी भी समस्याएं, जिनका तत्काल निराकरण संभव नहीं है। उन समस्याओं के समाधान के लिए एक सप्ताह का समय संबंधित अधिकारियों को दिया जा रहा है।

दिव्यांग भी समाज के अंग है, उन्हें मुख्यधारा में लाने तथा उन्हें समान अवसर व अधिकार देने के लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है। लेकिन इस सुविधा का वे हकदार तब हैं, जब उनके पास दिव्यांग होने का प्रमाणपत्र हो। इसलिए न्यायालय के माध्यम से एक ही छत के नीचे ऐसी व्यवस्था की गयी है।

## चार हजार दिव्यांगों का पंजीकरण, एक हजार को मिला प्रमाणपत्र



यहां निशक्त लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के साथ प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। ताकि उनकी जांच कर दिव्यांगों को प्रमाणपत्र हाथों-हाथ दिया जा सके। इस प्रमाणपत्र के आधार पर इन्हें लाभ मिल सके। चलंत लोक अदालत में पंजीयन के लिए 8 अलग-अलग काउंटर बनाये गये थे। वहीं दिव्यांगों के लिए सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित विभागों का भी अलग काउंटर स्थापित किया गया था।

8 अलग-अलग  
काउंटर बनाये



# गोपालगंज किया



1000000

रुपये तक स्वरोजगार के लिए मिलता है ऋण



280

से अधिक दिव्यांगों ने लिया हिस्सा



प्रखंडों का दौरा

24 | सितंबर | 2019

पंचायत स्तर पर हुआ दिव्यांग समूहों का गठन

पंचायत स्तरीय कमेटी घर पहुंचकर दिव्यांगों की समस्याओं का करेगी निराकरण

21 श्रेणी में अब दिव्यांगों को मिलेगा प्रमाणपत्र



**च** लंत लोक अदालत लगाने से पूर्व राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने गोपालगंज जिले के सभी प्रखंडों का दौरा कर वहां दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं का पिछले तीन वर्षों का जायजा लिया। राज्य निःशक्तता आयुक्त ने जिले के बैकुंठपुर, सिधवलिया, बरौली, मांझा और गोपालगंज प्रखंड का जायजा लिया। उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत बताया कि वर्ष 1995 तक दिव्यांगों की सात श्रेणी थी, जो बढ़कर 21 हो गयी है। सभी 21 प्रकार के दिव्यांगों को उनका हक दिलाना है। दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर आगामी 27 सितंबर को जिला मुख्यालय में चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया है। वहां पर दिव्यांगजनों के पेंशन, आवास, रोजगार, ऋण सहित अन्य समस्याओं का निदान किया जायेगा। अब दिव्यांगजनों को नये

## दिव्यांगजन समूह का किया गठन

फुलवरिया पहुंच कर आयुक्त ने दिव्यांगजनों के समूह का गठन किया। प्रधान सहायक रवींद्र सिंह ने बताया कि इसमें सभी पंचायत में पांच-पांच संख्या में दिव्यांगजनों का एक समूह का गठन किया गया। इस समूह में 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के आयु के कम से कम पांच सदस्य होने अनिवार्य हैं। बैठक में पंचायत सचिव शिवजी प्रसाद व अन्य लोग मौजूद थे। बरौली प्रखंड पहुंचे आयुक्त ने दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं का निरीक्षण किया। साथ ही वहां के बीडीओ को कहा कि 27 को जिला मुख्यालय में चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिसमें दिव्यांगों के सभी समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। अपने प्रखंड के सभी दिव्यांगों को इसके बारे में सूचित कर दें। ताकि वह अपनी समस्याओं की शिकायत दर्ज करा सकें। मौके पर नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी सपना सिंह और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

प्रपत्र में दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी दिया जायेगा। उनकी समस्याओं का निराकरण उनके घर पर पहुंचकर पंचायत स्तरीय समूह करेगी। इनको लेकर पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर समिति का गठन किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 25 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण कम ब्याज पर देने का प्रवधान है।



दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल देते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार

वहां पर दिव्यांगजनों के पेंशन, आवास, रोजगार, ऋण सहित अन्य समस्याओं का निदान किया जायेगा। अब दिव्यांगजनों को नये प्रपत्र में दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी दिया जायेगा। **उनकी समस्याओं का निराकरण उनके घर पर पहुंचकर पंचायत स्तरीय समूह करेगी।**



# गोपालगंज जिला

## रा

ज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार ने जिले के विजयीपुर, भोरे, कटेया प्रखंडों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत स्तर पर दिव्यांगजन समूह का गठन कराया। दिव्यांगजनों के हित के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं की स्थिति से अवगत हुए। इतनी ही नहीं दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं में त्वरित गति लाये जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। जबकि दोपहर में जिला मुख्यालय में जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को सामान अधिकार दिया जाये। नौकरी से लेकर अन्य कार्यों में दिव्यांगों को बेहतर सुविधा मुहैया कराया जाये। उन्होंने दिव्यांगों

को स्वरोजगार से जोड़ने को लेकर बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इतना ही नहीं दिव्यांगों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर समुदायिक भवन, दुकान रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि का निरीक्षण कर संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों में दिव्यांगों को आनेजाने के लिए रैंप बनाया जाये। वहीं सुलभ शौचालय का निर्माण दिव्यांगों को ध्यान में रखकर कराया जाये। आयुक्त के साथ बैठक में वरीय उपसमाहर्ता अनंत कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। उपविकास आयुक्त सज्जन आर, श्रम अधीक्षक मनोज कुमार दुबे, वरीय उपसमाहर्ता नेहा कुमारी, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मो इरफान, जिला पंचायत राज पदाधिकारी बृज किशोर सिंह व अन्य मौजूद थे।



# 320

से अधिक ने बैठकों में लिया हिस्सा

## समीक्षा बैठक

दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं में लायें गति

दिव्यांगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बैंक आगे आयें

सभी सरकारी व प्राइवेट भवनों में दिव्यांगों के लिए बने रैंप

25 | सितंबर | 2019

आयोजन • पंतदेवरी में दिव्यांग आयुक्त की अनुपस्थिति में बीडीओ ने की समीक्षा बैठक और कर्मचारियों को दिए निर्देश

## दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए सरकार देगी हर तरह की सहायता

बिहार (संवाद)

दिव्यांगों के गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए स्थानीय स्तर पर बनेगी टीम

दिव्यांगों के समुचित विकास के लिए सरकार हर तरह की सहायता देगी। उका कारी पंचायतों प्रखंड स्तर पर भी गुणवत्ता के विकास पर समीक्षा बैठक के दौरान स्थानीय बीडीओ डॉ अजय कुमार सिन्हा ने कहा।

विहार सरकार द्वारा दिव्यांगों के समुचित विकास से संबंधित अधिनियम के अंतर्गत ही विकास शुरू करने का निर्देश देते हुए बीडीओ ने कहा कि प्रखंड स्तर पर गुणवत्ता के विकास आयुक्त शिवाजी कुमार श्रीवास्तव द्वारा की गई है।

स्थानीय प्रखंड में दिव्यांगों को अधिक सुविधा मुहैया कराने के लिए जोड़ने के लिए प्रखंड स्तर पर बैठक कर, वहीं इस प्रखंड पर के विकास से उनके जीवन में स्थिरता और समुचित विकास हो सके। कार्यक्रम में जिला से आये हुए पदाधिकारी उपस्थित हुए। उन्होंने दिव्यांगों के गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए स्थानीय स्तर पर टीम बना कर इनका विकास किए जायेंगे, विराटी देवप्रसाद स्वयंसेवक बीडीओ के द्वारा की जायेंगे। बैठक में सभी 6 पंचायतों के सभी विकासकर्ताओं को उपस्थिति के साथ ही साथ अपनी बीडीओ अजय कुमार सिन्हा, प्रखंड समन्वयक पदाधिकारी विजय कुमार, प्रखंड स्थानीय पदाधिकारी राजकुमार, जिला समन्वयक सुनील कुमार सिंह, वरीय पीओ अमित कुमार सिंह सभी पदाधिकारी एवं विकास विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

दिव्यांगों के समुचित विकास के जीवन में आने वाले हर मुद्दे-समस्या का समाधान करने के लिए प्रखंड स्तर पर स्थानीय विकास के लिए टीम बनाई जाएगी। विहार सरकार उनके अधिकारों को सुरक्षित रखेगी।



पंतदेवरी में दिव्यांगों की बैठक करते बीडीओ



अधिकारियों के साथ बैठक करते राज्य निःशक्तता आयुक्त

## दिव्यांगों को दी गयी ट्राइसाइकिल

थावे प्रखंड पहुंचकर राज्य निःशक्तता आयुक्त ने बैठक की। बैठक में आयुक्त ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं को उन तक हर हाल में पहुंचाया जाये। वैसे दिव्यांगों को तलाश कर लाभ पहुंचाये, जिन्हें अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। मौके पर आयुक्त द्वारा सेमरा पंचायत के सुंदर पटी गांव के बिट्टू सिंह व धतिवाना पंचायत के प्यारेपुर गांव के प्रमोद कुमार पाठक को ट्राइसाइकिल प्रदान किया गया। बैठक के दौरान बीडीओ सुमन सिंह, प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉ. संजय कुमार सिंह, आकाश सिंह व अन्य लोग मौजूद थे।

उन्होंने दिव्यांगों को स्वरोजगार से जोड़ने को लेकर बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इतना ही नहीं दिव्यांगों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर समुदायिक भवन, दुकान रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि का निरीक्षण कर संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिया।



# गोपालगंज जिला



4000

से अधिक दिव्यांगों ने दिया आवेदन



1007

दिव्यांग का ऑन द स्पॉट मिला प्रमाणपत्र



30300

से अधिक लोग जुड़े ऑनलाइन



25000

लोग मीडिया के माध्यम से जुड़े



27 | सितंबर | 2019 चलंत न्यायालय



■ दिव्यांगजन अपनी समस्या को सुनते हुये।



आं

बेडकर भवन में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तत्वावधान में जिले के दिव्यांगजनो के लिए चलंत लोक अदालत का आयोजन राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार की देखरेख में हुआ। लोक अदालत में जिले के सभी प्रखंडों व शहरी क्षेत्रों से आये दिव्यांगजनों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा आंबेडकर भवन परिसर में सभी विभागों के काउंटर लगाये गये थे। यहां अधिकारियों ने

लोक अदालत में जिले के सभी प्रखंडों व शहरी क्षेत्रों से आये दिव्यांगजनों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा आंबेडकर भवन परिसर में सभी विभागों के काउंटर लगाये गये थे। यहां अधिकारियों ने दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनीं।

दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनीं। वहीं जो समस्याएं ऑन द स्पॉट निष्पादित नहीं की जा सकीं, उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग को एक महीने के कार्यदिवस में निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। अदालत को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी काफी अलर्ट

अदालत में निःशक्तता आयुक्त ने दिव्यांगजनों के हक और अधिकार के बारे में भी जानकारी दी।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में निहित सभी प्रावधानों के बारे में विस्तृत से बताया।

दिखे। वरीय उप समाहर्ता पंकी कुमारी व अनंत कुमार सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी अदालत में उपस्थित थे।

चलंत लोक अदालत में निःशक्तता आयुक्त ने दिव्यांगजनों के हक और अधिकार के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में निहित सभी प्रावधानों के बारे में विस्तृत से बताया। आयुक्त ने जिला प्रशासन को दिव्यांगों से जुड़ी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने का भी निर्देश दिया। कार्यक्रम को डीएम अरशद अजीज ने भी संबोधित किया। डीएम ने दिव्यांगजनों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को समय से दूर दिया जायेगा।

मोबाइल कोर्ट में अपनी समस्याओं के निष्पादन के लिए दिव्यांगजन सुबह से पहुंचने लगे थे। जिले के थावे, माझा, बरौली, सिधवलिया, कुचायकोट, सदर, हथुआ, उचकागांव व फुलविरया आदि प्रखंडों से चार हजार से अधिक संख्या में दिव्यांग पहुंचे थे। दिव्यांगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित काउंटर पर पहुंचकर आवेदन दिया।



# सुपौल जिला



120

से अधिक दिव्यांग एवं अभिभावकों को फायदा



300

से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा



2500

से अधिक लोग जुड़े ऑनलाइन



20000

लोग मीडिया के माध्यम से जुड़े

## शिक्षक दिवस समारोह

29 | सितंबर | 2019



■ शिक्षकों को सम्मानित करते डॉ शिवाजी कुमार.



प्रा

इवेंट स्कूल्स एसोसिएशन के द्वारा सुपौल के मिलन पैलेस में आयोजित जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के भविष्य को गढ़ने के लिए निजी और सरकारी शिक्षकों को साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि आप लोग सभी बच्चों के प्रेरणा है। उनके जीवन सबसे नाजुक समय आपलोगों की देखरेख में

सम्मान समारोह में दिव्यांग शिक्षकों को भी स्मानित किया गया। जो कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा का अलाख जगाये हुए हैं। राज्य आयुक्त ने त्रिवेणीगंज के दिव्यांग शिक्षक संतोष कुमार को प्रतीक चिह्न और शॉल देकर सम्मानित किया।

गुजरता है। इसलिए एक बेहतर शिक्षक हजारों बेहतर विद्यार्थी तैयार करने का मद्दा रखता है। आपलोगों से सभी अभिभावकों को उम्मीद रहती है कि मेरे बच्चे के लिए आप बेहतर मार्गदर्शक साबित होंगे। इसलिए आपका दायित्व बनता है कि उस नौनिहाल को इस भीड़ में एक ऐसा पहचान दें की पूरी दुनिया

समाज को सही दिशा देने में शिक्षकों की है अहम भूमिका

देश का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी शिक्षकों के हाथ में

आपके कार्यों की लोहा माने। शिक्षा के साथ-साथ बच्चों में शिष्टाचार भी आप ही के द्वारा दिया जाता है। आपके द्वारा सिखाया गया हर पाठ उसके जीवन में कहीं न कहीं काम आता है। आपके ऊपर सबसे बड़ा दायित्व समाज की ओर से दिया गया है। जिसे आप बखूबी निभाते भी हैं। आपसे हम आशा करते हैं कि आपके स्कूलों के बच्चे नये किर्तिमान रचें, जिससे आपका देश दुनिया में नाम रौशन हो। मौके पर आयुक्त ने कहा कि शिक्षकों का सम्मान एक सराहनीय काम है, क्योंकि शिक्षक ही समाज को गढ़ने का काम करते हैं। सरकारी स्कूल वाले अगर बड़े भाई हैं तो, निजी विद्यालय वाले छोटे भाई, दोनों मिलकर कार्य करें इसमें बच्चों को लाभ मिलेगा। मौके पर मौजूद डीइओ योगेश मिश्रा ने कहा कि शिक्षक ही समाज का असली मार्गदर्शक है। शिक्षक ही एकता और शांति के दूत हैं। जिलाध्यक्ष श्याम किशोर ठाकुर ने कहा कि हम शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आरएसएम स्कूल के प्राचार्य डॉ. विश्वासचंद्र मिश्र ने गुरु और शिष्य की परंपरा पर प्रकाश डाला।



क्र०सं०	वाद सं०	जिला	वादी एवं प्रतिवादी	विषय
39.	39/2019	पटना	वादी :- श्री मुन्ना कुमार , पटना प्रतिवादी :- अर्सेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना एवं अन्य	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र नहीं बनने के संबंध में
40.	40/2019	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	वादी :- श्रीमती रेखा देवी, पति श्री सुरेन्द्र सिंह, पश्चिम चम्पारण, बेतिया प्रतिवादी :- जिला आपूर्ति , पश्चिम चम्पारण, बेतिया	जनवितरण प्रणाली की दुकान के संबंध में
41.	41/2019	पटना	वादी :- श्री राजा, पिता-राजदेव राय, पटना प्रतिवादी :- अर्सेनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना एवं अन्य	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र टालमटोल करने के संबंध में
42	42/2019	समस्तीपुर	वादी :- श्री अमर भूषण प्रकाश, समस्तीपुर प्रतिवादी :-शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम समस्तीपुर	भारतीय जीवन बीमा निगम की चेक की राशि का भुगतान के संबंध में
43.	43/2019	पटना	वादी :- श्री बासकित साह (वरिष्ठ नागरिक), पटना प्रतिवादी :- उप नगर आव्युत, पटना नगर निगम, पटना एवं अन्य	सड़क निर्माण के सम्बन्ध में
44.	44/2019	मधुबनी	वादी : श्री हरिबोल यादव, मधुबनी प्रतिवादी :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधुबनी	पेंशन स्वीकृति के संबंध में
45.	45/2019	रोहतास	वादी :- श्री देव मुन्नी सिंह, रोहतास प्रतिवादी :- जिला पदाधिकारी रोहतास एवं अन्य	राज्य आव्युत निःशक्तता द्वारा आदेश अनुपालन नहीं करने के संबंध में
46.	46/2019	पटना	वादी :-दिव्यांगजनों से शिक्षक नियोजन 2019-20 के संबंध में। स्वतः संज्ञान प्रतिवादी :- प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार	शिक्षक नियोजन 2019-20 की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में
47.	47/2019	पटना	वादी :- श्रीमती मिली बंसल, एन्जिबिशन रोड, पटना प्रतिवादी :- शाखा प्रबंधक, एच०डी०एफ०सी० बैंक, पटना एवं अन्य	खाता खोलने के संबंध में
48.	48/2019	बेगूसराय	वादी :- श्री श्याम बाबु साह, श्री पप्पु साह तथा श्री भोला साह, बेगूसराय प्रतिवादी :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेगूसराय	चलन्त न्यायालय में पारित ओदश का अनुपालन नहीं किये जाने के संबंध में
49.	49/2019	बेगूसराय	वादी :-श्री संतोष कुमार, बेगूसराय प्रतिवादी :- अचलाधिकारी, प्रखण्ड-बेगूसराय सदर, जिला-बेगूसराय, बिहार	निःशुल्क नापी करवाकर सीमांकन करवाने के संबंध में
50.	50/2019	पटना	वादी :- श्रीमती अंजली कुमारी, पटना प्रतिवादी :- श्रीमती मनीषा कृष्ण, सचिव, उत्कर्ष सेवा संस्थान बहादुर, पटना	बिना कोई सूचना के विशेष स्कूल से वापस करने के संबंध में
51.	51/2019	पटना	वादी :- श्री प्रियांशु कुमार, पटना प्रतिवादी :- निदेशक लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, पटना	दिव्यांगता प्रमाण पत्र से संबंधी
52.	52/2019	भोजपुर (आरा)	वादी :- श्री कमलेश कुमार गुप्ता, बन्धन टोला, क्षेत्रीय स्कूल के पास, आरा प्रतिवादी :- शाखा प्रबंधक, सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मौलाबाग, आरा (भोजपुर)	सहारा में जमा राशि के परिपक्वता अवधि पूर्ण हो जाने के उपरांती भी राशि भुगतान नहीं करने के संबंध में





OCTOBER 2019

# अक्टूबर 2019



24 घंटे दर्ज होगी  
शिकायत...

pg-098



मानसिक स्वास्थ्य पर  
कार्यशाला

pg-099



मधेपुरा चलंत  
न्यायालय

pg-102



शैक्षणिक संस्थानों में  
दिव्यांगों के लिए...

pg-101

## प्रखंडों का निरीक्षण

न्यायालय में सुनवाई दिव्यांगजनों के उद्धार के लिए चल रही सभी योजनाओं पर होगी। मौके पर उन्होंने ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष तक के दिव्यांगों को मुफ्त शिक्षा, गरीबी निवारण योजनाओं में आरक्षण, दिव्यांगता के आधार पर किसी तरह के भेदभाव नहीं करना चाहिए सहित कई जानकारी दी।

pg-100





11 | अक्टूबर | 2019

## दिव्यांगों के लिए हेल्पलाइन नंबर

**हेल्पलाइन नंबर - 8448385590, दूरभाष- 0612-2215041, वेबसाइट - www.scdisabilites.org, ईमेल- scdisability2008@gmail.com**

# 24 घंटे दर्ज होगी शिकायत

दि

दिव्यांगों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार लगातार कार्य कर रहे हैं। दिव्यांगों की सहायता के लिए उन्होंने अब हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। जहां दिव्यांग 24 घंटे अपनी समस्याओं की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह नंबर सातों दिन एक्टिव रहेगा। इसके तहत जिन दिव्यांगों को प्रमाणपत्र बनवाने में, पेंशन पाने आदि में परेशानी हो रही है वे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गाली-गलौज से जुड़े मामले या जिनके लीगल गार्जियन नहीं हैं वैसे दिव्यांग भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह शिकायत रिकॉर्ड की जाएगी। रिकॉर्ड होने के बाद एक नंबर दिया जायेगा। इसके बाद संबंधित मामले पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य निःशक्तता आयुक्त ने बताया कि वेबसाइट को भी अपडेट किया जा रहा है।

यहां भी दिव्यांग शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दिव्यांग, बैंक या अस्पताल जिस सार्वजनिक स्थल पर जा रहे हैं और वहां रैंप नहीं है तो ऐसी तस्वीरें या वीडियो भेज सकते हैं। यह वीडियो बतायेगा कि दिव्यांगों को कैसी असुविधा हो रही है। फोटो या वीडियो भेजने के साथ ही वह शिकायत के रूप में दर्ज हो जायेगा। यानी अलग से आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराने की जरूरत नहीं रहेगी। पेपरलेस वर्क करने के लिए यह सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। निःशक्तता आयुक्त



इसके बाद संबंधित मामले पर कार्रवाई की जाएगी। गाली-गलौज से जुड़े मामले या जिनके लीगल गार्जियन नहीं हैं वैसे दिव्यांग भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह शिकायत रिकॉर्ड की जाएगी। रिकॉर्ड होने के बाद एक नंबर दिया जायेगा। इसके बाद संबंधित मामले पर कार्रवाई की जाएगी।

- 👉 हेल्पलाइन पर किसी भी प्रकार की कर सकते हैं शिकायत होगी कार्रवाई
- 👉 कलर ब्लाइंडनेस के शिकार दिव्यांगों के लिए वेबसाइट बना अनुकूल
- 👉 सातों दिन और 24 घंटे के लिए शुरू किया गया हेल्पलाइन नंबर
- 👉 वेबसाइट पर शिकायतों की वीडियो बनाकर करें अपलोड, होगी कार्रवाई



**23000**

दिव्यांगों को मिला  
लाभ



**532**

दिव्यांगजनों ने भेजी  
रिकॉर्डिंग शिकायतें



**25** हजार

लोग जानें  
मीडिया से

की वेबसाइट पर कलर ब्लाइंडनेस के शिकार दिव्यांग भी अब वहां शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह वेबसाइट अब उनके अनुकूल बना दिया गया है। आयुक्त ने बताया कि जहां दिव्यांगों

से जुड़ा साइनेज नहीं है वहां लगाया जायेगा। इसकी शुरुआत सचिवालय से होगी। दिव्यांगों से जुड़ी सुविधाओं को चेक करने के लिए एक्सेस ऑडिटर बनाये गये हैं।



12 | अक्टूबर | 2019



## मानसिक स्वास्थ्य पर कार्यशाला आयोजित

# मानसिक दिव्यांगों के लिए पूनर्वास कार्यक्रम

रा

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) बिहार, पटना, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के तत्वाधान में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य भर से अस्सी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का आरम्भ अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप-प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) बिहार, पटना द्वारा कार्यशाला के संबोधन में बताया गया की राज्य में दिव्यांगजन के हित में व्यापक कार्य हो रहे। दिव्यांगजन से संबंधित कानून बिहार में लागू कर दिया गया है। अब इससे जुड़े लाभार्थी ससमय उचित लाभ ले रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में

बताया कि बिहार सरकार इस दिशा में कार्य हेतु प्रयासशील है। बड़े पैमाने पर मनोवैज्ञानिक प्रोफेशनल व मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को प्रशिक्षण देने की दरकार है। आज के इस कार्यशाला में सूबे के राज्य आयुक्त निःशक्तता ने तमाम प्रोफेशनल को यह शपथ दिलाया की राजधानी और अन्य जिलों में मानसिक रोगी भटके नहीं खासतौर से महिला मानसिक रोगियों को देखने पर तत्काल उन्हें सूचित करें। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं पहले और बाद में अन्य सभी प्रोफेशनल को यह शपथ दिलायी की मानसिक बीमारी से जूझते बेसहारों का सहारा बना जाये। इन्होंने हर स्कूल में एक मनोवैज्ञानिक रखने का सुझाव दिया।

इस अवसर पर डॉ॰ पी.के. सिंह, विभागाध्यक्ष व निदेशक कोईलवर मेंटल अस्पताल ने बताया कि बिहार में औसतन मनोरोगी की संख्या कुल आबादी का 10% है। राज्य सरकार की ओर से मानसिक स्वास्थ्य पर अभी 11 जिलों में कार्य हो रहे और अभी 20 चिन्हित जिलों में काम होने जा रहा। इन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा की बिहार में तत्काल 1000 मनोचिकित्सक तथा उससे बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक प्रोफेशनल की सख्त से सख्त आवश्यकता है। कोईलवर मेंटल हास्पिटल में अबतक 65000 मरीज 2018 तक व इस साल 2019 में 70000 मानसिक रोगियों का ईलाज किया जा चुका है।

इस अवसर पर पटना के मनोवैज्ञानिक डॉ॰ मनोज कुमार ने बताया की बिहार में बच्चों, किशोरों, युवाओं, व्यस्कों और बुजुर्गों में अलग-अलग किस्म के मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इन्होंने अपने कार्यशाला के संबोधन में किशोरों के बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य पर सजग होने की जरूरत पर बल दिया। कम उम्र के बच्चों में अवसाद, मोबाइल पर निर्भरता व खेलकूद से दूरी व माता-पिता के वर्किंग होने से बच्चों में भावनात्मक विकास सही से नहीं हो रहा जिससे मानसिक बीमारियां धर कर रही। किशोरों में परीक्षा के दबाव, अधिक पैसे खर्च, उच्च इमेज और शोखी बघाड़ने व नशा आदि का प्रचलन बढ़ना भी उन्हें मानसिक रोग की आगोश में धकेल रहा। इसी प्रकार व्यस्कों में भी वैवाहिक जीवन, रोजगार से संबंधित तनाव, नशा, आत्महत्या जैसे मानसिक समस्या बिहार में देखी जा रही। कार्यक्रम में इन्होंने यह भी कहा कि बुजुर्गों को भी समाज में दरकिनार किया जा रहा जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतीकूल असर पड़ रहा।



आत्महत्या जैसे मानसिक समस्या बिहार में देखी जा रही। कार्यक्रम में इन्होंने यह भी कहा कि बुजुर्गों को भी समाज में दरकिनार किया जा रहा जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतीकूल असर



103

विशेषज्ञों हुये  
शामिल



5000

लोग सीधे जुड़े  
कार्यक्रम से



323

सेमिनार में  
थे शामिल



08 हजार

लोग जानें  
मीडिया से



15 | अक्टूबर | 2019



## प्रखंडों का निरीक्षण / मधेपुरा



■ दिव्यांगों के साथ बैठक कर उनकी परेशानी जानते राज्य निःशक्तता आयुक्त।



### दिव्यांगों को मिली अधिकारों की जानकारी



400

से अधिक लोग बैठक में लिये हिस्सा

18 वर्ष तक दिव्यांगों को मुफ्त शिक्षा को हर हाल में व्यवस्था हो

गरीबी निवारण योजनाओं में आरक्षण का मिले लाभ

विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान चिह्नित कर दें

च

लंत लोक अदालत इस बार मधेपुरा में लगेगा। इसके पहले राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार सभी प्रखंडों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित करने पहुंचे की दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है कि नहीं। शंकपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में बैठक कर वहां चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। मौके पर आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 80 के अंतर्गत राज्य निःशक्तता आयुक्त द्वारा दिव्यांगों की समस्याओं के निपटाने के लिए चलंत न्यायालय लगाया जायेगा। न्यायालय में सुनवाई दिव्यांगजनों के उद्धार के लिए चल रही सभी योजनाओं पर होगी। मौके पर उन्होंने ने बताया



कि राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष तक के दिव्यांगों को मुफ्त शिक्षा, गरीबी निवारण योजनाओं में आरक्षण,

दिव्यांगता के आधार पर किसी तरह के भेदभाव नहीं करना चाहिए सहित कई जानकारी दी। वहीं दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, स्वरोजगार ऋण योजना, दिव्यांग को रोजगार में चार प्रतिशत का आरक्षण आदि योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। वहीं मनरेगा पीओ मनोज कुमार ने कहा कि दिव्यांगों को मनरेगा का जॉब कार्ड 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जायेगा।

**न्यायालय में सुनवाई दिव्यांगजनों के उद्धार के लिए चल रही सभी योजनाओं पर होगी।** मौके पर उन्होंने ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष तक के दिव्यांगों को मुफ्त शिक्षा, गरीबी निवारण योजनाओं में आरक्षण, दिव्यांगता के आधार पर किसी तरह के भेदभाव नहीं करना चाहिए सहित कई जानकारी दी।



16 | अक्टूबर | 2019



अधिकारियों के साथ  
बैठक/मधेपुरा



# शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगों के लिए बने रैंप

प्रति कुलपति डॉ. फारुक अली ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं है। भगवान ने उन्हें स्पेशल बनाकर दिये शक्ति दी है। हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वर्षों से उपेक्षित दिव्यांग पिछड़े नहीं हैं, उन्हें पछाड़ दिया गया है। प्रतीकुलपति ने विवि स्तर से दिव्यांगजनों के लिए हर संभव कार्य करने की बात कही।



**243**

दिव्यांगजनों को हुआ फायदा



**400**

से अधिक लोगों ने लिया भाग



**8000**

से ज्यादा सोशल मीडिया से जागरूकता



**15000**

मीडिया के माध्यम से जन जागरूक



■ दिव्यांगों के साथ बैठक कर उनकी परेशानी जानते राज्य निःशक्तता आयुक्त।

जागरूकता अभियान चलायें। विव के ऑडिटोरियम व मंच पर पहुंचने के लिए दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था नहीं रहने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बैठक में मौजूद विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यों व विवि के अधिकारियों से सभी महाविद्यालयों और विभागों में दिव्यांगजनों के लिए रैंप की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही।

प्रति कुलपति डॉ. फारुक अली ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं है। भगवान ने उन्हें स्पेशल बनाकर दिये शक्ति दी है। हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वर्षों से उपेक्षित दिव्यांग पिछड़े नहीं हैं, उन्हें पछाड़ दिया गया है। प्रतीकुलपति ने विवि स्तर से दिव्यांगजनों के लिए हर संभव कार्य करने की बात कही। उन्होंने सभी प्राचार्यों को निर्देश दिया कि महाविद्यालय में रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

बी

एन मंडल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने बैठक की। इसमें विश्वविद्यालय व कॉलेजों में दिव्यांगजनों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में चर्चा की गयी। आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलायी जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय व महाविद्यालय स्तर से



18 | अक्टूबर | 2019



## चलंत न्यायालय/मधेपुरा



■ चलंत लोक अदालत में शामिल दिव्यांगजन और उनके परिजन।

4732

दिव्यांगों ने दर्ज की शिकायत

1256

दिव्यांगों को ऑन द स्पॉट मिला प्रमाणपत्र

723

दिव्यांगों ने सामाजिक पेंशन

042

आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आये

दि



दिव्यांगजनों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए रासबिहारी हाईस्कूल के खेल मैदान में मोबाइल अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, डीएम नवदीप शुक्ला और एसपी संजय कुमार ने संयुक्त रूप से किया। आयुक्त ने दिव्यांगों के लिए मोबाइल कोर्ट में विभिन्न समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया। विभिन्न आयुवर्ग के दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर राज्य आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये। आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने सभी दिव्यांगों के राशन कार्ड, डीएल सहित अन्य मामले ऑन द स्पॉट निपटारे। वहीं सरकारी



अनुदान, लोन जैसे अन्य कार्य भी एक महीने के भीतर निपटा लेने का निर्देश जारी किया। उन्होंने सभी दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आपके लिए सिर्फ पेंशन योजना ही नहीं लायी है, बल्कि दिव्यांगों को शिक्षा लोन, व्यवसाय ऋण सहित रोजगार में आरक्षण सहित अन्य योजना भी लायी है। दिव्यांगों को अब जिला मुख्यालय का चक्कर

नहीं लगाना पड़ेगा।

डीएम नवदीप शुक्ला ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं का लाभ देने के लिए राज्य आयुक्त खुद जिले में तीन दिनों से लगातार प्रयासरत हैं। एसपी संजय कुमार ने कहा कि दिव्यांगों की सुविधा के लिए विशेष कानून का अधिकार भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि अन्याय या दुर्यवहार होने पर नजदीकी थाने में जानकारी देने को कहा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिविर स्थल पर स्वास्थ्य विभाग, परिवहन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सहित विभिन्न प्रखंड क्षेत्र का स्टॉल लगा हुआ था। जहां संबंधित क्षेत्र के दिव्यांगों ने अपना फॉर्म जमा किया।

डीएम नवदीप शुक्ला ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं का लाभ देने के लिए राज्य आयुक्त खुद जिले में तीन दिनों से लगातार प्रयासरत हैं। एसपी संजय कुमार ने कहा कि दिव्यांगों की सुविधा के लिए विशेष कानून का अधिकार भी दिया गया है।



# NOVEMBER 2019

## नवंबर 2019



प्रखंडों का  
निरीक्षण मधुबनी जिला

pg-105



विभागीय निर्देश के  
अनुसार...

pg-106



प्रखंडों का  
निरीक्षण

pg-108



प्रखंडों का  
निरीक्षण...

pg-111



कई जगहों पर  
दिव्यांगजनों से ...

pg-114



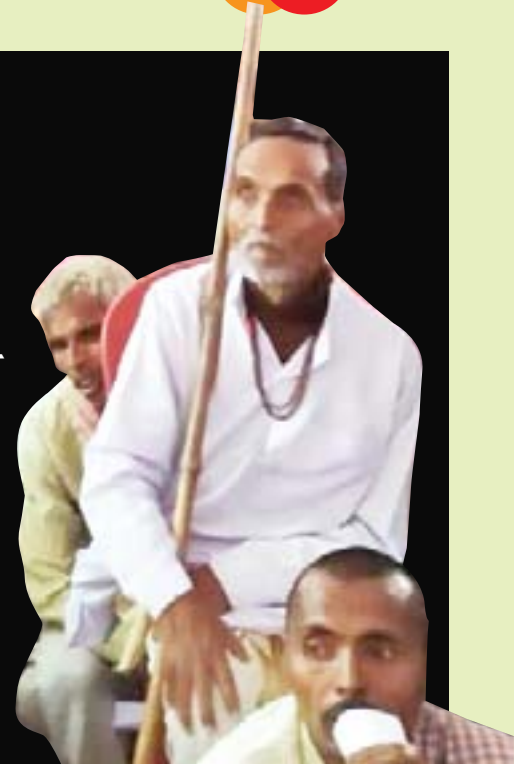
नगर भवन में  
आयोजित कार्यशाला

pg-120

### दिव्यांगजनों के समूह का हुआ गठन

खुटौना प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं दिव्यांग समूह के साथ बैठक की। उन्होंने दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग के अंतर्गत मुख्यमंत्री निःशक्त सहायता योजना के बारे में प्रखंड से आये सभी दिव्यांगों को बारीकी से समझाया। उन्होंने प्रखंड के पांच पंचायतों से आये शिकायत का संज्ञान लेते हुए...

pg-107



06 | नवंबर | 2019



## प्रखंडों का मधुबनी निरीक्षण जिला



■ दिव्यांगों व प्रखंड के अधिकारियों के साथ बैठक करते राज्य आयुक्त।



300

से अधिक दिव्यांग हुए शामिल

गरीबी उन्मूलन योजना का लाभ दिव्यांगों को हर हाल में मिलेगा

दिव्यांग को पेंशन व ट्राइसाइकिल से ऊपर उठना होगा

शिक्षा, आवास और भूमिहीन को जमीन का भी मिलता है लाभ

अ

ब दिव्यांग को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए बिहार सरकार ने कई अहम निर्णय लिया है। मधुबनी के प्रेस क्लब में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों को घर बैठे लाभ पहुंचाने के लिए पंचायत, प्रखंड व जिला स्तर पर दिव्यांग समूह का गठन किया गया है। पंचायत समूह में मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, शिक्षा विभाग के बीआरपी, सेविका, एएनएम, समाजसेवी, किसान सलाहकार, रोजगार सेवक, न्याय मित्र, आवास सहायक, विकास मित्र, टोला सेवक एवं बीएलओ को शामिल किया गया है। समूह में शामिल लोगों की नियमित बैठक होगी। वे

## दिव्यांगों को घर बैठे मिलेगा योजनाओं का लाभ

मधुबनी | बि. समाज

जब दिव्यांगों को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसके लिए बिहार सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं। मधुबनी के प्रेस क्लब में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों को घर बैठे लाभ पहुंचाने के लिए पंचायत, प्रखंड व जिला स्तर पर दिव्यांग समूह का गठन किया गया है।



दिव्यांगों को घर बैठे मिलेगा योजनाओं का लाभ

दिव्यांगों को घर बैठे मिलेगा योजनाओं का लाभ

जब दिव्यांगों को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसके लिए बिहार सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं। मधुबनी के प्रेस क्लब में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों को घर बैठे लाभ पहुंचाने के लिए पंचायत, प्रखंड व जिला स्तर पर दिव्यांग समूह का गठन किया गया है।

दिव्यांग तक जरूरी लाभ पहुंचायेंगे। प्रखंड स्तर पर गठित समूह को भी रिपोर्ट करेंगे।

राज्य आयुक्त ने कहा कि गरीबी उन्मूलन योजना का लाभ दिव्यांगों को हर हाल में मिलेगा। इसके लिए अनुमंडल स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने यह भी बताया कि 14 नवंबर को फुलपरास एवं 15 नवंबर को बेनीपट्टी अनुमंडल में चलंत न्यायालय का आयोजन

किया गया है। इसमें दिव्यांग अपनी समस्या रख सकते हैं। डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि लोगों को सोंच बदलनी होगी। दिव्यांग को पेंशन व ट्राइसाइकिल से ऊपर उठना होगा। अब सरकार शिक्षा, आवास, भूमिहीन को जमीन, मनरेगा सहित कई अन्य लाभ देगी। राज्य आयुक्त ने जिले के कई प्रखंडों का दौरा किया। बीडीओ, सीओ, अस्पताल प्रभारी व एमओ सहित अन्य कई विभागीय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर दिव्यांगों को मिलनेवाली योजनाओं के लाभ व सुविधाओं की जानकारी ली। राज्य आयुक्त ने मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया करानेवाली योजनाओं की समीक्षा की। मजदूरी करने लायक 18 वर्ष से ऊपर के सभी दिव्यांगों को 15 दिन के अंदर जॉब कार्ड निर्गत करने का निर्देश दिया।

राज्य आयुक्त ने कहा कि गरीबी उन्मूलन योजना का लाभ दिव्यांगों को हर हाल में मिलेगा। इसके लिए अनुमंडल स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने यह भी बताया कि 14 नवंबर को फुलपरास एवं 15 नवंबर को बेनीपट्टी अनुमंडल में चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया है।







07 | नवंबर | 2019

# मधुबनी जिला



■ बैठक में शामिल दिव्यांगजन और जिले के अधिकारी।



2016 अधिकार अधिनियम में 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है दिव्यांगों को ध्यान में रखकर भवनों का निर्माण किया जाये निजी संस्थानों में भी दिव्यांगों को दिया जाना है पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ

## रा

ज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने मधुबनी के समाहरणालय सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत 21 तरह के दिव्यांग होते हैं। इसमें चलंत संबंधी दिव्यांगता, मांसपेशीय दुर्विकार, ठीक किया हुआ कुष्ठ, प्रमांस्तम्ब घात, बौनापन, अम्ल हमले की पीड़ित, कम दृष्टि दृष्टिहीनता, श्रवण क्षति, सुनने में कठिनाई, वाक एवं भाषा का दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मानसिक रूग्णता, क्रोनिक स्त्रायविक, स्थिति, बहुल काठिन्य, पार्किंसन रोग, हीमोफीलिया,



थैलेसेमिया तथा सिकल सेल रोग संबंधी दिव्यांग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण तथा संबंधित विभाग के निर्माण निगम के द्वारा कार्यालयों का निर्माण इस प्रकार से किया जाये, जिससे कि दिव्यांगजनों को कार्यालय में प्रवेश करने में कोई परेशानी नहीं हो। विभागीय निर्देश के अनुसार किसी भी निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों में पांच प्रतिशत दिव्यांगजनों का चयन किया जाना है। उच्च स्तरीय शिक्षा

## अनुमंडल में बैठक

यथा बीएड, एमएड तथा मेडिकल इत्यादि में भी दिव्यांगजनों को पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाना है। उन्होंने श्रम संसाधन विभाग को एक माह के अंदर दिव्यांगजन कामगारों की पहचान कर विभाग से परिचय पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी विभागों के पदाधिकारियों को अपने-अपने विभाग से जुड़े लाभार्थियों की सूची बनाने का निर्देश दिया। ताकि यह पता चल सके कि किस दिव्यांगजन को उनके विभाग के द्वारा कौन-कौन से लाभ दिये गये हैं। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना एवं विकास कार्यक्रम में पांच प्रतिशत दिव्यांगजनों को लाभ दिया जाना है।

विभागीय निर्देश के अनुसार किसी भी निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों में पांच प्रतिशत दिव्यांगजनों का चयन किया जाना है। उच्च स्तरीय शिक्षा यथा बीएड, एमएड तथा मेडिकल इत्यादि में भी दिव्यांगजनों को पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाना है।



08 | नवंबर | 2019

# प्रखंडों बैठक मधुबनी जिला



उन्होंने प्रखंड के पांच पंचायतों से आये शिकायत का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को इसे जल्द निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने 15 दिनों पर पंचायत स्तरीय कमेटी को बैठक करने का निर्देश दिया।

बैठक में दिव्यांग अधिकार अधिनियम की दी जानकारी

दिव्यांगजनों के समूह का हुआ गठन

प्रखंड स्तर पर दिव्यांगजन को चिह्नित कर दिया जायेगा सुविधाओं का लाभ

■ अधिकारियों व दिव्यांगों के साथ बैठक करते राज्य निःशक्तता आयुक्त।

उन्होंने 15 दिनों पर पंचायत स्तरीय कमेटी को बैठक करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अब कुल 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है। इसी के तहत बीडीओ को दिव्यांगों की सूची बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने धारा 72 के अंतर्गत दिव्यांगजन समूह का गठन कर दिव्यांगों को योजना के बारे में जानकारी देने को कहा।

बैठक में एसडीओ गणेश कुमार, बीडीओ किशोर कुमार, बीएओ पवन कुमार यादव, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. विजय मोहन केशरी, मनरेगा पीओ जितेंद्र कुमार सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। लौकही प्रखंड पहुंचे आयुक्त ने बीडीओ को निर्देश दिया कि प्रखंड के सभी दिव्यांगजनों को चयनित कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने व उनके अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाया जाये।

टौना प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं दिव्यांग समूह के साथ बैठक की। उन्होंने दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग के अंतर्गत मुख्यमंत्री निःशक्त सहायता योजना के बारे में प्रखंड से आये सभी दिव्यांगों को बारीकी से समझाया। उन्होंने प्रखंड के पांच पंचायतों से आये शिकायत का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को इसे जल्द निपटाने का निर्देश दिया।



## अधिकार से वंचित न हों एक भी दिव्यांग: शिवाजी



09 | नवंबर | 2019



# प्रखंडों का निरीक्षण मधुबनी जिला



राज्य आयुक्त ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों की सहयोग की आवश्यकता है। बिना सहयोग किये दिव्यांगों को सही लाभ नहीं मिल सकता है।



**400**

से अधिक दिव्यांगजनों व जनप्रतिनिधियों ने लिया बैठक में हिस्सा

पंचायत स्तर पर गठित दिव्यांगों के समूह का प्रत्येक 15 दिनों पर होगी बैठक

दिव्यांगों तक लाभ पहुंचाने के लिए पदाधिकारी करें हरसंभव प्रयास

चलंत न्यायालय में दिव्यांगों के सभी शिकायतों का एक जगह होगा सामाधान

## हरलाखी प्रखंड

सहित दर्जनों मुखिया उपस्थित थे।

राज्य आयुक्त ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों की सहयोग की आवश्यकता है। बिना सहयोग किये दिव्यांगों को सही लाभ नहीं मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही है, लेकिन जागरूकता के अभाव में दिव्यांगजन इसका समुचित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसी कारण पंचायत स्तर तक दिव्यांग समूह का गठन किया गया है। हर 15 दिन पर इस समूह की बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को बेनीपट्टी स्थित बुनियाद केंद्र कार्यालय में प्रमाणीकरण का कार्य एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण तथा निष्पादन के लिए चलंत न्यायालय का आयोजन किया जायेगा। मौके पर प्रखंड प्रमुख राजेश कुमार व अन्य मौजूद थे।

■ हरलाखी प्रखंड में दिव्यांगजन व जनप्रतिनिधियों से मुखातिब राज्य निःशक्तता आयुक्त।

रा

ज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए चलायी जा रही सभी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर इसका लाभ उठाने के प्रति दिव्यांगों को जागरूक किया जा रहा है। आयुक्त हरलाखी प्रखंड स्थित नये जनप्रतिनिधि भवन में सैकड़ों दिव्यांगों को जागरूक करने पहुंचे थे। बीडीओ अरुणा कुमार चौधरी की देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बैठक में बीडीओ, सौओ शशिभूषण प्रसाद सिंह, प्रमुख राजेश कुमार पांडेय उर्फ बालाजी,



दिव्यांगों के सशक्तीकरण को किए जा रहे प्रयास, सहायता की अपील

हर बैठे मिल रहा सशक्तता दिव्यांग का लाभ, समरक्षण वतने की अपील





10 | नवंबर | 2019

# प्रखंड मधवापुर

असहायों का अधिकार हनन होने की स्थिति में की जाने वाली कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजनों को दी। उन्होंने कहा कि निःशक्तों के लिए अनुमंडल स्तरीय लोक अदालत लगायी जाएगी।



■ प्रखंड के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व दिव्यांगों के साथ बैठक



**350**

से अधिक दिव्यांग पहुंचे बैठक में

दिव्यांगों को सुविधा पहुंचाने में अधिकार नहीं बर्ते उदासिनता

इंसानियत की हैसियत से दिव्यांगों की करें सुरक्षा

देश में दिव्यांगों के लिए भी समान अवसर

## क्षे

त्र के दिव्यांगजनों को प्राथमिकता के आधार पर उनकी हर संभव सहायता करें। वह भी हमारी तरह देश के सम्मानित नागरिक हैं। वह अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें इंसानियत की हैसियत से

उनकी सेवा करनी चाहिए। उक्त बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहीं। मधवापुर प्रखंड परिसर में कई विभाग के पदाधिकारियों व दिव्यांगजनों को संबोधित कर रहे थे। मौका था दिव्यांग कल्याण कार्यशाला के आयोजन का। राज्य आयुक्त ने निःशक्तों के लिए किये जाने वाले कार्यों की जानकारी स्थानीय पदाधिकारियों से ली। उन्होंने असहायों को उनका अधिकार दिलाने में उदासिनता नहीं बरतने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। असहायों का अधिकार हनन होने की स्थिति में की जाने वाली कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजनों को दी। उन्होंने कहा कि निःशक्तों के लिए अनुमंडल स्तरीय लोक अदालत लगायी जाएगी। वहां दिव्यांगजन अपनी समस्याएं रख कर उसका निराकरण करा सकते हैं। कार्यक्रम का आयोजन मधुबनी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा आयोजित हुई थी।

## दिव्यांगों को मिला प्रमाणपत्र व कृत्रिम अंग

किसान भवन सभागार में भारत सरकार के एपिड योजना के अंतर्गत एक दिवसीय दिव्यांग परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 200 से अधिक दिव्यांगों ने हिस्सा लिया। शिविर में अनुमंडल के झंझारपुर, मधुपुर, अंधराठाढ़ी और लाखनौर प्रखंड के दिव्यांगजन ने अपना परीक्षण कराया। मौके पर एसडीओ ने कहा कि दिव्यांगजनों को जांच पड़ताल के बाद सर्टिफिकेट दिया जायेगा। साथ ही ऐसे दिव्यांगों को कृत्रिम अंग भी दिया जायेगा। एलिमको कंपनी के द्वारा उपकरण के लिए दिव्यांगों को छह से सात सप्ताह में उन्हें उपकरण उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस दिव्यांग परीक्षण शिविर में सभी विभाग के डॉक्टर मौजूद थे।

### राज्य दिव्यांग आयुक्त ने दिए निर्देश पंचायत दिव्यांग कमेटी होगी गठित

जिले के दो शिविरों के दौरान राज्य दिव्यांग आयुक्त ने की कई बैठकें



राज्य आयुक्त ने दिव्यांगों के साथ बैठकें की

दिव्यांगों को सुविधा पहुंचाने में अधिकार नहीं बर्ते उदासिनता

इंसानियत की हैसियत से दिव्यांगों की करें सुरक्षा

देश में दिव्यांगों के लिए भी समान अवसर

11 | नवंबर | 2019



# प्रखंड लदनियां

पंचायत से प्रखंड स्तर पर दिव्यांगजनों को संगठित व सशक्तिकरण पर बल दिया। उन्होंने बीडीओ नवल किशोर ठाकुर को निर्देश दिया कि पंचायत स्तर पर पंद्रह दिनों पर बैठक कर दिव्यांगजनों की समस्या का समाधान किया जायेगा।



विभिन्न प्रखंडों में राज्य आयुक्त ने दिव्यांगों व अधिकारियों के साथ की बैठक।



**450**

से अधिक दिव्यांगों के साथ प्रखंडवार हुई बैठक

सीमावर्ती क्षेत्र दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाने में लायें तेजी

जागरूकता कार्यक्रम का हो आयोजन

पांचयतस्तर पर हर 15 दिन में हो दिव्यांग समूह की बैठक

**प्र**

खंड कार्यालय परिसर स्थित सामुदायिक प्रशिक्षण भवन सभागार में बीडीओ नवल किशोर ठाकुर

द्वारा दिव्यांगजनों के समूह एवं सशक्तिकरण को लेकर बैठक आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता राज्य नि:शक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने की। आयुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र दिव्यांगजनों को अभी तक सभी सुविधाएं देने में उम्मीद से कम सफलता हासिल कर पाया है। जानकारी के अभाव में दिव्यांगजनों को कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पंचायत से प्रखंड स्तर पर

दिव्यांगजनों को संगठित व सशक्तिकरण पर बल दिया। उन्होंने बीडीओ नवल किशोर ठाकुर को निर्देश दिया कि पंचायत स्तर पर पंद्रह दिनों पर बैठक कर दिव्यांगजनों की समस्या का समाधान किया जायेगा। सरकार से मिलने वाली सुविधा की जानकारी दी गयी। आवास, राशन कार्ड देने के लिए बीडीओ को आवश्यक निर्देश दिया। दिव्यांगजनों का शिकायत दर्ज करने का निर्देश पुलिस पदाधिकारी को दिया। सीओ को भूमिहीन दिव्यांगजनों को कम से कम तीन डिसमिल जमीन देना का भी निर्देश दिया। बैठक में जिला अध्यक्ष राम प्रकाश यादव व अन्य उपस्थित थे।

## दिव्यांगों के हित में कार्य जारी रखने का निर्देश

जयनगर अनुमंडल कार्यालय के सभागार में आयुक्त ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने स्तर से 21 प्रकार के दिव्यांगों को लाभ पहुंचाये। राज्य आयुक्त ने सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को दिव्यांगों के समग्र विकास, मान सम्मान, समस्या व अधिकार को लेकर सरकार के निर्देशों का अनुपालन का निर्देश दिया। प्रत्येक पंचायत में पंचायत भवन में महिना में दो बार पंद्रह दिन के अंतराल पर पांचयत के दिव्यांगों के साथ बैठक का निर्देश दिया गया। जिसके नोडल पदाधिकारी मनरेगा पीओ एवं पीडब्ल्यूओ को बनाया गया। बैठक में पंचायत प्रतिनिधि के अलावा सभी संबंधित विभागों के अधिकारी हिस्सा लेंगे और दिव्यांगों के समस्याओं को सुनेंगे।

## दिव्यांगजनों की बैठक में आयुक्त बोले- 15 दिन पर पंचायत स्तरीय व प्रति माह प्रखंड स्तरीय बैठक करें

**मन्नार नगर (सूरी)**  
मन्नार नगर की प्रखंड कार्यालय के परिसर में दिव्यांग विभाग के अगुआ अजय ठा. शिवाजी कुमार के अध्यक्षता में बीडीओ, प्रखंड प्रमुख सहित अन्य सरकारी पदाधिकारी, कर्म, जन प्रतिनिधि, पंचायत स्तरीय सरकारी कर्म एवं जन प्रतिनिधि के पास दिव्यांगजन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राज्य आयुक्त ने कहा कि प्रखंड स्तर पर दिव्यांगजनों को संगठित व सशक्तिकरण पर बल दिया जायेगा। उन्होंने बीडीओ नवल किशोर ठाकुर को निर्देश दिया कि पंचायत स्तर पर पंद्रह दिनों पर बैठक कर दिव्यांगजनों की समस्या का समाधान किया जायेगा। सरकार से मिलने वाली सुविधा की जानकारी दी गयी। आवास, राशन कार्ड देने के लिए बीडीओ को आवश्यक निर्देश दिया। दिव्यांगजनों का शिकायत दर्ज करने का निर्देश पुलिस पदाधिकारी को दिया। सीओ को भूमिहीन दिव्यांगजनों को कम से कम तीन डिसमिल जमीन देना का भी निर्देश दिया। बैठक में जिला अध्यक्ष राम प्रकाश यादव व अन्य उपस्थित थे।





12 | नवंबर | 2019

## प्रखंडों का निरीक्षण

बैठक में बताया गया कि दिव्यांगजनों के लिए मधुबनी जिले में विशेष थाना बनाया गया है। दिव्यांगजन वहां अपनी समस्या से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

■ प्रखंडस्तरीय बैठक में हिस्सा लेते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार.



500

से अधिक लोग बैठक से हुए लाभांशित

प्र

शिक्षण भवन के सभागार में जिला दिव्यांग सशक्तिकरण को लेकर दिव्यांगों के समग्र विकास, मान सम्मान, अधिकार

तथा समस्या के निराकरण को ले बैठक हुई। अध्यक्षता राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने की। संचालन दिव्यांग संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश पंजियार ने किया। राज्य आयुक्त ने दिव्यांगों की समग्र विकास, मान सम्मान, अधिकार व समस्या के निराकरण को लेकर कार्य को गति देने पर

बल दिया। बैठक में सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए किये जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गयी।

बैठक में बताया गया कि दिव्यांगजनों के लिए मधुबनी जिले में विशेष थाना बनाया गया है। दिव्यांगजन वहां अपनी समस्या से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सांख्यिकी पदाधिकारी मुकेश कुमार को 15 दिनों के भीतर प्रखंड के सभी दिव्यांगों की सूची बनाने का आदेश दिया। पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, विकास मित्र के अलावा प्रमुख शीला देवी जिला परिषद सदस्य चंद्रेश्वर राय सहित बड़ी संख्या में दिव्यांगजन मौजूद थे।

## दिव्यांगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएं

कलुआही प्रखंड कार्यालय के सभागार में अधिकारियों व दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए राज्य निःशक्तता आयुक्त ने कहा कि अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति ने दिव्यांग महिला के साथ शादी की है, तो दोनों जनों को दो लाख मिलेगा। दिव्यांग व्यक्ति दूसरी जाति के दिव्यांग महिला से शादी करती है तो एक लाख अलग से कुल तीन लाख राशि मिलेगी। अगर दिव्यांग छात्र प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो कुल खर्च का 25 प्रतिशत राज्य सरकार भार उठाती है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट के लिए कैंप लगाया जायेगा।

दिव्यांग को शादी करने पर राज्य सरकार देती है तीन लाख तक का सहयोग

दिव्यांग व्यक्ति दूसरी जाति के दिव्यांग महिला से शादी करती है तो एक लाख अलग से कुल तीन लाख राशि मिलेगी।

प्राइवेट स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने पर आनेवाले खर्च का 25 प्रतिशत राज्य सरकार करती है वहन

## आयुक्त ने जिले के तीन प्रखंडों में दिव्यांगजन समूह की बैठक की

### भूमिहीन दिव्यांगजन को बासगीत पर्चा और जॉब कार्ड दिया जाएगा





13 | नवंबर | 2019

प्रखंड में बैठक  
अंधराठाढ़ी



# दिव्यांग अब हर क्षेत्र में आगे, करें प्रेरित

समय के साथ दिव्यांगों के प्रति लोगों को मानसिकता बदलनी होगी। अब दिव्यांग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें समय-समय पर प्रोत्साहित करने की जरूरत है। जागरूकता के अभाव में अधिकतर दिव्यांग सरकारी सेवा का लाभ नहीं ले पाते हैं। दिव्यांगों को सरकार की हर योजना का लाभ देना है।



**350**

से अधिक दिव्यांगजनों ने जागरूकता शिविर में लिया हिस्सा



प्रत्येक 15 दिनों पर पंचायत स्तर के दिव्यांग समूह का होगा बैठक



प्रखंड स्तरीय दिव्यांग समूह की बैठक हर महीने



दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता



■ अपने अधिकारों की जानकारी लेने बैठक में पहुंचे दिव्यांगजन।

इसके लिए दिव्यांग अधिकार अधिनियम कानून भी बनाया गया है। समय के साथ दिव्यांगों के प्रति लोगों को मानसिकता बदलनी होगी। अब दिव्यांग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें समय-समय पर प्रोत्साहित करने की जरूरत है। जागरूकता के अभाव में अधिकतर दिव्यांग सरकारी सेवा का लाभ नहीं ले पाते हैं। दिव्यांगों को सरकार की हर योजना का लाभ देना है। साथ ही इन लोगों की समस्याओं को तत्काल प्रभाव से निपटाया जायेगा। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। खजौली प्रखंड पहुंचे आयुक्त ने कहा कि पंचायत स्तर पर प्रत्येक 15 दिन पर दिव्यांग समूह का बैठक आयोजित कराना है। प्रखंडस्तर पर प्रत्येक माह समूह की बैठक होगी। इस समूह में 18 से 40 वर्ष तक पढ़े लिखे दिव्यांगों को रखा जायेगा। वहीं सभी दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ने के लिए मनरेगा का जॉब कार्ड बनाया जायेगा।

अं

धराठाढ़ी प्रखंड परिसर स्थित टीपीसी भवन में दिव्यांगों के जागरूकता एवं उन्नयन को लेकर बैठक हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर इसका लाभ उठाने के लिए दिव्यांगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। सरकार की प्राथमिकता दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ना है।

दिव्यांग अब हर क्षेत्र में आगे, करें प्रेरित

राज्य निराश्रित आयुक्त ने दिव्यांगों के जागरूकता व उन्नयन को लेकर की बैठक



14 | नवंबर | 2019



**चलंत न्यायालय**

**फुलपरास**

**अनुमंडल**



आयुक्त ने बताया कि जब तक सभी दिव्यांगों की जांच व प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा। तब तक शिविर में कार्य किया जायेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शीघ्र ही अनुमंडल दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग फुलपरास का कार्यालय बुनियाद केंद्र में स्थापित की जाएगी।

■ फुलपरास में दिव्यांगजनों की आवेदन भरने के लिये उमड़ी गीड़।

3252 दिव्यांगों ने चलंत न्यायालय में दर्ज करायी शिकायत

786 दिव्यांगों को आन द स्पॉट दिया गया प्रमाणपत्र

1200 दिव्यांगता पेंशन के मामले को किया गया निष्पादित

140 दिव्यांगों ने उपकरण के लिए किया आवेदन, हुआ निष्पादन

**स**

फुलपरास प्रखंड कार्यालय में नवनिर्मित बुनियाद केंद्र में चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया। अनुमंडल दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग फुलपरास द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने किया। मौके पर आयुक्त ने कहा कि अनुमंडल में अभी तक दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ नहीं हो सका है। सभी विभागों के पदाधिकारी इस पर ध्यान दें तो इस अनुमंडल में प्रत्येक दिव्यांगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है।

आयुक्त ने बताया कि जब तक सभी दिव्यांगों की जांच व

प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा। तब तक शिविर में कार्य किया जायेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शीघ्र ही अनुमंडल दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग फुलपरास का कार्यालय बुनियाद केंद्र में स्थापित की जाएगी।

चलंत न्यायालय में लगभग 3252 दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन हुआ एवं उनके शिकायत पर राज्य आयुक्त का आदेश हुआ। न्यायालय में अधिकांश लोग दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए आये थे। साथ ही रोजगार, कृषि, शिक्षा आदि की भी शिकायत दर्ज की गयी। न्यायालय में दिव्यांगता प्रमाणपत्र संबंधित 786 मामले का निष्पादन किया

गया। दिव्यांगता पेंशन के 1200 मामले निष्पादित किये गये। 140 दिव्यांग उपकरण के मामले को आन द स्पॉट निष्पादित किये गये। 40 मामले दिव्यांग को प्रताड़ित करने का निष्पादन हुआ। भूमि से संबंधित 20 मामले का निष्पादन हुआ, 128 मुद्रा लोन के मामले निष्पादित हुए, खेलकूद से संबंधित 12 मामले निष्पादित हुए, राशन कार्ड से संबंधित 160 आवेदनों को निष्पादित किया गया। शिक्षा संबंधित 140 मामले निष्पादित हुए एवं कृषि एवं पशुपालन से संबंधित 60 मामले निष्पादित हुए, 52 मामले रेलवे टिकट में रियायत के लिए निष्पादित किये गये।

3252 दिव्यांगों का हुआ रजिस्ट्रेशन, न्यायालय में दिव्यांग प्रमाण पत्र के अफिकेता मामले आर

**चलंत न्यायालय में दिव्यांगता प्रमाण पत्र संबंधित 13 सौ मामले का हुआ निष्पादन**



160 मामले राशन कार्ड के निष्पादित किये गये

128 मामले मुद्रा लोन के आये, जिन पर तत्काल विचार किया गया





15 | नवंबर | 2019



**चलंत  
न्यायालय**

**बेनीपट्टी**

**अनुमंडल**



कई जगहों पर दिव्यांगजनों से आवेदन भरने के नाम पर अवैध उगाही किये जाने के मामले सामने आ चुके हैं।  
**इसलिए आप सतर्क रहें और अपना आवेदन खुद भरें। केवल आधारकार्ड या पहचान पत्र के आधार पर ही दिव्यांगों का पंजीकरण और जांच किया जा सकता है**

■ बेनीपट्टी में दिव्यांगजनों की आवेदन भरने के लिये उमड़ी मीड़।

**बे**

नीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित बुनियाद केंद्र में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों के लिए चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया।

इस दौरान आयुक्त ने दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों की सभी प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें निबंधन, अस्थि दिव्यांगता, मूक बधिर जांच, नेत्र दिव्यांगता जांच और बहू निःशक्त जांच सहित कुल 60 स्टॉल लगाकर दिव्यांगजनों की

समस्याएं सुनी जा रही है और सभी का शीघ्र निष्पादन करने का भी प्रयास किया जायेगा। उन्होंने दिव्यांगों को कहा कि आवेदन जमा करने या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के मामले में कोई भी दिव्यांग किसी भी बिचौलियों के फेर में नहीं पड़े। कई जगहों पर दिव्यांगजनों से आवेदन भरने के नाम पर अवैध उगाही किये जाने के मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए आप सतर्क रहें और अपना आवेदन खुद भरें। केवल आधारकार्ड या पहचान पत्र के आधार पर ही दिव्यांगों का पंजीकरण और जांच किया जा सकता है और जबतक सभी

दिव्यांगों की जांच नहीं होगी तब तक अदालत चलती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांगों के जीवन स्तर बेहतर और सशक्तिकरण करने को सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

चलंत न्यायालय में करीब 5000 हजार दिव्यांगों ने अपनी शिकायतें दर्ज करायीं। इसमें से दिव्यांग प्रमाणपत्र के 856 मामले का निष्पादन किया गया। रेलवे रियायत से संबंधित 124, दिव्यांग पेंशन योजना के 856, भूमि विवाद एवं आवंटन के 38, मुद्रा लोन के 78, आवास के 164, राशन कार्ड के 186, ड्राइविंग लाइसेंस के 26, छात्रवृत्ति के 464, कृषि एवं पशुपालन के 192, दिव्यांग उत्पीड़न के 16 मामले का निष्पादन किया गया। दिव्यांगों को प्रमाणपत्र देने के लिए 12 डॉक्टरों की टीम लगी हुई थी।

5000 से अधिक आवेदन आये चलंत लोक अदालत में

856 दिव्यांगों को ऑन द स्पॉट मिला प्रमाणपत्र

856 दिव्यांग पेंशन मामले का हुआ निपटारा

464 दिव्यांगों के छात्रवृत्ति संबंधित शिकायत का हुआ निष्पादन



192

कृषि एवं पशुपालन संबंधित मामले का हुआ निपटारा



16 | नवंबर | 2019



## सभी को मिले समय पर न्याय



13000

से अधिक मामले चलंत न्यायालय के माध्यम से बीते दो वर्षों में निष्पादित किया गया

स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच जागरूकता से न्यायालय पर कम बोझ

न्याय मित्र और पैरा लीगल वोलेंटियर निभा सकते हैं अहम भूमिका

शिवाजी ने बताया कि चलंत लोक अदालत के माध्यम से पिछले दो वर्षों में एक लाख 30 हजार से ज्यादा मामले को स्थानीय स्तर पर निपटाया जा सका है। लोक अदालत एवं स्थानीय स्तर के न्यायिक प्रक्रिया, ग्रामीण स्तर पर पंचों की भूमिका, प्रखंड स्तर पर बीडीओ की भूमिका, अनुमंडल स्तर पर हमारे अनुमंडलाधिकारी की भूमिका न्यायिक मामले में नकारा नहीं जा सकता है।

बदलाव नहीं होगा, तो फैसला मिल सकता है, न्याय नहीं : जस्टिस राजेंद्र



इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पटना कॉलेज के प्राचार्य प्रो. डॉ. मोहम्मद शरीफ ने कहा कि समाज में शांति पूर्णतः बहाल है। इसका मतलब है कि लोगों को न्याय मिल रहा है। सेमिनार में कई लोगों ने अपने

विचार रखे। इस सेमिनार में विषय पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। जिसमें ईशा, शिराया, अनुराधा, साकेत, राहुल, रवि झा समेत अन्य लोगों को पुरस्कृत किया गया।



■ प्रेमचंद्र रंगशाला में आयोजित कार्यक्रम में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार व अन्य।

ज

स्टिस राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि देश के न्यायपालिका के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान न्यायिक व्यवस्था ही है। क्योंकि यह न्याय व्यवस्था अंग्रेजों की बनायी हुई है। अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के अनुकूल न्याय व्यवस्था का गठन करना तथा वर्तमान मानसिक परिवेश के अनुकूल कानून में परिवर्तन लाना भी चुनौती है। जब तक न्याय व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तब तक फैसला तो मिल सकता है, लेकिन न्याय नहीं। जस्टिस प्रसाद जस्टिस फॉर सोसाइटी के तत्वावधान में पांचवें राष्ट्रीय सेमिनार में न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियों के विषय पर बोल रहे थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि न्यायपालिका को समाज के अनुकूल सशक्त करने की आवश्यकता है।

शिवाजी ने बताया कि चलंत लोक अदालत के माध्यम से पिछले दो वर्षों में एक लाख 30 हजार से ज्यादा मामले को स्थानीय स्तर पर निपटाया जा सका है। लोक अदालत एवं स्थानीय स्तर के न्यायिक प्रक्रिया, ग्रामीण स्तर पर पंचों की भूमिका, प्रखंड स्तर पर बीडीओ की भूमिका, अनुमंडल स्तर पर हमारे अनुमंडलाधिकारी की भूमिका न्यायिक मामले में नकारा नहीं जा सकता है। अगर यहां सही कार्य कर मामले को निपटाने का प्रयास किया जाये और लोगों को इसकी जानकारी दी जाये तो, न्यायालय का भार कुछ कम हो जायेगा। इसमें न्याय मित्र और पैरा लीगल वोलेंटियर अहम भूमिका निभा सकते हैं।

इस विषय पर लिखने वाले हुए पुरस्कृत



17 | नवंबर | 2019

## दुर्दर्शन बिहार पर लाइव कार्यक्रम



■ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने लाइव टॉक शो करते हुये।

दिव्यांगों को सम्मान देने के साथ समय-समय पर मदद भी करनी चाहिए

जैविक तरीके से खेती करने की करें पहल

जैविक तरीके से उत्पन्न उत्पाद मानव जीवन के लिए सुरक्षित

स

प्रखंड सरैया / मुजफ्फरपुर

रैया प्रखंड के बहिलवारा गोविंद पंचायत के भटौलिया गांव में मुजफ्फरपुर बॉटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट परिसर में संस्थान के नौवें स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार कृषि महोत्सव सह भगवान जानकी स्मृति सम्मान का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, पूर्व कुलपति डॉ गोपालजी त्रिवेदी, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ राजीव कुमार सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

मौके पर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि किसान रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक तरीके से खेती करने की पहल करें। जैविक तरीके से खेती से उत्पन्न उत्पाद मानव जीवन के लिए सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन को सम्मान देने के साथ समय-समय पर उनकी मदद करनी चाहिए। एमबीआरआई के संस्थापक अविनाश जैसे कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से खेत व खलिहानों में हरियाली लौटने लगी है। आरएयू पूषा के पूर्व कुलपति

मौके पर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि किसान रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक तरीके से खेती करने की पहल करें। जैविक तरीके से खेती से उत्पन्न उत्पाद मानव जीवन के लिए सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन को सम्मान देने के साथ समय-समय पर उनकी मदद करनी चाहिए।

प्रदेश में मौसमी व नासपाती खेती उगाई जा सकती है अच्छी फसल : डॉ. गोपालजी



जैविक खेती का उत्पाद मानव जीवन के लिए सुरक्षित : आयुक्त



डॉ. गोपालजी त्रिवेदी ने कहा कि गांव के किसान देश का हृदय हैं। जब गांव विकास करेगा तब देश विकास करेगा। साहित्यकार डॉ संजय पंकज ने कहा कि पहले ऋषि व कृषि संस्कृति थी। अब कुर्सी संस्कृति है। जीवन को बचाना है तो, कृषि को बचाना होगा। मौके पर स्लम बस्ती के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।



19 | नवंबर | 2019



## चार दिवसीय दौरा अरवल जिला

# दिव्यांगों को जागरूक करने की पहल



## प्रखंडों का दौरा

दि

दिव्यांगजनों की समस्या दूर करने के लिए अरवल के नगर भवन में चलंत न्यायालय का आयोजन होगा। 22 नवंबर को चलंत लोक अदालत की सफलता के लिए प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने समाहरणालय में बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग जन परिवार के माध्यम से अपना शिकायत पत्र दाखिल करेंगे। जिस पर सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए कई योजनाओं चलायी जा रही है। इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 2016 में नये कानून बनाये गये थे। उक्त कानून का अनुपालन हो रहा है या नहीं। इसकी भी जानकारी ली जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 20 नवंबर को जिला सभागार, पुलिस सभागार, शिक्षा विभाग, बस स्टैंड आदि जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर आमलोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। 21 नवंबर को जिला परिषद और नगर परिषद के अलावा सदर अस्पताल में बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रखंडों में भी बैठक कर चलंत न्यायालय की सफलता के लिए पहल की जयेगी। उन्होंने सभी दिव्यांगजनों को उनसे संबंधित कई प्रमुख

योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान 2016, मुख्यमंत्री निःशक्तजन रोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना, दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण, दिव्यांगजनों को रोजगार में चार प्रतिशत का आरक्षण, गरीबी निवारण योजनाओं में आरक्षण का लाभ देना है।

इसके अलावा दिव्यांगजनों को अन्य सरकारी अनुदेश में वर्णित अधिकार एवं सुविधाएं मुहैया करना है। दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बर्दाश्त करने के लिए सरकार तरह-तरह की योजनाएं चलाकर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर दिव्यांग बच्चा किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहे तो, उसे निःशुल्क पढ़ायी भी करायी जा रही है। प्राइवेट स्कूलों में उनके कुल फीस का 25 प्रतिशत सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। बैठक के माध्यम से उन्होंने दिव्यांगजनों को अति महत्वपूर्ण बातें विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी विरेद्र कुमार सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

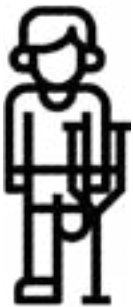
मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत तीन लाख रुपये तक दिये जाते हैं

रोजगार के लिए कम दर पर बैंकों से ऋण देने का है

प्रावधान

दिव्यांगों को निःशुल्क विशेष उपकरण दिये जाते हैं

दिव्यांगजनों को रोजगार में चार प्रतिशत आरक्षण का दिया जाता है लाभ



### दिव्यांगों को उपलब्ध कराई जाएंगी कई सुविधाएं



20 | नवंबर | 2019



जिला  
अरवल



# पदाधिकारियों के साथ बैठक



दि

दिव्यांगजनों के परिवार की सुनवाई के लिए 22 नवंबर को अंबेडकर नगर भवन में चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया है। इसे लेकर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने विभिन्न विभाग की बैठक अलग-अलग जगहों पर की और लोगों से कहा कि जिले में दिव्यांगजनों के लिए जो अधिकार हैं, उस पर अमल करें। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और सभी थानाध्यक्षों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। साथ ही उन्होंने ने निर्देश दिया की अगर कोई भी दिव्यांग अपनी प्रताड़ना की शिकायत करता है तो पुलिस उसपर तुरंत कार्रवाई करे। अगर वह दिव्यांग थाने तक पहुंचने में असमर्थ है तो, पुलिस उसके घर पर जाकर उसका रिपोर्ट लिखेगी और कार्रवाई करेगी।

शिक्षा विभाग में विभिन्न कोचिंग संस्थान व उच्च शिक्षण संस्थान के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। साथ ही निर्देश दिया की दिव्यांग के लिए चिह्नित सुविधाओं का लाभ उन्हें पहुंचाये।

जिले में संचालित बैंक के पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक की। सभी को दिव्यांगजनों के अधिकारों से अवगत कराया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उनसे अवगत करायें। उन्होंने कहा कि चलंत न्यायालय में दिव्यांगजन अपना प्रमाणपत्र सहित तमाम तरह की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। 21 नवंबर को जिला

परषद, नगर परषद, बीआरसीसी, सदर अस्पताल, चलंत न्यायालय के आयोजन स्थल पर बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में 21 प्रकार के दिव्यांगों को शामिल किया गया है।

## समीक्षात्मक बैठक

21 प्रकार के दिव्यांगों को नयी सूची में किया गया है शामिल

निःशक्तजनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार चला रही है योजनाएं

दिव्यांगों को हर हाल में सभी सुविधाएं करायें मुहैया

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने की अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और सभी थानाध्यक्षों के साथ समीक्षात्मक बैठक की।

शिक्षा विभाग में विभिन्न कोचिंग संस्थान व उच्च शिक्षण संस्थान के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। साथ ही निर्देश दिया की दिव्यांग के लिए चिह्नित सुविधाओं का लाभ उन्हें पहुंचाये।





21 नवंबर 2019

# अरवल

## औचक निरीक्षण

दिव्यांगों को मदद के लिए जनप्रतिनिधि आगे आयें

प्रत्येक पंचायत में बनायें दिव्यांगों का समूह

पंचायतस्तर पर बनी कमेटी का हर 15 दिनों पर होगा बैठक



जिसमें जैसे दिव्यांगों को शामिल किया जाये, जो पढ़े लिखे हों और उन्हें सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी हो। इस समूह की बैठक हर 15 दिन पर होगी।

■ वंशी प्रखंड कार्यालय परिसर में सभी पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, विकास मित्रों व अधिकारियों की बैठक।

# रा

वंशी प्रखंड कार्यालय परिसर में सभी पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, विकास मित्रों व अधिकारियों की बैठक हुई। इस मौके पर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगों को सहयोग करने के लिए सभी लोग आगे आयें। दिव्यांगों के विकास के लिए सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलायी जा रही है। इसका लाभ उन्हें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को पेंशन से लेकर अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है। पंचायत प्रतिनिधि इस मामले में सक्रिय भूमिका निभायें। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों के दिव्यांगों की पहचान कर चलंत न्यायालय तक लेकर आयें। उन्होंने कहा कि जिन दिव्यांगों को अब तक प्रमाणपत्र नहीं मिला है या अन्य सुविधाओं के लाभ से वंचित रहे हैं। ऐसे लोगों को लाभ देने के लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है।

उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि पंचायत स्तर पर दिव्यांगों के हितों के लिए एक समूह का गठन किया जाये। जिसमें जैसे दिव्यांगों को शामिल किया जाये, जो पढ़े लिखे हों और उन्हें सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी हो। इस समूह की बैठक हर 15 दिन पर होगी। प्रखंड पदाधिकारियों को राज्य आयुक्त ने प्रखंड स्तर पर एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया। इस कमेटी की बैठक प्रत्येक महीने होगी। इस कमेटी को पंचायत कमेटी अपनी शिकायतों को सौंपेगी।

## दिव्यांगों को सभी लोग करें सहयोग

कठपौती | मित्र संवाददाता

बैठक

वंशी प्रखंड कार्यालय परिसर में गुरुवार को सभी पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, विकास मित्रों व

● पंचायत प्रतिनिधि दिव्यांगों की करें पहचान, योजनाओं का दे लाभ  
● नगर भवन में आयोजित शिद्विर

वहीं वार्ड पार्षदों के साथ बैठक में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगों को हर संभव मदद करने के लिए आप लोग आगे आयें। उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा कई

योजनाएं चलायी जा रही हैं। प्रचार-प्रसार के अभाव में दिव्यांगजन इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए आपलोग उनको इन सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार का सहयोग करें।

दिव्यांगों को हर संभव मदद करें





22 | नवंबर | 2019

# चलंत न्यायालय अरवल

**3051**

से अधिक दिव्यांगजनों ने चलंत न्यायालय में दर्ज करायी शिकायत

**371**

मामला दिव्यांग पेंशन के लिए आये

**300**

मामले मुद्रा लोन संबंधित

**200**

मामले रेलवे रियायत के



■ अरवल जिला में आयोजित चलंत लोक अदालत में आयुक्त को अपनी फरियाद सुनाते दिव्यांगजन।

नगर भवन में आयोजित चलंत लोक अदालत का उद्घाटन निःशक्तता आयुक्त और डीएम रविशंकर चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। निःशक्तता आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों से भेदभाव न बरतें। इन्हें हर संभव सहयोग करें। इनके विकास के लिए अधिकारी भी पूरी दिलचस्पी दिखायें।

दि

व्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार के द्वारा इनके विकास के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही है। इन योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। उक्त बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कही। नगर भवन में आयोजित चलंत लोक अदालत का उद्घाटन निःशक्तता आयुक्त और डीएम रविशंकर चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। निःशक्तता आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों से भेदभाव न बरतें। इन्हें हर संभव सहयोग करें। इनके विकास के लिए अधिकारी भी पूरी दिलचस्पी दिखायें।

इस मौके पर डीएम ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम से दिव्यांगों में जागरूकता आयेगी और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चलंत लोक अदालत में लगभग 3051से अधिक मामले आये। दिव्यांग पेंशन से संबंधित 371, मुद्रा लोन से संबंधित 300, रेलवे रियायत टिकट से संबंधित 200, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित 90 तथा राशन कार्ड से संबंधित 100 से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया। न्यायालय में ऑन द स्पॉट 12 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने दिव्यांगों का प्रमाणपत्र बनाया। लालपुर निवासी जीतेंद्र कुमार ने बताया कि यह अच्छी पहल है। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अन्य मामलों को एक महीने के अंदर निष्पादित करें। साथ ही आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिना भेदभाव के दिव्यांगजनों की मदद करें।

## दिव्यांगों को सुविधा देने को सरकार संकल्पित

चलंत लोक अदालत का आयोजन, निराश्रित आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार व डीएम ने किया उद्घाटन



आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगों से भेदभाव न बरतें। इन्हें हर संभव सहयोग करें। इनके विकास के लिए अधिकारी भी पूरी दिलचस्पी दिखायें।

100 से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया।

न्यायालय में ऑन द स्पॉट 12 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने दिव्यांगों का प्रमाणपत्र बनाया।



28 | नवंबर | 2019



**दरभंगा  
कार्यशाला**



# दिव्यांगों के हितों की रक्षा करने के मामले में बिहार देश में अक्वल

रोचक प्रश्नोत्तर सत्र में साधनसेवी ने प्रतिभागियों की शंकाओं का संतोषजनक जवाब देकर उन्हें संतुष्ट किया। इस अवसर पर डॉ. अनुपम कुमार सिंह, डॉ. अभिलाषा कुमारी, प्रो रागिनी रंजन, डॉ. पुनीता कुमारी, डॉ. मीनाक्षी कुमारी व अन्य मौजूद थे।



**2005**

से ही इंटरनेशनल खिलाड़ियों को नौकरी दे रही है।

■ यहां दिव्यांगों के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू है।



■ आयुक्त ने प्रतिनिधियों के साथ की बैठक।

इलाज के साथ-साथ उनकी सामाजिक स्वीकार्यता बेहद जरूरी है। हम सबों की नैतिक जिम्मेदारी है कि दिव्यांगजनों को सही इलाज स्थल तक पहुंचाये तथा उन्हें सरकारी सुविधाओं की जानकारी देकर उनका वास्तविक लाभ दिव्यांगों को दिलावाये। उन्होंने कहा कि न्यूटन, मारकोनी, आइंस्टीन, ग्राहम बेल आदि विख्यात वैज्ञानिक भी दिव्यांग थे। विश्व के सर्वाधिक धनाढ्य व्यक्ति बिल गेट्स भी दिव्यांग हैं। दिव्यांगों को भी समाज में पूरे सम्मान के साथ जीने का पूर्ण अधिकार है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां दिव्यांगों के लिए विशेष कोर्ट गठित किये गये हैं। यहां दिव्यांगों के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू है। बिहार सरकार यहां 2005 से ही इंटरनेशनल खिलाड़ियों को नौकरी दे रही है। समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य डॉ. मुश्ताक अहमद ने कहा कि इस कार्यशाला से सामान्य लोगों को भी दिव्यांगजनों के बारे में विस्तृत जानकारी मिली है। तकनीकी सत्र में साधनसेवी के रूप में यूपी कॉलेज, पूसा के मनोविज्ञान विभाग के प्राध्यापक तथा नैदानिक चिकित्सक डॉ. दीपक भारद्वाज ने कहा कि दिव्यांगता किसी भी अवस्था, क्षेत्र, स्थिति में हो सकता है, जिनकी सही पहचान तथा उनकी वास्तविक जरूरत पूरी होनी चाहिए।

**दि**

व्यांगों के अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। दिव्यांगों के हित रक्षा तथा पुनर्वास के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामाजिक, कानूनी, शैक्षणिक तथा आर्थिक व्यवस्था आवश्यक है। ये बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने सीएम कॉलेज में कही। वे कॉलेज के स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग तथा भारतीय स्वास्थ्य, शोध एवं कल्याण संघ, हिसार के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांगों के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप विषयक तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मानसिक दिव्यांगों का समुचित

दिव्यांगों के हितों की रक्षा करने के मामले में बिहार देश में अक्वल





29 | नवंबर | 2019



**राज्यस्तरीय  
कार्यशाला**

**अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग  
सप्ताह कार्यक्रम**



# दिव्यांगजनों का क्षमता संवर्धन जरूरी : आयुक्त

इसके साथ ही उन्होंने चयनित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला स्तरीय दिव्यांगजन समिति में चयनित प्रतिनिधियों के लिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि पंचायत से लेकर जिले तक आम से खास दिव्यांगों को उनके एक-एक अधिकारों को जन-जन तक पहुंचाया जाये।



**38**

जिलों के दिव्यांग प्रतिनिधियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया।



■ आयुक्त ने प्रतिनिधियों के साथ की बैठक।

सुपौल, वैशाली और पश्चिम चंपारण के कुल 19 जिलों के दिव्यांग प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस तरह दो दिनों के कार्यशाला में बिहार के कुल 38 जिलों के दिव्यांग प्रतिनिधियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। विदित हो कि राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन एक पखवाड़ा तक किया जा रहा है। यह पखवाड़ा 29 नवंबर से शुरू हो कर 13 दिसंबर तक चलेगा। इसी पखवाड़ा के तहत पंचायत से लेकर जिला स्तर पर दिव्यांगजनों की पहचान एवं क्षमता संवर्धन के लिए राज्य भर में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। पटना में आयोजित इस कार्यशाला में हर जिले से दिव्यांग प्रतिनिधियों को मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया गया है।

यही मास्टर ट्रेनर अपने जिले और जिले के पंचायतों में दिव्यांगों को प्रशिक्षित करेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार द्वारा मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित करते हुए कहा गया कि वह इस प्रशिक्षण का उपयोग अपने क्षेत्र के दिव्यांगजनों के हित में करें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पंचायत स्तर पर भी दिव्यांगजनों के अधिकारों व हक के बारे में जन जागरूकता लाने का काम आज से शुरू किया जाये।

**रा**ज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) कार्यालय, बिहार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के पूर्व राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। दो दिवसीय इस कार्यशाला का उद्देश्य दिव्यांगजन की क्षमता संवर्धन है। ज्ञातव्य है कि इस कार्यशाला में बिहार के विभिन्न जिलों से आये प्रखंडस्तरीय दिव्यांगजन समिति व जिला स्तरीय दिव्यांगजन समिति व जिला स्तरीय दिव्यांगजन समिति के चयनित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यशाला के अंतिम दिन मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान,

**सूबे के दिव्यांगजनों को  
किया जाएगा जागरूक**

कार्यशाला

दिव्यांगजन समिति के प्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए कि वे आम दिव्यांगजनों को उनका हक और

पटना | दिव्यांग जन



क्र०सं०	वाद सं०	जिला	वादी एवं प्रतिवादी	विषय
53.	53/2019	बक्सर	वादी :- श्री सोना लाल वर्मा, पिता-श्री भगवान प्रसाद वर्मा, बक्सर प्रतिवादी :- सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना	प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के संबंध में
54.	54/2019	अरवल	वादी :- मो० फिरदौस अख्तर, पिता-मो० सम्मी अख्तर, अरवल। प्रतिवादी :- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अरवल	लगड़ा कह कर प्रताड़ित करने एवं अपमानित करने के संबंध में
55.	55/2019	भागलपुर	वादी :- श्री परमानन्द चौधरी पुत्र श्री मोहन चौधरी, भागलपुर प्रतिवादी :- आरक्षी अधीक्षक, भागलपुर, बिहार करने के संबंध में	दो लाख रूपया रंगदारी माँगने, मार-पीट करने तथा अन्य तरह से प्रताड़ित
56.	56/2019	नालंदा	वादी :- श्री अतुल्या दीपक कुमार, नालंदा प्रतिवादी :- सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना	ए०एन०एम० (ANM) पद के लिए प्रकाशित अनुशासित अभ्यर्थियों की त्रुटीपूर्ण के संबंध में
57.	57/2019	मधेपुरा	वादी :- श्री गौतम कुमार गंभीर, पिता-श्री कुमार जयकृष्ण प्रसाद, मधेपुरा प्रतिवादी :- सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा एवं अन्य	दिव्यांगता पेंशन राशि के भुगतान के संबंध में
58.	58/2019	सीतामढ़ी	वादी :- श्रीमती शीला कुमारी, पत्नी श्री अवधेश नायक, सीतामढ़ी प्रतिवादी :- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस, सीतामढ़ी, बिहार	अवैध रूप से सेविका की नियुक्ति के संबंध में
59.	59/2019	नालंदा	वादी :- श्री सुदर्शन कुमार, जिला-नालंदा। प्रतिवादी :- सिविल सर्जन, नालंदा, बिहार	दिव्यांगता प्रतिशत कम करने के संबंध में।
60.	60/2019	मुजफ्फरपुर	वादी :- श्रीमती राधा साह, पति-श्री अनिल कुमार, मुजफ्फरपुर प्रतिवादी :- अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिम अनुमंडल मुजफ्फरपुर एवं अन्य	जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति से वंचित किये जाने संबंध में
61.	61/2019	वैशाली	वादी :- श्री लाल बाबु राय, पिता- श्री कपिलदेव राय, वैशाली। प्रतिवादी :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली एवं अन्य	40 प्रतिशत दिव्यांग को आरक्षित पद पर नियुक्त के संबंध में
62.	62/2019	मधुबनी	वादी :- श्री हरिबोल यादव, मधुबनी। प्रतिवादी :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधुबनी।	दिव्यांग पेंशन स्वीकृती हेतु।
62.	63/2019	रोहतास	वादी :- श्री संदीप कुमार सिंह, रोहतास (सासाराम)। प्रतिवादी :- परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन राष्ट्रभाषा परिषद, सैदपुर, पटना (बिहार)	प्रखण्ड साधन सेवी (समावेशी शिक्षा) को उच्च स्तरीय कमिटी की सेवा सुविधा प्रदान करने के संबंध में
64.	64/2019	पटना	वादी :- श्री मुकेश कुमार सिन्हा, पटना प्रतिवादी :- सचिव, जगमणी पैलेस अपार्टमेंट, शक्ति नगर, खोजा इमली, अनिसाबाद, पटना	मारपीट एवं दुर्व्यवहार करने के संबंध में



DECEMBER 2019

# दिसंबर 2019



## विकास निगम द्वारा स्वरोजगार के लिए कम दर पर मिलता ऋण

टेढ़ागाछ प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार भवन में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने जनप्रतिनिधियों एवं दिव्यांगजनों के साथ बैठक की। बैठक कर उन्होंने विभिन्न दिव्यांगता के प्रकार की जानकारी देते हुए शत प्रतिशत निःशक्तता प्रमाणपत्र बनाने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को दी जाने वाली लाभ की जानकारी दी।

pg-138



### राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग दिवस कार्यक्रम

pg-126



### पाक्षिक दिव्यांगता दिवस कार्यक्रम

pg-127



### दो सप्ताह तक अलग-अलग...

pg-128



### दिव्यांगजन जागरूकता कार्यक्रम

pg-130



### ऑन द स्पॉट बनायें दिव्यांगता प्रमाणपत्र

pg-131



### पंचायत स्तर पर ऑन द स्पॉट निरीक्षण

pg-139





03 | दिसंबर | 2019

## राज्यस्तरीय कार्यशाला

करने के पूर्व राज्य निःशक्तता के कार्यालय में निबंधन कराना होगा। वहीं 20 कर्मिकों वाले निजी संस्थान को एक दिव्यांग को नियुक्त करना होगा। संस्थान को वेबसाइट पर समान अवसर नीति का प्रदर्शन करना होगा।

आयुक्त ने कहा कि निजी संस्थानों द्वारा दिव्यांगजन समान अवसर नीति का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। संस्थान का निबंधन संबंधित विभागों के द्वारा रद्द किये जाने की अनुशंसा की जा सकती है। मौके पर मौजूद अपर आयुक्त निःशक्तता शंभु कुमार रजक ने बताया कि इस नीति का पहले प्रचार-प्रसार किया जायेगा ताकि निजी क्षेत्र के संस्थान दिव्यांगजनों के अधिकार के प्रति जागरूक हो सकें।



रा

ज्य के निजी संस्थानों में दिव्यांगजनों की पांच फीसदी नियुक्ति अनिवार्य हो गयी है। जिस निजी संस्थान में 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, वहां पांच फीसदी दिव्यांगजनों की नियुक्ति करनी होगी। उनको सामान्य व्यक्तियों की तरह समान सुविधाओं प्रदान करनी होगी। निजी संस्थानों में कंपनी, फार्मा, सहकारी या अन्य सोसायटी, संगम, न्यास, अभिकरण, संस्था, संगठन, संघ, कारखाना सभी शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने निजी स्थापना के लिए दिव्यांगजन समान अवसर नीति जारी कर दी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 21 (1) के अनुसार प्रत्येक स्थापना में समान अवसर नीति को लागू किया जाना अनिवार्य है। इसी के तहत केंद्र ने दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 जारी की है, जिसके नियम-8 के तहत समान अवसर के प्रकाशन की नीति का प्रवाधान किया गया है। डॉ. शिवाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि निजी संस्थानों को दिव्यांगजन समान अवसर नीति के पालन



55

हजार दिव्यांग शामिल हुये 38 जिलों में



■ आयुक्त ने प्रतिनिधियों के बातचीत करते।



234

सेमिनार में थे शामिल



234

लोग सीधे जुड़े कार्यक्रम से



08

हजार लोग जानें मीडिया से



## अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस

दिव्यांगजन समान अवसर नीति का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। संस्थान का निबंधन संबंधित विभागों के द्वारा रद्द किये जाने की अनुशंसा की जा सकती है। **मौके पर मौजूद अपर आयुक्त निःशक्तता शंभु कुमार रजक ने बताया कि इस नीति का पहले प्रचार-प्रसार किया जायेगा ताकि निजी क्षेत्र के संस्थान दिव्यांगजनों के अधिकार के प्रति जागरूक हो सकें।**

## सभी दिव्यांगों को मिलेगा सरकारी सुविधा का लाभ

बिहार सरकार जिलों में जन जागरूकता अभियान चला कर दिव्यांगों को जागरूक कर रही है। सरकार का लक्ष्य है की दिव्यांग इस योजना से वंचित न रहें। उक्त बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहीं। वह विश्व दिव्यांग दिवस जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में उन्होंने स्वीकार किया कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ऐसे दिव्यांग हैं। जिन्हें सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी नहीं है। इसको लेकर दिव्यांगों को जागरूक करना होगा। हर एक पंचायत, प्रखंड और जिलों में दिव्यांग दिवस पर आमसभा कर उन्हें जागरूक किया जाये। उसके लिए जनसंपर्क अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाना चाहिए।





07 | दिसंबर | 2019

## 86वीं पूर्वी क्षेत्रीय अभिभावक सम्मेलन



टलिपुत्र पैरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड एवं संभव मधुबनी के संयुक्त तत्वावधान में विश्व दिव्यांग जागरूकता पखवारा के तहत दो दिवसीय 86वीं पूर्वी क्षेत्रीय अभिभावक सम्मेलन का शुभारंभ आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह, राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने कहा कि इस तरह के सम्मेलन से बौद्धिक अक्षम बच्चों के अभिभावकों को नयी ऊर्जा मिलेगी। आशा की नयी किरण खिलेगी। राज्य के दिव्यांगों के कल्याण के लिए नीतीश सरकार पूरी तरह संवेदनशील रहते हुए कार्य कर रही है। दिव्यांगों के विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उनके विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा चुका है। आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने कहा कि दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए उनके परिजनों को सजग रहने की जरूरत है। दिव्यांगों के लिए निर्धारित योजनाओं के लाभ के लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों को जागरूक होना होगा। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि बौद्धिक दिव्यांग, ऑटिज्म, सेरिब्रल

**समाज कल्याण माननीय मंत्री श्री रामसेवक सिंह द्वारा किया गया उद्घाटन।**

पाल्सी बच्चों के लिए सरकार कार्य कर रही है। जरूरत है अभिभावकों को जागरूक होने की। सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव में दिव्यांग सरकारी लाभ से वंचित हो जाते हैं। राज्य के दिव्यांगजनों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सम्मेलन में एनआइएपीआईडी अध्यक्ष श्रीरंग बिजूर, क्षेत्रीय निदेशक डॉ. हेमंत केशवाल, डॉ. राजीव गंगौल, झारखंड

पैरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष दीपा चौधरी, संदीप कुमार व अन्य मौजूद थे। इस कार्यक्रम में बौद्धिक दिव्यांग, ऑटिज्म सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों का शिक्षण-प्रशिक्षण व्यवसायिक परीक्षण, सामाजिक परिवेश, लिविंग विथ डिग्नटी, सेल्फ एडवोकेसी की जानकारी दी गयी।

**200** से अधिक मानसिक दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा

**4000** से अधिक लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े



दिव्यांग बच्चों को सरकारी लाभ मिले, इसके लिए अभिभावक को रहना होगा जागरूक

सरकार विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के लिए कई योजनाओं पर कर रही है कार्य



12 | दिसंबर | 2019



# समाजिक आंकेक्षण

## एक साल में चलंत कोर्ट में दिव्यांगों के 59694 मामले

दिव्यांगता प्रमाणपत्र	27365*
दिव्यांग पेंशन	9498 *निबटाये गये केसों की
पुनर्वास	719
उपकरण संबंधित	3218
ड्राइविंग लाइसेंस	1511
खेलकूद संबंधित	199
राशन कार्ड	3781
रेलवे रियायत	6087
पीएम मुद्रा ऋण	2169
शिक्षा ऋण	669



■ आयुक्त ने दिव्यांगजनों के साथ की थी बैठक।



राज्य निःशक्तता आयुक्त के कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 20 जिलों में 23 चलंत न्यायालय लगाया गया। जहां उन दिव्यांगजनों के वैसे मामलों को सुना गया, जिसे संबंधित विभाग ने सुनने से इन्कार कर दिया था। अधिकारियों के मुताबिक कोर्ट में सबसे अधिक शिकायत दिव्यांगता प्रमाणपत्र अस्तपतालियों में नहीं बनाने को लेकर आया था। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी

कुमार ने कहा दिव्यांगों के शिकायत पर सभी सिविल सर्जन को निर्देश भेजा गया है कि दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने में लापरवाही नहीं करें। अगर वह अपने कार्यशैली में सुधार नहीं लाते हैं, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चलंत न्यायालय में दिव्यांगजनों के शिकायतों का निपटारा तुरंत किया जाता है। सबसे अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने का मामला था। इस संबंध में पूर्व में भी सभी सिविल सर्जन को दिशा निर्देश भेजा गया है। अब कार्रवाई के लिए विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

### चलंत कोर्ट में दिव्यांगों के 59,694 मामले निबटे

संवाददस्ता	पटना	इन शिकायतों का निबटा
राज्य आयुक्त निःशक्तता दिव्यांगजन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 20 जिलों में 23 चलंत न्यायालय लगाया गया, जहां उन दिव्यांगजनों के वैसे मामलों को सुना गया, जिसे संबंधित विभाग ने सुनने से इन्कार कर दिया था।	दिव्यांगता प्रमाणपत्र दिव्यांग पेंशन पुनर्वास उपकरण संबंधित ड्राइविंग लाइसेंस खेलकूद संबंधित राशन कार्ड रेलवे कनेक्शन	27,365 9,498 719 3,218 1,511 199 3,781 6,087 2169



14 | दिसंबर | 2019

## दो सप्ताह तक अलग-अलग हिस्सों में दिव्यांग दिवस मनाया गया

स

रकारों और समाज की जिम्मेवारी बनती है उन्हें बराबरी के मौके उपलब्ध कराने की। राज्य आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि सरकार चाहती है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। दिव्यांगों के लिए एक नया कानून आया है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। कहा कि पहले दिव्यांगों की श्रेणी सात थी लेकिन अब यह इक्कीस हो गई है। इसमें चलंत संबंधी दिव्यांगता, मांसपेशीय दुर्विकार, ठीक किया हुआ कुष्ठ, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण क्षति, सुनने में कठिनाई, वाक और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मानसिक रूग्णता, क्रानिक स्त्रायविक स्थिति, बहुल काठिन्य, पार्किन्सन रोग, हीमोफीलिया, थैलसीमिया तथा सिकल सेल रोग को शामिल किया गया है। अगर कोई व्यक्ति 40 प्रतिशत दिव्यांग है तो वह केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकता है। लेकिन अगर उससे कम प्रतिशत दिव्यांग है और उसके आवेदन को चिकित्सक निरस्त कर रहे हैं तो उसे उसका कारण भी बताना

होगा। अन्यथा उस चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कहा कि दिव्यांगों कई योजनाएं हैं जिनमें मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना 2016, मुख्यमंत्री निःशक्त जन स्वरोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना- दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण, मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना- विकलांगजनों का सर्वेक्षण एवं प्रमाणीकरण शामिल है। 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए समुचित वातावरण एवं मुफ्त शिक्षा, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण, गरीबी निवारण योजनाओं में आरक्षण, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 व संबंधित नियमावलियों में कार्यकारी आदेशों व अन्य सरकारी अनुदेशों में दिव्यांगों के लिए वर्णित अधिकार व सुविधाएं तथा दिव्यांगता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव संबंधित मामले की सुनवाई की जाएगी। वहां 42 सौ दिव्यांगजन का ऑर्डर पास करना पड़ा। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी दिव्यांगों का सर्टिफिकेट बनाने का कार्य पूरा कर लिया जाय अन्यथा कार्रवाई होगी। अगर कोई चिकित्सक किसी दिव्यांगजन को बाहर रेफर करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। दिव्यांगों की शिकायत सुनने के लिए एक टोल फ्री नंबर चालू किया गया। इस नंबर पर कोई भी दिव्यांगजन अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. उमाशंकर सिन्हा द्वारा किया गया।



दो सप्ताह तक अलग-अलग हिस्सों में दिव्यांग दिवस मनाया गया



■ आस्था चैरिटेबल संस्था के द्वारा सम्मानन समारोह का आयोजन



■ आयुक्त ने दिव्यांगजनों से मुलाकात करते हुये।

सभी दिव्यांगों का सर्टिफिकेट बनाने का कार्य पूरा कर लिया जाय अन्यथा कार्रवाई होगी। अगर कोई चिकित्सक किसी दिव्यांगजन को बाहर रेफर करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। दिव्यांगों की शिकायत सुनने के लिए एक टोल फ्री नंबर चालू किया गया। इस नंबर पर कोई भी दिव्यांगजन अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।



250

दिव्यांग शामिल हुये



1000

अभिभावक हुये जाकरूक



6243

लोग सीधे जुड़े कार्यक्रम से



15 हजार

लोग जानें मीडिया से





17 | दिसंबर | 2019

## चलंत न्यायालय कटिहार



■ आयुक्त ने प्रतिनिधियों के साथ की बैठक।



# 21

श्रेणी में रखा गया है दिव्यांगों को

# दि

व्यांग समुदाये को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार की कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। जागरूकता के अभाव में दिव्यांगजन उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। यहीं वजह है कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से दिव्यांगजनों

को जागरूक करते हुए उसे लाभान्वित करने की कोशिश शुरू की गयी है। चार दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने विभिन्न प्रखंडों का दौरा करने के बाद समाहरणालय के सभाकक्ष में संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब कुल 21 श्रेणी के दिव्यांग हैं। सभी श्रेणी के दिव्यांगों को कानून एवं योजना के मुताबिक लाभ दिया जाना है। उन्होंने कहा कि पहली बार बिहार में दिव्यांगजनों के लिए चलंत अदालत लगाया जा रहा है। अब तक 33 जिले में चलंत अदालत लगाया जा चुका है। आगामी 20 दिसंबर को कटिहार में चलंत अदालत लगाया जायेगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली

## प्रखंडों का दौरा

2017 के तहत दिव्यांगजनों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। अधिनियम व नियमावली के तहत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों तक पहुंचाने के लिए अब मिशन मोड में अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर दिव्यांगों को पेंशन की समस्या या उसके बारे में ही जानकारी होती है। जबकि दिव्यांग अधिकार को लेकर अब कानून बन चुका है। बिहार सरकार नियमावली भी बना दी है। ऐसे में उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य के 534 प्रखंडों में इस बार तीन दिसंबर

## निर्देश • ब्लॉक में निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कभी दिव्यांग समूह की बैठक बरारी ब्लॉक में दिव्यांगों के लिए आयुक्त ने कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी



को दिव्यांगों के लिए मनरेगा योजना के तहत प्रखंड स्तर पर कैंप लगाया गया। करीब एक लाख दिव्यांगों का जॉब कार्ड बनाया गया। उन्होंने बताया कि सरकारी सेवाओं में दिव्यांगजनों को चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दी गयी है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर अर्थात मॉल, निजी स्कूल, कॉलेज सहित निजी क्षेत्र के सभी तरह के प्रतिष्ठान व उपक्रम में दिव्यांगों को आरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन को लेकर दिव्यांगों के बीच कई तरह की प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी है। कौशल विकास एवं रोजगार के प्रावधान को लेकर सरकारी की कई योजनाएं चल रही है।





18 | दिसंबर | 2019



चलंत  
न्यायालय / कटिहार



# उचित प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया राज्य आयुक्त ने

राज्य आयुक्त ने स्टेशन पर दिव्यांगों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर भी बातचीत की। राज्य आयुक्त ने शहर के मॉल एवं बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान के संचालक से भी दिव्यांगों को मिल रही सुविधा की जानकारी ली। इस मौके पर सदर एसडीओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

**40%**

अधिक दिव्यांगता होने पर ही बनाये स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र

सार्वजनिक स्थलों/ भवनों का एक्सेस ऑडिट

सुगम्य भारत अभियान



■ आयुक्त ने प्रतिनिधियों के साथ की बैठक करते हुये।

किये हैं उनके खिलाफ अभियान चलाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुष्ठ शताब्दी पेंशन योजना के तहत भी 1500 रुपये दिये जाते हैं। राज्य निःशक्तता आयुक्त ने बैठक में पुलिस अधीक्षक और थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि थाना में दिव्यांगजनों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। उन्होंने बैंक के पदाधिकारियों एवं कोचिंग संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। डंडखोरा प्रखंड पहुंचे राज्य निःशक्तता आयुक्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुपालन को लेकर बैठक की। राज्य निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार ने प्रखंड क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा की। सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों तक शत प्रतिशत पहुंचाने के लिए उन्होंने बीडीओ और सीओ को निर्देश दिया। साथ ही कहा कि प्रत्येक दिव्यांग को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य दें। प्रत्येक पंचायत में दिव्यांगों के समूह का गठन करायें।

**प**

हले केवल सात प्रकार के दिव्यांगजनों के कैटेगरी का प्रावधान था। अब दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार के प्रावधान किये गये हैं। जिसमें हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल रोग पार्किन्सन रोग आदि शामिल हैं। सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत एवं गैर सरकारी नौकरी में पांच प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। उक्त बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में कहीं। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता की स्थिति में ही स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनावें। 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता का प्रमाणपत्र पर जो गलत तरीके से नौकरी प्राप्त

राज्य आयुक्त ने रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगों को मिल रही सुविधा का जायजा लिया। स्टेशन के रैंप का भी जायजा लिया। राज्य आयुक्त ने टिकट काउंटर पर पहुंचकर वहां मौजूद दिव्यांगों से होने वाली असुविधा की जानकारी ली।



19 | दिसंबर | 2019



## अनुमंडल/प्रखंड/ पंचायत दिव्यांग समूह के साथ बैठक

60

से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने विशेष प्रशिक्षण में लिया हिस्सा

16

प्रखंडों के प्रभारी व जांच टीम ने लिया प्रशिक्षण शिविर में भाग

● दिव्यांगों को प्रमाणपत्र बनाने के लिए बार-बार नहीं लगाना पड़े अस्पताल का चक्कर

# ऑन द स्पॉट बनायें दिव्यांगता प्रमाणपत्र



दर अस्पताल के सभागार में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

मौके पर आयुक्त ने निःशक्तता प्रमाणपत्र बनाने के सभी तकनीकी से अवगत कराया। फार्म भरने के तरीके से लेकर निःशक्तता होने के प्रमुख बीमारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 21 प्रकार की बीमारियां लोगों को हो सकती है। इससे मानसिक व शारीरिक रूप से लोग दिव्यांग हो सकते हैं। इलाज करते समय सभी चिकित्सक इस बात का ख्याल रखें कि इलाज की प्रक्रिया या दवा का उपयोग करने से दिव्यांगता का कारण नहीं बने। साथ ही प्रमाणपत्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि

दिव्यांग लोगों को बार-बार विभाग या डॉक्टर का चक्कर नहीं लगाना पड़े। उन्होंने जिले के सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों से कहा कि दिव्यांगजनों को परेशान नहीं करे। वह दैनिक कार्य अवधि में जिस समय अस्पताल आते हैं। उसी समय उन्हें दिव्यांगता प्रमाणपत्र मिल जाना चाहिए। दिव्यांगता प्रमाणपत्र देने के लिए किसी शिविर का इंतजार नहीं करें तथा विशेष तिथि निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। सभी संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को यह सोचना होगा कि पैर और आंख से दिव्यांग व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचने में कितनी परेशानी होती है। उनके परेशानियों को महसूस कर प्रमाणपत्र निर्गत करें। आयुक्त ने बैठक में सख्त निर्देश दिया कि दिव्यांगों की ओर से मिलने वाली शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

## कटिहार



■ आयुक्त ने सभी दिव्यांगजनों की फरियाद सुनी।

## मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी व जीविका डीपीएम के वेतन पर रोक

निःशक्तता आयुक्त की बैठक में देर से पहुंचने पर कार्रवाई का निर्देश

कटिहार, 19 दिसंबर (संवाद) - राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कटिहार में बैठक की। बैठक में प्रखंड बॉर्डर के निःशक्तता अधिकारी व जांच टीम के सदस्यों ने भाग लिया। आयुक्त ने बैठक में सख्त निर्देश दिया कि दिव्यांगों की ओर से मिलने वाली शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।



20 | दिसंबर | 2019



## चलंत न्यायालय कटिहार

**3052** परिवादों का चलंत अदालत में हुई सुनवाई

**934** से अधिक प्रमाणपत्र बनाने को आये आवेदन

**456** आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए आये

**120** आवेदन रेलवे में दिव्यांगों को मिलने वाली छूट को लेकर आये

# ऑन द स्पॉट निपटारा

**क** टिहार जिले में दिव्यांग चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें 32 काउंटर बनाये गये थे, जिसमें सभी 3052 परिवादों की सुनवाई की गयी। चलंत अदालत के माध्यम से दिव्यांगजनों के प्रमाणपत्र का निर्गमन, 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए समुचित वातावरण एवं मुफ्त शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण, गरीबी निवारण योजनाओं में आरक्षण पर विशेष रूप से चर्चा भी किया गया। मौके पर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि चलंत न्यायालय का आयोजन आगे चलकर प्रखंडस्तर पर भी लगाया जा सकता है। जिससे दिव्यांगजनों की लंबित समस्याओं का निपटारा किया जाये। विभागीय अधिकारी व कर्मि बारी-बारी से आने वाले दिव्यांगों के समस्याओं का समाधान कर रहे थे। मनरेगा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, डीआरडए, डीआरसीसी, बैंक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, राजस्व सहित अन्य विभागों के द्वारा काउंटर

लगाया गया था। जिसमें संबंधित विभाग से पीड़ित दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी गयी। चलंत न्यायालय में दिव्यांगजनों के द्वारा दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाने वाले काउंटर में सबसे अधिक भीड़ लगी रही। डीपीआरओ संजीव कुमार सज्जन ने बताया कि कुल 2650 परिवादों में केवल 934 परिवार दिव्यांग प्रमाणपत्र के लिए आये थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित 456, रेलवे छूट प्रमाणपत्र से संबंधित 120, व्हील चेयर से संबंधित कुल आठ परिवार दर्ज किये गये। इसके अलावा रोजगार, उपकरण सहित अन्य मामलों के भी परिवादों का निपटारा किया गया।

मौके पर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां के दिव्यांगों के समस्या समाधान के लिए सरकार प्रशासन खुद उन तक पहुंच रही है। राज्य सरकार कटिहार ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी दिव्यांगों की समस्या के लिए तत्काल संबंधित अधिकारियों को समाधान का निर्देश दे रही है।



■ आयुक्त ने 1600 मामलों का निपटारा किया।



23 | दिसंबर | 2019



## शिक्षक नियोजन

# न्यायालय ने शिक्षक नियोजन मामले में सुनवाई की

**रा**ज्य निःशक्तता आयुक्त के न्यायालय ने राज्य में होने वाले शिक्षक नियोजन के तहत दिव्यांगजनों के आरक्षण रोस्टर में खामी पाये जाने के बाद इसमें सुधार करने का निर्देश दिया है। साथ ही हर प्रखंड में एक-एक पद पर दिव्यांगों द्वारा आवेदन करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय देने का निर्देश दिया है।

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने न्यायालय ने शिक्षक नियोजन मामले में सुनवाई की। इसमें सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। नालंदा के माहिम राय और सहरसा के शिवशंकर कुमार से प्राप्त शिकायत की सुनवाई की गयी। शिकायतकर्ताओं ने प्रारंभिक शिक्षक नियोजन, 2019-20 में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सभी

जिलों में दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों के लिए अनुमान्य रिक्तियों का स्पष्ट प्रकाशन नहीं किये जाने की शिकायत सक्षम न्यायालय से की थी। सुनवाई के दौरान यह जानकारी मिली कि सभी जिलों में शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन प्राप्त किये जाने को लेकर प्रकाशित विज्ञापन में स्पष्टता एवं एकरूपता का अभाव है। इसके कारण दिव्यांगजनों को आवेदन करने में काफी परेशानी हो रही है। दिव्यांगजनों के लिए प्रकाशित आरक्षित पदों की गणना में भी प्रथम दृष्टया त्रुटि पायी गयी है।

राज्य निःशक्तता आयुक्त ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि दिव्यांगजनों के लिए स्पष्ट रिक्ति की सूची बनाकर प्रत्येक प्रखंड में एक स्थान पर आवेदन करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय दें। बढ़ायी गयी तिथि का प्रचार-प्रसार भी करायें। बड़े हुए समय की गणना रोस्टर प्रकाशन की तिथि से होगी। कोर्ट ने दिव्यांगजनों को दिये जाने वाले चार फीसदी क्षैतिज आरक्षण को लेकर निदेशक माध्यमिक शिक्षा व प्राथमिक शिक्षा को भी आवश्यक निर्देश देने को कहा है। कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी प्रतिवादी बनाते हुए उनका पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया। कोर्ट द्वारा इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी प्रतिवादी बनाते हुए उनका पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया।



■ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने न्यायालय ने शिक्षक नियोजन मामले में सुनवाई की।



सामान्य प्रशासन व शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों को भेजा गया नोटिस

दिव्यांगों को राज्य सरकारी की नियुक्ति में चार प्रतिशत आरक्षण का मिले लाभ



26 | दिसंबर | 2019



## किशनगंज जिला

# प्रखंडों का दौरा और एडवोकेसी बैठकें



दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलायी जा रही है, लेकिन जानकारी व जागरूकता के अभाव में दिव्यांगजन

इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ये बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कही। किशनगंज समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में विशेष कोर्ट का गठन किया गया है। दिव्यांगजनों को अलग से जॉब कार्ड मुहैया कराना है। जीविका में भी दिव्यांगजनों का समूह बनाया जाना है। आयुक्त ने कहा कि जिले में पांच दिवसीय कार्यक्रम निर्धारित है। जिसके तहत जिले में प्रखंडवार समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक प्रखंड में दिव्यांग समूह का गठन किया जायेगा। **कौशल विकास एवं रोजगार का प्रावधान :** डॉ. शिवाजी कुमार ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए मुख्यधारा के सभी औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यवसाय एवं कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाना है।

विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजनों को पर्याप्त सहयोग प्रदान करना है। दिव्यांगों के अधिकार के संबंध में बताते हुए उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए सरकारी इकाइयों में अनुकूल एवं उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति की प्रोन्नति से इन्कार नहीं किया जा सकता है। कोई भी सरकारी इकाई किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवा के दौरान दिव्यांगता से ग्रसित होने पर उसे अविमुक्त या रैंक में कमी नहीं कर सकता है। राज्य आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों की आजीविका के लिए राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार एवं अन्य आर्थिक कार्यों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग एवं अन्य उद्योगों के लिए 50 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण का प्रावधान है। दीनदायल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण एवं रोजगार का प्रावधान है। जन धन योजना के तहत भी दिव्यांगजनों को आर्थिक समावेश का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण तथा दिव्यांगजनों के समूह को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। रोजगार महानिदेशालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी दिव्यांगजनों को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं आर्थिक पुनर्वास सहायता प्रदान करता है।

रोजगार महानिदेशालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी दिव्यांगजनों को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं आर्थिक पुनर्वास सहायता प्रदान करता है।



50 हजार से 10 लाख रुपये तक कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है रोजगार के लिए दिव्यांगों को

750 से अधिक लोग इस कार्यक्रम से जुड़े

कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत दिव्यांग भी प्रशिक्षित किया जायेगा

नौकरी के दौरान दिव्यांग हुए व्यक्ति को प्रोन्नति देने से नहीं कर सकते इन्कार

आयुक्त ने किशनगंज समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की।



26 | दिसंबर | 2019



# किशनगंज जिला



3100 से अधिक दिव्यांगों ने कई प्रखंडों में हुई बैठक में हिस्सा लिया

दिव्यांगों को केवल पेंशन ही नहीं रोजगार से जोड़ने का भी करें प्रयास

प्रत्येक पंचायत में शिक्षित दिव्यांगों का समूह बनाना जरूरी

शिक्षा से आये पदाधिकारियों से दिव्यांगों से संबंधित जानकारी मांगी। मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी सतीश कुमार को आयुक्त ने निर्देश दिया कि 15 दिनों के अंदर प्रखंड क्षेत्र के तीन हजार दिव्यांगों को कार्य प्रदान करते हुए उनके खाते में उनको मिलने वाली राशि भेजना सुनिश्चित करें।

महीने में दो बार होगी समूह की बैठक, हर गांव के दिव्यांगों की समस्या का होगा समाधान

रा

ज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने किशनगंज में चलंत लोक अदालत लगाने से पूर्व सभी प्रखंडों का दौर और समीक्षा बैठक किया। उन्होंने सभी प्रखंडों में दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं का जायजा भी लिया। ठाकुरगंज प्रखंड कार्यालय पहुंचकर राज्य आयुक्त ने अधिकारियों और दिव्यांगजनों के साथ बैठक की। बैठक में आयुक्त ने सरकार द्वारा दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए चलायी जा रही प्रमुख लाभकारी एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि ऐसा प्रायः देखा जाता है कि दिव्यांग व्यक्ति का प्रमाणपत्र बनवाने के बाद सिर्फ उन्हें सरकार



आयुक्त ने की प्रतिनिधियों के साथ की बैठक



द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि का ही लाभ मिल पाता है, जागरूकता के अभाव में दिव्यांगों को उनका वास्तविक लाभ व अधिकार नहीं मिल पाता है, जिससे दिव्यांगजन को जमीनी स्तर पर सरकारी सहायता का लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों की सहायता के लिए पेंशन के अलावा दिव्यांग ऋण, आवास योजना, मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना आदि कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। परंतु जागरूकता व जानकारी के अभाव में समाज के वैसे व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जिसको लेकर उन्होंने प्रत्येक पंचायत में पांच दिव्यांग शिक्षित व्यक्ति का समूह बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे समूह के लोग गांव-गांव घूमकर अन्य दिव्यांग लोगों की सहायता कर योजनाओं के बारे में जानकारी साझा कर उन्हें लाभ दिलवाने का काम करेंगे। इस दौरान दिव्यांग सह शिक्षक अतारूर रहमान, संतोष झा, देवलाल हेमब्रम, राजू मुर्मू, कियासुदीन, रोशन पासवान आदि मौजूद थे। इसके बाद पोठिया प्रखंड पहुंचकर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी। मौके पर उन्होंने कहा कि दिव्यांग सशक्तिकरण अधिनियम 2016 की धारा 72 की तहत पंचायत दिव्यांग समूह बनाने तथा प्रत्येक माह में दो बार समीक्षात्मक बैठक किया जाना है।

करवर्कड • 3100 से अधिक दिव्यांगों ने कई प्रखंडों में हुई बैठक में हिस्सा लिया



27 | दिसंबर | 2019



# किशनगंज जिला पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक



■ आयुक्त ने सुनी सबकी फरियाद।



दिव्यांगों को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने का करें प्रयास

दिव्यांगों को रोजगार के लिए बैंक ऋण देने में करें सहायता

दिव्यांगों को एक दिन में बनाकर दें दिव्यांगता प्रमाणपत्र

## सभी बैंकों के साथ बैठक

सभी बैंकों के साथ बैठक में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत कौशल विकास एवं रोजगार हेतु प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 में कौशल विकास के लिए नीति का उल्लेख किया गया है। नियमावली के तहत राज्य के सभी योजनाओं में दिव्यांगजनों का समावेश सुनिश्चित करना ही उद्देश्य है।

**रा**ज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने डीआरडीए कार्यालय के सभागार में दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधा को लेकर विभिन्न विभागों के साथ बैठक की। इस दौरान दिव्यांगजनों की सुविधाओं को लेकर विभिन्न विभागों में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की और दिव्यांगजनों को विभिन्न मामलों में दिये जा रहे सरकारी सुविधाओं के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि 30 दिसंबर को शहीद अशफाक उल्लाह

खां स्टेडियम खगड़ा में दिव्यांगजनों के परिवारों की सुनावई हेतु चलंत न्यायालय लगाया जायेगा। इसके लिए सभी विभागों को निर्देशित किया गया है। विशेषकर स्वास्थ्य और परिवहन आपूर्ति, समाजिक सुरक्षा आदि के पदाधिकारी एवं कर्मी अपने संसाधन के साथ उपस्थित रहेंगे और तत्काल उन्हें प्रमाणपत्र और अन्य जानकारी उपलब्ध करायेंगे। इस दौरान एसडीएम शाहनवाज अहमद नियाजी ने कहा कि जिले में जनवितरण प्रणाली की 575 विक्रेताओं में से 12 जनवितरण प्रणाली विक्रेता दिव्यांगजन चला रहे हैं। वहीं पुलिस उपाध्यक्ष

सहित सभी थानों के थानाध्यक्ष को दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील बनने एवं उनके अधिकार को दिलाने का जानकारी विस्तार से दिया गया। इस दौरान उपस्थित सभी पदाधिकारियों को दिव्यांगजन अधिकार 2016 अंतर्गत विनिर्दिष्ट दिव्यांगजन के बारे में विस्तार से बताया गया।



28 | दिसंबर | 2019



**समीक्षा बैठक**



# जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ बैठक

**रा**

ज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने डीआरडीए रचना भवन के सभागार में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए चलायी जा रही योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को अब यूनिक आइडी कार्ड दिया जायेगा। आयुक्त ने बताया कि कुल 21 प्रकार के दिव्यांग होते हैं। जिसमें

चलने संबंधी दिव्यांगता, मांसपेशीय दूर्विकार, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, अम्ल हमले की पीड़ित, दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, श्रवण क्षति, वाक एवं भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता ऑटिज्म, थैलेसीमिया, हिमोफीलिया, मानसिक रूग्णता, सिकल सेल रोग, सुनने में कठिनाई, पार्किन्सन रोग आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रखंड में दिव्यांगजनों का समूह बनाया गया है। किस विभाग में दिव्यांगजनों के लिए कौन सी योजनाएं चल रही है, जिससे उन्हें लाभ दिलाया जा सकता है। इससे लाभुक को अवगत कराया।

इस बैठक के बाद बहादुरगंज प्रखंड कार्यालय पहुंचे राज्य आयुक्त ने कहा कि घर बैठे ही अब दिव्यांगों की शिकायतों का निपटारा होगा। दिव्यांगजनों को भी सरकारी योजनाओं के संचालन की जानकारी उपलब्ध होगी एवं कौशल विकास व रोजगार पर आधारित योजनाओं से भी वे अधिक से अधिक लाभ उठा पायेंगे। प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर में सरकारी कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ दिव्यांग समूह की जागरूकता बैठक में राज्य आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगों को भी सरकार की संचालित योजनाओं का यथोचित फायदा मिले। सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। दिव्यांगों की शिकायत का निपटारा समय रहते ही करना होगा, जिसके लिए वक्त निर्धारित कर दिया गया है। इससे पहले राज्य आयुक्त प्रखंड क्षेत्र के अलग-अलग पंचायतों से प्राप्त दिव्यांगजनों के परिवारों की सुनवाई एवं शिकायत के बाबत संबंधित विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके कार्यशैली को सही करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के हितों की अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। योजना के सुचारू संचालन की दिशा में सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपनी कार्यशैली में

21

प्रकार के दिव्यांगों को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है

दिव्यांगों को पहचान के लिए दिया जा रहा है यूनिक आइडी कार्ड

दिव्यांगों के आवेदन को प्राथमिकता से लेकर करें निदान

दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण जरूर

■ समीक्षा बैठक में उपस्थित डॉ. शिवाजी कुमार व अन्य।

बहादुरगंज प्रखंड कार्यालय पहुंचे राज्य आयुक्त ने कहा कि घर बैठे ही अब दिव्यांगों की शिकायतों का निपटारा होगा। दिव्यांगजनों को भी सरकारी योजनाओं के संचालन की जानकारी उपलब्ध होगी एवं कौशल विकास व रोजगार पर आधारित योजनाओं से भी वे अधिक से अधिक लाभ उठा पायेंगे।

## निबटारा, घर बैठे मिलेगी जानकारी



यथोचित बदलाव लायें एवं दिव्यांगों के हितों को प्राथमिकता में शामिल करें. जागरूकता बैठक व परिवारों की सुनवाई के समापन के पश्चात

राज्य आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगों के परिवारों को सुना और जल्द ही उनकी शिकायतों के निपटारे का भरोसा भी दिलाया।





29 | दिसंबर | 2019



**दिव्यांगजन  
समूह बैठक**

**किशनगंज जिला**



2500 से अधिक दिव्यांगजनों ने प्रखंडों में हुई बैठक में लिया हिस्सा

21 प्रकार के दिव्यांगों को मिलता है सरकारी योजना का लाभ



■ दिव्यांगों को कुटीर उद्योग के लिए 25 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान

■ पेट्रोल पंप के आवंटन में पांच फीसद दिव्यांगों के लिए आरक्षण की सुविधा



■ आयुक्त ने दिव्यांगजनों की फरियाद सुनते।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु सहयोग, जनधन योजना के तहत आर्थिक समावेश का प्रयास, पेट्रोल पंप के आवंटन में शारीरिक दिव्यांगजनों को पांच फीसदी आरक्षण के साथ कई अन्य लाभ दिये जा रहे हैं।



राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार के लिए कम दर पर मिलता है ऋण



**टे**

ढागाछ प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार भवन में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने जनप्रतिनिधियों एवं दिव्यांगजनों के साथ बैठक की। बैठक कर उन्होंने विभिन्न दिव्यांगता के प्रकार की जानकारी देते हुए शत प्रतिशत निःशक्तता प्रमाणपत्र बनाने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को दी जाने वाली लाभ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों की श्रेणी को बढ़ाकर अब 21 कर दिया गया है, जिसमें चलंत संबंधी दिव्यांगता, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, अम्ल हमले की पीड़ित, कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण क्षति, सुनने में कठिनाई, वाक और भाषा दिव्यांगता,

बौद्धिक दिव्यांगता आदि शामिल है। राज्य निःशक्तता आयुक्त ने बताया कि सरकार प्रायोजित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में आमजनों को मिलने वाले लाभ से पांच फीसद अधिक लाभ दिव्यांगजनों को दी जाएगी। इसके लिए पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक दिव्यांगजनों के साथ एक समूह का गठन किया जा रहा है। जिसमें दिव्यांगजनों को जीविका हेतु भी कई योजना बनायी गयी है। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार एवं आर्थिक कार्यों के लिए कम दर पर ऋण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग हेतु तीन श्रेणी में 25 हजार से 10 लाख रुपये तक का कम दर पर ऋण, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु सहयोग, जनधन योजना के तहत आर्थिक समावेश का प्रयास, पेट्रोल पंप के आवंटन में शारीरिक दिव्यांगजनों को पांच फीसदी आरक्षण के साथ कई अन्य लाभ दिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजीविका हेतु संस्थाओं के माध्यम से योजनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। दिव्यांगजनों के साथ विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गयी।

दिव्यांगों को उपयुक्त ऋण की सुविधा के तहत राज्य निःशक्तता आयुक्त ने आयुक्त कक्ष-हर दिव्यांगों को मिले सही लाभ





30 | दिसंबर | 2019

## चलंत न्यायालय



**4719** कुल  
परिवादों का चलंत  
न्यायालय में हुआ  
निबंधन

**1237**  
दिव्यांगों को ऑन  
द स्पॉट दिया गया  
दिव्यांगता प्रमाणपत्र

**400** मामले  
शिक्षा विभाग  
संबंधित आये,  
जिनका ऑन द स्पॉट  
गया निपटारा

**114**  
मामले बैंक संबंधित  
चलंत न्यायालय में  
आये, जिसपर हुई  
सुनवाई

**274** डीआरडीए संबंधित मामलों की  
गयी सुनवाई

ले के दिव्यांगजनों की शिकायतों के निपटारा के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 80 के अंतर्गत चलंत न्यायालय लगाया गया। खगड़ा स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खां स्टेडियम में आयोजित चलंत न्यायालय सुबह से शाम तक चली। जिसमें विभिन्न विषयों से संबंधित मामलों की सुनवाई के साथ दिव्यांगजनों को प्रमाणपत्र भी दिये गये।

इसके पूर्व राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने चलंत न्यायालय का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर उन्होंने कहा कि चलंत न्यायालय में सुनवाई संबंधित प्राप्त परिवादों के निबंधन की संख्या 4719 रही। इसके अंतर्गत बैंक संबंधित परिवादों की संख्या 114, डीआरडीए के 274, डीआरसीसी के 12, शिक्षा विभाग के 400, मनरेगा के 220, श्रम विभाग के 32 और आपूर्ति विभाग के 64 मामले रहे। साथ ही खेल विभाग के छह, अंग एवं उपकरण के 156, यूडीआइडी के 90, रेलवे रियायत पास के 52 और सामाजिक सुरक्षा कोषांग के 89 मामले न्यायालय में आये। इसके अलावा 1237 मामले दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आये, जिनका ऑन द स्पॉट निराकरण किया गया। चलंत न्यायालय के प्रति दिव्यांगजनों का विश्वास बढ़ा है। अब उन्हें लगने लगा है



कड़के की ठंढ़ होने के बावजूद भी चलंत न्यायालय में बड़ी संख्या में दिव्यांग पहुंचे।

इस न्यायालय में परिवादों के निबंधन और सुनवाई के लिए दिव्यांग अपने साथ दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आधार कार्ड सहित अन्य वांछित कागजात के साथ चलंत न्यायालय में शामिल हुए थे।

■ सबकी फरियाद सुनते राज्य निःशक्तता आयुक्त।

इसके अंतर्गत बैंक संबंधित परिवादों की संख्या 114, डीआरडीए के 274, डीआरसीसी के 12, शिक्षा विभाग के 400, मनरेगा के 220, श्रम विभाग के 32 और आपूर्ति विभाग के 64 मामले रहे।

दिव्यांगों के अधिकार व सुरक्षा को लेकर लगे चलंत न्यायालय में 2350 मामले निपटे



कि ऐसे चलंत न्यायालय में पहुंचकर समस्याओं का त्वरित निष्पादन हो जायेगा। इस वजह से कड़के की ठंढ़ होने के बावजूद भी चलंत न्यायालय में बड़ी संख्या में दिव्यांग पहुंचे। इस न्यायालय में परिवादों के निबंधन और

सुनवाई के लिए दिव्यांग अपने साथ दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आधार कार्ड सहित अन्य वांछित कागजात के साथ चलंत न्यायालय में शामिल हुए थे। परिवादों के निबंधन के लिए आठ काउंटर बनाये गये थे।





31 | दिसंबर | 2019

## दिव्यांगजनों के लिए अनुमंडलीय स्तर पर कैंप



■ अपनी फरियाद सुनाते दिव्यांगजन।

## सुपौल



300

से अधिक दिव्यांगजनों ने इस कार्यक्रम में लिया हिस्सा



54

दिव्यांगजनों को दिया गया मनरेगा का जॉब कार्ड

52

दिव्यांगजनों को ऑन द स्पोर्ट दिया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र

रा

ज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में जिला सामाजिक सुरक्षा सह दिव्यांग सशक्तिकरण तहत वीरपुर अनुमंडल के सभी कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं दिव्यांगों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में दिव्यांगों के परिवारों की सुनवाई हुई। इसके अलावा अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों

को राज्य निःशक्तता आयुक्त ने दिव्यांगों के लिए चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण मोहन प्रसाद, आरडीओ देवानंद कुमार सिंह एवं बसंतपुर के पीओ अजीत कुमार झा और पीएचसी प्रभारी डॉ. अर्जुन चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक के बाद पत्रकारों से राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि बैठक में दिव्यांगों की शिकायतों का निपटारा भी किया गया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को मिलने वाले प्रमाणपत्र चिकित्सकों द्वारा जांच कर देने की प्रक्रिया ऑन द स्पोर्ट की गयी है

तथा मिलने वाला लाभ भी तुरंत स्वीकृत किया जायेगा। ताकि लाभार्थियों को भटकना न पड़े। इतना ही नहीं जो भी संबंधित कर्मचारी इसमें शिथिलता बरतेंगे या उन्हें लाभ से वंचित रहने को मजबूर करेंगे। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिविर में 52 दिव्यांगजनों को प्रमाणपत्र दिया गया और 54 दिव्यांगजनों को जॉब कार्ड राज्य आयुक्त एवं सिविल सर्जन के हाथों प्रदान किया गया। जॉब कार्ड धारक को सरकार द्वारा एकमुश्त पेंशन की राशि खाते में उपलब्ध करायी जाएगी। जिसका उपयोग वे अपने उत्थान के लिए करेंगे।

### दिव्यांग को लाभान्वित करने का पहला राज्य बना बिहार : राज्य निःशक्तता आयुक्त



क्र०सं०	वाद सं०	जिला	वादी एवं प्रतिवादी	विषय
65.	65/2019	मुजफ्फरपुर	वादी :- श्री तनिस राज, पिता- श्री सतेन्द्र कुमार, मुजफ्फरपुर प्रतिवादी :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोतीपुर (पश्चिमी अनुमंडल ) मुजफ्फरपुर	सरकारी योजना जो दिव्यांगों के लिए अनुमान्य है का लाभ नहीं मिलने के संबंध में
66.	66/2019	दरभंगा	वादी :- दरभंगा जिलान्तर्गत जाले प्रखण्ड के दिव्यांगजन से प्राप्त परिवाद पत्रों के सम्बन्ध में (स्वतः संज्ञान) प्रतिवादी :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड- जाले दरभंगा	राज्य आव्युत निःशक्तता द्वारा आदेश अनुपालन नहीं करने के संबंध में
67.	67/2019	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	वादी :- श्री भूषण कुमार, एवं श्री कामेश्वर पटेल, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) प्रतिवादी :- जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) एवं अन्य	समाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) को नीचे तल्ले पर लाने के संबंध में
68.	68/2019	मुजफ्फरपुर	वादी :- श्री अवनीश कुमार, मुजफ्फरपुर प्रतिवादी :- कुल सचिव, भीम राव अम्बेदकर (बिहार) विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	नामांकन के क्रम में दिव्यांग कोटे का लाभ नहीं दिए जाने के संबंध में
69.	69/2019	पटना	वादी :- श्री मिथिलेश कुमार, श्री इन्द्र प्रसाद सिंह, पटना प्रतिवादी :- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पटना	सातवाँ वेतन निर्धारण का लाभ देने संबंधी में
70.	70/2019	बेतिया	वादी :- सुश्री माला कुमारी, बेतिया प्रतिवादी :- श्री दीपक चतराज (सी०ई०ओ०), राउरकेला उड़ीसा एवं अन्य	चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों की नियुक्ति नहीं किए जाने से संबंधित
71.	71/2019	सिवान	वादी :- श्री रजनीश कुमार शाही, सिवान प्रतिवादी :- सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान	पेंशन राशि के भुगतान के संबंध में
72.	72/2019	औरंगाबाद	वादी :- श्री राम पुकार पासवान, औरंगाबाद प्रतिवादी :- जिला पदाधिकारी-सह-समाहता , औरंगाबाद	चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पद पर नियुक्ति के संबंध में
73.	73/2019	बेगूसराय	वादी :- श्री संतोष कुमार, पिता- श्री विष्णुदेव चौधरी, बेगूसराय प्रतिवादी :- अंचलाधिकारी, सदर प्रखंड, बेगूसराय	सरकारी अमीन से निःशुल्क नापी करवाने के संबंध में
74.	74/2019	रोहतास	वादी :- श्रीमती चंचला देवी, रोहतास प्रतिवादी :- अंचलाधिकारी, प्रखंड सझौली, रोहतास	आश्रय हीन करने के संबंध में
75.	75/2019	पटना	वादी :- श्री वाणी भूषण पाण्डेय, पिता-स्व० बाल्मीकी पाण्डेय, पटना प्रतिवादी :- आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण, पटना एवं अन्य	पैतृक घर से बेदखल करने के संबंध में
76.	76/2019	पटना	वादी :- श्रीमती शोभा देवी, (कुमारी), पिता-स्व० नरेश प्रसाद, पटना प्रतिवादी :- उप विकास आव्युत, पटना एवं अन्य	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास आवंटन हेतु
77.	77/2019	गोपालगंज	वादी :- श्री चन्दन कुमार सिंह, गोपालगंज प्रतिवादी :- प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, नया सचिवालय परिसर बिहार, पटना एवं अन्य	शिक्षक नियोजन में दिव्यांगजनों के आवेदन स्वीकार करने के संबंध में



# जनवरी 2020

# JANUARY 2020

राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार खिलाड़ियों की नियुक्ति में 10 प्रतिशत देती है आरक्षण



लुई ब्रेल की जयंती...

pg-143



लुई ब्रेल समापन समारोह...

pg-144



मकर संक्रांति अवसर पर आयोजन

pg-145



न्यूरो दिव्यांग का इलाज...

pg-147

द्वितीय युवा राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन हो गया। मुख्य अतिथि राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने विजेता व उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान किया। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के हित में कई सारे कार्य कर रही है। सरकार द्वारा खिलाड़ियों को नियुक्ति में दस प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।

pg-146



04 | जनवरी | 2020

कार्यशाला  
आयोजित

# लुई ब्रेल की जयंती



रा

ज्य में दृष्टिबाधितों के जल्द पहचान के लिए रोडमैप बनेगा। लुई ब्रेल की 211वीं जयंती पर दृष्टिबाधित दिव्यांगता की रोकथाम पर आयोजित कार्यशाला में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि जल्द पहचान नहीं होने के कारण राज्य में दृष्टिबाधित दिव्यांगता बढ़ रही है। इसपर प्रभावी रोक लगाने के लिए अर्ली इंटरवेंशन जरूरी है। सरकार इसके प्रति गंभीर है और जल्द ही अर्ली इंटरवेंशन में आये विशेषज्ञों से इस दिशा में काम करने का अह्वान किया।

बिहार विद्यापीठ के अध्यक्ष विजय प्रकाश ने कहा कि दिव्यांगों को अवसर की समानता नहीं वरन समानता का अवसर मिलना चाहिए। आजकल शारीरिक कमियों को कृत्रिम अंगों के जरिये दूर किया जा रहा है। कृत्रिम अंग प्राकृतिक अंगों पर भारी पड़ रहे हैं। विशेषज्ञों को दिव्यांगों के लिए नयी तकनीक पर काम करने की आवश्यकता है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय की सहायक निदेशिका पंकी कुमारी ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 23 लाख दिव्यांग थे, जिसमें 14 लाख 63 हजार को प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जा चुका है। विभाग का लक्ष्य सभी दिव्यांगों को प्रमाणपत्र और उससे जुड़े लाभ देने की है। कार्यशाला में डॉ. राजीव गंगौल, मोती लाल सिंह, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. अश्विनी कुमार, डॉ. नवल किशोर शर्मा आदि ने विचार रखें। कार्यशाला में राज्यभर से आये नेत्र रोग विशेषज्ञों और दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे सरकारी और गैरसरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा समर्पण स्पेशल स्कूल, नेत्रहीन यूनिट की ओर से अंतरराष्ट्रीय लुई ब्रेल दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने किया। इस अवसर पर डॉ. सुभाष चंदा, मधु श्रीवास्तव व अन्य मौजूद थे।

■ लुई ब्रेल की 211वीं जयंती पर दृष्टिबाधित दिव्यांगता की रोकथाम पर आयोजित कार्यशाला।



2011

की जनगणना के अनुसार बिहार में 23 लाख है दिव्यांगों की संख्या



14.63

लाख दिव्यांगों को अब तक दिया गया है दिव्यांगता प्रमाणपत्र

✍ जल्द पहचान नहीं होने पर बढ़ रही है दृष्टिबाधित दिव्यांगता।

✍ विभाग का लक्ष्य सभी दिव्यांगों को प्रमाणपत्र और उससे जुड़े लाभ देने की है।

समर्पण स्पेशल स्कूल, नेत्रहीन यूनिट की ओर से अंतरराष्ट्रीय लुई ब्रेल दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने किया। इस अवसर पर डॉ. सुभाष चंदा, मधु श्रीवास्तव व अन्य मौजूद थे।





12 | जनवरी | 2020

# पटना जिला



## लुई ब्रेल समापन समारोह

दि



■ लुई ब्रेल के 211वीं स्मृति सप्ताह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगजन।

व्यांगजनों के लिए आरक्षण की दर बढ़ायी गयी है। स्कूल व कॉलेजों में दिव्यांगों को अब चार की जगह पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं सरकारी नौकरी में तीन के बदले चार प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। राजधानी के दो बड़े अस्पताल आइजीआइएमएस व एनएमसीएच में मार्च से आई बैंक चालू हो जायेगा। ये बातें उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कुम्हरार स्थित अंतरज्योति बालिका विद्यालय में लुई ब्रेल के 211वीं स्मृति सप्ताह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कही।

उन्होंने कहा कि दिव्यांगों का परीक्षा शुल्क भी सामान्य के मुकाबले एक चौथाई के साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा में दस वर्ष की छूट दी जा रही है। उपमुख्यमंत्री ने पटना, भागलपुर व दरभंगा में चल रहे नेत्रहीन विद्यालय का नया भवन बनाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दधीची देहदान समिति के माध्यम से नेत्रहीन छात्र-छात्राओं की स्क्रीनिंग कर उन्हें नेत्रदान किया जा रहा है। दो छात्राओं का प्रत्येक वर्ष रौशनी लौटाने का प्रयास होगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कॉर्निया इंप्लांट के लिए इसी वर्ष मार्च महीने से आइजीआइएमएस व एनएमसीएच में आई बैंक शुरू किया जायेगा। परिषद के महासचिव विजय कुमार सिंह, राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन प्रो. आनंदमूर्ति ने किया।

☞ सरकारी नौकरी में तीन के बदले अब चार प्रतिशत आरक्षण दिव्यांगों को दिया जा रहा है

☞ आइजीआइएमएस व एनएमसीएच में शुरू होगा आई बैंक

☞ स्कूल और कॉलेजों में चार के स्थान पर अब पांच प्रतिशत आरक्षण दिव्यांगों के लिए

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कॉर्निया इंप्लांट के लिए इसी वर्ष मार्च महीने से आइजीआइएमएस व एनएमसीएच में आई बैंक शुरू किया जायेगा। परिषद के महासचिव विजय कुमार सिंह, राज्य निःशक्तता आयुक्त शिवाजी कुमार ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन प्रो. आनंदमूर्ति ने किया।

### दृष्टिबाधितों को अब नौकरी में मिलेगा चार फीसद आरक्षण : उपमुख्यमंत्री

बिहार सरकार ने लुई ब्रेल की जयंति एक सप्ताह तक मनाने का लिया है निर्णय

211 वर्ष के लुई ब्रेल के स्मृति सप्ताह का शुभारंभ

151 वर्ष के लुई ब्रेल के स्मृति सप्ताह का शुभारंभ

25 वर्ष के लुई ब्रेल के स्मृति सप्ताह का शुभारंभ

दुनिया से गए हैं सत्येंद्र, दिलों से नहीं



12 | जनवरी | 2020



## मकर संक्रांति अवसर पर आयोजन

# मिली सफलता

**प**टना के ठाकुर प्रसाद कम्युनिटी हॉल के सभागार में दिव्यांगजनों का अधिकार संवाद सह मकर संक्रांति उत्सव का आयोजन किया गया समदृष्टि चौरिटेबल फाउंडेशन तथा दिव्यांग फ्यूचर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने सवालियों को समाधान की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में राज्य सरकार खासकर दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय पटना भारत का पहला दिव्यांगजनों के ऊपर सबसे ज्यादा कार्य करने वाला राज्य बना है। बिहार राज्य में दिव्यांगों के रोजगार के लिए सरकार निजी कंपनियों को पत्र जारी कर प्रत्येक 20 कर्मचारी में एक दिव्यांग कर्मचारी रखने का आदेश दिया है।

दिव्यांगजनों को यूआइडी कार्ड, रेलवे रियायत प्रमाणपत्र, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना, उपकरण योजना, ऋण योजना के साथ दिव्यांग अधिकार अधिनियम की धाराओं की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान अधिनियम में दिव्यांगों को यदि कोई व्यक्ति अभद्र भाषा बोलता है तो उन्हें जुर्माना के साथ जेल जाना होगा।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की पत्नी प्रो. माया शंकर ने कहा कि दिव्यांगों के विकास एवं उनकी जरूरत के लिए हमारी ओर से हर संभव प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने पटना जिले के दिव्यांगों को बैटरी वाली ट्राइसाइकिल सांसद निधि से दिलवाने की बात कही। साथ ही साथ फुटपाथ पर अलग से दिव्यांगों के जीविका के लिए दिव्यांग वेंडर जोन बनाने की मांग राज्य सरकार से की।

चिकित्सक संजय प्रसाद राणा ने कहा कि अपने सेवा में यदि कोई दिव्यांग हमारे पास आते हैं तो आजीवन उनका फीस नहीं लूंगा। मौके पर बिहार नेत्रहीन परिषद के माहसचिव डॉ. नवल किशोर शर्मा, दिव्यांग फ्यूचर एसोसिएशन के अनील कुमार, आदित्य राज व अन्य मौजूद थे।

■ समदृष्टि चौरिटेबल फाउंडेशन तथा दिव्यांग फ्यूचर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।



**20** कर्मचारी वाले निजी संस्थान में एक दिव्यांग को नौकरी देना जरूरी

- ☞ बिहार के दिव्यांगजनों को दिया जा रहा है यूनिक आइडी कार्ड
- ☞ मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांगों को तीन लाख रुपये तक का अनुदान
- ☞ दिव्यांगों को स्थानीय सांसद अपने निधि से दें बैट्री चलित ट्राइसाइकिल

दिव्यांगों के विकास एवं उनकी जरूरत के लिए हमारी ओर से हर संभव प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने पटना जिले के दिव्यांगों को बैटरी वाली ट्राइसाइकिल सांसद निधि से दिलवाने की बात कही।

## 'दिव्यांगों के लिए फुटपाथ पर बनें स्थाई दुकानें'

पटना (एसएनबी)। राजधानी के ठाकुर प्रसाद कम्युनिटी हॉल के सभागार में दिव्यांगजनों का अधिकार संवाद सह मकर संक्रांति उत्सव-2020 आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन सम दृष्टि चौरिटेबल फाउंडेशन और दिव्यांग फ्यूचर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था।



लिए हमारी ओर से हर संभव प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने पटना जिले के दिव्यांगों को बैटरी वाली ट्राइ साइकिल सांसद निधि से दिलवाने की बात कही साथ ही साथ फुटपाथ पर अलग से दिव्यांगों के जीविका हेतु दिव्यांगों के लिए वेंडर जोन बनाने की मांग राज्य सरकार से की। वहीं चिकित्सक संजय प्रसाद राणा ने कहा कि अपने सेवा में यदि कोई दिव्यांग हमारे पास आते हैं तो आजीवन उनका फीस नहीं लूंगा और प्रो. माया शंकर ने कहा कि बिहार में खासकर पटना जिले में अलग से





27 | जनवरी | 2020

## बॉल बैडमिंटन चैम्पियनशिप

राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार खिलाड़ियों की नियुक्ति में 10 प्रतिशत देती है आरक्षण

खिलाड़ी कल्याण कोष से खिलाड़ियों को हर साल लाखों रुपये की दी जाती है मदद

खेल संघों को आयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा दिये जाते हैं लाखों रुपये

दिव्यांग खिलाड़ियों को भी नियुक्ति में मिलती है प्राथमिकता

■ भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ के निर्देशन में प्रथम युवा राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैम्पियनशिप का शुभारंभ

द्वितीय युवा राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैम्पियनशिप का समापन हो गया। मुख्य अतिथि राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने विजेता व उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान किया। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के हित में कई सारे कार्य कर रही है। सरकार द्वारा खिलाड़ियों को नियुक्ति में दस प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा खेल को बढ़ावा देने के लिए कई सारी खेल गतिविधियां करायी जा रही हैं। खिलाड़ियों के मदद के लिए खिलाड़ी कल्याण कोष से हर साल लाखों रुपये दिये जा रहे हैं। इसके अलावा खिलाड़ी सम्मान राशि को भी अन्य राज्यों के अपेक्षा कई गुना अधिक दी जा रही है। साथ ही दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी राज्य सरकार द्वारा मदद किया जाता है। राज्य के दिव्यांग खिलाड़ी विदेशों में

अपने नाम का परचम लहरा रहे हैं। यह चैम्पियनशिप भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ के निर्देशानुसार बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में पूर्वी चंपारण जिला बॉल बैडमिंटन संघ की ओर से आयोजित था। मैच एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल गायघाट, मोतिहारी में खेला गया। इस चैम्पियनशिप के बालक वर्ग के फाइनल मुकाबले का खिताब आंध्रप्रदेश ने तमिलनाडु को 35-31 और 35-30 से हराकर अपने नाम किया जबकि, बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने केरल को 35-29 और 35-28 से हराया और विजेता बनी। वहीं, बालक वर्ग में केरल व तेलंगाना को एवं बालिका वर्ग में मेजबान बिहार व आंध्रप्रदेश को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इससे पहले खेले गये बालक वर्ग के पहले सेमीफाइनल में तमिलनाडु ने केरल को 35-32

और 35-20 से व दूसरे सेमीफाइनल में आंध्रप्रदेश ने तेलंगाना को 35-25 और 35-16 से हराया। बालिका वर्ग के पहले सेमीफाइनल में तमिलनाडु ने बिहार को 35-21 और 35-20 से और दूसरे सेमीफाइनल में केरल ने आंध्रप्रदेश को 35-22 और 35-28 से पराजित किया। चैम्पियनशिप में बिहार की बालक टीम को छठे स्थान से संतोष करना पड़ा। बिहार की बालिका टीम ने कांस्य पदक जीता। बिहार बालिका टीम की ओर से प्रिया सिंह, वंदना कुमारी, तुलसी कुमारी, मुस्कान और सोनाली घोष ने शानदार प्रदर्शन किया।

# मोतिहारी जिला



30 | जनवरी | 2020



## कार्यक्रम आइएचआइएफ

# न्यूरो दिव्यांग का इलाज



म

स्तिष्क में गंभीर चोट (हेड इन्जरी) अथवा किसी अन्य कारणों से न्यूरो दिव्यांगता के शिकार हुए लोग पुनः सामान्य जीवन जी सकते हैं। अगर उन्हें सही इलाज के साथ तकनीकी रूप से सक्षम रिहैबिटेशन सेंटर की मदद मिले। इसमें उनके परिवार और समाज के लोगों की मदद मिले तो और आसानी होगी। ये बातें इंडियन हेड इन्जरी फाउंडेशन (आइएचआइएफ) और कारा मेडिकल फाउंडेशन के अध्यक्ष सह ट्रस्टी डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने न्यूरो रिहैब सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहीं। उन्होंने कहा कि आइएचआइएफ बिहार के सभी 38 जिलों में दिव्यांगों को व्हील चेयर, वॉकर, श्रवण यंत्र, जैसे उपकरण भी उपलब्ध कराने का काम करेगा। अभी फाउंडेशन द्वारा पटना में रिहैब सेंटर की स्थापना की गयी है। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा पीड़ितों की मदद की जा रही है। प्रेस वार्ता में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. सुभाष चंद्रा, इंग्लैंड के हेल्थ सर्विस विशेषज्ञ प्रो. ल्यूक डे, डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय सलाहकार डॉ. पतंजलि नायर व डॉ. गौरव गुप्ता मौजूद रहे। दिव्यांग मरीजों के पुनर्वासन में मदद के लिए डब्ल्यूएचओ 50 प्रकार के सहायक उपकरण उपलब्ध कराता है। ये उपकरण राज्य सरकार अथवा रिहैब सेंटरों की मदद से मरीज निःशुल्क भी प्राप्त कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ के डॉ. पतंजलि ने डब्ल्यूएचओ से मिलने वाले सहायक उपकरणों की सूची भी जारी की। कहा कि आइएचआइएफ और सरकार के प्रयासों से राज्य के पांच लाख दिव्यांगों को सहायता मिल सकेगी।

■ फाउंडेशन द्वारा पटना में रिहैब सेंटर की स्थापना की गयी है।



# 50

प्रकार का सहायक उपकरण डब्ल्यूएचओ दिव्यांगों को निःशुल्क उपलब्ध कराता है

👉 आइएचआइएफ के सहायता से राज्य के पांच लाख दिव्यांगों को मिली सहायता

👉 38 जिलों में दिव्यांगों को व्हील चेयर, वॉकर, श्रवण यंत्र, जैसे उपकरण भी उपलब्ध कराने का काम करेगा

राज्य निःशक्तता आयुक्त के कार्यालय के तत्वाधान में दिव्यांगजनों के लिए सहायक तकनीक एवं उपकरण विषय पर आयोजित एकदिवसीय कार्यशाला एवं उच्चस्तरीय बैठक में विमर्श के दौरान ये बातें सामने आयी। बैठक का उद्घाटन समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने की।

## न्यूरो दिव्यांग पीड़ितों का इलाज संभव

आइएचआइएफ

पटना | 30 जनवरी 2020

स्तिष्क में गंभीर चोट (हेड इन्जरी) अथवा किसी अन्य कारणों से न्यूरो दिव्यांगता के शिकार हुए लोग पुनः सामान्य जीवन जी सकते हैं। अगर उन्हें सही इलाज के साथ तकनीकी रूप से सक्षम रिहैबिटेशन सेंटर की मदद मिले। इसमें उनके परिवार और समाज के लोगों की मदद मिले तो और आसानी होगी। ये बातें इंडियन हेड इन्जरी फाउंडेशन के अध्यक्ष सह ट्रस्टी डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने न्यूरो रिहैब सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहीं। उन्होंने कहा कि आइएचआइएफ बिहार के सभी 38 जिलों में दिव्यांगों को व्हील चेयर, वॉकर, श्रवण यंत्र, जैसे उपकरण भी उपलब्ध कराने का काम करेगा। अभी फाउंडेशन द्वारा पटना में रिहैब सेंटर की स्थापना की गयी है। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा पीड़ितों की मदद की जा रही है। प्रेस वार्ता में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. सुभाष चंद्रा, इंग्लैंड के हेल्थ सर्विस विशेषज्ञ प्रो. ल्यूक डे, डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय सलाहकार डॉ. पतंजलि नायर व डॉ. गौरव गुप्ता मौजूद रहे। दिव्यांग मरीजों के पुनर्वासन में मदद के लिए डब्ल्यूएचओ 50 प्रकार के सहायक उपकरण उपलब्ध कराता है। ये उपकरण राज्य सरकार अथवा रिहैब सेंटरों की मदद से मरीज निःशुल्क भी प्राप्त कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ के डॉ. पतंजलि ने डब्ल्यूएचओ से मिलने वाले सहायक उपकरणों की सूची भी जारी की। कहा कि आइएचआइएफ और सरकार के प्रयासों से राज्य के पांच लाख दिव्यांगों को सहायता मिल सकेगी।



न्यूरो दिव्यांगता के शिकार हुए लोग पुनः सामान्य जीवन जी सकते हैं। अगर उन्हें सही इलाज के साथ तकनीकी रूप से सक्षम रिहैबिटेशन सेंटर की मदद मिले। इसमें उनके परिवार और समाज के लोगों की मदद मिले तो और आसानी होगी। ये बातें इंडियन हेड इन्जरी फाउंडेशन के अध्यक्ष सह ट्रस्टी डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने न्यूरो रिहैब सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहीं। उन्होंने कहा कि आइएचआइएफ बिहार के सभी 38 जिलों में दिव्यांगों को व्हील चेयर, वॉकर, श्रवण यंत्र, जैसे उपकरण भी उपलब्ध कराने का काम करेगा। अभी फाउंडेशन द्वारा पटना में रिहैब सेंटर की स्थापना की गयी है। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा पीड़ितों की मदद की जा रही है। प्रेस वार्ता में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. सुभाष चंद्रा, इंग्लैंड के हेल्थ सर्विस विशेषज्ञ प्रो. ल्यूक डे, डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय सलाहकार डॉ. पतंजलि नायर व डॉ. गौरव गुप्ता मौजूद रहे। दिव्यांग मरीजों के पुनर्वासन में मदद के लिए डब्ल्यूएचओ 50 प्रकार के सहायक उपकरण उपलब्ध कराता है। ये उपकरण राज्य सरकार अथवा रिहैब सेंटरों की मदद से मरीज निःशुल्क भी प्राप्त कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ के डॉ. पतंजलि ने डब्ल्यूएचओ से मिलने वाले सहायक उपकरणों की सूची भी जारी की। कहा कि आइएचआइएफ और सरकार के प्रयासों से राज्य के पांच लाख दिव्यांगों को सहायता मिल सकेगी।



FEBRUARY 2020

# फरवरी 2020

समस्तीपुर जिला का दौरा

## प्रखंडों का निरीक्षण

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी ने कहा कि किसी भी दिव्यांगजन को किसी भी स्तर पर उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर कई कानून भी बनाया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसा करती है तो उसके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

pg-149



समीक्षात्मक बैठक

pg-150



जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक...

pg-151



लखीसराय जिला चलंत न्यायालय

pg-152



अधिकारियों के साथ बैठक...

pg-153



जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक...

pg-154



थैलेसीमिया से अब नहीं मरेगे...

pg-156



11 | फरवरी | 2020



# समस्तीपुर

3000

## प्रखंडों का निरीक्षण

से अधिक दिव्यांगजनों ने विभिन्न प्रखंडों में हुई बैठक में लिया हिस्सा

दिव्यांगजनों को किसी भी स्तर पर उपेक्षित नहीं किया जा सकता

युवती अपने आपको कभी कमजोर न समझें। सरकार के द्वारा उनके उत्थान एवं आत्मनिर्भरता के लिए अनेकों योजनाएं चलायी जा रही हैं, जिसका लाभ उठाकर दिव्यांगजन अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं।



■ निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी ने दिव्यांगजन को सारी बातें सूनी।



0001

से अधिक लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े



रा

ज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी ने कहा कि किसी भी दिव्यांगजन को किसी भी स्तर पर उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर कई कानून भी बनाया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसा करती है तो उसके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सभी योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण दी है। साथ ही उनके बेहतर विकास के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित हो रही हैं। जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। जिले में पहली बार निःशक्तता आयुक्त ने विभिन्न प्रखंडों का जायजा लिया और दिव्यांगजन समूह बनाने के लिए बैठकें भी आयोजित की गयीं।

उन्होंने बताया कि 14 फरवरी को जितवारपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित डीआरसीसी परिसर

में दिव्यांगजनों के लिए चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया है। जहां दिव्यांगजनों से संबंधित मामले का निष्पादन किया जायेगा। इससे पूर्व प्रखंडों में समीक्षा की जा रही है। साथ ही अधिकारियों के साथ ही समीक्षा कर दिव्यांगजनों की योजनाओं का हाल लिया जा रहा है। ताजपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में शामिल अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए आयुक्त ने कहा कि दिव्यांग युवक-युवती अपने आपको कभी कमजोर न समझें। सरकार के द्वारा उनके उत्थान एवं आत्मनिर्भरता के लिए अनेकों योजनाएं चलायी जा रही हैं, जिसका लाभ उठाकर दिव्यांगजन अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं। उन्होंने मनरेगा के द्वारा सभी दिव्यांगों को जॉब कार्ड बनवाने, भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने, शिक्षित दिव्यांग युवकों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण देने आदि के बारे में भी जानकारी दी।

## बैंक की समस्याओं पर दिलाया ध्यान

वारिसनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित इ-किसान भवन में प्रखंड अधिकारी व दिव्यांगजनों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता बीडीओ अजमल परवेज ने की। बैठक में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगों को मिलने वाली लाभ के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान कुसैया पंचायत के शुखपुर गांव के दिव्यांग मो. इबरान ने आयुक्त का बैंक से जुड़ी समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। इस पर उन्होंने दरोगा जेपी साह को इबरान से आवेदन लेकर कार्रवाई का निर्देश दिया।



12 | फरवरी | 2020



# समस्तीपुर

4000

## अधिनियम के अनुपालनार्थ पदाधिकारियों के साथ बैठकें

से अधिक दिव्यांगजनों ने विभिन्न प्रखंडों में हुए कार्यक्रम में लिया हिस्सा

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिव्यांगों का बनाया जाये दिव्यांगता प्रमाणपत्र

युवती अपने आपको कभी कमजोर न समझें। सरकार के द्वारा उनके उत्थान एवं आत्मनिर्भरता के लिए अनेकों योजनाएं चलायी जा रही हैं, जिसका लाभ उठाकर दिव्यांगजन अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं।



■ निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी ने सबकी फरियाद सुनते।



32000

से अधिक लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ली जानकारी, हर दिव्यांग को दिया जाये राशन कार्ड संबंधित सभी प्रकार के योजनाओं का लाभ



स

मस्तीपुर समाहरणालय सभाकक्ष में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, कोचिंग संस्थाओं और बैंकर्स के साथ अलग-अलग समीक्षा बैठक की। इस दौरान विभागों के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए किये गये कार्यों की गहन समीक्षा की गयी। साथ ही सभी विभागों के द्वारा दिव्यांगजनों को दी जा रही सुविधाओं की सूची उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। साथ ही उन्हें कहा गया किसी भी योजनाओं में दिव्यांगजन को प्राथमिकता के आधार पर चयनित करें। सभी योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए पांच प्रतिशत रिजर्व किया गया है। ताकि कोई भी दिव्यांग अपने को समाज से अलग थलग नहीं समझें। मौके पर डीडी सी बरुण कुमार मिश्रा, सीएस डॉ. सीयाराम मिश्र व अन्य मौजूद थे। राज्य आयुक्त ने सभी

दिव्यांगजनों के प्रमाणपत्र बनाने के लिए सभी पीएचसी पर शिविर लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने ने कहा कि इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, पेंशन, बैंक लोन आदि योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने का आदेश संबंधित विभागों को दिया गया है। साथ ही कोचिंग संस्थानों को भी दिव्यांगजन को शिक्षित करने को कहा गया। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का भी निर्देश परिवहन विभाग को दिया गया। दिव्यांग भूमिहीनों को भी मिलेगी तीन डिसमिल भूमि : भूमिहीन दिव्यांगों को भी तीन डिसमिल जमीन शीघ्र उपलब्ध करायी जाएगी। यह बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने मोरवा प्रखंड मुख्यालय परिसर में आयोजित दिव्यांग महापंचायत में कही। इस दौरान उन्होंने सभी सरकारी योजनाओं में दिव्यांगों को प्राथमिकता देने और सभी प्रकार के सरकारी नियोजन में चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राथमिकता के आधार पर देने का निर्देश दिया।

योजना की समीक्षा के दौरान प्रखंड के सभी दिव्यांगों को अब तक जॉब कार्ड नहीं दिये जाने पर उन्होंने मनरेगा पदाधिकारी राजेश कुमार को जल्द जॉब कार्ड देने का निर्देश दिया। इसके बाद सरायरंजन प्रखंड पहुंचे राज्य आयुक्त ने बैठक में शामिल अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांग व्यक्ति भी समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। उनके भी विकास का पूर्ण ख्याल रखा जाना आवश्यक है। तभी समरस समाज का निर्माण होगा। उन्होंने कहा जिन दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। वह इसकी शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज करा सकते हैं। जांचोपरांत वैसे कर्मी व पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। जिसका सभी को लाभ उठाना चाहिए।



# समस्तीपुर



**700**

से अधिक पंचायत/जनप्रतिनिधियों और दिव्यांगजनों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा



**12000**

से अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम के बारे में सोशल मीडिया/प्रिंट मीडिया से जाना

**4%**

आरक्षण दिव्यांगजनों को रोजगार में मिलता है



समाज के अंतिम दिव्यांग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना एकमात्र लक्ष्य

स्वरोजगार ऋण योजना के तहत कम दर पर उन्हें ऋण दिया जाता है

■ योजनाओं की जानकारी देते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

13 | फरवरी | 2020



त्रिस्तरीय पंचायत

## जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक

**स**

मस्तीपुर के सत्यनारायण सिन्हा नगर भवन में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार की ओर से जिले के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रमुख प्रतिनिधियों को संबोधित किया

गया। इस दौरान राज्य आयुक्त ने कहा कि निःशक्तता विभाग का दायित्व ही पूरी तौर पर दिव्यांगों के लिए समर्पित है। हमारे माध्यम से समाज के अंतिम दिव्यांग तक सरकार की ओर से उनके लिए चलायी जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही एकमात्र लक्ष्य है। इसके लिए समाज के हर जगह में जाकर एक-एक दिव्यांग से मिलने का काम किया जा रहा है। ताकि पेंशन के अलावे उनके आवास, शौचालय, ट्राइसाइकिल,

स्वास्थ्य सहित अन्य सभी समस्याओं को जानकर उसका तत्काल निदान किया जायेगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र में आने वाले सभी दिव्यांगों की पहचान कर उन्हें होने वाली असुविधाओं से विभाग को अवगत कराने व उन्हें हर प्रकार से सहायता दिलाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग की सहायक निदेशिका गायत्री कुमारी ने बताया कि दिव्यांगों को रोजगार में चार फीसदी आरक्षण मिल रहा है। इसके लिए उन्हें प्रमाणपत्र दिया जाता है। वहीं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश व गरीबी निवारण योजनाओं में आरक्षण आदि का लाभ दिलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को विवाह प्रोत्साहन, स्वरोजगार ऋण योजना, संबल योजना का लाभ दिया जाता है।

### कार्यक्रम | निःशक्तता के राज्य आयुक्त ने जनप्रतिनिधियों को अपने यहां मौजूद हर एक दिव्यांग को लाभ दिलाने का किया आह्वान

## समाज के अंतिम दिव्यांग तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही है लक्ष्य

दिव्यांगों को होने वाली असुविधाओं से विभाग को अवगत कराने का आह्वान

दिव्यांगजनों को रोजगार में मिल रहा 4 फीसदी तक आरक्षण

चलन्त न्यायालय के माध्यम से आज होगा परिवारों का निपटारा



# समस्तीपुर जिला

## 4526

शिकायतें दर्ज हुई चलंत न्यायालय में

## 1067

दिव्यांगों का बनाया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र

14 | फरवरी | 2020 चलंत न्यायालय



80 को दिव्यांगता प्रमाणपत्र, 16 को रेलवे रियायत एवं 35 दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड का लाभ दिया गया। वहीं 465 दिव्यांगों को मनरेगा का जॉब कार्ड, 195 को इंदिरा आवास व 225 दिव्यांगों को राशन कार्ड का लाभ दिलाया गया।

## जि

ला दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग, समस्तीपुर द्वारा चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया। जितवारपुर स्थित डीआरसीसी पसिर स्थित चलंत लोक अदालत का उद्घाटन राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने किया। इस दौरान अधिकारियों ने दिव्यांगजनों के लिए केंद्र व राज्य सरकार के स्तर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन दिव्यांगजन की समस्या है, उससे संबंधित विभागों का काउंटर बनाया गया है। इन काउंटर पर एक-एक कर दिव्यांगों ने अपनी शिकायतें दर्ज करायीं। पिछले तीन दिनों से राज्य निःशक्तता आयुक्त द्वारा सभी प्रखंडों में

बैठक कर समीक्षा की गयी। जिसके कारण जिले के विभिन्न क्षेत्रों से दर्जनों दिव्यांगजन लोक अदालत में पहुंचकर अपनी समस्याओं को रखा। जिसमें कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। वहीं अन्य आवेदन को संबंधित विभाग के पास भेजकर दिव्यांगजन को एक तिथि का निर्धारण किया गया। दिव्यांगजनों के लिए आयोजित चलंत लोक अदालत में कुल 4526 मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें लाभांशित किया गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 1067 को लाभ दिया गया। इसमें 80 को दिव्यांगता प्रमाणपत्र, 16 को रेलवे रियायत एवं 35 दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड का लाभ दिया गया। वहीं 465 दिव्यांगों को मनरेगा का जॉब कार्ड, 367 को इंदिरा आवास व 457 दिव्यांगों को राशन कार्ड का लाभ दिलाया गया। राज्य निःशक्तता आयुक्त ने कहा कि मॉल, होटल, दुकान या फिर वैसे संस्थान जहां कम से कम बीस या फिर उससे अधिक कर्मी कार्यरत हैं, तो उस स्थान पर एक दिव्यांगजन कर्मी की उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसे संस्थान पर अगर दिव्यांग नहीं हैं और कोई दिव्यांगजन काम की तलाश में आते हैं तो, संस्था के द्वारा उसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। वहीं सरकार की सभी योजनाओं में दिव्यांगजन के लिए पांच प्रतिशत आरक्षित किया गया है।

■ जितवारपुर स्थित डीआरसीसी परिसर में आयोजित चलंत न्यायालय.

## 367

दिव्यांगों को हुआ इंदिरा आवास का आवंटन

## 457

राशन कार्ड की शिकायतें



## 465

दिव्यांगों को दिया गया मनरेगा का जॉब कार्ड



18 | फरवरी | 2020



लखीसराय



## रामगढ़ चौक प्रखंड

राज्य आयुक्त 19 फरवरी को सदर अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। 20 फरवरी को स्थानीय गांधी मैदान में दिव्यांगजनों की समस्याओं का चलंत न्यायालय के माध्यम से ऑन द स्पॉट निराकरण भी किया जायेगा।



7000 सोशल मीडिया से जुड़े

- सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं संचालित
- दिव्यांगों के लिए पांच फीसदी आरक्षण का किया गया है व्यवस्था
- सामुदायिक भवनों, सरकारी भवनों में दिव्यांगों की सुविधा के लिए बनाये जाये रैंप



■ अपनी समस्याओं को लेकर शिविर पहुंचे फरीयादी।

## अधिकारियों के साथ बैठक



दिव्यांगों के कल्याण के लिए चलायी जा रही योजनाओं तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रति अधिकारियों में संवेदनशीलता लाने के उद्देश्य से बिहार के राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार लखीसराय पहुंचे। उन्होंने समाहरणालय कक्ष में जिला स्तरीय विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं है।

सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उन योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों को मिले, उनके साथ किसी प्रकार की गैर बराबरी नहीं हो। आपका छोटा प्रयास

दिव्यांगजनों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने बैठक के दौरान पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों के लिए समता और अविभेद, उनके सामुदायिक जीवन संरक्षण और सुरक्षा, प्रजनन अधिकार, मतदान में पहुंच, विधिक सामर्थ्य, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं स्वनियोजन, समान अवसर की नीति, सामाजिक सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की देखरेख, बीमा स्कीमें, संरक्षता के लिए उपबंध, पुनर्वास, शिक्षण, हिंसा और शोषण से संरक्षण सहित अन्य अधिकार सुनिश्चित किये गये हैं।

उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए पांच फीसद आरक्षण की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि बैंकों एवं अन्य सरकारी भवनों, सामुदायिक भवनों में दिव्यांगों की सुविधा के लिए रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को ऐसे सभी भवनों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही सभी विभाग के पदाधिकारियों को अपने क्षेत्राधीन विगत तीन वर्ष में दिव्यांगों के कल्याण के लिए किये गये कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।





19 | फरवरी | 2020



लखीसराय



उसी प्रकार परिवर्तित योजना के माध्यम से भी दिव्यांगों को लाभान्वित किये जाने की व्यवस्था है। इसके अलावा दिव्यांगों को मनरेगा के माध्यम से वरुष कार्ड, श्रम संसाधन विभाग की ओर से श्रम कार्ड दिये जाने का प्रवाधान है। विवाह प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, भूमिहीन दिव्यांगों को प्रावधान के अनुसार भूमि उलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है, सभी निकायों में विकास बजट का पांच प्रतिशत राशि दिव्यांगजन के लिए खर्च किये जाने का प्रावधान है।



कार्यक्रम में सबकी समस्या सन्तुते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

## जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक

ल

खीसराय जिला परिषद सभागार में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों, मुखिया, प्रमुख, उपप्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, वार्ड पार्षदों के साथ दिव्यांगों के कल्याण के लिए संचालित सरकारी योजनाओं एवं कानूनी प्रावधानों के विषय में उन्मुखीकरण कार्यशाला को संबोधित करते हुए बिहार के राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगों के जीवन में गुणात्मक एवं रचनात्मक सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है एवं इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति काफी प्रतिभाशाली होते हैं आवश्यकता है उन्हें पहचानने

की एवं निखारने की। आप जानते हैं कि थॉमस एडिसन, ग्राहम बेल जैसे लोग दिव्यांग होते हुए वैज्ञानिक हुए, जिनके अनुसंधान से आज दुनिया को लाभ मिल रहा है। इस कड़ी में उन्होंने बिल गेट्स की उपलब्धियों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि दिव्यांग शारीरिक एवं मानसिक चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं जरूरत इस बात की है कि हमारा और आपका सहयोग एवं संबल उन्हें मिले, तो वे काफी आगे जा सकते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उनके कल्याण के लिए कई सरकारी योजनाएं संचालित हैं। सरकार दिव्यांगों के कल्याण के लिए कृत्संकल्पित है। उन्होंने बताया कि पूर्व में सात प्रकार की दिव्यांगता के लिए ही प्रमाणीकरण किये जाते थे परंतु अब नये कानूनी अधिकार के माध्यम से 21 प्रकार की दिव्यांगता के तहत दिव्यांगों को सुविधा एवं सहूलियत प्रदान की जा रही हैं। ऐसी सभी दिव्यांगता के लिए चलंत न्यायालय में दिव्यांगता प्रमाणपत्र तत्क्षण मुहैया कराने की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा भी कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपनी समस्याओं के लिए चलंत न्यायालय में भाग ले सकते हैं। उन्होंने सरकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि कुष्ठ रोगियों के लिए पंद्रह सौ रुपये प्रतिमाह की राशि दिये जाने का प्रावधान है।



3200

सोशल मीडिया से जुड़े



300

से अधिक जनप्रतिनिधियों व दिव्यांगजनों ने लिया बैठक में हिस्सा



सभी निकायों में विकास बजट का पांच प्रतिशत दिव्यांगों पर खर्च करने का प्रवाधान



20 | फरवरी | 2020



लखीसराय



स्वास्थ्य केंद्रों पर दिव्यांग प्रमाणीकरण होगा। उन्होंने दिव्यांगों से अपील की कि आप अपने संबंधित प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर अपना दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार पिछले तीन दिनों से लखीसराय के दौरे पर हैं।



■ कार्यक्रम में फरियाद सनुते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

## चलंत न्यायालय

3744

कुल मामले आये चलंत न्यायालय में

252

मामले बैंक से ऋण

संबंधी आये, जिनका हुआ निपटारा

1008

दिव्यांगों को ऑन

द स्पॉट मिला दिव्यांगता प्रमाणपत्र

रा

ज्य निःशक्तता आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी शोभेंद्र कुमार चौधरी की मौजूदगी में जिला प्रशासन की ओर से दिव्यांगजनों की समस्याओं के तत्क्षण निष्पादन को लेकर गांधी मैदान में आयोजित चलंत न्यायालय में हजारों की संख्या में

दिव्यांगों की समस्याओं का निराकरण किया गया। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगों की समस्याओं को सुनकर तत्काल उन्हें वांछित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए चलंत न्यायालय में आदेश पारित किये। इस दौरान कुल 3744 आवेदन न्यायालय के समक्ष आये, जिसमें बैंक लोन से संबंधित 252 मामला 1008 लोगों को ऑन द स्पॉट विभिन्न प्रकार का प्रमाणपत्र

दिया गया। इस दौरान रामगढ़ चौक के फेंकू भगत एवं विभिन्न प्रखंडों से आये घोल्टन मंडल, कुंती देवी, बुधनी देवी, कृष्णा महतो, लक्ष्मी रजक, सबिला खातुन, बाल सुंदर तांती, भरत कुमार पासवान, जगदेव सिंह, शंभु कुमार, सुमित कुमार सहित हजारों की संख्या में दिव्यांगों को प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम कार्ड, रेलवे कंसेशन पास, ट्राइसाइकिल, सामाजिकसुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, रोजगार के लिए ऋण सहित अन्य विभिन्न योजनाओं का लाभ उनकी अहर्ता एवं वांछित योग्यता के अनुसार दिलाने के लिए अनुशासित किया गया।

सहायक निदेशक समाजिक सुरक्षा कोषांग राकेश कुमार ने बताया कि जिन दिव्यांगों का आज के चलंत न्यायालय में दिव्यांगता प्रमाणपत्र नहीं बन पाया है। उनके लिए भी उनके संबंधित प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्रों पर दिव्यांग प्रमाणीकरण होगा। उन्होंने दिव्यांगों से अपील की कि आप अपने संबंधित प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर अपना दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार पिछले तीन दिनों से लखीसराय के दौरे पर हैं।



23 | फरवरी | 2020



शिविर  
आयोजित



■ थैलेसीमिया शिविर में भाग लेते केंद्रीय माननीय मंत्री श्री अश्वनी चौबे।



थैलेसीमिया  
से अब नहीं  
मरेंगे पीड़ित

इस अधिनियम के  
तहत प्रधानमंत्री  
रोजगार सृजन  
कार्यक्रम के अंतर्गत  
महिला दिव्यांग को स्वयं  
के पांच फीसदी अंशदान  
पर ग्रामीण क्षेत्र में 25  
फीसदी अनुदान दिया  
जायेगा।



इस बीमारी  
से पीड़ित बच्चों का राज्य  
सरकार बनायेगी दिव्यांगता  
प्रमाणपत्र

थैलेसीमिया से पीड़ित  
लोगों के इलाज के लिए  
सरकार करेगी हरसंभव मदद



300

से अधिक  
थैलेसीमिया  
पीड़ित बच्चों  
का शिविर में  
किया गया  
जांच

रा

ज्य भर के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए पटना के प्रेस क्लब परिसर में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। जांच शिविर में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि अब दिव्यांगों को सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। इन बच्चों को राज्य सरकार दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगी।

इस शिविर में राज्य भर से 300 से अधिक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे अपने माता-पिता और भाई-बहन के साथ पहुंचे थे। इससे पूर्व शिविर का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने कहा कि थैलेसीमिया पीड़ित एक भी बच्चे को सरकार मरने नहीं देगी। केंद्र सरकार राज्य सरकार

के साथ मिलकर हरसंभव सहयोग करेगी। इन बच्चों की चिकित्सा के लिए हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

मौके पर उन्होंने पद्मश्री समाजसेवी बिमल जैन को सम्मानित किया और कहा कि इनके प्रयास से हजारों दिव्यांगों को नयी जिंदगी मिली है। शिविर के संयोजक नंद किशोर अग्रवाल ने बताया कि पहली बार निर्धन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है। समिति के अध्यक्ष सुशील संदरका ने बताया कि थैलेसीमिया एक गंभीर बीमारी है और इसके मरीजों को कुछ दिनों पर खून चढ़ाने की जरूरत होती है।

निजी क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए पांच प्रतिशत पद रहेंगे सुरक्षित : उद्योग विभाग ने निर्णय लिया है कि राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद के तहत

स्थापित किसी भी औद्योगिक यूनिट में पांच फीसदी पद दिव्यांगों के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे। यह निर्णय एक अप्रैल को शुरू होने वाले नये वित्तिय वर्ष में प्रभावी किया जायेगा।

दिव्यांगों खासकर वार विडो, थर्ड जेंडर और एसिड अटैक पीड़िता की तरफ से अगर नया उद्यम स्थापित किया जाता है तो, ब्याज की दर 11.5 प्रतिशत या कर्ज पर वास्तविक ब्याज की दर सामान्य से कम रखी जाएगी। हाल ही में उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में यह निर्णय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का पालन कराने की दीशा में उठाया गया है। इस अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत महिला दिव्यांग को स्वयं के पांच फीसदी अंशदान पर ग्रामीण क्षेत्र में 25 फीसदी अनुदान दिया जायेगा।



क्र०सं०	वाद सं०	जिला	वादी एवं प्रतिवादी	विषय
78.	78/2019	सिवान	वादी :- श्री रजनीश कुमार शाही, सिवान प्रतिवादी :- सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान एवं अन्य	पेंशन राशि के भुगतान के संबंध में
79.	79/2019	दरभंगा	वादी :- श्री धिरोज कुमार झा, दरभंगा प्रतिवादी :- जिला पदाधिकारी, दरभंगा	चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति से संबंधित
80.	80/2019	बेगूसराय	वादी :- श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव प्रतिवादी :- सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बेगूसराय एवं अन्य	पेंशन के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में
81.	81/2019	बेगूसराय	वादी :- श्री बिरजू कुमार, बेगूसराय प्रतिवादी :- सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बेगूसराय	पेंशन से संबंधित
82.	82/2019	पटना	वादी :- श्री माहिम राय, पिता-श्री रंजित प्रसाद, पटना प्रतिवादी :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना	शिक्षक नियोजन 2019-20 में दिव्यांग के लिए रोस्टर प्वाइंट- 13 जारी करने के संबंध में
83.	83/2019	सहरसा	वादी:- श्री शिवशंकर कुमार, सहरसा प्रतिवादी :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा	शिक्षक नियोजन 2019-20 में दिव्यांगजनों के लिए अनुमान्य रिक्ति का स्पष्ट प्रकाशित नहीं किये जाने के संबंध में
84.	84/2019	नालंदा	वादी :- श्री माहिम राय, नालंदा प्रतिवादी :- सभी जिला के 'जिला शिक्षा पदाधिकारी', बिहार एवं अन्य	शिक्षक नियोजन 2019-20 में दिव्यांगजनों के लिए अनुमान्य रिक्ति का स्पष्ट प्रकाशित नहीं किये जाने के संबंध में
85.	85/2019	मोतिहारी	वादी :- श्री दिलीप कुमार, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण प्रतिवादी :- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एवं अन्य	दृष्टिबाधित विद्यार्थी को दाखिल से इनकार करने के संबंध में
86.	86/2019	खगड़िया	वादी :- श्री रोहित कुमार, खगड़िया प्रतिवादी :- उप सचिव, (बजट) नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना, बिहार एवं अन्य	आवंटन के अभाव में नौ माह से वेतन नहीं मिलने के संबंध में
87.	87/2019	सिवान	वादी :- श्री प्रिंस कुमार, सिवान प्रतिवादी :- सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान, बिहार एवं अन्य	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनवाने के क्रम में उत्पन्न हो रही कठिनाइयों के संबंध में
88.	88/2019	पटना	वादी :- श्री ऋषि कुमार, पिता-श्री संतोष कुमार मेहता, पटना। प्रतिवादी :- सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना एवं अन्य	दिव्यांगता पेंशन भुगतान की स्वीकृति के अनुमोदन के संबंध में
89.	89/2019	पटना	वादी :- श्री अतुल रंजन, पटना प्रतिवादी :- श्री मनीष रंजन एवं राधा कुमारी, पटना	मानसिक रूप से प्रताड़ित



# मार्च 2020



**मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने की अपील की है**  
बिहार के अंतरराष्ट्रीय पारा एथलीट शरद कुमार ने कोरोना महामारी (कोविड - 19) से निपटने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में एक लाख रुपया दान दिया है।

pg-167



**दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए...**

pg-159



**राज्य निःशक्तता आयुक्त...**

pg-160



**प्रखंडों का निरीक्षण**

pg-161



**प्रखंड अधिकारियों के साथ बैठक...**

pg-162



**149 दिव्यांगों को ऑन द स्पॉट**

pg-163



**दिव्यांगों को मिला अधिकार...**

pg-164

# MARCH 2020



05 | मार्च | 2020



# अररिया



■ आयुक्त ने अपने पांच दिवसीय यात्रा के पहले दिन आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए

**7023** पंचायतों का अबतक जाना है



**320000**

दिव्यांग अब तक हो चुके हैं लाभान्वित



**20** से ज्यादा संख्या वाली कंपनी में एक दिव्यांग की नियुक्ति जरूरी

**23000** से अधिक शिकायतें टॉल फ्री नंबर पर की जा चुकी हैं दर्ज



दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण के क्रम में अररिया पहुंचे राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने अपने पांच दिवसीय यात्रा के पहले दिन आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। पांच दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज के मुख्यधारा में शामिल करने के लिए केंद्र व राज्य स्तर पर कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इन

योजनाओं के शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के लिए वे अब तक राज्य के 36 जिलों का भ्रमण कर चुके हैं।

इस क्रम में राज्य के 454 प्रखंड अंतर्गत लगभग सात हजार 23 पंचायतों का भ्रमण अब तक संपन्न हो चुका है। इस क्रम में 3.5 लाख दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं। राज्य आयुक्त ने कहा कि यात्रा के क्रम में वे विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक करेंगे। दिव्यांगजनों को जरूरी आर्थिक मदद के लिए बैंक अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक प्रस्तावित है। इस क्रम में वे जिले के सभी प्रखंडों में बैठक आयोजित कर निःशक्तजनों के लिए संचालित योजनाओं के अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेंगे। साथ ही योजनाओं का लाभ दिव्यांगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में नौ मार्च को दिव्यांगजनों से संबंधित परिवादों के त्वरित निष्पादन के लिए चलंत लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सीमांचल क्षेत्र में दिव्यांगता का मामला ज्यादा है। लिहाजा दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक किये जाने की जरूरत है। तमाम तरह के लोक कल्याणकारी योजनाओं में दिव्यांगजनों को पांच

प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। साथ ही वैसे संस्था जहां 20 से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। वहां एक दिव्यांग को निश्चित रूप से काम पर रखने का प्रावधान है। इतना ही नहीं दिव्यांगजनों से जुड़ी समस्याओं के निपटारा के लिए एक टॉल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। दिव्यांगजन 8448385590 पर संपर्क कर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। उक्त टॉल फ्री नंबर पर अब तक 23000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुये हैं।

राज्य आयुक्त ने कहा कि अप्रैल 2017 से दिव्यांगता प्रमाणपत्र नये प्रारूप में जारी किया जा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किये जाने के इंतजाम संबंध जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता के क्रम में दी।





06 | मार्च | 2020

# समीक्षात्मक बैठक अररिया जिला



■ दिव्यांगजनों की समस्या की समाधान करते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

श्रेणियों में बांटा गया है दिव्यांगता को, सभी श्रेणी के दिव्यांगों को मिलता है लाभ

**18348**

कुल संख्या है अररिया जिले में दिव्यांगों की

मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत तीन लाख तक अनुदान



**21**

राज्य निःशक्तता

आयुक्त डॉ. शिवाजी

कुमार ने समाहरणालय

स्थित सभा भवन में अलग-

अलग विभाग के पदाधिकारियों

के साथ समीक्षात्मक बैठक कर

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम

की जानकारी दी। इस अवसर पर

उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन को उनके

अधिकार के प्रति जागरूक करना

जरूरी है। अधिकारी दिव्यांगजनों से

बात करें। गले मिलें और हाथ मिलाया

ताकि उनको एहसास नहीं हो कि

वे आम लोगों से अलग हैं। उन्होंने

कहा कि दिव्यांगों के लिए संचालित

योजनाओं का लाभ भी दिलायें। इसमें

विलंब न करें। राज्य आयुक्त ने बताया

कि दिव्यांगता की कुल 21 श्रेणियां

होती हैं, इसी क्रम में उन्होंने सभी विभागों को दिव्यांगजनों को दिये जा रहे एवं पूर्व में दिये गये लाभ की विस्तृत रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने सभी सरकारी कार्यालय में रैंप की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना, कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण सुविधा योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को रोजगार के लिए सरकारी विभाग में चार प्रतिशत और निजी क्षेत्र में पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। वहीं बैठक में बताया गया कि जिले में दिव्यांगजनों की संख्या 18348 है। इसके पूर्व राज्य आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने रानीगंज व भरगामा प्रखंड में प्रखंडस्तरीय बैठक में भी भाग लिया। बैठक में उन्होंने दिव्यांगजनों की समस्या सुनी व समस्या के निराकरण को लेकर संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही वह रानीगंज प्रखंड के हांसा पंचायत का औचक निरीक्षण भी किया। जबकि बैठक के बाद वे शहर

स्थित एक माल भी पहुंचे। माल में दिव्यांगजनों के लिए रैंप व शौचालय की सुविधा नहीं देखे जाने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने 15 दिनों के अंदर दोनों तरह की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश वहां के प्रबंधक को दिया।

भरगामा प्रखंड मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। जागरूकता के अभाव में कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक योजनाओं यथा आवास, भूमि, कृषि, पशुपालन, मनरेगा, जनवितरण आदि में पांच प्रतिशत का लाभ मिलता है। उन्होंने मनरेगा पीओ सुधांशु शेखर को एक सप्ताह के अंदर दिव्यांगों को जांब कार्ड देने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना का लाभ दिव्यांगों के लिए

## सभी कार्यालयों में निःशक्त जनों के लिए रैंप व शौचालय सुनिश्चित कराए



07 | मार्च | 2020



**अररिया**



**प्रखंडों का निरीक्षण**



- दिव्यांगजनों की शिकायतों को गंभीरता से लें अधिकारी और दिलायें योजनाओं का लाभ
- दिव्यांगों को परेशान करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

**रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी विभाग में चार प्रतिशत व निजी क्षेत्र में पांच प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान हैं। इसके बाद राज्य आयुक्त ने आंगनबाड़ी कर्मी, विकास मित्र व बुनियादी केंद्र के कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की।**



■ दिव्यांगों से बात करते मुख्य अतिथि राज्य निःशक्तता आयुक्त ।



**रा**

ज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने फारबिसगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में विभिन्न विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों व पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिसमें बड़ी संख्या में प्रखंड के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांगजनों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में राज्य आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजन पहले इंसान हैं तब दिव्यांग है। इनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुने व इनका हर संभव सहायता करें। जो सरकारी योजनाएं है उनकी जानकारी दें व समुचित लाभ इन्हें मुहैया करायें।

नरपतगंज प्रखंड कार्यालय पहुंचे राज्य निःशक्तता आयुक्त ने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व दिव्यांगजनों के साथ बैठक की। बैठक में दिव्यांगजनों की समस्या से अवगत हुए। जहां दिव्यांगजन की कई तरह की समस्या



**नरपतगंज प्रखंड**

से अवगत होते हुए स्थानीय पदाधिकारी को कई दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन के साथ एक भी लापरवाही बर्दास्त नहीं होगी। इसके बाद अररिया में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर राज्य आयुक्त ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं। उन्होंने

कहा कि दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी विभाग में चार प्रतिशत व निजी क्षेत्र में पांच प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान हैं। इसके बाद राज्य आयुक्त ने आंगनबाड़ी कर्मी, विकास मित्र व बुनियादी केंद्र के कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की।





08 | मार्च | 2020



# अरुणिया



## प्रखंड अधिकारियों के साथ बैठक



3000

से अधिक दिव्यांगों ने विभिन्न प्रखंडों में आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा

साथ ही मुख्यालय पहुंचे दिव्यांगजनों की शिकायतें भी सुनी। उन्होंने मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी दिव्यांगों की शिकायतों का जल्द निपटारा किया जाये।



■ दिव्यांगों की समस्या सुनते मुख्य अतिथि राज्य निःशक्तता आयुक्त ।

### नरपतगंज में एमओ व मनरेगा पीओ के वेतन पर रोक

नरपतगंज | 08 मार्च 2020

#### कार्रवाई

- राज्य निःशक्तता आयुक्त ने सी.एम.ओ., नरपतगंज का अयोग्य
- शिक्षणन ही संन्यास में सहायी का विवरण प्रस्तुत



नरपतगंज प्रखंड मुख्यालय पीओ के वेतन पर रोक लगा दी। राज्य निःशक्तता आयुक्त ने सी.एम.ओ., नरपतगंज का अयोग्य माना और उनके वेतन पर रोक लगा दी। उन्होंने सी.एम.ओ. को प्रखंड विकास पदाधिकारी के वेतन पर रोक लगा दी। उन्होंने सी.एम.ओ. को प्रखंड विकास पदाधिकारी के वेतन पर रोक लगा दी। उन्होंने सी.एम.ओ. को प्रखंड विकास पदाधिकारी के वेतन पर रोक लगा दी।

रा

ज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने पलासी मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी। राज्य आयुक्त ने अधिकारियों

को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि दिव्यांगों की समस्याओं को हल कराने में किसी तरह की आनाकानी नहीं करें। इस क्रम में उन्होंने एक दिव्यांग बच्ची को अपने समीप कुर्सी पर बैठाया और उसकी हौसला अफजाई की। कहा कि पंचायतों में कम से कम 15 दिनों पर व प्रखंड मुख्यालय में माह में कम से कम

एक बार दिव्यांगों की बैठक होनी जरूरी है। बैठक में आयुक्त ने कहा कि 21 प्रकार के दिव्यांगों का सर्वे कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलायें। सरकारी योजना के तहत भूमिहीन को भूमि देने, रेलवे आरक्षण सहित अन्य सुविधाएं देने का प्रावधान है।

पलासी प्रखंड कार्यालय पहुंचे राज्य निःशक्तता आयुक्त ने प्रखंड अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। साथ ही मुख्यालय पहुंचे दिव्यांगजनों की शिकायतें भी सुनी। उन्होंने मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी दिव्यांगों की शिकायतों का जल्द निपटारा किया जाये। इन्हें मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड और पेंशन स्कीम का जल्द से जल्द लाभ दिलाया जाये।

### पलासी प्रखंड



11 | मार्च | 2020



## चलंत न्यायालय

# 149 दिव्यांगों को ऑन द स्पॉट यूडीआइडी कार्ड

अ

ररिया शहर के टाउन हॉल में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस शिविर में दूर दराज से दिव्यांग पहुंचे। दिव्यांगों की अप्रत्याशित भीड़ उमड़ने पर राज्य आयुक्त ने 28 मार्च को सभी प्रखंडों में शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य निःशक्तता आयुक्त ने कहा कि चलंत न्यायालय में आये हुए जो भी दिव्यांग वंचित रह गये हैं उनके लिए 28 मार्च को शिविर आयोजित की जाएगी। निःशक्तता विभाग के आंकड़ों के अनुसार 6500 दिव्यांगों का निबंधन किया गया, जिसमें 350 दिव्यांगों का प्रमाणपत्र बनाया गया। 149 दिव्यांगों के यूडीआइडी कार्ड बनाये गये। बैंक एलडीएम ने 15 दिव्यांगों का लोन का आवेदन पत्र प्राप्त किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य निःशक्तता आयुक्त ने कहा कि चलंत न्यायालय में आये हुए जो भी दिव्यांग वंचित रह गये हैं उनके लिए 28 मार्च को शिविर आयोजित की जाएगी। निःशक्तता विभाग के आंकड़ों के अनुसार 6500 दिव्यांगों का निबंधन किया गया, जिसमें 350 दिव्यांगों का प्रमाणपत्र बनाया गया। 149 दिव्यांगों के यूडीआइडी कार्ड बनाये गये। बैंक एलडीएम ने 15 दिव्यांगों का लोन का आवेदन पत्र प्राप्त किया।



### आयोजन • मुख्यवस्था का शिवाग्र हुआ दिव्यांग शिविर, 28 मार्च को प्रखंड स्तर पर लगेय शिविर चलंत न्यायालय में 6500 दिव्यांगों का किया रजिस्ट्रेशन, 500 को दिया गया प्रमाण-पत्र

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय में चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य निःशक्तता आयुक्त ने कहा कि चलंत न्यायालय में आये हुए जो भी दिव्यांग वंचित रह गये हैं उनके लिए 28 मार्च को शिविर आयोजित की जाएगी। निःशक्तता विभाग के आंकड़ों के अनुसार 6500 दिव्यांगों का निबंधन किया गया, जिसमें 350 दिव्यांगों का प्रमाणपत्र बनाया गया। 149 दिव्यांगों के यूडीआइडी कार्ड बनाये गये। बैंक एलडीएम ने 15 दिव्यांगों का लोन का आवेदन पत्र प्राप्त किया।

- 6500 दिव्यांगों ने लोक अदालत में दर्ज करायी शिकायतें
- 1456 दिव्यांगों को ऑन द स्पॉट दिया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र
- 15 दिव्यांगों ने रोजगार के लिए ऋण के लिए बैंक को दिया आवेदन

कार्यक्रम में फरियाद सनुते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

निःशक्तता विभाग के आंकड़ों के अनुसार 6500 दिव्यांगों का निबंधन किया गया, जिसमें 350 दिव्यांगों का प्रमाणपत्र बनाया गया। 149 दिव्यांगों के यूडीआइडी कार्ड बनाये गये। बैंक एलडीएम ने 15 दिव्यांगों का लोन का आवेदन पत्र प्राप्त किया।





14 | मार्च | 2020

## दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016

# दिव्यांगों को मिला अधिकार



रा

ज्य सरकार बिहार राज्य आवास बोर्ड के भवनों और भूमि के आवंटन में दिव्यांगों को आरक्षण देगी। इसके साथ ही नगर निकायों द्वारा सरकारी भूमि पर निर्मित दुकानों के आवंटन में भी पांच फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा। नगर विकास विभाग ने दिव्यांगों को आरक्षण देने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड और सभी नगर निकायों को आवंटन के प्रावधानों में बदलाव करने का निर्देश दिया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों



और सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में दिये गये निर्णय के तहत दिव्यांगों को ये सुविधाएं दी जानी है। विभाग ने बिहार राज्य आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के अलावा चारों स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशक, नगर आयुक्त और नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को इन प्रावधानों को लागू करने का निर्देश दिया है।



इसके अलावा शहरों में बनने वाले सभी व्यावसायिक भवनों में दिव्यांगों की सुविधा के लिए रैंप का निर्माण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए बिल्डिंग बायलॉज में भी बदलाव की अनुशंसा की गयी है। व्यावसायिक परिसरों का नक्शा पास कराने के लिए भवनों में रैंप का प्रावधान अनिवार्य किया गया है। स्मार्ट सिटी की योजनाओं में दिव्यांगों के लिए जरूरी सुविधा को शामिल किया जायेगा। इसकी प्लानिंग में दिव्यांगों के लिए सुगम्यता, बाधारहित परिसर और वातावरण उपलब्ध कराने का प्रावधान शामिल करने का निर्देश दिया गया है। नगर विकास विभाग के सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्रों के फुटपाथ और सड़कों के डिवाइडरों का निर्माण दिव्यांगों की सुविधा के अनुसार किया जाये।

## आवास बोर्ड और निकायों की जमीन पर बनी दुकानों में दिव्यांगों को 5% आरक्षण

व्यावसायिक परिसरों में नक्शा पास कराने के लिए रैंप का निर्माण होगा अनिवार्य

बिहार सरकार

राज्य सरकार बिहार राज्य आवास बोर्ड के भवनों और भूमि के आवंटन में दिव्यांगों को आरक्षण देगी। इसके साथ ही नगर निकायों द्वारा सरकारी भूमि पर निर्मित दुकानों के आवंटन में भी पांच फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा। नगर विकास विभाग ने दिव्यांगों को आरक्षण देने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड और सभी नगर निकायों को आवंटन के प्रावधानों में बदलाव करने का निर्देश दिया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में दिये गये निर्णय के तहत दिव्यांगों को ये सुविधाएं दी जानी है। विभाग ने बिहार राज्य आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के अलावा चारों स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशक, नगर आयुक्त और नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को इन प्रावधानों को लागू करने का निर्देश दिया है।

### पहाड़ी इलाकों में जल संचय के लिए बनेगा कार्लैड-टैंक

पटना : प्रदेश के पहाड़ी व जंगली इलाकों में जल संचय के लिए कार्लैड-टैंक का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत मातृ कृषि का निर्माण किया जायेगा। कार्लैड-टैंक जल संचयन व जल संचयन में मदद करता है। जल संचयन विभाग के अलग अलग विभागों को आरक्षण के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा चारों स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशक, नगर आयुक्त और नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्रों के फुटपाथ और सड़कों के डिवाइडरों का निर्माण दिव्यांगों की सुविधा के अनुसार किया जाये।

नगर विकास विभाग के सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्रों के फुटपाथ और सड़कों के डिवाइडरों का निर्माण दिव्यांगों की सुविधा के अनुसार किया जाये।



14 | मार्च | 2020



# खेलकूद

## दिव्यांग व सामान्य खिलाड़ियों की प्रतियोगिता एक साथ

बि

हार देश का दूसरा बड़ा राज्य है, जहां दिव्यांगजनों की संख्या करीब 50 लाख से अधिक है इनके जीवन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार कई महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। इसी के तहत 10 लाख दिव्यांगजन को खेलकूद से जोड़ने का प्रयास शुरू हो गया है। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने इसके लिए अब तक 26 जिला खेल संघों के साथ चर्चा कर इसे पूर्ण रूप देने की तैयारी की है। फिलहाल किसी भी खेल संघ द्वारा दिव्यांग खेलों का आयोजन नहीं कराया जाता है। राज्य में दिव्यांग खेलकूद के आयोजन की पूरी जिम्मेदारी बिहार पैराओलिंपिक कमेटी के जिम्मे है। बिहार की पैरालिंपिक कमेटी की शुरुआती ट्रेनिंग के दम पर ही शरद कुमार और अर्जुन अवाडी प्रमोद भगत जैसे पैरा एथलीट दुनिया में राज्य का नाम रोशन करने में सफल रहे हैं।

राज्य निःशक्तता आयुक्त ने बताया कि राज्य में दिव्यांगजनों के समावेशी विकास के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के धारा में यह निहित है कि जहां पर सामान्य बच्चों के लिए खेलकूद की व्यवस्था हो। वहीं पर दिव्यांगों के लिए भी सारी सुविधा उपलब्ध हो, जिस तरह से ओलिंपिक खेलों का आयोजन जहां होता है। वहीं पर पैरालिंपिक खेलों का भी आयोजन कराया जाता है। उसी तरह राज्य में भी ऐसी व्यवस्था सभी राज्य खेल संघों को मिलकर करनी होगी। इसके लिए राज्य संघों को अलग से खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अन्य क्षेत्रों में भी इसी कानून के तहत दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने की जरूरत है।



Search Twitter

999

Log in

Sign up



Narendra Modi @narendram... · 14m

I met the remarkable @satendr91697923, who is an outstanding para-swimmer. He has won several laurels and his life journey can motivate many. Sometime back, he swam across the Catalina Channel.

Best wishes to this bright athlete.



ट्वीटर पर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते प्रधानमंत्री।

### दिव्यांग व सामान्य खिलाड़ियों की प्रतियोगिता एक साथ

वहीं पर पैरालिंपिक खेलों का भी आयोजन कराया जाता है। उसी तरह राज्य में भी ऐसी व्यवस्था सभी राज्य खेल संघों को मिलकर करनी होगी। इसके लिए राज्य संघों को अलग से खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अन्य क्षेत्रों में भी इसी कानून के तहत दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने की जरूरत है।



10 लाख दिव्यांगजनों को खेल से जोड़ने का हो रहा है प्रयास

26 जिला खेल संघों के साथ अबतक हो चुकी है बैठक

30 में निहित है यह व्यवस्था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के धारा



29 | मार्च | 2020



पटना

# कोरोना महामारी



बि

हार के अंतरराष्ट्रीय पारा एथलीट शरद कुमार ने कोरोना महामारी (कोविड -19) से निपटने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में एक लाख रुपया दान दिया है। शरद के पिता सुरेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शरद फिलहाल अपनी तैयारियों के सिलसिले में यूक्रेन में है। इनसे पहले बिहार के रहने वाले क्रिकेटर इशान किशन ने कोरोना पीड़ितों के लिए 2.5 लाख रुपये दान किये थे।

शरद ने देश भर के लोगों से हौसला बनाये रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अपने संदेश में कहा कि पूरे लॉकडाउन तक घर में रहें और सुरक्षित रहें। बहुत जरूर हो तभी घर से बाहर निकलें और अगर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग जरूर करें। आपकी एक छोटी सी गलती सैकड़ों लोगों को संक्रमित कर सकती है।

शरद ने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर बिहार और देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने लंदन में हुई विश्व पारा एथलेटिक्स के लांग जंप में रजत पदक जीता था। इसके बाद एशियन पारा एथलेटिक्स में भी देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था. उनके उत्कृष्ट खेल के लिए बिहार सरकार उन्हें सम्मानित भी कर चुकी है।

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने भी राज्य में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों व अधिकारियों से मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने की अपील की है, ताकि इस महामारी को हराया जा सके।

कोविड-19 से लड़ने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी और अधिकारी सरकार की करें मदद

लॉकडाउन का पालन कर इस महामारी को हम सबको मिलकर हराना है

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने भी राज्य में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों व अधिकारियों से मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने की अपील की है, ताकि इस महामारी को हराया जा सके।



# SUCCESS STORY

दिव्यांग होना अभिशाप नहीं है। यह राज्य के दिव्यांगों ने साबित किया है। हर क्षेत्र खेल, कला, साहित्य, समाजसेवा और प्रशासनिक सेवा में अपने कार्यों का लोहा मनवाया है। इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में सराहनीय कार्य किये। इन्हीं दिव्यांगों की प्रेरणाओं को सक्सेस स्टोरी के रूप में वार्षिक प्रतिवेदन में संकलित किया गया है। जो राज्य के लिए गौरव का विषय है...





## मानव सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया

वा

दोनों पैरों के दिव्यांगता से जुड़ने वाले आमीर उल इस्लाम के पास हौसले की कोई कमी नहीं है। रात हो या दिन हर समय जरूरतमंद लोगों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। पोलियो के कारण दिव्यांग हुए आमीर ने मानव सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। गरीब निस्सहाय लोगों की मदद करना बीमार लोगों को अस्पताल में मुफ्त इलाज कराना, रक्तदान के द्वारा जरूरतमंदों को रक्त की आपूर्ति करवाना अपना दायित्व समझते हैं। लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते पिछले एक माह में 300 से अधिक बीमार लोगों को सदर अस्पताल पहुंचाने का काम किया। पिछले 15 दिनों में संगठनों के सहयोग से 200 जरूरतमंद लोगों को कंबल दिलवाने का काम किया, जो रात में सड़क किनारे सोये हुए थे।

■ मुंगेर (बिहार)

नाम

आमीर उल इस्लाम

इकट्ठा कर सड़क पर रह रहे बेघर लोगों की भूख मिटाने का काम भी करते हैं। दिनभर सामाजिक कार्यों में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। गरीब लड़कियों की शादी में मदद और बच्चों को शिक्षा बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुसार छोटा-मोटा रोजगार दिलाने में सहयोगी की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। आमीर उल इस्लाम यह कहते हैं कि वह कभी भी अपने आपको दिव्यांग महसूस नहीं करते, लेकिन एक वक्त है जब राष्ट्रगान के सम्मान के लिए सब खड़े हो जाते हैं उस वक्त आमीर को लगता है कि इनके पास पैर होता, तो मैं भी राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा हो सकता है। इसलिए मैं अपने खुदा से 52 सेकेंड के लिए पैर देने की भी मांग करता हूं। लोगों के काम आना उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक वक्त था जब 15 साल तक चार दीवारों में गुजारा होता था और बाहर निकलना एक सपने जैसा था और एक चैलेंजिंग जीवन लिए यह मैसेज देना है।

वहीं लोगों के घरों से भोजन

## पहले दृष्टिबाधित उपायुक्त राजेश

बिहार के पटना जिले के रहनेवाले आइएएस राजेश कुमार सिंह ने बोकारो डीसी का पदभार ग्रहण किया। राजेश कुमार को पदभार निवर्तमान डीसी मुकेश कुमार द्वारा प्रदान किया गया। डीसी राजेश कुमार सिंह दृष्टिहीन हैं तथा लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। डीसी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने पहली बार किसी दृष्टिहीन अधिकारी को जिले की कमान सौंपी है। मैं मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव का आभार प्रकट करते हुए उन्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा।

एसडीओ व एडीएम के रूप में काम कर चुके हैं : 2007 बैच के राजेश सिंह ने बतौर डीसी अपनी पहली पदस्थापना के लिए सीएम हेमंत सोरेन के निर्णय को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि चूंकि वह एसडीओ व एडीएम के रूप में काम कर चुके हैं। इसलिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण तो नहीं, परंतु कोरोना काल की विकट परिस्थिति में डीसी के पद पर

काम करना यकीनन एक चैलेंजिंग जॉब होगा। बिहार के रहने वाले हैं राजेश कुमार सिंह: राजेश कुमार सिंह पटना के धनरूआ के गोविंदपुर गांव के रहने वाले हैं। उनके दो भाई और एक बहन हैं। पिता सिविल कोर्ट में काम करते थे। सिर पर चोट लगने से तीसरी कक्षा में ही उनकी दृष्टिबाधित हो गई। आंखों की रोशनी चले जाने के बाद उनका एडमिशन देहरादून के एक स्पेशल स्कूल में कराया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू से भी पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा। राजेश सिंह ने साल 2007 में यूपीएससी की परीक्षा पास की। लेकिन उनकी नियुक्ति लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2011 में हो पाई। वो सुप्रीम कोर्ट तक में गए, जहां उनके हक में फैसला आया। 2013 में उनकी शादी हुई। हौसले बलुंद हो तो दृष्टिहीन होना अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है : पदभार लेने के बाद डीसी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि अगर आपके हौसले मजबूत हैं तथा लक्ष्य निर्धारित है तो, दृष्टिहीन होना कोई अभिशाप नहीं है। भारत में डायवर्सिटी की एक अलग पहचान है। असमानता के बावजूद भी जो इस कसौटी पर बेहतर तरीके से मुकाम हासिल करते हैं, मुझे दृष्टिहीन कमजोरी के रूप में नहीं दिखती बल्कि यह मुझे अन्य लोगों से भिन्न बनाती है। ताकि मैं एक समान सभी को समान अधिकार दिला सकूं। लक्ष्य निर्धारण करते वक्त मुझे किसी का चेहरा नहीं दिखायी देता बल्कि मैं लक्ष्य को लेकर ही चलता हूं।

■ धनरूआ पटना (बिहार)



नाम

राजेश कुमार

## हौसले से बनायी पहचान



खे

तिहर परिवार के धीरज कुमार के लिए सोनपुर मेला देखना तब महंगा पड़ गया जब लौटने के क्रम में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। इस हादसे में उनके दोस्त की मौत हो गयी, लेकिन धीरज बच गये। हालांकि इस हादसे ने उन्हें दिव्यांग बना दिया। इस हादसे में धीरज को स्पाइनल इंज्यूरी हो गयी और उनका शरीर कमर से सून्न हो गया। उनके दोनो पैर काम करना बंद कर दिया। यह घटना 2015 में हुई, जब धीरज की उम्र 22 वर्ष थी

■ आरा (मोजपुर)

हादसे से टूट गये सपने : धीरज बीए की पढ़ाई कर डिफेंस में जाने की तैयारी कर रहे थे। इन्होंने इसके लिए परीक्षा भी दे दी थी और मेडिकल व फीजिकल दोनों ही टेस्ट पास कर लिए थे। लेकिन इस दुर्घटना से इनका फौज में ऑफिसर बनने का सपना टूट कर बिखर गया। काफी लंबे इलाज व फिर

थेरेपी कराते काफी समय गुजरते गये और धीरज अंदर ही अंदर टूटते गये। खुद को संभालने के लिए धीरज ने प्रशिक्षण व पुनर्वास का सहारा लिया। धीरे-धीरे को खुद को संभालने लगे। पहले से खुद को बेहतर समझने लगे।

धीरज अपने में हौसले को संजोना शुरू कर दिया। जिससे वह अपनी नयी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। दिव्यांगता को हराने के लिए धीरज ने खेल को अपना हथियार बनाया। जिसमें बिहार पैरालिंपिक कमेटी ने अहम भूमिका निभायी। धीरज ने पहली बार व्हीलचेयर मैराथन में हिस्सा लिया, जिसमें वह पांचवें स्थान पर रहे। इसके बाद इन्होंने व्हीलचेयर रग्बी में हाथ आजमाया जिसमें इन्होंने सफलता के झंडे गाड़े। अपनी कप्तानी में इन्होंने राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी में बिहार टीम को पहली बार सिल्वर मेडल दिलाया। इसके अलावा दीपक व्हीलचेयर बास्केटबॉल के भी अच्छे खिलाड़ी हैं। दीपक बिहार और ओडिशा दोनों टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

नाम

धीरज कुमार

## खेलकूद ने बनाया संबल

दि

दिव्यांगता अभिशाप नहीं है। यह सामान्य लोगों से बेहतर करने की प्रेरणा है। हर किसी के पास दिव्यांगता से लड़ने का हौसला नहीं होता है, लेकिन जो इससे लड़कर आगे बढ़ता है। उसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी अताउर रहमान की है। बचपन से दोनों पैरों से दिव्यांग अताउर ने दिव्यांगता को हराने के लिए अपनी नयी जिंदगी की शुरुआत खेलकूद से कि और अब वह शिक्षा के क्षेत्र

हरक्षेत्र में बेहतर करना मदद मिला। आज के समय में अताउर रहमान स्कूल में शिक्षक के रूप नियुक्त हैं। ठाकुरगंज प्रखंड के लौधावाड़ी में बतौर शिक्षक अताउर अपना योगदान दे रहे हैं।

में अलख जगा रहे हैं।

अताउर रहमान ने अपनी इस कमजोरी को औजार बनाकर सफलता की सीढ़ियां तय की वह आज किशनगंज जिले के दिव्यांगों के लिए नजीर बन गये हैं। दिव्यांग होने के बाद भी अपनी शारीरिक कमजोरी को अपनी ढाल बनाकर खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य ही नहीं दूसरे राज्यों में भी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इन्होंने खेल में प्रतिभा का परचम लहराया और जिले व राज्य का नाम रोशन किया। ऑल इंडिया दिव्यांग टेबुल टेनिस प्रतियोगिता, राज्यस्तरीय खेलकूद दिव्यांग एथलेटिक्स प्रतियोगिता, राष्ट्रीय पैरालिंपिक प्रतियोगिता सहित प्रमंडलीय स्तर के दर्जनों प्रतियोगिता में भाग लेकर अताउर रहमान ने अपनी योग्यता का लोहा मनवाया।

लोकसभा चुनाव (किशनगंज) में जिले भर के दिव्यांग मतदाताओं के लिए उनका चयन रोल मॉडल के रूप में भी किया गया। राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार से इन्हें हरक्षेत्र में बेहतर करना मदद मिला। आज के समय में अताउर रहमान स्कूल में शिक्षक के रूप नियुक्त हैं। ठाकुरगंज प्रखंड के लौधावाड़ी में बतौर शिक्षक अताउर अपना योगदान दे रहे हैं।

## ■ किशनगंज (बिहार)



नाम

अताउर रहमान





## हादसे से हारे नहीं उठाने लगे औरों का बोझ

हो

नी-अनहोनी जीवन का एक हिस्सा है कहीं बोझ बन जाती है, कहीं औरों का बोझ उठाने वाली जिंदगी। निभर इस बात पर कि कौन इसे किस रूप में लेता है। गोपालगंज जिले के नीतीश कुमार सिंह ऐसे ही शख्स हैं, जिनके साथ हादसा हुआ। वे इससे हारे नहीं, बल्कि औरों का भी बोझ उठाने लगे। एक प्रेरणा कि जीना इसी का नाम है। कुचायकोट प्रखंड के उचकागांव निवासी नीतीश 01 अगस्त 2014 में देवघर से पूजा कर लौट रहे थे उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। गंभीर रूप से जख्मी हो गये। दो साल तक एम्स, दिल्ली में इलाज चला। नयी जिंदगी तो मिली, पर गर्दन के नीचे के हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया। रीढ़ की हड्डी टूट गयी थी। दिव्यांगता जीवन भर की साथी बन चुकी थी, लेकिन व न तो हताश हुए, न जिंदगी से निराश। औरों की खुशी में सुकून ढूंढना शुरू किया। 2018 से एक नये मिशन में

जुट गये। नाते-रिश्तेदारों और मित्रों के साथ मिलकर एक टीम बनायी। चंदा इकट्ठा कर जो पैसे आये, उससे व्हीलचेयर खरीदी और अपने जैसे उन लोगों को भेंट की, जो खरीदने में सक्षम नहीं थे। अब तक तीन दर्जन से ज्यादा व्हीलचेयर बांट चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद दिव्यांगों तक राशन पहुंचाया। वे व्हीलचेयर पर खुद से नहीं बैठ पाते हैं। घर के लोग उठाकर बिठाते हैं, पर नीतीश अपने जैसे और भी दिव्यांगों का सहारा बन चुके हैं। वे मनरेगा में दिव्यांगों के लिए तीन फीसदी आरक्षण की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कुचायकोट के जागीर सेमरा गांव निवासी नागेंद्र सिंह सहित आठ लोगों का दिल्ली में इलाज भी कराया। ये सभी हादसे का शिकार हो दिव्यांग हो चुके थे। ऐसे लोगों के इलाज के लिए चेन्नई की एक संस्था द स्पाइनल फाउंडेशन की भी मदद लेते हैं। थावे प्रखंड के विदेशी टोला निवासी रमेश यादव कहते हैं कि नीतीश ने ही उनमें नयी ऊर्जा भरी। रमेश जिले के नामी पहलवान थे। एक दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी टूट गयी।

नाम

नीतीश कुमार सिंह

गोपालगंज (बिहार)

## दुर्घटना ने व्हीलचेयर पर बैठाया

विषम परिस्थितियों में राह बनानेवाले अक्सर विरले होते हैं, वह भी तब जब सामान्य जीवन से एकाएक दिव्यांग जीवन में इंसान प्रवेश कर जाये। दिव्यांगता के चुनौतियों से पार पाना कोई आम बात नहीं है। इसमें बहुत समय और दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत होती है, जैसे ही लोगों को खुद पर विश्वास बढ़ता है। वह दिव्यांगता को चुनौती देने में कामयाब होते हैं। पटना के अनुराग की भी यहीं कहानी है। 25 वर्षों तक सामान्य जीवन जीने वाले अनुराग को एक हादसे में गोली लग गयी, जिससे उनका शरीर

50 प्रतिशत कार्य करना बंद कर दिया। उन्हें इस हादसे में स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी हुई। उनकी जिंदगी व्हीलचेयर पर सिमट गयी। इच्छाशक्ति भी धीरे-धीरे समाप्त होने लगी। इसी दौरान उनकी मुलाकात राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार से हुई, जिन्होंने उनका सही मार्गदर्शन करने के साथ-साथ हौसला भी बढ़ाया। इसके बाद से अनुराग की जिंदगी में धीरे-धीरे बदलाव शुरू हो गया। उन्होंने अपने जैसे लोगों की मदद करने की राह चुनी। इन्होंने अपने जैसे लोगों का एक व्हाट्सएफ ग्रुप बनाया। इनका मकसद स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी से जुड़े रहे लोगों की हिम्मत बढ़ाना और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा था। इस मकसद से बने इस ग्रुप में बिहार से झारखंड तक के लोग जुड़े। इसके बाद द स्पाइनल फाउंडेशन की स्थापना हुई। करीब 200 लोगों को अब तक इनके द्वारा मदद पहुंचायी गयी है। इस परेशानी से जुड़े रहे लोगों को मोटिवेट करना। उन्हें यह जानकारी देना की आप इस अवस्था में क्या बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए। इन सब बातों को बताया जाता है। उनके अधिकार और लाभ के बारे में जानकारी दी जाती है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से अनुराग लोगों में अलख जगा रहे हैं। वह अपनी इस नयी जिंदगी से खुश हैं। अनुराग कहते हैं अब दूसरों के लिए जीना है। मैं जीन हालातों में कुछ दिनों के लिए था। वैसे हालात दूसरों के साथ न हो इसके लिए मैं हरसंभव प्रयास करूंगा।

अब दूसरों के लिए जीना है। मैं जीन हालातों में कुछ दिनों के लिए था। वैसे हालात दूसरों के साथ न हो इसके लिए मैं हरसंभव प्रयास करूंगा।

पटना (बिहार)



नाम

अनुराग



## समाजसेवा को बनाया अपना लक्ष्य

मु

जफ्फरपुर जिले के मिर्जापुर गांव के रहने वाले शांती मुकुल को बचपन में पोलियो ने अपने चपेट में ले लिया। इसकी वजह से यह एक पैर से दिव्यांग हो गये। इन विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने खुद को समाज में बनाये रखने के लिए हर संभव प्रयास किया और बहुत हद तक सफल भी हुए। अनुबंध समाप्त होने के बाद एकबार फिर शांती बेरोजगार हो गये। नौकरी की तलाश में उनकी मुलाकात उषा मानकी से हुई जो जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल चलाती थी। इन्हीं के द्वारा राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार से मुलाकात हुई। इसके बाद जैसे मेरी जिंदगी में रोशनी आ गयी। इनकी प्रेरणा के बाद मैं पूर्ण रूप से समाज सेवा में लग गया। मैंने एक लक्ष्य बनाया कि सरकारी योजनाओं का लाभ जिले के प्रत्येक दिव्यांगों को दिलाउंगा। मेरे कार्यों को देखते हुए

मुझे जिला स्तरीय दिव्यांग संगठन का सदस्य बनाया गया। मेरी पत्नी कुमारी सरिता भी समाजसेवा के लिए मुझे प्रेरित करते रहती है। वह भी हाथ और पैर से दिव्यांग है। सरिता स्नातक कर चुकी है और प्रतियोगिता परिक्षा की तैयारी कर रही है।

- कार्य के लिए इन सम्मानों से नवाजा गया। ● समाज सेवा के लिए मिला सम्मान ● पुनर्वास और संशाधन केंद्र सम्मान (2007)
- राष्ट्रीय कोचिंग शिविर एथलेटिक्स में प्रमाण पत्र सम्मान (2008) ● महात्मा बुद्ध सम्मान (2008) विशेष ओलंपिक बिहार ● राज्यस्तरी विचार गोष्ठी सम्मान ● जिला खेलकूद में भाग लेने के लिए कोच के रूप में सम्मानित (2018) ● भागवान जानकी स्मृति सम्मान (2019) समाजसेवा ● निर्मल अनुपम फाउंडेशन से सम्मान (2019) मानव सेवा के लिए ● उम्मीद कर्मवीर योद्धा सम्मान (2020) ● हेलेन केलर की 140 वीं जयंती पर प्रशंसा प्रमाणपत्र, राज्य आयुक्त के द्वारा (2020)



■ मुजफ्फरपुर

नाम

शांती मुकुल

## धीरज दिव्यांगों को कर रहे हैं जागरूक

ना

लंदा जिले के थरथरी बाजार के रहने वाले धीरज कुमार दिव्यांगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं। बचपन में पोलियो के शिकार हुए धीरज अपने जिले के दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए वह दिव्यांग जागरूकता मंच बनाकर कार्य कर रहे हैं। धीरज कुमार ने बताया कि राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार से मिलने के बाद दिव्यांगों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सफल हो

दिव्यांगता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए धीरज को अभिमन्यु सम्मान से राज्य पैरालिंपिक कमेटी सम्मानित कर चुकी है। इसके अलावा इन्हें अन्य सम्मान से भी नवाजा गया है।

## 2013 में इन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से स्नातक किया।

रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था, जब मुझे दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनवाने में तीन हप्ता लग गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अपने दिव्यांग मित्रों का प्रमाणपत्र अब कुछ दिनों में ही बन जाता है। यह राज्य आयुक्त की वजह से संभव हो पाया है।

घर से आर्थिक रूप से कमजोर धीरज स्कूल टाइम से ही बच्चों पढ़ाने का काम करते हैं। इसमें भी गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। इसके अलावा इन बच्चों को वह कॉपी किताब भी मुहैया कराते हैं। 2013 में इन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। अब शिक्षा के क्षेत्र में खुद को स्थापित करने के लिए बीइडी कर रहे हैं। इनकी पत्नी इनके हर निर्णय में सहयोग करती है। जिसकी वजह से आज यह दिव्यांगों को मदद करने में सफल हो रहे हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए धीरज को अभिमन्यु सम्मान से राज्य पैरालिंपिक कमेटी सम्मानित कर चुकी है। इसके अलावा इन्हें अन्य सम्मान से भी नवाजा गया है।

■ नालंदा (बिहार)



नाम

धीरज कुमार

## अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शम्स ने बिहार का नाम किया रोशन



“कौ

न कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों।” इस कहावत को मधुबनी के रहने वाले अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराक मो शम्स आलम ने सच कर दिखाया है। वो अब तक कई सारे रिकॉर्ड्स स्थापित कर चुके हैं। इन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक मिल चुका है। पिछले साल 8 दिसंबर को बिहार स्विमिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित मिश्रीलाल मेमोरियल विंटर स्विमिंग कंपटीशन 2019 में फास्टेस्ट पैराप्लेजिक स्विमर का रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने गंगा नदी में सबसे तेज दो किलोमीटर की तैराकी 12:23:04 मिनट में पूरा कर लिया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी रिकॉर्ड के लिए उनका नाम इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। मोहम्मद शम्स बताते

हैं कि इस रिकॉर्ड के लिए उन्होंने पिछले साल हुए मिश्रीलाल मेमोरियल विंटर स्विमिंग कंपटीशन 2019 में रिकॉर्ड बनाने के बाद अप्लाई किया था, जिसके वेरिफिकेशन के बाद उन्हें इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला है। 2019 में बनाये गये फास्टेस्ट पैराप्लेजिक स्विमर के रिकॉर्ड के आधार पर मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया है।

**दो बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ चुका है नाम :** वो आगे बताते हैं कि इससे पहले उनका नाम दो बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ चुका है। साल 2014 में उन्होंने एक घंटा 40 मिनट में 6 किलोमीटर की स्विमिंग मुंबई में आयोजित कंपटीशन में किया था, जबकि साल 2017 में उन्होंने गोवा में आयोजित स्विमिंग कंपटीशन में 8 किलोमीटर की तैराकी की थी।

नाम

शम्स आलम

■ मधुबनी (बिहार)

## पढ़ाई के ललक में 10 दिनों में ब्रेल सीख ली

ज

ज्वा का दूसरा नाम है कविता कुमारी । कविता कुमारी का जन्म सीतामढ़ी जिले के पमरा गांव में मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन में वे स्वस्थ थी। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव के पास के स्कूल विद्या मंदीर से पूरी की। अचानक 2010 में इण्टरमिडिएट की परीक्षा के बाद अगस्त में तबीयत खराब हुई और बुखार लगी। बुखार की दवा लेने के कारण आंखों में खराबी एवं लाल निशान बन गए। आंख के डॉक्टर से दिखावे के बाद उन्होंने दवा दिया जो रिएक्शन कर गया एवं आंखों की रोशनी चली गई। एम्स में इलाज चली लेकिन

आज अपने दृढ़ निश्चय के कारण जॉब कर रही है एवं दूसरे नेत्रहीन को प्रोत्साहित कर रही है।

कोई फायदा नहीं हुआ। इंटरमिडिएट अच्छे अंको से पास की। समाज में तरह-तरह के बातें चलने लगी। हरकोई ताना देना शुरू कर दिया। एक जन्म से अंधा होना और एक अचानक अंधा होना बहुत तकलीफदेह होता है। मन में तरह-तरह का सवाल एवं आत्महत्या करने का ख्याल आने लगा। लेकिन कविता की दृढ़निश्चय ने सफल बना दिया। बहुत आग्रह करने पर ममरे भाई ने नेट से ब्लाइंड स्कूल एवं उनसे जुड़े लोगों का नम्बर सर्च कर दिया। बहुत मुश्किल से सुदामा सर से सम्पर्क हुआ लेकिन उन्होंने बताया कि हम रिटायर हो गये हैं फिर उन्होंने पटना के सुनिल कुमार का नम्बर दिया। उनसे बात करने पर उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया एवं आगे पढ़ाई देहरादुन में करने के बोला। देहरादुन जाने के बाद आगे की पढ़ाई के ललक में 10 दिनों में ब्रेल सीख ली। कोबा कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा दी एवं सफल हो गई। सफल होने के एक वर्ष की कोबा कोर्स की। आज अपने दृढ़ निश्चय के कारण जॉब कर रही है एवं दूसरे नेत्रहीन को प्रोत्साहित कर रही है। कविता का कहना आंखों की रोशनी से नहीं मन की रोशनी से देखिए सब समान्य लगेगा।

■ सीतामढ़ी (बिहार)



नाम

कविता कुमारी



# खुद खेले और अब दिव्यांगों को जोड़ रहे हैं खेल से

## ह

रिमोहन सिंह पिता सुभाष कुमार सिंह यह नाम अब किसी सफलता का मोहताज नहीं है। इन्होंने खुद तो खेल से नाम कमाया ही अब जिले और राज्य के दिव्यांग बच्चों के भी खेल से जोड़ने में लगे हुए हैं। मुंगेर के कल्याणपुर गांव के रहने वाले हरिमोहन एथलेटिक्स, क्रिकेट और खो-खो सहित कई खेलों में हाथ आजमा चुके हैं। एथलेटिक्स में इन्होंने कई पदक भी अपने नाम किये हैं। हरिमोहन बताते हैं कि वह पढ़ाई में भी बेहतर थे। इसलिए मेरे परिवार को लगता था कि मैं बड़ा होकर कोई सरकारी नौकरी जरूर करूंगा। लेकिन कब खेल से मैं दिल से जुड़ गया पता ही नहीं चला। पहली बार 2012 में मुझे प्रखंडस्तरीय खेल में हिस्सा लेने का मौका मिला। इस स्कूली चैंपियनशिप के लिए सभी स्कूलों के खिलाड़ी पहले से तैयारी

में जुटे हुए थे। इस संबंध में मैंने भी अपने प्रधानाध्यापक महोदय से जानकारी ली, तो उन्होंने मुझे भी इस प्रतियोगिता में अपनी विधालय की टीम की ओर से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। इस प्रतियोगिता में मैंने सिल्वर मेडल जीता। प्रखंडस्तर पर सिल्वर मेडल जीतने के बाद भी मेरा चयन जिला स्तर के टीम में नहीं हुआ। इस टीम में उसे चुना गया, जिसे तीसरा स्थान मिला था। बस यहीं बात मुझे खट गयी और मैं स्पोर्ट्स को अपना कैरियर मानकर इससे जुड़ गया। मैंने इस सेलेक्शन पर आपत्ति भी दर्ज करायी, लेकिन उनकी मनमानी के आगे मेरी एक न चली। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि प्राइज मिल गई न अब अपने घर जाओ और किसका सेलेक्शन करना है और किसका नहीं ये मुझे अब मत सिखाओ। मैंने देखा कि टैलेंट का यहां कोई कद्र नहीं होता।

■ मुंगेर (बिहार)

नाम

हरिमोहन सिंह

## अब रक्तदान कर बनाया रिकॉर्ड

## र

रक्तदान, एक ऐसा दान, जो मनुष्य को इंसान होने की पहचान देता है। अगर यहां भी रिकॉर्ड बने तो कई मायनों में सबसे महान कार्य है। यह रिकॉर्ड कोई और नहीं डॉ संदीप कुमार ने बनाया है। वैशाली जिले के गोरौल मोहनपुर के रहने वाले संदीप 2010 में एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर गंवा दिये। इस हादसे में इन्हें बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत थी। जिन्हें एक व्यक्ति ने दिया। इसके बाद से संदीप उस व्यक्ति के लिए सबकुछ देने को तैयार हो गये। संदीप 2013 से 2017 तक में पूरे बिहार झारखंड के हर एक जिले में साइकिल से पहुंच कर रक्तदान शिविर लगा चुके हैं, जिसके लिए इन्हें इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह दिया जा चुका है। इन्हें लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी संवाद आ चुका है। संदीप एक ऐसे सेवक हैं की कोई 12 बजे रात को भी मदद मांगे तो, बेहिचक संदीप उनका मदद करने को तैयार रहते हैं। ये किसी राजनीतिक

पार्टियों से संबंध नहीं रखते और न ही राजनीति करते हैं। मानव सेवा इनका परम कर्म है। संदीप कहते हैं मानव रूप में जन्म लिए हैं अगर मानव के लिए कुछ न किया जाये तो मानव रूप में जन्म लेना बेकार है। एक मानव ही दूसरे मानव को काम आता है। इसलिए एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। 2010 में हुए हादसे के बाद जितने दिन इन्होंने जिंदगी जिया है उससे कई गुना ज्यादा लोगों की जिंदगियां दें चुके हैं। संदीप लॉकडाउन में निःशुल्क सेवा तो दे ही रहे हैं साथ ही निःशुल्क प्रतियोगिता शिक्षा सेवा, निःशुल्क रक्त सेवा भी देते हैं। गरीब बेसहारा बच्चों की पढ़ाई लिखायी भी कराते हैं।

माउंट एवरेस्ट फतह करने का लक्ष्य : इनका कहना है की मैं आशीर्वाद इसलिए पा रहा हूं, क्योंकि मुझे माउंट एवरेस्ट भी फतह करना है, जिसके लिए मैं ट्रेनिंग भी कर रहा हूं। वहां से जिंदा लौटूँ, इसलिए आशीर्वाद पाने को सेवा करता रहता हूं। कुछ काम आये न आये दुआ जरूर काम आती है। संदीप की आर्थिक स्थिति भले ही बहुत अच्छी नहीं हो पर वह दिल से बहुत मजबूत हैं। संदीप के दोनों पैर कृत्रिम हैं और वह उसी के सहारे जीवन जी रहे हैं। संदीप के बड़े भाई प्रदीप आज भी साइकिल पर कपड़ा बेचते हैं और पिता बैद्यनाथ साह हाट में सब्जियां बेचते हैं। ऐसे हालात में भी इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान 1730 गरीबों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया। इस कार्य में इनके दोस्तों ने भी मदद की।

■ वैशाली (बिहार)



नाम

डॉ संदीप

## बिहार का पहला तैराक, जो सामान्य तैराकों को देता है चुनौती



नाम

गजेन्द्र सहनी

समस्तीपुर (बिहार)

### खेल कोटे से बिहार सरकार ने दी नौकरी

जीते हैं। वर्ष 2005 से लेकर 2011 तक प्रदेश में आयोजित हर तैराकी प्रतियोगिता में उसने भाग लिया। सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि तीन बार बेस्ट स्विमर का खिताब भी हासिल किया। इन सफलताओं ने उसके जज्बे को ऊंचाई देनी शुरू की। फिर क्या था, कामयाबी की दौड़ में उसे इस बात की कसक कभी नहीं रही कि काश बचपन में उसके एक पैर को लकवे ने नहीं छुआ होता। उसने अपने हौसले से बुलंदी की जो लकीर खिंची है, वह दूसरे युवकों के लिए नजीर बन गयी है। गजेन्द्र को इस बात का कभी मलाल नहीं रहा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आता है। उसके तीन भाई और एक बहन है। सभी पढ़ाई कर रहे हैं। गजेन्द्र कहता है कि उसे इस बात का तनिक भी पता नहीं था कि बागमती में गोता लगाते-लगाते वह इंग्लिश चैनल पर करने का ख्वाब देखने लगेगा। उसे इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगले कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जरूर झटकेगा। इसी मंशे से वह दो ढाई महीने से बंगलुरु में रहकर स्विमिंग पुल में प्रैक्टिस कर रहा है। उसके को एसआर सिंधिया बड़े पुख्ता अंदाज में कहते हैं कि गजेन्द्र निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर का तैराक बनेगा। इसकी मेहनत जरूर रंग लायेगी। बस चाहिए तो इसके चाहने वालों की शुभकामनाएं।



### उपलब्धि

- 👉 पैरा कॉमनवेल्थ में गेम्स 2010 ( नयी दिल्ली) में सहभागिता
- 👉 13वीं नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप (2013) में पांच गोल्ड मेडल
- 👉 12वीं नेशनल तैराकी चैंपियनशिप (2012) में एक गोल्ड, दो सिल्वर और दो ब्रांज मेडल
- 👉 11वीं राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप (2011) में एक गोल्ड, दो सिल्वर, एक ब्रांज मेडल
- 👉 10वीं तैराकी चैंपियनशिप (2010) दो सिल्वर, दो ब्रांज मेडल
- 👉 बिहार के मुख्यमंत्री की ओर से लगातार तीन साल मिला सम्मान (2011, 2012 व 2013)
- 👉 2013 में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड इटीवी की ओर से मिला
- 👉 बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बीपीइडी)
- 👉 डिप्लोमा इन स्विमिंग

प्र

तिभा अपनी राह खुद बना लेती है और उस मुकाम तक पहुंचा डालती है, जो उसके सपने में पल रहा होता है। बशर्ते कि उसके सपने को पर लगाने में मजबूत इच्छाशक्ति उसका साथ दे रही हो। कुछ ऐसा ही हुआ है जिले के वारिसनगर प्रखंड के डरसुरबलिपुर के गजेन्द्र सहनी के साथ। बचपन से बागमती नदी में डुबकी लगाने वाले युवक के अंदर इंग्लिश चैनल पार करने का ख्वाब पल रहा है। निःशक्तता की परवाह न करते हुए इस होनहार ने राज्य के लिए 18 मेडल जीते हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन्होंने तैराकी में बिहार का परचम हमेशा लहराया है। गजेन्द्र बिहार के

पहले तैराक हैं, जिन्होंने तैराकी में बैचलर डिग्री हासिल की है। इसके अलावा इन्होंने नये तैराक तैयार करने के लिए तैराकी में डिप्लोमा कर स्पेशलाइजेशन भी हासिल किया है। फिलहाल गजेन्द्र बंगलुरु में युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। गजेन्द्र ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आयोजित ग्यारहवीं नेशनल पैरालिंपिक तैराकी चैंपियनशिप में तीसरा स्थान लाकर देश स्तर पर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। उसे यह खिताब बेस्ट स्ट्रोक में मिला है। इस प्रतियोगिता में सूबे से शिरकत करने वालों में बीस खिलाड़ी शुमार हैं। गजेन्द्र ने अब तक तीस मेडल

मंशे से वह दो ढाई महीने से बंगलुरु में रहकर स्विमिंग पुल में प्रैक्टिस कर रहा है। उसके एसआर सिंधिया बड़े पुख्ता अंदाज में कहते हैं कि गजेन्द्र निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर का तैराक बनेगा। इसकी मेहनत जरूर रंग लायेगी। बस चाहिए तो इसके चाहने वालों की शुभकामनाएं।



## जबसे मैं मौत को दिया मात, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का बढ़ाया मान



नाम

अर्चना कुमारी

■ बांका (बिहार)

का

मयाबी उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मत कर इतना यकीन हाथों की इन लकीरों पर तकदीर तो उनकी भी होती है, जिनके हाथ नहीं होते। यह कथन बांका की दिव्यांग खिलाड़ी अर्चना पर कुमारी पर सटीक बैठती है, जिन्होंने अपनी शारीरिक दिव्यांगता को धत्ता बताते हुए बतौर खिलाड़ी अपने राज्य का नाम रौशन किया। अर्चना के कमर के नीचे का भाग बेजान है बावजूद इसके उसने पैरालिंपिक गेम्स में कई अंतरराष्ट्रीय पदक हासिल किये हैं। इस उपलब्धि के कारण चुनाव आयोग ने अर्चना को मतदाता

जागरूकता के लिए ब्रांड एंबेसडर भी बनाया था और उसे सरकारी नौकरी भी मिली।

छत से उतरने के क्रम में हुई थी घटना: 25 अक्टूबर 1992 को जन्मी अर्चना, महेश मंडल एवं फूलवती देवी के चार संतानों में इकलौती बेटी है। 18 अगस्त 2006 की रात छत से उतरने के दौरान सीधे जमीन पर आ गिरी। इस दुर्घटना ने उसके कमर से नीचे का भाग बेजान कर दिया। परिवार वाले अर्चना के इलाज में कोई कसर न छोड़े पर सारा प्रयास विफल रहा।

एक फौजी चिकित्सक ने दिखायी राह : सेना से सेवानिवृत्त

अर्चना ने डिस्क थ्रो में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके बाद वर्ष 2010 में हरियाणा में आयोजित एक प्रतियोगिता में अर्चना ने शॉटपुट एवं डिस्क थ्रो में दूसरा तथा जेवलिन थ्रो में तीसरा स्थान हासिल किया।

एक चिकित्सक ने इलाज के दौरान अर्चना का हौसला बढ़ाया और उसे कुछ व्यायाम सिखाये। उसके बाद अर्चना के अंदर भी कुछ कर गुजरने की भावना ने जन्म लिया। उसके बाद अर्चना ने दिव्यांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और न तो पढ़ाई न खेल में उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजधानी पटना में प्रैक्टिस के दौरान उसे राज्यस्तरीय पारा एथलेटिक्स में भाग लेने का अवसर मिला। अर्चना ने मिले इस अवसर को अच्छी तरह से भुनाया और जेवलिन थ्रो, डिस्क थ्रो, और शॉटपुट में बेहतरीन प्रदर्शन किया। यहीं से अर्चना का वर्ष 2009 में नेशनल जूनियर पैरा एथलेटिक्स में चयन हो गया। जहां अर्चना ने डिस्क थ्रो में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके बाद वर्ष 2010 में हरियाणा में आयोजित एक प्रतियोगिता में अर्चना ने शॉटपुट एवं डिस्क थ्रो में दूसरा तथा जेवलिन थ्रो में तीसरा स्थान हासिल किया।



## बिहार सरकार ने दी नौकरी

चीन के बीजिंग, इंडोनेशिया के जकार्ता एवं दुबई के आईवास तक भारत की प्रतिनिधि बन अर्चना ने अपने हौसलों के बल पर बेहतर प्रदर्शन किया, परिणाम स्वरूप 24 जनवरी बालिका दिवस के अवसर पर भागलपुर समाहर्णालय में बतौर लिपिक पद के लिए अर्चना को नियुक्ति पत्र दिया गया और 27 जनवरी से अर्चना यहां पर अपनी सेवा दे रही हैं।

बिहार पैरालिंपिक कमेटी ने दिखायी राह : अर्चना को खेल में बेहतर करने के लिए बिहार पैरालिंपिक कमेटी ने अहम भूमिका निभायी। अर्चना को बेहतर ट्रेनिंग मिले इसके लिए अच्छे कोचों की भी व्यवस्था की गयी। एक समय अर्चना भारत की बेस्ट दिव्यांग शॉटपुट खिलाड़ी दीपा मलिक को भी चुनौती देती थी। दीपा को अर्चना ने कई बार अपने बेहतर खेल से चौंकाया।

## दिव्यांगों के लिए प्रेरणा हैं गया की शिक्षिका रीता रानी



नाम

रीता रानी प्रसाद

■ गया (बिहार)



दि

व्यांगता अभिशाप नहीं वरदान है। इसके कई उदाहरण समाज में मिल जायेंगे। विषम परिस्थितियों से निकलकर मुकाम हासिल करने वाली गया की रीता रानी प्रसाद आज दिव्यांगों के लिए प्रेरणा बन गयी हैं। पिछले दस वर्षों से समाज में शिक्षा का अलख जगा रही हैं। साथ ही दिव्यांगों को समाज से जोड़ने का भी कार्य कर रही हैं। गया के धनावां मध्य विद्यालय में बतौर सहायक शिक्षिका के रूप में कार्यरत रीता बौनापन की शिकार हैं। इनकी हाइट तीन फीट है, लेकिन हौसला इतना है कि उसको मापा नहीं जा सकता है। वह चाहती हैं कि समाज का नजरिया

जैसे उनके लिए अब बदल गया है। वैसे ही राज्य के सभी दिव्यांगों के लिए समाज का नजरिया बदले। रीता ने बताया कि वह सरकारी विद्यालय में पढ़ने के अलावा मानसिक दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा और प्रशिक्षण का लाभ पहुंचाती हैं। आकांक्षा मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल है, जिसमें रीता करीब 12 वर्षों से पढ़ा रही हैं। यहां तक का सफर तय करने में रीता को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन उन सभी परेशानियों को इन्होंने अपने लक्ष्य के आगे छोटा साबित किया है। रीता ने कहा कि हमारे समाज

रीता कहती हैं कि मैं महिलाओं में एक हौसला उत्पन्न करना चाहती हूँ कि कभी भी अपनी शारीरिक अक्षमताओं से घबरायें नहीं, क्योंकि समस्याओं में ही निदान छिपा होता है, यही मेरे जीवन का सूत्र वाक्य भी है।

में महिलाओं को सदैव कमजोर समझने की मनोभावना है। उसमें भी दिव्यांग होने से समाज में दोहरा व्यवहार होता है। मगर इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और समाज में खुद अपने मेहनत के मुकाम पर खड़ा किया। इसके पिछे परिवार और मेरे शिक्षकों का अहम योगदान रहा। इनकी हौसलाओं में मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

पहले मैट्रिक, इंटर और फिर स्नातक की डिग्री हासिल कर रीता शुरू से ही पढ़ने और पढ़ाने के कार्य से जुड़ गयी। रीता कहती हैं कि मैं महिलाओं में एक हौसला उत्पन्न करना चाहती हूँ कि कभी भी अपनी शारीरिक अक्षमताओं से घबरायें नहीं, क्योंकि समस्याओं में ही निदान छिपा होता है, यही मेरे जीवन का सूत्र वाक्य भी है।

## सेना में दिखाया शौर्य, खेल से बढ़ा रहा देश का मान



नाम

अजीत कुमार शुक्ला

■ भोजपुर  
(आरा)

मा

रत की सेना का गौरवगाथा पूरा विश्व जानता है। उनकी हिम्मत और शौर्य की कहानियों से पूरे देश का बच्चा-बच्चा वाकीफ है। इसका प्रमाण बिहार के अजीत कुमार शुक्ला को देख कर मिल जाता है। सेना के शौर्य में इजाफा करने के बाद अब अजीत दुनिया में खेल के माध्यम से देश का ना रोशन कर रहे हैं।

भोजपुर जिला के शुकुलपुरा गांव के रहने वाले अजीत कुमार शुक्ला मैट्रिक पास करते ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे। देश सेवा के लिए इन्होंने इंडियन आर्मी को चुना और वर्ष 2000 में महज 20 वर्ष की आयु में इनका चयन आर्मी में

हो गया। हालांकि करियर के पांचवें साल में ही इनके साथ एक हादसा हो गया, जिसमें इनके रिढ़ की हड्डी में चोट लग गयी और इनकी जिंदगी व्हीलचेयर पर आ गयी। अजीत बताते हैं कि 58 राष्ट्रीय राइफल में उनकी टीम का मुठभेड़ 25 फरवरी 2005 को आंतकवादियों से हुई, जिसमें यह हादसा हो गया। इस हादसे से उबरने में एक वर्ष लग गया। अपने हौसला के बलबूते इन्होंने 2006 में बास्केटबॉल व्हीलचेयर में रूचि दिखायी। इसके बाद से इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुके अजीत दिव्यांगों के लिए प्रेरणा

अपने हौसला के बलबूते इन्होंने 2006 में बास्केटबॉल व्हीलचेयर में रूचि दिखायी। इसके बाद से इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुके अजीत दिव्यांगों के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। इनकी जिंदगी से हादसे में दिव्यांगता के शिकार हुए लोग सिख सकते हैं।

से कम नहीं है। इनकी जिंदगी से हादसे में दिव्यांगता के शिकार हुए लोग सिख सकते हैं, जिंदगी कैसे जी जाती है।

व्हीलचेयर बास्केटबॉल से जुड़ने के बाद अजीत लगातार अभ्यास कर जीवन के दूसरे पड़ाव को भी यादगार बनाने में लग गये। 2015 में नयी दिल्ली में आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में इन्हें पंजाब टीम में शामिल किया गया। टीम ने इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता, जिसमें अजीत की भूमिका अहम रही। ऑलराउंडर के रूप में टीम से जुड़े अजीत इस चैंपियनशिप में अपना ऐसा जलवा दिखाया कि फिर हर राष्ट्रीय टूर्नामेंट में टीम का हिस्सा बने रहे।

महज दो साल के प्रदर्शन से इन्होंने राष्ट्रीय टीम में हिस्सा बना ली। 2017 में अजीत को अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए इंडिया टीम में चयन किया गया। चतुर्थ बाली कप व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में इंडिया टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही अजीत का करियर ग्राफ भी बढ़ा और इन्हें लगातार इंडिया टीम में जगह मिलने लगा। एशिया ओसियान जोन चैंपियनशिप 2019 में भी इन्हें इंडिया टीम में शामिल किया गया।



### डाटा इंट्री ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हैं

यह चैंपियनशिप 2020 टोक्यो पैरालिंपिक गेम्स की क्वालिफर भी थी। इस चैंपियनशिप में इंडोनेशिया को हराकर टीम ने 13वां स्थान हासिल किया। जो टीम एक बहुत बड़ी जीत थी। खेलों के अलावा अजीत और भी कई कार्य में निपुण हैं। फिलहाल वह एक सरकारी स्कूल में डाटा इंट्री ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा अजीत कंप्यूटर कोर्स में भी निपुणता हासिल कर रहे हैं।

वहीं कपड़ा सिलने का भी हुनर इन्होंने सिख रखा है। इसके अलावा मोमबत्ती बनाने का भी कोर्स इन्होंने किया है। अजीत अपनी दूसरी जिंदगी के लिए राष्ट्रीय व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन को धन्यवाद देते हैं। वह कहते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि फेडरेशन को मेरी प्रतिभा दिखी। मैं फेडरेशन और देश के लिए इसी लगन के साथ पदक जीतूंगा।





## कभी हार नहीं मानने की जिद ने बना दिया सितारा



नाम

नारायण ठाकुर

■ दरभंगा (बिहार)

मा

रतीय पैरा एथलीट नारायण ठाकुर की अब तक की राह बेहद कठिन परिस्थितियों में गुजरी है, लेकिन कुछ कर दिखाने की जिद और हार नहीं मानने की आदत ने उन्हें एक उभरता हुआ सितारा बना दिया। रेहड़ी लगाकर अपना पेट भरने और अपने सपने को बुनने वाले नारायण की कहानी बेहद संघर्षपूर्ण रही है। जब उन्होंने इस खेल को चुना तो लोगों ने उन्हें खेल छोड़ने की सलाह देते हुए ताने मारना शुरू कर दिया। नारायण कहते हैं, यहां तक पहुंचना मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन दिल से कहूं तो दिव्यांग होना ही अभिशाप है। पहले तो अपनी दिव्यंगता से लड़ना

होता है और फिर उन लोगों से, जो हमेशा यह अहसास कराते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन, पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर मैंने बस यह बताने की कोशिश की है कि किसी भी चीज को पाने के लिए मेहनत और लगन जरूरी है। 27 वर्षीय नारायण दिल्ली के समयपुर बादली में रहते हैं, लेकिन उनका परिवार बिहार के दरभंगा से है। उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए क्या कुछ नहीं किया, होटल में वेटर का काम किया, बस डिपो में सफाई का काम किया और अब रेहड़ी लगाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। हालांकि, इस रेहड़ी पर कभी वह,

कभी उनकी मां और कभी परिवार का कोई अन्य सदस्य बैठता है। नारायण ने बताया, 'हम गरीब हैं और पिताजी के देहांत के बाद हालात और खराब हो गए। पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना था और ऐसे में सभी ने कहा कि खेल को छोड़कर सिर्फ काम पर ध्यान दो, ताकि घर परिवार का खर्चा चल सके। लेकिन, मैंने हार नहीं मानी। मेरे लिए सबसे ज्यादा संघर्ष त्यागराज स्टेडियम तक पहुंचने का रहता है। मैं शुरू से ही त्यागराज स्टेडियम में अभ्यास करने जाता हूं, जो मेरे घर से 35 किमी दूर है। घर से स्टेडियम तक आजे-जाने में छह घंटे का समय लग जाता है। मेट्रो का किराया महंगा है और ऐसे में मुझे बस से सफर करना होता है। हमारा परिवार 2010 तक यहां झुग्गी में रहता था, लेकिन इसके बाद हमने छोटा सा मकान लिया, जिसमें हमारे पांच परिवार रहते हैं।' जब नारायण से पूछा कि पदक जीतने के बाद क्या बदलाव आया तो उन्होंने कहा, 'ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जीत लिया हो। मेरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पहला पदक है। सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं।'

## आर्थिक मदद भी की

इतना सब कुछ मेरे कोच अमित खन्ना से ही मिला, जिन्होंने मेरा सही समय पर चयन करके मुझे प्रशिक्षण देने के साथ आर्थिक मदद भी की। लेकिन इस खेल में मुझे प्रदीप राज लेकर आए जो दिव्यांग लोगों के लिए काफी कार्य करते हैं। उन्होंने ही मुझे खन्ना सर से मिलवाया, जिसके बाद मेरा प्रशिक्षण शुरू हो पाया। इसके अलावा राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने भी समय-समय पर मेरा हौसला बढ़ाया। नारायण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात को यादगार पल बताया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी प्रधानमंत्री जी से भी मिल पाऊंगा। हमारे खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के प्रयासों से ही यह संभव हो पाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग भविष्य में कभी भी हिम्मत नहीं हारना। आप सभी ने साबित कर दिया है कि आप भी किसी से कम नहीं हैं।



जब नारायण से पूछा कि पदक जीतने के बाद क्या बदलाव आया तो उन्होंने कहा, 'ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जीत लिया हो। मेरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पहला पदक है। सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं।'





## बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं पटना के संदीप

ए

क या दो कार्यों में दक्ष होना आम बात है, लेकिन कई कार्यों से लोगों को प्रभावित करने वाले लोग विरले ही होती हैं। ऐसा ही कुछ पटना के दिव्यांग एथलीट संदीप कुमार के बारे में कहा जाता है। पढ़ाई के साथ-साथ संदीप खेल में भी अक्ल रहे हैं और अब इनके द्वारा खेल की बारिकियां सिखने वाले खिलाड़ी भी राज्य का नाम रौशन कर रहे हैं। संदीप जियोग्राफी से नेट क्वालिफाइ कर चुके हैं। वहीं स्पोर्ट्स में वह एक अच्छे प्रशासक और कोच की भूमिका भी निभा रहे हैं।

वर्ष 2000 से स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए जुड़े संदीप ने कई अहम प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व किया। इन प्रतियोगिताओं में यह 12 से भी अधिक पदक अपने नाम किये। खासकर के 100 मीटर फर्टा दौड़ में इनकी उपलब्धि सबसे बेहतर रही है। इसके अलावा भाला फेंक में भी इन्होंने कई पदक अपने नाम किये हैं।

■ पटना (बिहार)

नाम

संदीप कुमार

## राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों के अधिकार के लिए लड़ाई

अ रवल जिले के पुरन गांव के रहने वाले हर्ष शर्मा राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जन्म में पैरालाइसिस का शिकार हुए हर्ष बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। हर्ष के पिता वेंकटेश शर्मा ने मेधावी

बेटे की समुचित शिक्षा के लिए जब बेहतर विद्यालय में नामांकन कराने गये, तो उन्हें वापस लौटा दिया गया। अंत में उन्होंने हर्ष का नामांकन साधारण विद्यालय शिवम कॉन्वेंट में कराया। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए हर्ष ने दिल्ली जाना बेहतर समझा और अपने मेधा के दम पर देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिल लिया। यहीं पर फिलहाल वह विकास अध्ययन केंद्र में शोधार्थी हैं।

उन्होंने अपने साथ घटे हुए एक वाक्या को बताया कि दिल्ली के एक रेस्टोरेंट ने दिव्यांग होने के कारण अपने यहां खाना खाने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने दिव्यांगों के अधिकार के लिए हर जगह लड़ाई शुरू कर दी। अब हर राज्य में घुम घुमकर दिव्यांगों के हक लिए आवाज उठाते हैं।

एक रेस्टोरेंट ने दिव्यांग होने के कारण अपने यहां खाना खाने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने दिव्यांगों के अधिकार के लिए हर जगह लड़ाई शुरू कर दी।

■ अरवल (बिहार)



नाम

हर्ष राज



नवादा में पहुंच मार्ग-Access Route का निरीक्षण करते हुए, बेगूसराय मोबाईल कोर्ट के दौरान बेगूसराय सदर अस् पताल पहुंच मार्ग-Access Route का निरीक्षण करते हुए.

ACCESS AUDIT

## बिहार में दिव्यांगजनों की सुगम्यता हेतू बाधा रहित वातावरण बढ़ाने के लिए एक्सेस ऑडिट



राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) कार्यालय ने अपने विशेष कार्य योजना के तहत एक्सेस ऑडिट (अंकक्षण) कार्यक्रम चलाया। बाधारहित सुगम वातावरण दिव्यांगजनों को उपलब्ध हो सके, ऐसी कोशिश की जा रही है। इस कोशिश के तहत राज्य भर के कई शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक भवनों, आदि का दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित वातावरण से संबंधित जांच राज्य आयुक्त द्वारा किया गया। और जरूरत के अनुसार संबंधित अधिकारियों या संस्थान प्रमुखों को निर्देश भी दिये गये। इस सुगम्यता अंकक्षण में 116 बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है।



# वित्तिय वर्ष 19-20 में बिहार जिलों में बाधारहित सुगम्यता अंकेक्षण किये गये उनकी सूची



18 फरवरी 2020 को लख्खीसराय मे विशाल मेगामार्ट सुलभ प्रवेश निरीक्षण करते हुए. मधेपुरा में शॉपिंग मॉल का में सीढ़ी का निरीक्षण करते हुए. मधेपुरा में शॉपिंग मॉल का में सीढ़ी का निरीक्षण करते हुए.

ACCESS AUDIT



बेगूसराय रेलवे स्टेशन का सुलभ पेयजल सुविधा निरीक्षण.



मधेपुरा मोबाइल कार्ट के दौरान रेलवे स्टेशन मधेपुरा का सुलभ प्रवेश निरीक्षण करते हुए, नवादा जिला मोबाइल कोर्ट के दौरान रेलवे स्टेशन नवादा का सुलभ प्रवेश निरीक्षण करते.





नवादा में पहुंच मार्ग-Access Route का निरीक्षण करते हुए, बेगुसराय मोबाईल कोर्ट के दौरान बेगुसराय सदर अस्पताल पहुंच मार्ग-Access Route का निरीक्षण करते हुए.



लखीसराय में मोबाईल कोर्ट के दौरान रेलवे स्टेशन में सुलभ पार्किंग का निरीक्षण करते हुए



नवादा जिला मोबाइल कोर्ट के दौरान रेलवे स्टेशन नवादा में सुलभ शौचालय का निरीक्षण करते.

The following accessibility features are inspected



- 1) Access Route
- 2) Accessible Parking
- 3) Accessible Entrance
- 4) Accessible Reception
- 5) Corridors – Tactile Paths
- 6) Staircase
- 7) Elevators
- 8) Accessible Toilets
- 9) Accessible Drinking Water Facility
- 10) Signage
- 11) Other innovative or unique feature provided





मोतीहारी रेलवे स्टेशन के सुलभ शौचालय का निरीक्षण करते हुए. Corridors – Tactile Path Accessibility Audit Inspections Corridors – Tactile Paths of Begusarai Railway Station.

# ACCESS AUDIT



बेगुसराय में शॉपिंग मॉल Elevator लिफ्ट का निरीक्षण करते हुए.



Other innovative or unique feature provided अन्य नवीन या अद्वितीय सुविधा प्रदान की गई. लखीसराय में मोबाईल कोर्ट के दौरान रेलवे स्टेशन में साइनेज का निरीक्षण करते हुए



18 फरवरी 2020 को लखीसराय शॉपिंगमॉल में सीढ़ी का निरीक्षण करते हुए, मधेपुरा में शॉपिंग मॉल का में सीढ़ी का निरीक्षण करते हुए.







# समाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट

की बात सुनकर मंच से सीधे उतरकर आवेदन लेने पहुंच जाना। कार्यक्रम में जिलाधिकारी (DM) तथा एस.पी. (SP) की उपस्थिति में खुद ही दिन-दिन भर कार्य करना, आदेश देना तथा तुरंत दिव्यांगजनों का कार्य हो जाना एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। अपनी लगातार यात्राओं के जिला स्तरीय प्ररिक्षण से ही समाज में दिव्यांगजनों के प्रति सोच बदलने में कामयाब हुए और लोगों की मनोवृत्ति भी बदल सके हैं। अनेकों कार्यों में एक कार्य अभी होना बाकी है जिसमें दिव्यांगजनों को पंचायत स्तर पर एक सर्वे करवाएं ताकि ज्यादा-से-ज्यादा दिव्यांगजन विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सके।

**2** इसी संदर्भ में पुनपुन, पटना के समाजिक कार्यकर्ता श्री अजय कुमार जो कई वर्षों से दिव्यांगजनों के हितों में कार्यरत हैं वह बताते हैं कि राज्य आयुक्त निःशक्तता को कार्यभर संभाले दो वर्ष हो गये। मैं मानता हूं कि



डॉ० शिवाजी के दूरदृष्टि से ही चुनाव आयोग ने पिछले लोकसभा चुनाव में दिव्यांगजन फ्रेंडली मतदान केन्द्रों की स्थापना की जिसमें हजारों दिव्यांगों ने अपने मत का प्रयोग कर देश हित में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है।

समाज में दिव्यांगजनों के प्रति लोगों का नजरिया बदला है परंतु अभी भी समाज में दिव्यांगजनों का सरकारी स्तर पर कार्य नहीं हो पा रहा। श्री कुमार बताते हैं कि पुनपुन ब्लॉक में इन्होंने दिव्यांगजनों की सहायता के लिए साईकिल, पेंशन, राशन कार्ड हेतु आवेदन दिया था पर बाबुओं ने आजतक वह कार्य नहीं किया। राज्य आयुक्त के कार्य भले ही राज्य के अन्य जिलों में दिखते हों परंतु पुनपुन में ब्लॉक अधिकारी ब्यान नहीं देते।

**3** समाजिक अंकेक्षण के सिलसिले में बेगुसराय के रहनेवाले तथा मुंगेर में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में व्याख्याता(प्रोफेसर) के पद पर कार्यरत डॉ० गौतम कुमार बताते हैं कि वह भी बौनापन दिव्यांगता से जूझ रहे हैं लेकिन जब राज्य

आयुक्त के कार्यों को देखते हैं तो उन्हें काफी प्रेरणा बल मिलता है।

वह खुशी जताते हुए कहते हैं कि राज्य आयुक्त वर्ष 2019-20 में अनेकों जगह चलंत न्यायालय लगाकर दिव्यांगजनों के दुखों को दूर करने का कार्य किया है। चलंत न्यायालय व दिव्यांगजनों को मतदान का मिला अधिकार को वह सफलता मानते हैं। वह बताते हैं कि पहले मतदान केन्द्रों पर जो बूथ होते थे वह काफी बाधा से भरे थे।

डॉ० शिवाजी के दूरदृष्टि से ही चुनाव आयोग ने पिछले लोकसभा चुनाव में दिव्यांगजन फ्रेंडली मतदान केन्द्रों की स्थापना की जिसमें हजारों दिव्यांगों ने अपने मत का प्रयोग कर देश हित में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है।

अस्थि दिव्यांगता से ग्रसित







# समाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट

## 4 प्रतिशत आरक्षण भी मिला

**4** नवादा के सत्येन्द्र कुमार बताते हैं कि राज्य आयुक्त के 2019-20 के कार्य समाजिक चेतना जगाने को लेकर कहा जाता है। दिव्यांगजनों के प्रति लोगों की सोच बदलवाना को मैं उपलब्धि मानता हूँ लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि राज्य आयुक्त अपने पद पर रहते हुए दूरदृष्टि का पालन प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दिव्यांगजनों के प्रति नहीं कर रहे हैं। 1995 में वर्णित अधिनियम की बात करें तो तब 7 प्रकार की दिव्यांगता थी और इन सातों प्रकार की दिव्यांगता में नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण भी मिला था लेकिन RPWD Act 2016 में दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इसके साथ ही नौकरियों में आरक्षण 4 प्रतिशत भी कर दिया गया है। यहां चिंतन करनेवाली बात है कि सिर्फ एक फीसदी आरक्षण बढ़ाकर 14 श्रेणियां अन्य दिव्यांगता को जोड़ दी गयी है क्या यह राज्य आयुक्त



अपने जैसे दूसरे लोगों को यह खेल सिखाते भी हैं। राष्ट्रीयस्तर पर चयन होने के बाद इन्हें चेन्नई जाना था तथा इनका यू.डी.आई.डी. बनाने में काफी समस्या हो रही थी। इन्होंने राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) बिहार से मदद की गुहार लगायी थी। राज्य आयुक्तद्वारा तत्काल ही उनकी समस्या का निराकरण करा दिया गया।

के लिए चुनौती नहीं है। क्या वह इस खामी को दूर करा पाये।

**5** अरवल के जिला दिव्यांग अध्यक्ष स्वयं अस्थि दिव्यांगता से पीड़ित हैं लोग उनके बड़े प्यार से मों०फिरदौस अख्तर के नाम से जानते हैं वह बड़े अदब से बताते हैं कि एक बार इनका चयन राष्ट्रीय स्तर के एक खेल में हो गया था चूंकि मो० अख्तर

सीटिंग बॉलीवॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं तथा ये अपने जैसे दूसरे लोगों को यह खेल सिखाते भी हैं। राष्ट्रीयस्तर पर चयन होने के बाद इन्हें चेन्नई जाना था तथा इनका यू.डी.आई.डी. बनाने में काफी समस्या हो रही थी। इन्होंने राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) बिहार से मदद की गुहार लगायी थी। राज्य आयुक्तद्वारा तत्काल ही उनकी समस्या का निराकरण करा दिया गया। यह मदद उन्हें राज्य आयुक्त के मोबाईल कोर्ट के माध्यम से मिला। इसी तरह उनके जैसे कई खिलाड़ियों को रोजगार करना था इनके जिले में मोबाईल कोर्ट लगा और राज्य आयुक्त की पहल पर उन खिलाड़ियों को ऋण मुहैया हो सका। मोबाईल कोर्ट द्वारा तत्काल समस्या समाधान करा देना वर्ष 2019-20 के सबसे महत्वपूर्ण





## पुरजोर ख्याल रखा गया है...

उपलब्धि राज्य आयुक्त का माना जायेगा।

**6** अस्थि दिव्यांगता से पीड़ित औरंगाबाद के दिव्यांग जिलाध्यक्ष श्री शंभु प्रसाद बारी का कहना है कि राज्य आयुक्त के जितने दौरे हुए वह काफी दिव्यांगजनों के ज्यादा से ज्यादा मदद के लिए आशावादित रहे। दिव्यांग समूह बनाकर एक-दूसरे के मददगार कैसे हो इस बात का पुरजोर ख्याल रखा गया है। राज्य आयुक्त द्वारा दिव्यांगजनों के लिए अनगिनत कार्य हुए हैं। जरा भी कोई समस्या हुई है उनके कार्यालय से पत्र जारी हुए। बिहार



का दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ती। सरकारी महकमा में राज्य आयुक्त के पत्रों को दबा दिया जाता है।

**7** मधेपुरा के प्रकाश कुमार, जिला सचिव, दिव्यांग संघ बताते हैं कि वर्ष 2019-20 में राज्य आयुक्त का कार्यकाल मील का पत्थर साबित हुआ है। इनके जिले में कोई भी दिव्यांग सरकारी याजनाओं से मरहूम नहीं है। अबतक सभी के राशन कार्ड, पेंशन, प्रमाणपत्रों जैसे सैंकड़ों कार्यों का निष्पादन राज्य आयुक्त स्वयं आकर व चलंत न्यायालय लगाकर कर चुके हैं। इसके वाइस मैसेज द्वारा त्वरित मामले निष्पादित होते रहे हैं।

**8** दिव्यांगजनों के लिए कार्य करनेवाले छपरा के दिनेश कुमार बहुत संतुष्ट होकर कहते हैं



राज्य आयुक्त सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनते हैं तथा उसका त्वरित निराकरण करते आये हैं यह एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि सरकारी कार्यों की गति धीमी है अगर राज्य आयुक्त इसपर ध्यान दे तो बिहार के तमाम दिव्यांगजनों की अपना अधिकार पाने व समझने में मदद मिलती रहेगी।

कि डॉ० शिवाजी कुमार सारण में अप्रत्याशित कार्य किए हैं। पुरे जिले के दिव्यांग की समस्याएं लोक अदालत के माध्यम से किए गए हैं। साथ ही पेंशन और राशन जैसे सुविधाएं यहां उनके द्वारा मिली है।









**9** पटना सिटी के रहनेवाले, दिव्यांग जिलाध्यक्ष, पटना के केशरी किशोर खुद अस्थि दिव्यांगता से पीड़ित हैं वह बताते हैं राज्य आयुक्त सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनते हैं तथा उसका त्वरित निराकरण करते आये हैं यह एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि सरकारी कार्यों की गति धीमी है अगर राज्य आयुक्त इसपर ध्यान दे तो बिहार के तमाम दिव्यांगजनों की अपना अधिकार पाने व समझने में मदद मिलती रहेगी।



# राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय द्वारा निबंधित सरकारी बाल गृह/ पर्यवेक्षण गृह/ अल्पावास गृह/ आसरा गृह /मूक-बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालय/ विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान/वृद्धाश्रम 'सहारा'/शांति कटीर तथा गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थानों की सूची

क्र. सं.	जिला का नाम	सरकारी बाल गृह/पर्यवेक्षण गृह/अल्पावास गृह/आसरा गृह/मूक-बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालय/ विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान/वृद्धाश्रम 'सहारा'/शांति कुटीर तथा गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं का नाम एवं पूरा पता	निबंधन की अवधि	निबंधन संख्या	निबंधन हेतु कार्यालय पत्रांक/दिनांक	
1.	Araria	पर्यवेक्षण गृह, अररिया, पता-निकट नवोदय विद्यालय, अररिया	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-25/सर0सं0 दिनांक-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
2.	Arwal	अल्पावास गृह, अरवल, पता-गोवर्धन चौक, मोकरी रोड अरवल	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-111/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1006 आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
3.	Aurangabad	अल्पावास गृह, औरंगाबाद, पता-न्युएरिया, सिंह निवास, जैन मंदिर के बगल में, औरंगाबाद	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-109/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
4.	Aurangabad	UTMOST SERVE FOUNDATION, Barun Road, Ward No.-8, Near Police Station, Daudnagar, Aurangabad	03/07/2018 से 02/07/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-205	378/आ0नि0को0 दि0-03.07.2018	
5.	Banka	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, बाँका, पता-बाबू टोला, ईदगाह रोड, बाँका	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-88/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2022	
6.	Banka	अंगिका नया सवेरा, बाँका, करहरिया दुर्गा स्थान, बाँका	30.06.2020 से 29.06.2025 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-230	956/आ0नि0को0 दि0-30.06.2020	
7.	Begusarai	बाल गृह (बालक), बेगूसराय, पता-एन.एच.-31, न्युचाणक्य नगर, वीणा वाटिका, बेगूसराय	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-31/सर0सं0 दिनांक-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-4.09.2023	
8.	Begusarai	बाल गृह (बालिका), बेगूसराय, पता-सोनी सदन, निराला नगर, रतनपुर, बेगूसराय	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-55/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2024	
9.	Begusarai	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, बेगूसराय, पता-चित्रगुप्त नगर, पोखईपर, वार्ड नं0-39, बेगूसराय-851101	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-67/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2025	
10.	Begusarai	अल्पावास गृह, बेगूसराय, पता-शक्तिवाटिका, विष्णुपुर चतुर्भुज, काली मंदिर के बगल में, बेगूसराय	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-106/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
11.	Bhagalpur	'स्पर्श', जामुनी, पीसता चौक, मागलपुर	03/05/2019 से 02/05/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-219	511/आ0नि0को0 दि0-03.05.2019	





12.	Bhagalpur	राजकीय नेत्रहीन मध्य आवासीय विद्यालय, भागलपुर, पता- भीखनपुर, भागलपुर	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-14/2019-06/सर0सं0 दि0-25.08.2019	999/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
13.	Bhagalpur	राजकीय मूक-बधिर मध्य आवासीय विद्यालय, भागलपुर, पता-बड़ी खंजरपुर, रिफयुजी कॉलोनी, भागलपुर	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-14/2019-07/सर0सं0 दि0-25.08.2019	999/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
14.	Bhagalpur	पर्यवेक्षण गृह, भागलपुर, पता-बड़ी खंजरपुर, डी0आई0जी0 ऑफिस के पीछे, भागलपुर-812001	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-23/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2029	
15.	Bhagalpur	बाल गृह (बालक), भागलपुर, पता-रेशम नगर, जीरो माईल, भागलपुर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-52/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2030	
16.	Bhagalpur	बाल गृह (बालिका), भागलपुर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-63/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2031	
17.	Bhagalpur	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, भागलपुर, पता-रामनन्दी देवी, हिन्दू अनाथालय, नाथनगर, भागलपुर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-79/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2032	
18.	Bhagalpur	वृद्धाश्रम 'सहारा', भागलपुर	27.08.2019 से 26.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-16/2019-91/सर0सं0 दि0-27.08.2019	1005/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
19.	Bhojpur	पर्यवेक्षण गृह, भोजपुर, पता-घनपुरा, भोजपुर-802301	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-19/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2034	
20.	Bhojpur	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, भोजपुर, पता-महाराजा हाता, गली नं0-3, आरा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-90/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2035	
21.	Bhojpur	अल्पावास गृह, भोजपुर (आरा), पता-डॉ0 रुग्ंटा गली, के0जी0 रोड, आरा	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-104/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
22.	Bhojpur	संकल्प साधना, साथी स्पेशल स्कूल, संकट मोचन नगर, नीयर ब्रहम स्थान, न्यूपुलिस लाईन, चांदवारा मोड़ रोड, भोजपुर (आरा)	03/12/2018 से 02/12/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-213	887/आ0नि0को0 दि0- 03.12.2018	
23.	Buxar	'देव एजुकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट', चीनी मील, पो0-गजाधर गंज, थाना-बक्सर टाउन, जिला-बक्सर	31/07/2019 से 30/07/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-222	864/आ0नि0को0 दि0-31.07.2019	
24.	Buxar	बाल गृह (बालक), बक्सर, पता-नयी बाजार, के0के0 महिला कॉलेज के निकट, बक्सर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-34/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2037	
25.	Buxar	अल्पावास गृह, बक्सर, पता-महात्मा गाँधी नगर, बाजार समिति रोड, बक्सर	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-101/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
26.	Darbhanga	राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय, दरभंगा, पता-श्री कमेश्वरी प्रिया पुअर होम, दरभंगा	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-14/2019-02/सर0सं0 दि0-25.08.2019	999/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
	Darbhanga	राजकीय मूक-बधिर आवासीय मध्य विद्यालय, दरभंगा, पता-श्री कमेश्वरी प्रिया पुअर होम, दरभंगा	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-14/2019-01/सर0सं0 दि0-25.08.2019	999/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
28.	Darbhanga	पर्यवेक्षण गृह, दरभंगा, पता-सैदनगर, नियर लोहिया चौक, लहेरिया सराय, दरभंगा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-22/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0 -04.09.2041	



29.	Darbhanga	बाल गृह (बालक), दरभंगा, पता-पर्यवेक्षण गृह कैम्पस, सैदनगर, नियर लोहिया चौक, लहेरिया सराय, दरभंगा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-35/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2042	
30.	Darbhanga	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, दरभंगा, पता-पर्यवेक्षण गृह, सैदनगर, नियर लोहिया चौक, लहेरिया सराय, दरभंगा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-81/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2043	
31.	Darbhanga	गोदावरी सेवा आश्रम, कबीर चक, दोनार गुमती, दरभंगा	21/12/2018 से 20/12/2023 तक दि0-पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-217 20.12.2018	969/आ0नि0को0	
32.	Gaya	गया नेत्रहीन विद्यालय, चाकन्द बाजार, गया	22/06/2017 से 21/06/2020 तक तीन वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-119	268/आ0नि0को0 दि0-06.09.2017	
33.	Gaya	बुद्धम शरणम, इस्लामगंज, कटारी हील, चन्दौती, गया	16/12/2019 से 15/12/2024 तक तीन वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-229	1399/आ0नि0को0 दि0-16.12.2019	
34.	Gaya	पर्यवेक्षण गृह, गया, पता-सी0आर0पी0एफ0 कैम्पस, जेल रोड, गया	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-16/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2044	
35.	Gaya	बाल गृह (बालक), गया, पता-159, सी0आर0पी0एफ0 कैम्पस, गया	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-49/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2045	
36.	Gaya	बाल गृह (बालिका), गया, पता-नस्तीपुर, बोधगया, गया	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-59/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2046	
37.	Gaya	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, गया	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-83/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2047	
38.	Gaya	वृद्धाश्रम 'सहारा', गया	27.08.2019 से 26.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-से 16/2019-92/सर0सं0 दि0-27.08.2019	1005/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
39.	Gaya	अल्पावास गृह, गया, पता-द्वारा श्री मोहन कुमार, मोहल्ला झुमरी टाड़, थाना-विष्णु पथ, गया	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-107/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
40.	Gopalganj	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, गोपालगंज, पता-हजियापुर खांड, डी.एन.पी. स्कूल के नजदीक, गोपालगंज	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-75/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2050	
41.	Gopalganj	'महिला विकास एवं जन जागृति मंच', ग्राम-छितौना, पो0-छितौना, माया-बथुआ बाजार, जिला-गोपालगंज	31/07/2019 से 30/07/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-223	865/आ0नि0को0 दि0-31.07.2019	
42.	Jamui	पर्यवेक्षण गृह, जमुई, पता-नीमारंग, जमुई खैरा मुख्य मार्ग, जमुई-811307	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-26/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2051	
43.	Jamui	अल्पावास गृह, जमुई, पता-सिकन्दरा रोड, शारदा पेट्रोलियम के सामने, जमुई	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-105/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
44.	Jamui	बाल गृह (बालक), जमुई, पता-सिरचन्द नवादा, वार्ड नं0-8, नियर झाझा बस स्टैंड, जमुई	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-45/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2053	
45.	Jehanabad	अल्पावास गृह, जहानाबाद, पता-द्वारा श्री सत्यनारायण शर्मा, ऐसेन्ट पब्लिक स्कूल कैम्पस, स्वामी सहजानन्द नगर	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-108/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2054	



46.	<b>Kaimur</b>	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, कैमूर, पता-नीयर कैमूर स्तम्भ, वार्ड नं0-18, भभुआ, कैमूर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-72/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2055	
47.	<b>Katihar</b>	विशाल जागृति फाउण्डेशन, पी0 एण्ड टी चौक, बरमसिया, वार्ड नं0-8, जिला-कटिहार	20/07/2018 से 19/07/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-206	444/आ0नि0को0 दि0-20.07.2018	
48.	<b>Katihar</b>	बाल गृह (बालक), कटिहार, छापी, पोस्ट-थाना-रौतारा, गोविन्दपुर, कटिहार	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-43/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2056	
49.	<b>Katihar</b>	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, कटिहार	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-70/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2057	
50.	<b>Khagaria</b>	'ओउम त्रिमूर्ति संगम पीठ', बाबू चकला, महदीपुर, पसरहा, खगड़िया	11/10/2019 से 10/10/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-225	1114/आ0नि0को0 दि0-10.10.2019	
51.	<b>Kishanganj</b>	बाल गृह (बालक), किशनगंज, पता-कस्टम चौक के निकट, रङ्घासा कॉलोनी, किशनगंज	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-42/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2058	
52.	<b>Kishanganj</b>	बाल गृह (बालिका), किशनगंज, पता-पुलिस लाईन, शीतला चौक, किशनगंज, बिहार	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-57/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2059	
53.	<b>Madhepura</b>	पर्यवेक्षण गृह, मधेपुरा, पता-सुखासन मधेपुरा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-28/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2060	
54.	<b>Madhepura</b>	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, मधेपुरा, पता-साधु पथ, वार्ड नं0-2, मधेपुरा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-69/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2061	
55.	<b>Madhubani</b>	बाल गृह (बालक), मधुबनी, पता-हनुमान बाग कॉलोनी, वार्ड नं0-12, मंगरौनी दक्षिण, मधुबनी	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-47/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2062	
56.	<b>Madhubani</b>	बाल गृह (बालिका), मधुबनी, पता-सूरजगंज, बाँका चौक, वार्ड नं0-27, मधुबनी	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-58/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2063	
57.	<b>Madhubani</b>	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, मधुबनी, पता- जिला बाल संरक्षण इकाई, मधुबनी	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-68/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2064	
58.	<b>Madhubani</b>	अखण्ड दीप शिक्षा, ग्राम-सतधारा, पो0-सतधारा, माया-रैयाम सुगर फ़ैक्ट्री, थाना-रहिका, जिला-मधुबनी	03/08/2018 से 02/08/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-207	503/आ0नि0को0 दि0-03.08.2018	
59.	<b>Motihari</b>	पर्यवेक्षण गृह, पूर्वी चम्पारण, पता-सिविल कोर्ट के बगल में, मोतिहारी	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-21/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2065	
60.	<b>Motihari</b>	बाल गृह (बालक), मोतिहारी, पता-महर्षि नगर, वार्ड नं0-38, छोटा बरियारपुर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-50/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2066	
61.	<b>Motihari</b>	बाल गृह (बालिका), पूर्वी चम्पारण, पता-ग्राम बनकट, पो0-बरियारपुर, मोतिहारी	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-60/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2067	
62.	<b>Motihari</b>	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, पूर्वी चम्पारण, पता-बनकट, पो0-बरियारपुर, मोतिहारी	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-65/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2068	



63.	Munger	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, मुंगेर, पता-बलुआ घाट, मुंगेर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-87/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2069	
64.	Munger	राजकीय मूक-बधिर आवासीय मध्य विद्यालय, सदर प्रखण्ड मुंगेर, पता-सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, मुंगेर	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-14/2019-08/सर0सं0 दि0-25.08.2019	999/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
65.	Munger	पर्यवेक्षण गृह, मुंगेर, पता-बबुआ घाट, जिला परिसर, मुंगेर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-17/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2071	
66.	Munger	बाल गृह (बालक), मुंगेर, पता-बबुआ घाट रोड, समाहरणालय, मुंगेर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-48/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2072	
67.	Muzaffarpur	शांति कुटीर, मुजफ्फरपुर, पता-राम दयाल, बस स्टैंड, मुजफ्फरपुर	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-15/2019-13/सर0सं0 दि0-25.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2073	
68.	Muzaffarpur	पर्यवेक्षण गृह, मुजफ्फरपुर, पता-सिकन्दरपुर, वार्ड नं0-13, मुजफ्फरपुर-842001	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-24/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2074	
69.	Muzaffarpur	बाल गृह (बालक), मुजफ्फरपुर, पता-सिकन्दरपुर स्टेडियम, पावर ग्रिड के नजदीक, मुजफ्फरपुर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-33/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2075	
70.	Muzaffarpur	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, मुजफ्फरपुर, पता-रेलवे गुमटी नं0-6, खबड़ा, मुजफ्फरपुर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-80/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2076	
71.	Muzaffarpur	रानी लक्ष्मी बाई महिला विकास समिति, ग्राम-सुस्ता, थाना-सदर, जिला-मुजफ्फरपुर	07/10/2019 से 06/10/2024 तक तीन वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-158	800/आ0नि0को0 दि0-18.07.2019	
72.	Muzaffarpur	शुभम (विकलांग विकास संस्थान), पता-फरदोगोला, रेवा रोड, जिला-मुजफ्फरपुर	13/03/2018 से 12/03/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-2	149/आ0नि0को0 दि0-11.05.2018	
73.	Muzaffarpur	बाबा गरीब नाथ विकलांग-सह-जनसेवा संस्थान, कलमबाग चौक, मुजफ्फरपुर	22/05/2018 से 21/05/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-140	148/आ0नि0को0 दि0-11.05.2018	
74.	Nalanda	शांति कुटीर, नालन्दा, पता-मयड़ा, नालन्दा	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-15/2019-11/सर0सं0 दि0-25.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2077	
75.	Nalanda	पर्यवेक्षण गृह, नालन्दा, पता-देवी सराय, चक रसलपुर पथ, बिहारशरीफ	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-27/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2078	
76.	Nalanda	बाल गृह (बालक), नालन्दा, पता-कमरुद्दीन गंज, पो0-बिहारशरीफ, नालन्दा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-41/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2079	
77.	Nalanda	'श्री अरविन्द फाउण्डेशन', एन0एच0-33, ग्राम-अजनौरा, पो0-अजनौरा, जिला-नालन्दा	10/10/2019 से 09/10/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-221	1110/आ0नि0को0 दि0-10.10.2019	
78.	Nawada	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, नवादा, पता-अम्बेदकर नगर, सद्भावना चौक, नवादा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-73/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2080	
79.	Nawada	विकलांग समान संस्थान, परपा मोड़, राजगीर रोड, नवादा	22/04/2019 से 21/04/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-216	445/आ0नि0को0 दि0-22.04.2019	



80.	Patna	राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय, पटना, पता-कदमकुआँ, पटना-800003	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-14/2019-03/सर0सं0 दि0-25.08.2019	999/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
81	Patna	राजकीय मूक-बधिर मध्य बालक विद्यालय, पटना, पता-महेन्द्र, पटना-800006	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-14/2019-04/सर0सं0 दि0-25.08.2019	999/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
82.	Patna	राजकीय मूक-बधिर मध्य बालिका विद्यालय, पटना, पता-गायघाट, पटना-800007	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-14/2019-05/सर0सं0 दि0-25.08.2019	999/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
83.	Patna	शांति कुटीर, पटना, पता-शांति कुटीर महिला पुनर्वास केंद्र, मकान सं0-135, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना-800013	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-15/2019-09/सर0सं0 दि0-25.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2084	
84.	Patna	सेवा कुटीर, पटना, पता-शिवपुरी, पटना	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-15/2019-10/सर0सं0 दि0-25.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2085	
85.	Patna	पर्यवेक्षण गृह, पटना, पता-गायघाट, पटना	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-14/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2086	
86.	Patna	विशेष गृह, पटना, पता-गायघाट, पटना-800007	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-15/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2087	
87.	Patna	बाल गृह (बालक), पटना, पता-पुनाईचक, ललित भवन के पीछे, बेली रोड, पटना	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-30/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2088	
88.	Patna	बाल गृह (बालक), पटना	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-40/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2089	
89.	Patna	बाल गृह (बालक), पटना, पता-मेवा साव लेन, सुलतानगंज, पटना	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-46/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2090	
90.	Patna	बाल गृह (बालिका), निशांत पटना, पता-गायघाट, पटना	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-53/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2091	
91.	Patna	बाल गृह (बालिका), पटना, पता-नाजरथ हॉस्पिटलकेम्पस, मोकाना	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-61/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2092	
92.	Patna	बाल गृह (बालिका), पटना, पता-अब्दीन हाऊस, फ्रेजर रोड, पटना-01	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-62/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2093	
93.	Patna	बाल गृह (बालिका), पटना, पता-उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-64/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2094	
94.	Patna	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, पटना, पता-भोजपुर कोठी, लेखानगर, खगौल कैन्ट रोड, डी0ए0भी0 स्कूल, दानापुर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-77/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2095	
95.	Patna	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, पटना, पता-रूपसपुर नगर रोड, पीलर संख्या-98, पटना	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-78/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2096	
96.	Patna	वृद्धाश्रम 'सहारा', पटना	27.08.2019 से 26.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-16/2019-93/सर0सं0 दि0-27.08.2019	1005/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
















97.	Patna	आसरा गृह, पटना	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	संसं0-04/निबंधन- 14/2019-96/सर0सं0 दि0-25.08.2019		
98.	Patna	रक्षा गृह, पटना, पता-द्वारा श्री अशोक कुमार सिंह, (तौमर हाऊस), विधि नगर, गोला रोड, पटना	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	संसं0-04/निबंधन- 17/2019-97/सर0सं0 दिनांक-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
99.	Patna	फाउण्डेशन फॉर इन्टेग्रल ह्यूमन एडवांसमेंट, चाणक्यनगर, विकलांग स्कूल परिसर, कुम्हारार, पटना	21/05/2018 से 20/05/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-162	219/आ0नि0को0 दि0-29.05.2018	
100.	Patna	संकल्पज्योति, अशोक नगर-1, कंकड़बाग, पटना	22/05/2017 से 21/05/2020 तक तीन वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-196	46/आ0नि0को0 दि0-23.05.2017	
101.	Patna	आयुर्वेदिक एण्ड नेचुरेलेपी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, एन0एम0सी0एच0 हॉस्पिटलरोड, अगमकुआँ, पटना	22/05/2017 से 21/05/2020 तक तीन वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-197	48/आ0नि0को0 दि0-23.05.2017	
102.	Patna	मेगा इन्टरनेशनल, मुहल्ला-शियानारायण निकेतन, सरस्वती लेन, लोहानीपुर, कदमकुआँ, पटना	20/09/2018 से 19/09/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-208	717/आ0नि0को0 दि0-24.09.2018	
103.	Patna	बिहार राज्य बाल कल्याण परिषद, राजमवन, पटना	04/07/2017 से 03/07/2020 तक तीन वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-209	195/आ0नि0को0 दि0-22.05.2018	
104.	Patna	चाईल्ड कनसर्न, न्यूबहादुरपुर, बाजार समिति रोड, पटना	08/05/2020 से 07/05/2025 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-139	782/आ0नि0को0 दि0-08.05.2020	
105.	Patna	उत्कर्ष सेवा संस्थान, 2एच/77, बहादुरपुर हाऊसिंग कॉलोनी, पटना	05/06/2017 से 04/06/2020 तक तीन वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-199	71/आ0नि0को0 दि0-05.06.2017	
106.	Patna	समर्पण*, स्पेशल स्कूल, इलाहीबाग, पटना गया रोड, बादशाही पैन, नया बस स्टैंड बैरिया के पास, पटना	23/06/2020 से 22/06/2025 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-202	915/आ0नि0को0 दि0-23.06.2020	
107.	Patna	आनन्द विहार, गाँधीपुरम, पूर्वी रूपसपुर, पो0-नेटनरी कॉलेज, जिला-पटना	16/04/2018 से 15/04/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-203	116/आ0नि0को0 दि0-16.04.2018	
108.	Patna	बिहार विकलांग खेल अकादमी, 103, शीला कॉम्प्लेक्स, न्यूबहादुरपुर, बाजार समिति रोड, पटना	11/05/2018 से 10/05/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-204	147/आ0नि0को0 दि0-11.05.2018	
109.	Patna	पाटलीपुत्रा प्रैक्टिस एसोसिएशन ऑफ हैण्डिकैड, प्रकाश कोल्ड स्टोरेज, नासरीगंज दीघा, दानापुर, पटना	21/12/2018 से 20/12/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-214	970/आ0नि0को0 दि0-20.12.2018	
110.	Patna	उमंग बाल विकास आवासीय विकलांग प्रशिक्षण संस्थान, फेयर फिल्ड कॉलोनी, दीघा, पो0-दीघा, थाना-दीघा, पटना	20/10/2017 से 19/10/2022 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-131	107/आ0नि0को0 दि0-26.03.2018	
111.	Patna	आस्था चैरिटेबुल एण्ड वेलफेयर सोसायटी, F-104, NTPC, फेज-2, आशियाना नगर, पटना	24/11/2018 से 23/11/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-181	461/आ0नि0को0 दि0-25.04.2019	
112.	Patna	'मानव मानवी समाज कल्याण केन्द्र', बेऊर, पटना	13/08/2019 से 12/08/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-224	914/आ0नि0को0 दि0-13.08.2019	
113.	Patna	'स्टेट सोसायटी फॉर अल्टा पुअर एण्ड सोशल वेलफेयर (सक्षम), अपना घर, ललित भवन के पीछे, बेली रोड, पटना	09/08/2019 से 08/08/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-180	775/आ0नि0को0 दि0-10.07.2019	



114.	Patna	*जीवन ज्योति विकलांग सेवा संस्थान*, फेयर फिल्ड कॉलोनी, दीया घाट, पटना	28/10/2019 से 27/10/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-182	1169/आ0नि0को0 दि0-28.10.2019	
115.	Patna	*बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटीज*, पटेल कॉलोनी, संदलपुर, पो0-महेन्द्र, थाना-बहादुरपुर, पटना	30/10/2019 से 29/10/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-226	1181/आ0नि0को0 दि0-30.10.2019	
116.	Patna	*बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन*, 103, शीला कॉम्प्लेक्स, न्यूबहादुरपुर, बाजार समिति रोड, राजेन्द्र नगर, पटना	26/11/2019 से 25/11/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-228	1282/आ0नि0को0 दि0-26.11.2019	
117.	Patna	सिविल सोसाइटी फोरम*, एम0आई0जी0, 91, कंकड़बाग कॉलोनी, पटना	25/11/2019 से 26/11/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-227	1277/आ0नि0को0 दि0-22.11.2019	
118.	Patna	बिहार नेत्रहीन परिषद*, कुम्हारार, पटना	08/08/2018 से 07/08/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-147	558/आ0नि0को0 दि0-25.02.2020	
119.	Purnea	शांति कुटीर, पूर्णियाँ, पता-महिला मिश्रक पुनर्वासि गृह, संत कबीर नगर, पूर्णियाँ	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-15/2019-12/सर0सं0 दि0-25.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2100	
120.	Purnea	पर्यवेक्षण गृह, पूर्णियाँ, पता-श्रीनगर हाता, पूर्णियाँ-854301	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-18/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2101	
121.	Purnea	बाल गृह (बालक), पूर्णियाँ, पता-श्रीनगर हाता, पूर्णियाँ	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-39/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2102	
122.	Purnea	बाल गृह (बालिका), पूर्णियाँ, पता-जाफरी बाग, नियर इंडस्ट्री रोड, चाँदनी चौक, पूर्णियाँ	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-56/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2103	
123.	Purnea	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, पूर्णियाँ, पता- श्रीमती सुशीला देवी, सब्जी मण्डी चौक, भट्टा बाजार, पूर्णियाँ	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-86/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2104	
124.	Purnea	वृद्धाश्रम 'सहारा', पूर्णियाँ	27.08.2019 से 26.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-16/2019-94/सर0सं0 दि0-27.08.2019	1005/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
125.	Purnea	अल्पावास गृह, पूर्णियाँ, पता-एन0-31, बाईपास रोड, बैरियर के नजदीक, पूर्णियाँ	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-98/सर0सं0 दिनांक-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
126.	Rohtas	रोगी कल्याण समिति, सदर अस्पताल, सासाराम (रोहतास)	04/01/2019 से 03/01/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-215	07/आ0नि0को0 दि0-04.01.2019	
127.	Rohtas	बाल गृह (बालक), रोहतास, पता-कोयला डीपो, जी0टी0 रोड सखरा, पो0-खैरहॉ, डेहरी ऑन सोन, रोहतास	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-36/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2107	
128.	Rohtas	वृद्धाश्रम 'सहारा', रोहतास	27.08.2019 से 26.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-16/2019-95/सर0सं0 दि0-27.08.2019	1005/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
129.	Saharsa	बाल गृह (बालक), सहरसा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-37/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2109	
130.	Saharsa	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, सहरसा, पता-कोसी चौक, सहरसा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-84/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2110	



131.	Samastipur	बाल गृह (बालक), समस्तीपुर, पता-डॉ० अमिलाषा सिंह, आर०एन०आर० कॉलेज रोड, समस्तीपुर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं०सं०-04/निबंधन-18/2019-44/सर०सं० दि०-26.08.2019	1000/आ०नि०को० दि०-04.09.2111	
132.	Samastipur	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, समस्तीपुर, पता-ममता शिशु गृह, क्रियेशन इंडिया सोसायटी, 12 पत्थर, समस्तीपुर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं०सं०-04/निबंधन-18/2019-76/सर०सं० दि०-26.08.2019	1000/आ०नि०को० दि०-04.09.2112	
133.	Samastipur	अल्पावास गृह, समस्तीपुर, पता-गायत्री कॉम्प्लेक्स, नियर आई०डी०बी०आई० बैंक, समस्तीपुर	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं०सं०-04/निबंधन-17/2019-100/सर०सं० दि०-28.08.2019	1006/आ०नि०को० दि०-04.09.2019	
134.	Saran	पर्यवेक्षण गृह, सारण, पता-निकट भरत मिलाप चौक, मण्डल कारा के पीछे, सारण मिलाप चौक, मण्डल कारा के पीछे, सारण	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं०सं०-04/निबंधन-18/2019-20/सर०सं० दि०-26.08.2019	1000/आ०नि०को० दि०-04.09.2114	
135.	Saran	बाल गृह (बालक), सारण, पता-प्रभुनाथ नगर, छपरा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं०सं०-04/निबंधन-18/2019-38/सर०सं० दि०-26.08.2019	1000/आ०नि०को० दि०-04.09.2115	
136.	Saran	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, सारण, पता-नियर छपरा सेंट्रल स्कूल, साहा, छपरा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं०सं०-04/निबंधन-18/2019-82/सर०सं० दि०-26.08.2019	1000/आ०नि०को० दि०-04.09.2116	
137.	Saran	बाल गृह (बालिका), सारण, पता-खेमाजी टोला, साँढा, छपरा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं०सं०-04/निबंधन-18/2019-54/सर०सं० दि०-26.08.2019	1000/आ०नि०को० दि०-04.09.2117	
138.	shekhpura	सुरक्षित स्थान, शेखपुरा, पता-मटोखर दाह, शेखोपुर सहाय रोड, शेखपुरा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं०सं०-04/निबंधन-18/2019-29/सर०सं० दि०-26.08.2019	1000/आ०नि०को० दि०-04.09.2118	
139.	Sheohar	अल्पावास गृह, शिवहर, पता-द्वारा अरविन्द कुमार सिंह, वार्ड नं०-09, महिला पुलिस के सामने, पोस्ट ऑफिस के बगल में, शिवहर	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं०सं०-04/निबंधन-17/2019-99/सर०सं० दिनांक-28.08.2019	1006/आ०नि०को० दि०-04.09.2019	
140.	Sitamarhi	बाल गृह (बालक), सीतामढ़ी, पता-वरियारपुर, सीतामढ़ी	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं०सं०-04/निबंधन-18/2019-51/सर०सं० दि०-26.08.2019	1000/आ०नि०को० दि०-04.09.2120	
141.	Sitamarhi	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, सीतामढ़ी, पता-सीमरा रोड, सीतामढ़ी	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं०सं०-04/निबंधन-18/2019-66/सर०सं० दि०-26.08.2019	1000/आ०नि०को० दि०-04.09.2121	
142.	Sitamarhi	आर०एन०टी० सर्वोदय (आ०) विकलांग विकास संस्थान, कैलाशपुरी, डुमरा, सीतामढ़ी	04/07/2017 से 03/07/2020 तक तीन वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-212	136/आ०नि०को० दि०-04.07.2017	
143.	Siwan	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, सिवान, पता-नयी बस्ती, फतेहपुर, सिवान	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं०सं०-04/निबंधन-18/2019-71/सर०सं० दि०-26.08.2019	1000/आ०नि०को० दि०-04.09.2122	
144.	Siwan	अल्पावास गृह, सिवान, पता-रेड क्रॉस भवन, सिवान	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं०सं०-04/निबंधन-17/2019-103/सर०सं० दि०-28.08.2019	1006/आ०नि०को० दि०-04.09.2019	
145.	Siwan	सिवान नवज्योति उत्थान संस्थान, ग्राम-जगदम्बा नगर, पो०-जगदम्बा नगर, पंचमंदिर, जिला-सिवान	22/05/2017 से 21/05/2020 तक तीन वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-198	51/आ०नि०को० दि०-23.05.2017	
146.	Supaul	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, सुपौल, पता-नखुराही, वार्ड नं०-26, सुपौल	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं०सं०-04/निबंधन-18/2019-89/सर०सं० दि०-26.08.2019	1000/आ०नि०को० दि०-04.09.2124	
147.	Supaul	अल्पावास गृह, सुपौल, पता-वार्ड नं०-27, संत नगर, चकला निर्मली, सिंहेश्वर रोड, सुपौल	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं०सं०-04/निबंधन-17/2019-110/सर०सं० दि०-28.08.2019	1006/आ०नि०को० दि०-04.09.2019	





148.	Supaul	'सेवक', सुपौल, भवानीपुर, सीतापुर, सुपौल	19/07/2019 से 18/07/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-220	812/आ0नि0को0 दि0-19.07.2019	
149.	Supaul	जिला स्तरीय सम्पूर्ण विकलांग समावेशी शिक्षा विद्यालय, बैरिया, प्रखण्ड-पिपरा, जिला-सुपौल	24/02/2020 से 23/02/2025 तक पाँच वर्षों के लिए			
150.	Vaishali	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, वैशाली	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-74/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2126	
151.	West Champaran	प्रगति रूरल डेवलपमेन्ट, विक्टोरिया मिशन, पो0-गहिरी, जिला-पश्चिम चम्पारण	01/10/2018 से 30/09/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-211	813/आ0नि0को0 दि0-29.10.2018	
152.	West Champaran	तपोवन बहुविकलांग पुनर्वास संस्थान, करनमेया, लालगढ़, मुफ्सील, बेतिया, पश्चिम चम्पारण	23/11/2017 से 22/11/2020 तक तीन वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-156	533/आ0नि0को0 दि0-23.11.2017	
153.	West Champaran	जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, पुनर्वास भवन, कविवर नेपाली चौक, बेतिया, पश्चिम चम्पारण	30/09/2018 से 29/09/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-210	997/आ0नि0को0 दि0-26.10.2018	
154.	West	बाल गृह (बालक), पश्चिम चम्पारण, पता-झीलिया, वार्ड नं0-5, अमना उर्दू स्कूल के पीछे, छावनी, बेतिया	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-32/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2127	
155.	West	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, पश्चिम चम्पारण, पता-बानू छापर, संत कवि रोड, बेतिया, पश्चिम चम्पारण	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-85/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2128	
156.	West	अल्पावास गृह, पश्चिम चम्पारण, पता-सेवा सदन रोड, पूर्वी बानूछापर, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-102/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	

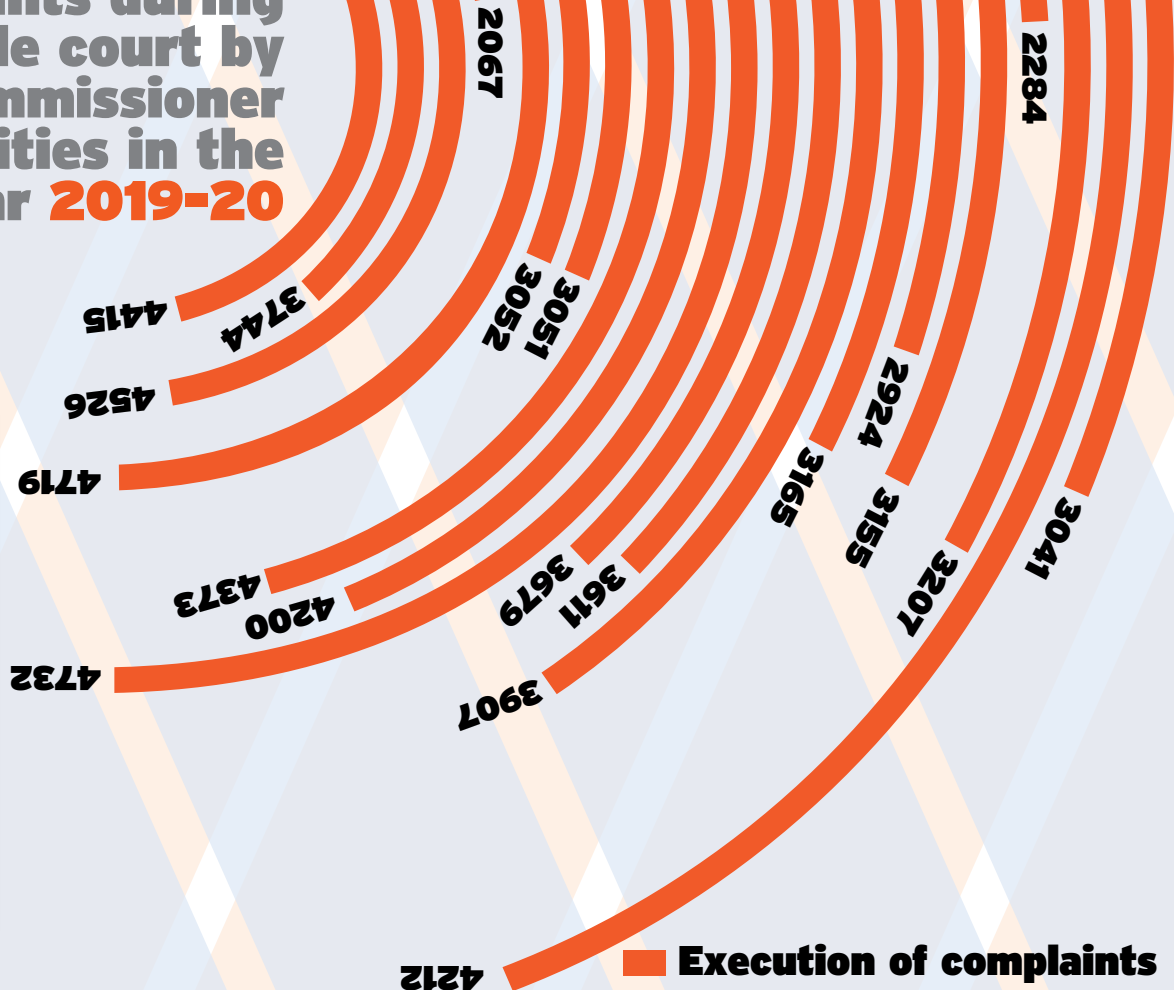
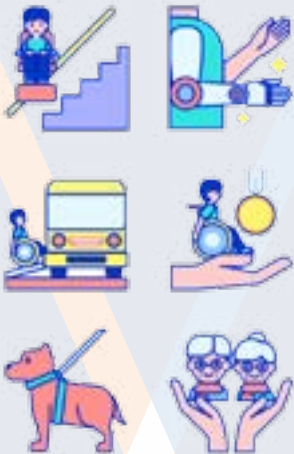
(डॉ0 शिवाजी कुमार)  
राज्य आयुक्त निःशक्तता  
बिहार, पटना।



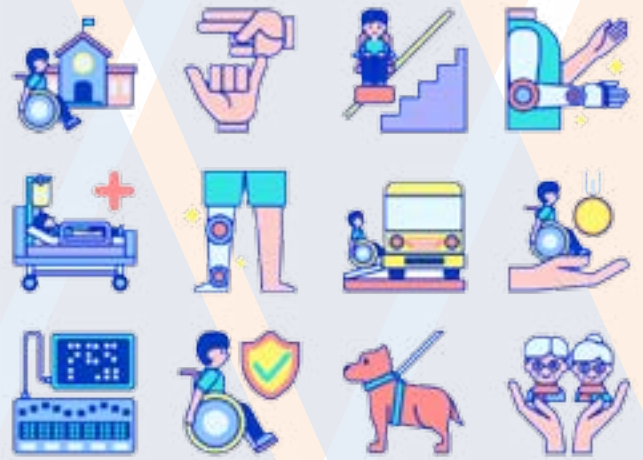
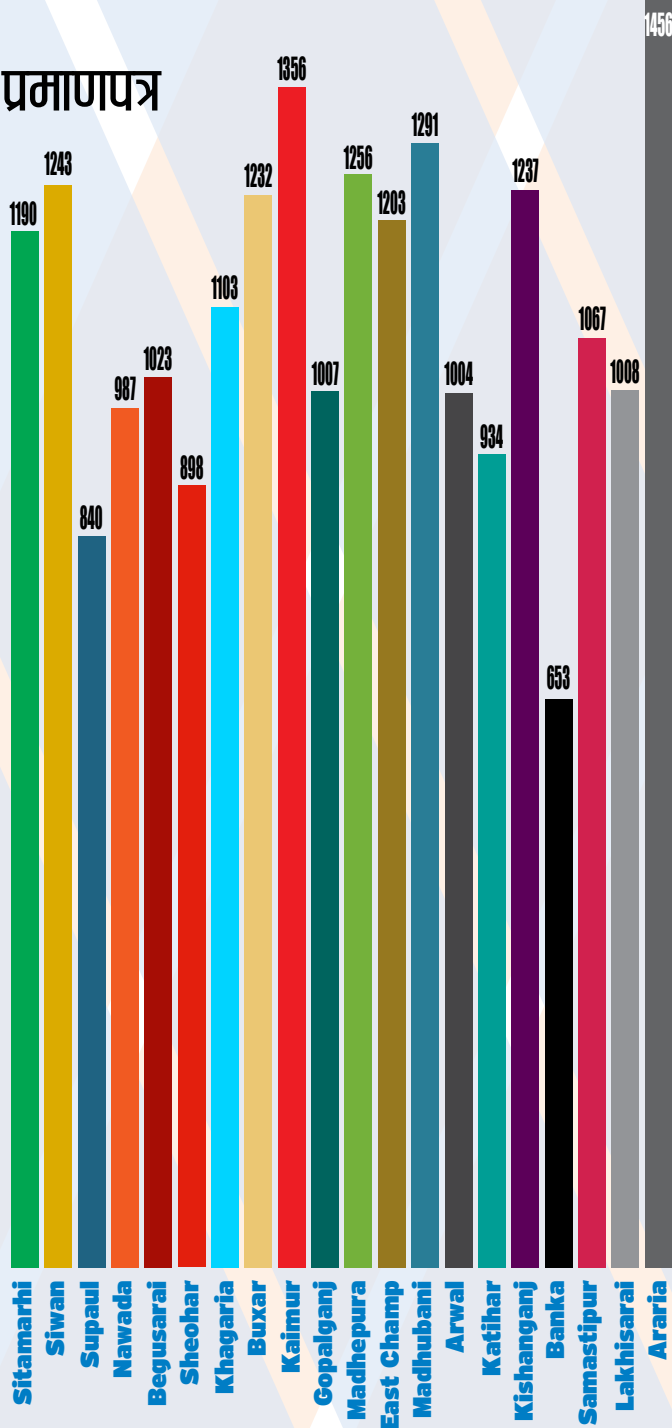
# आंकड़ों/ग्राफ में कुछ उपलब्धियाँ

- Sitamarhi
- Siwan
- Supaul
- Nawada
- Begusarai
- Sheohar
- Khagaria
- Buxar
- Kaimur
- Gopalganj
- Madhepura
- East Champ
- Madhubani
- Arwal
- Katihar
- Kishanganj
- Banka
- Samastipur
- Lakhisarai
- Araria

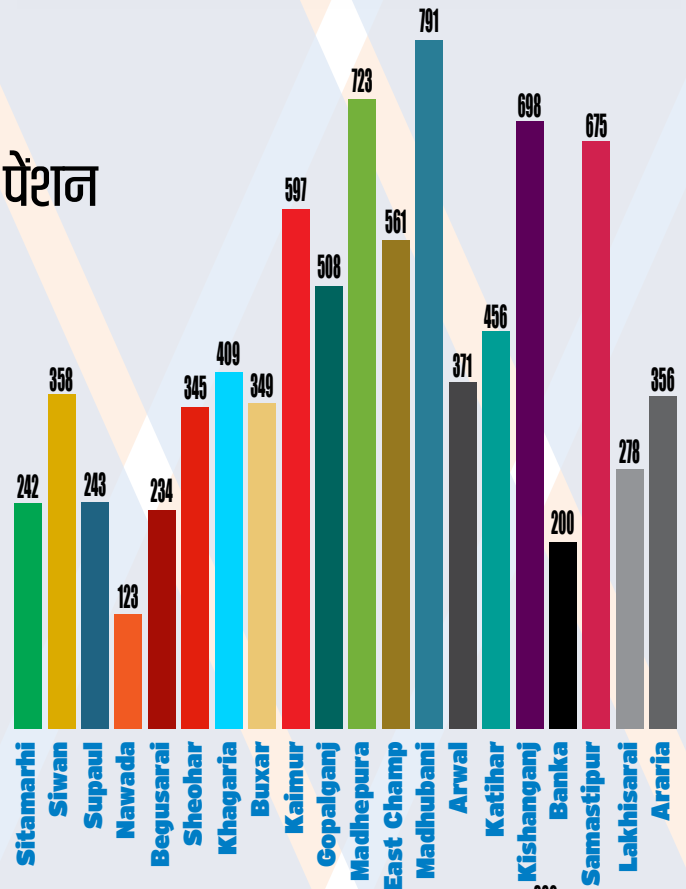
Execution of complaints during mobile court by State Commissioner Disabilities in the year **2019-20**



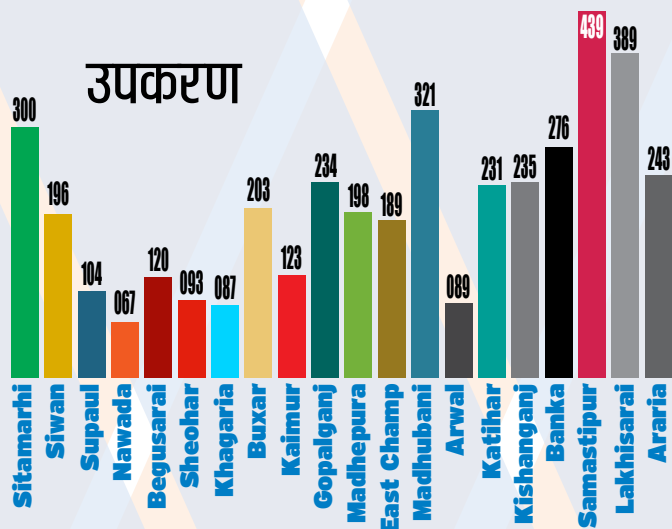
## प्रमाणपत्र



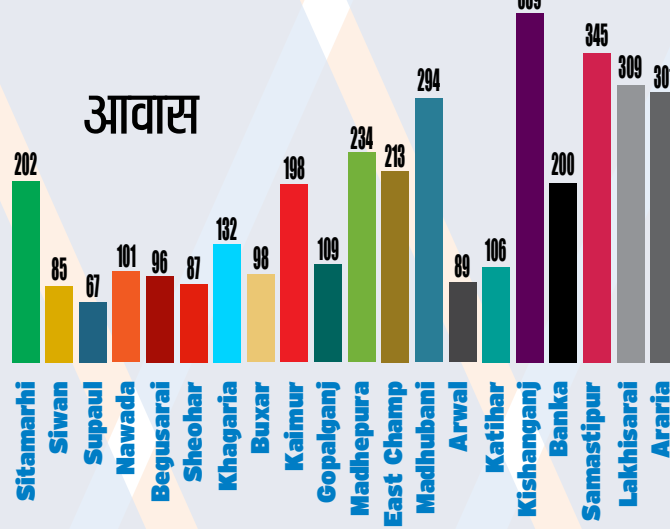
## पेंशन



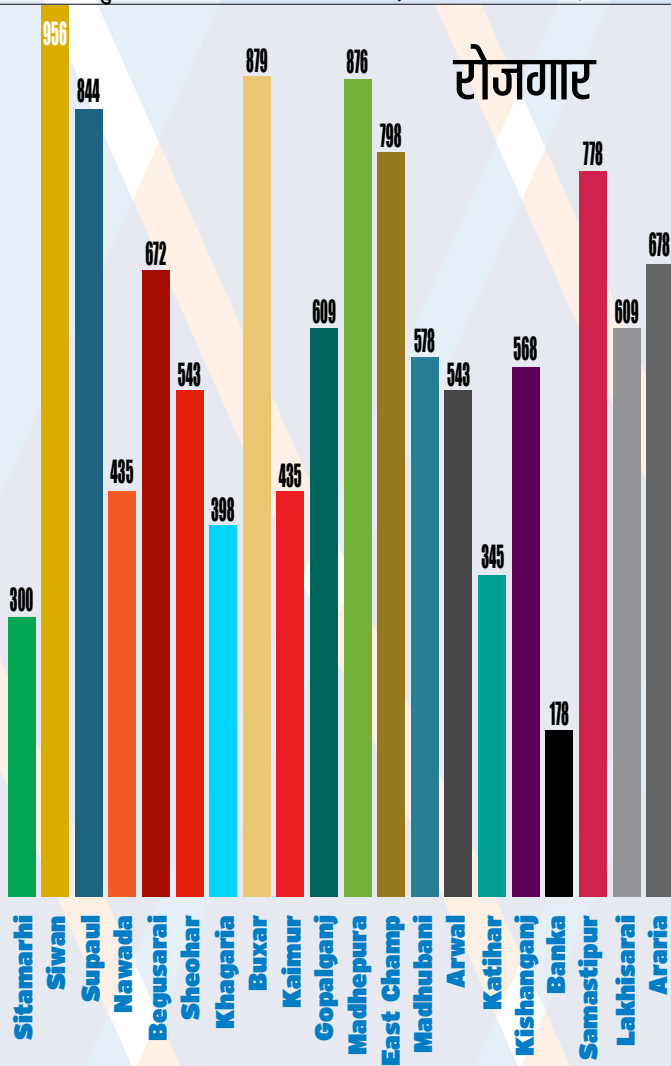
## उपकरण



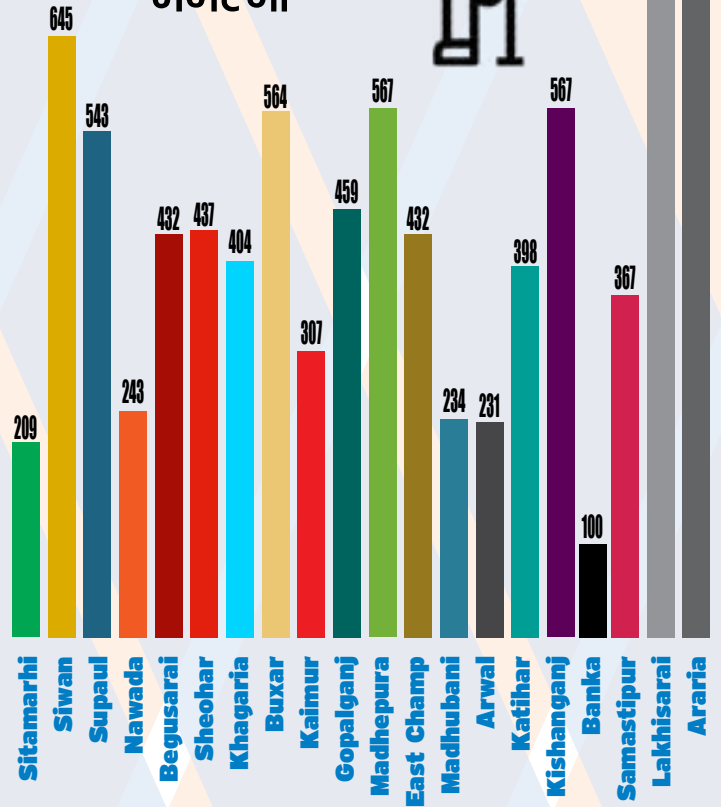
## आवास



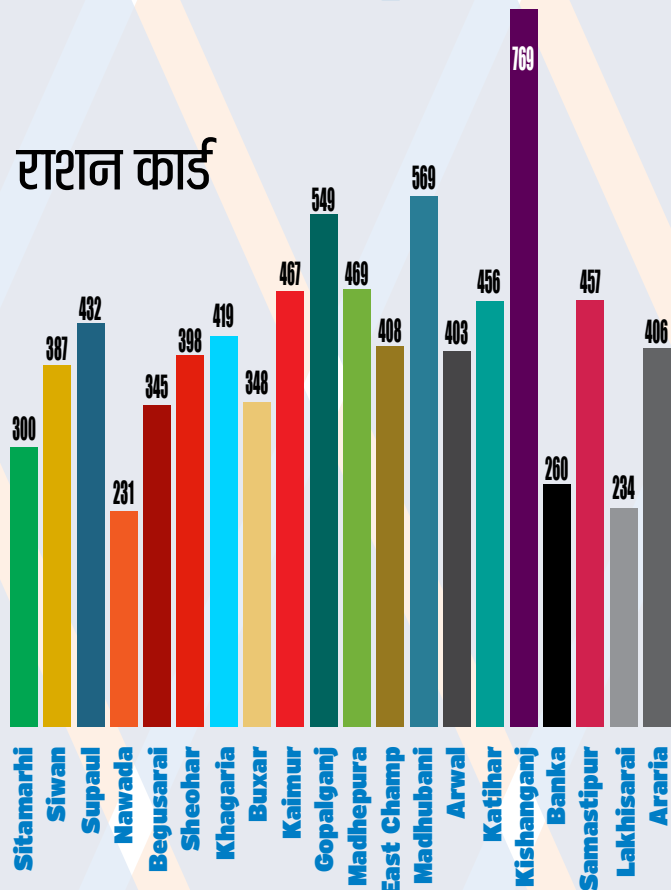
## रोजगार



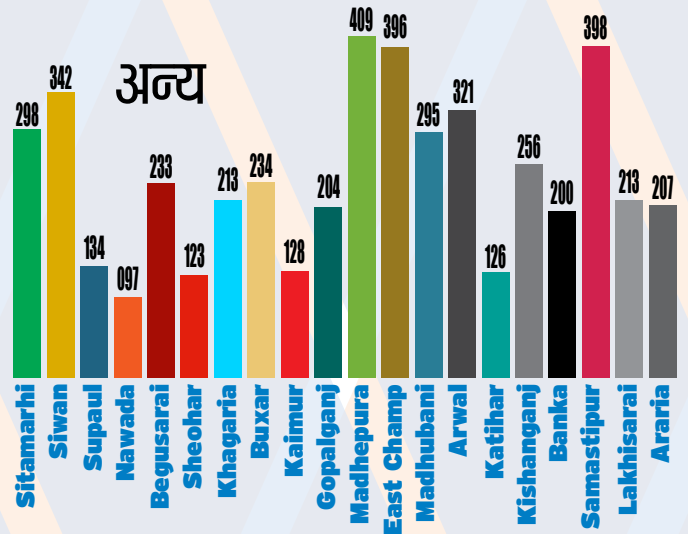
## मनरेगा



## राशन कार्ड



## अन्य



## आभार

मैं डॉ. शंभु कुमार रजक (अपर आयुक्त निःशक्तता) इस वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 के प्रकाशन में अप्रतिम सहयोग हेतु :- श्री वीरेन्द्र कुमार, श्रीमति विद्या कुमारी, डॉ. उमा शंकर सिन्हा, श्री राजकिशोर ठाकुर, श्री हर्ष राज, संतोष कुमार सिन्हा, डॉ. मनोज कुमार, श्री संदीप कुमार, श्री रणधीर कुमार, श्री अनोद सिंह, श्री मनीष कुमार, श्री मुकेश कुमार, श्री राहुल कुमार एवं अनीष कुमार सहित सभी जिला एवं राज्यस्तर के अधिकारियों का राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय की ओर से आभार व्यक्त करते हैं।



क्र०सं०	वाद सं०	जिला	वादी एवं प्रतिवादी	विषय
			एवं अन्य	करने के संबंध में
90.	90/2019	मोतिहारी पूर्वी चम्पारण	वादी :- श्री चितरंजन सिंह, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण प्रतिवादी :- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, पूर्वी चम्पारण	दिव्यांगजनों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु, प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में
91.	91/2019	समस्तीपुर	वादी :- मो० जब्बार, समस्तीपुर प्रतिवादी :- थाना प्रभारी, हथौड़ी, समस्तीपुर एवं अन्य	दिव्यांग पड़ोसी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में
91 a.	91 (क) /2019	वैशाली (हाजीपुर)	वादी :- मो० शहाबुद्दीन, वैशाली (हाजीपुर) प्रतिवादी :- सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, वैशाली (हाजीपुर) एवं अन्य	तिपहीया साइकिल सुलभ कराने से संबंधित
92.	92/2019	पटना	वादी :- श्री दीपक कुमार, पटना प्रतिवादी :- श्री राम पुकार सिंह, पटना एवं अन्य	शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में
93.	93/2019	पटना	वादी :- श्री इशांत कुमार, पटना प्रतिवादी :- प्रधानाध्यपक, Open Minds-A Birla School, Kankarbagh, पटना	परिवहन सुविधा के संबंध में
94.	94/2019	पूर्वी चम्पारण	वादी :- मो० ओबैदुल्लाह, पिता-मो० शमीम अख्तर, पूर्वी चम्पारण प्रतिवादी :- सहायक निदेशक-सह-नोडल, पदाधिकारी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्वी चम्पारण एवं अन्य	टाई साइकिल दिलवाने के संबंध में
95.	95/2019	मुजफ्फरपुर	वादी :- श्री शिवशंकर सहनी, मुजफ्फरपुर प्रतिवादी :- पोस्टमास्टर, शाखा डाकघर, मुजफ्फरपुर, बिहार	डाक विभाग से जीवन निर्वाह हेतु पेंशन की स्वीकृति हेतु
96.	96/2019	पटना	वादी :- श्री महेश कुमार शर्मा, पटना प्रतिवादी :- उप सचिव (स्थापना) पेंशन प्रभारी पदाधिकारी, साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी विभाग, पटना, बिहार	विधि सम्मतघोषण पत्र में शपथ पत्र नहीं देने के कारण जोड़ा नहीं गया है
97.	97/2019	जहानाबाद	वादी :- श्रीमती शांति देवी, जहानाबाद प्रतिवादी :- उपर समाहर्ता (राजस्व), जहानाबाद एवं अन्य	अवैध कब्जा से मुक्त करा कर आवेदिका को कब्जा दिलाने संबंधी।
98.	98/2019	सिवान	वादी :- श्री संतोष कुमार गुप्ता, सिवान प्रतिवादी :- आरक्षी अधीक्षक, सिवान एवं अन्य	प्रतिवादी के परिवार को फँसाने के संबंध में
99.	99/2019	राँची (झारखण्ड)	वादी :- श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, -राँची (झारखण्ड) प्रतिवादी :- अंचलाधिकारी, घनश्यामपुर, दरभंगा, बिहार	दाखिल-खारिज (जमाबंदी) कायम करने के संबंध में
100.	100/2019	मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण	वादी :- मो० फिरोज आलम, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण प्रतिवादी :- सहायक निदेशक-सह-नोडल	मुख्यमंत्री निःशक्तता विवाह प्रोत्साहन योजना







क्र०सं०	वाद सं०	जिला	वादी एवं प्रतिवादी	विषय
			पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	का लाभ सुलभ कराने के संबंध में
101.	101/2019	बक्सर	वादी :- श्री विरेन्द्र चौधरी, पिता-श्री सिद्धनाथ चौधरी, बक्सर प्रतिवादी :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर एवं अन्य	दिव्यांगता पेंशन भुगतान एवं राशन कार्ड बनवाने के संबंध में
102.	102/2019	समस्तीपुर	वादी :- सुश्री संजु कुमारी, पिता- श्री राज मनोज महतो, समस्तीपुर प्रतिवादी :- परीक्षा नियंत्रक (CTET) Central Teacher Eligibility Test, सी०बी०एस०ई० क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली	केन्द्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा में संशोधन करने के संबंध में
103.	103/2019	खगड़िया	वादी :- श्री हरिओम सराफ, पिता-श्री शिव कुमार सराफ, खगड़िया प्रतिवादी :- सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई, खगड़िया एवं अन्य	अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन की राशि दिव्यांग को स्वीकृत करने के संबंध में
104.	104/2019	सिवान	वाद :- श्रीमती विनीता कुमारी, सिवान प्रतिवादी :- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. समाज कल्याण विभाग, सिवान।	(चयन ऑगनवाड़ी सेविका ) आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने के संबंध में।
105.	105/2019	रोहतास	वादी :- श्री चितरंजन कुमार, श्रीमती प्रभा देवी एवं श्रीमती रीता देवी, रोहतास प्रतिवादी:- प्रखंड विकास पदाधिकारी, इन्द्रपुरी, रोहतास।	दिव्यांगता पेंशन भुगतान के संबंध में
106.	106/2019	औरंगाबद	वादी :- श्री रविकान्त चौधरी, औरंगाबद प्रतिवादी :- प्रभारी, प्रधानाध्यापक, राजकीय कादरी मध्य विद्यालय, औरंगाबद	नियुक्ति के उपरांत वेतन भुगतान से वंचित करने एवं सेवा से हटाने के संबंध में
107.	107/2019	पटना	वादी :- डॉ० शिव कुमार, पटना। प्रतिवादी :- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	पेंशन एवं बकाया के संबंध में
108.	108/2019	गया	वादी :- श्री शत्रुघन शर्मा, मानपुर, गया। प्रतिवादी :- थाना प्रभारी, मानपुर, गया एवं अन्य	पुत्र एवं पुत्रवध के द्वारा दिव्यांगता पिता को प्रताड़ित करने के संबंध में



# दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रवृत्त होने के पश्चात के वित्तीय वर्षों में कार्यालय से संबंध कार्य बिन्दुओं पर स्थिति

क्र० सं० कार्य के बिन्दु	2017-18	2018-19	2019-20
<b>1. अधिनियम के अनुपालन से सम्बन्धित बैठक/निरीक्षण</b>			
(a) क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक	---	423	568
(b) एडवोकेसी बैठक	---	673	1122
(c) सार्वजनिक स्थलों/भवनों का एक्सेस ऑडिट	---	98	123
(4) ऑन स्पॉट/ ग्राउड जीरो निरीक्षण	---	46	88
(e) औचक निरीक्षण	---	25	38
2. चलन्त न्यायालय & 'न्यायालय आपके द्वार' का आयोजन	01	23	38
<b>3. अनुपालन स्थिति के सम्बन्ध में स्थलीय समीक्षा</b>	---	38 जिला, 454 प्रखण्ड एवं 7081 पंचायत	
4. परिवादों/वादों का निष्पादन	115	1.3 लाख	1.9 लाख
(a.) कार्यालय पत्र के माध्यम से	104	205	368
(b.) न्यायालयीय प्रक्रिया द्वारा (स्थायी कोर्ट के माध्यम से)	11	86	108
(c.) चलन्त न्यायालय के माध्यम से	---	59694	72064
(d.) कार्यालय को प्राप्त पत्रों का त्वरित निष्पादन	05	208	487
(e.) व्यक्तिगत रूप से समस्याओं को सुनना (कार्यालय में उपस्थित दिव्यांग) एवं निष्पादन/सलाह	12	232	327
(f.) Helpline Number पर प्राप्त शिकायतों का निष्पादन	---	13580	23107
(g.) बेवसाइट के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त शिकायतों का निष्पादन	---	421	534
(h.) ई-मेल माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निष्पादन	18	912	1209
(i.) Voice मेल से प्राप्त शिकायतों का निष्पादन	---	417	532
(j.) मोबाईल/व्हाटसऐप माध्यम से प्राप्त शिकायतों /सुझाव/निर्देश/समाधान	22	32000	58000
(k.) सोशल मीडिया माध्यम-ट्यूटर, फेसबुक से जनजागरूकता	---	32 लाख	60 लाख
5. कार्यालय की गतिविधियों का समाचार पत्रों में प्रकाशन	08	212	302
6. व्यापक जनजागरूकता अभियान (Mass Awareness Campaign)	02	83	108
7. संस्थाओं का अनुश्रवण	08	23	58
8. अधिनियम के अनुपालनार्थ पदाधिकारियों के साथ बैठकें	02	11	17
9. निर्गत पत्रों की संख्या	568	1218	1456
10. महत्वपूर्ण दिवसों एवं कार्यशाला/सेमिनार/कॉन्फ्रेंस का आयोजन	---	16	18
11. प्रकाशित पुस्तकों व पॅम्पलेट्स की संख्या	---	2+5	1+4
12. सरकारी/गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं का निबंधन	08	11	123



कवच • अग्रज डॉ. शिवजी कुमार ने कवच- खा से जने एवं घर पहुंचने तक को निरभूत कवच आयोग कर रहा ऐसी व्यवस्था कि एक भी दिव्यांग वोट से न चूके

# 426 दिव्यांगों ने रखी समस्याएं

समाधान के निर्देश

ऑनलाइन लोक अदालत में दिव्यांग वने अपनों का सहारा



राज्य में दिव्य अदालत के शुरू कर जने में मदद, जने में सुझाव 1234 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

## विश्व आदिज्म दिवस : 2016 में पहली बार आदिज्म को दिव्यांगता की श्रेणी में लाया गया

रचनात्मक-कलात्मक क्षमता की दुनिया है आदिज्म

आदिज्म को पहली बार आदिज्म की श्रेणी में लाया गया है। यह आदिज्म को रचनात्मक-कलात्मक क्षमता की दुनिया है।

आदिज्म को पहली बार आदिज्म की श्रेणी में लाया गया है। यह आदिज्म को रचनात्मक-कलात्मक क्षमता की दुनिया है।

आदिज्म को पहली बार आदिज्म की श्रेणी में लाया गया है। यह आदिज्म को रचनात्मक-कलात्मक क्षमता की दुनिया है।

आदिज्म को पहली बार आदिज्म की श्रेणी में लाया गया है। यह आदिज्म को रचनात्मक-कलात्मक क्षमता की दुनिया है।

आदिज्म को पहली बार आदिज्म की श्रेणी में लाया गया है। यह आदिज्म को रचनात्मक-कलात्मक क्षमता की दुनिया है।

आदिज्म को पहली बार आदिज्म की श्रेणी में लाया गया है। यह आदिज्म को रचनात्मक-कलात्मक क्षमता की दुनिया है।

आदिज्म को पहली बार आदिज्म की श्रेणी में लाया गया है। यह आदिज्म को रचनात्मक-कलात्मक क्षमता की दुनिया है।

## व्यवहार न्यायालय में दिव्यांगों के लिए स

व्यवहार न्यायालय में दिव्यांगों के लिए स

व्यवहार न्यायालय में दिव्यांगों के लिए स

## बाय इन्व्दिशन

बाय इन्व्दिशन

बाय इन्व्दिशन

बाय इन्व्दिशन

## खरीदी जायेगी 20 लो फ्लोर बसें

खरीदी जायेगी 20 लो फ्लोर बसें

खरीदी जायेगी 20 लो फ्लोर बसें

खरीदी जायेगी 20 लो फ्लोर बसें

## 87.34 लाख राशन कार्डधारियों के खाते में भेजे गए एक-एक हजार रु.

87.34 लाख राशन कार्डधारियों के खाते में भेजे गए एक-एक हजार रु.

87.34 लाख राशन कार्डधारियों के खाते में भेजे गए एक-एक हजार रु.

87.34 लाख राशन कार्डधारियों के खाते में भेजे गए एक-एक हजार रु.

## गिता रस्सा

गिता रस्सा

गिता रस्सा

गिता रस्सा

## दिव्यांगजनों के लिए लोक अदालत कल

दिव्यांगजनों के लिए लोक अदालत कल

दिव्यांगजनों के लिए लोक अदालत कल

दिव्यांगजनों के लिए लोक अदालत कल

## खरीदी जायेगी 20 लो फ्लोर बसें

खरीदी जायेगी 20 लो फ्लोर बसें

खरीदी जायेगी 20 लो फ्लोर बसें

खरीदी जायेगी 20 लो फ्लोर बसें

## गिता रस्सा

गिता रस्सा

गिता रस्सा

गिता रस्सा

## गिता रस्सा

गिता रस्सा

गिता रस्सा

गिता रस्सा

## मतदान के दिन दिव्यांगों को बूथ पर लाने और घर पहुंचाने की व्यवस्था करेगा प्रशासन : आयुक्त

मतदान के दिन दिव्यांगों को बूथ पर लाने और घर पहुंचाने की व्यवस्था करेगा प्रशासन : आयुक्त

मतदान के दिन दिव्यांगों को बूथ पर लाने और घर पहुंचाने की व्यवस्था करेगा प्रशासन : आयुक्त

मतदान के दिन दिव्यांगों को बूथ पर लाने और घर पहुंचाने की व्यवस्था करेगा प्रशासन : आयुक्त

## दिव्यांग व सामान्य खिलाड़ियों की प्रतियोगिता एक साथ

दिव्यांग व सामान्य खिलाड़ियों की प्रतियोगिता एक साथ

दिव्यांग व सामान्य खिलाड़ियों की प्रतियोगिता एक साथ

दिव्यांग व सामान्य खिलाड़ियों की प्रतियोगिता एक साथ

## न्यूरो दिव्यांग पीड़ितों का इलाज संभव

न्यूरो दिव्यांग पीड़ितों का इलाज संभव

न्यूरो दिव्यांग पीड़ितों का इलाज संभव

न्यूरो दिव्यांग पीड़ितों का इलाज संभव

## जल्द पहचान नहीं होने के कारण राज्य में बढ़ रही है दृष्टि बाधित दिव्यांगता

जल्द पहचान नहीं होने के कारण राज्य में बढ़ रही है दृष्टि बाधित दिव्यांगता

जल्द पहचान नहीं होने के कारण राज्य में बढ़ रही है दृष्टि बाधित दिव्यांगता

जल्द पहचान नहीं होने के कारण राज्य में बढ़ रही है दृष्टि बाधित दिव्यांगता

## कोशिश होगी, थैलेसीमिया

कोशिश होगी, थैलेसीमिया

कोशिश होगी, थैलेसीमिया

कोशिश होगी, थैलेसीमिया

## दिव्यांग खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

दिव्यांग खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

दिव्यांग खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

दिव्यांग खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

## जल्द पहचान नहीं होने के कारण राज्य में बढ़ रही है दृष्टि बाधित दिव्यांगता

जल्द पहचान नहीं होने के कारण राज्य में बढ़ रही है दृष्टि बाधित दिव्यांगता

जल्द पहचान नहीं होने के कारण राज्य में बढ़ रही है दृष्टि बाधित दिव्यांगता

जल्द पहचान नहीं होने के कारण राज्य में बढ़ रही है दृष्टि बाधित दिव्यांगता

## दिव्यांगों का हुआ सम्मान

दिव्यांगों का हुआ सम्मान

दिव्यांगों का हुआ सम्मान

दिव्यांगों का हुआ सम्मान

## बसों धोते थे नारायण, एथलेटिक्स में जीता एशियाड का गोल्ड, ओलंपिक पर नजर

बसों धोते थे नारायण, एथलेटिक्स में जीता एशियाड का गोल्ड, ओलंपिक पर नजर

बसों धोते थे नारायण, एथलेटिक्स में जीता एशियाड का गोल्ड, ओलंपिक पर नजर

बसों धोते थे नारायण, एथलेटिक्स में जीता एशियाड का गोल्ड, ओलंपिक पर नजर

## दैनिक भास्कर 14/03/2021

दैनिक भास्कर 14/03/2021

दैनिक भास्कर 14/03/2021

दैनिक भास्कर 14/03/2021

## दिव्यांगों का हुआ सम्मान

दिव्यांगों का हुआ सम्मान

दिव्यांगों का हुआ सम्मान

दिव्यांगों का हुआ सम्मान

## दिव्यांगों का हुआ सम्मान

दिव्यांगों का हुआ सम्मान

दिव्यांगों का हुआ सम्मान

दिव्यांगों का हुआ सम्मान



19वीं बिहार ऑवार्ड सेरेमनी में भाग लेते दिव्यांगजन और अन्य।



भारत सरकार द्वारा स्टेट कमिश्नर डॉ शिवाजी कुमार सम्मानित होते हुए।



सुपौल के कार्यक्रम में संबोधित करते आयुक्त।



29 दिसंबर 2019 को किशनगंज में दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल मेंट करते आयुक्त।

# कार्यालय

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन), समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार,  
सिंचाई विभाग परिसर पुराना सचिवालय, पटना-800015 बिहार, दूरभाष- 0612-  
2215041, हेल्पलाईन नंबर - 8448385590, वेबसाईट - [www.scdisabilites.org](http://www.scdisabilites.org),  
ईमेल- [scdisability2008@gmail.com](mailto:scdisability2008@gmail.com)